खण्ड-521, अंक-08
मंगलवार, 09 फाल्गुन, शक संवत् 1944
(28 फरवरी, 2023 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2023)

(खण्ड 521 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-147
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ	147-149
जनपद-हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	149
जनपद-हाथरस की सदर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक सासनी में एक महाविद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	149
गत वर्ष 2020 में हुए टोक्यो पैरा ओलम्पिक प्रतियोगिता में सफल हुए प्रतियोगियों के स्टॉफ को सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	150
जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत अहरौरा में नया विकास खण्ड बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	150-151
जनपद-एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के अन्तर्गत ग्राम उभई असदनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	151
जनपद-सहारनपुर के विकास खण्ड पुवांरका के अन्तर्गत ग्राम मुगलमजरा से छपपुरा पीपल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	151
जनपद-बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत परसा पलई डीह विकास खण्ड गैसड़ी में निर्माणाधीन पॉलीटेक्निक का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	151-152
जनपद-आजमगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में सीवर की सफाई कराने हेतु तथा सफाई हेतु लगे मोटरों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	152
जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना में बाढ़ खण्ड की इकाई में सहायक अभियन्ता के पद को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	152-153

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवा की निचलौल तहसील में भू-माफिया द्वारा कब्जा की गई जमीन को मुक्त कराने तथा कठोर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	153
जनपद-हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ, ग्राम पंचायत मस्कारा को नगर पंचायत का दर्जा दिलाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	154
उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त वैयक्तिक सहायक का पी0एफ0 भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	154
जनपद-जौनपुर के जाफराबाद के अन्तर्गत प्रधानपुर कुसिया नेवढ़िया मार्ग का चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	155
जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ ब्लॉक सैया में ग्राम भिड़ावली से मंगल नगर तक रोड का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	155
जनपद-सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में स्थित राजकीय मेडिकल कालेज पिलखनी में कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसी अवनी परिधि द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	155
प्रदेश के अल्पसंख्यक घोषित विद्यालय में नीति बनाकर नयी नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	156
जनपद-बुलन्दशहर सदर तहसील से चीलघर तिराहे तक रोड का चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	156
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा सरया ब्लॉक सदर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	156-157
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ	157
सरकार द्वारा औचित्य के प्रश्नों पर व्यवस्था दिये जाने के बाद भी निर्देश का अनुपालन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	157-159
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ	159-169

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	170-210
आय-व्ययक की साधारण चर्चा के मध्य संसदीय कार्य मंत्री के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	211
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ...	212-279
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें दिनांक 01 मार्च, 2023 से आरम्भ करने हेतु कार्य-सूची में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	279-280
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा तथा हाजी इरफान सोलंकी, सदस्य विधान सभा द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना को विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित किये जाने की सूचना	280
याचिकाओं का उपस्थापन	281
इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	281-282
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद-फिरोजाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	282-283
डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-अयोध्या से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	283
डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	283-284
डॉ0 शिव प्रताप यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बलरामपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	284
डॉ0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-वाराणसी से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	285
डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य विधान की जनपद-मिर्जापुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	285
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	285-286
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मुरादाबाद से सम्बन्धित 04 तथा जनपद-सम्भल से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	286-287

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गोण्डा से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	287
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मेरठ से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	287
श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-चित्रकूट से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	288
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	288-289
श्री अरमान खान, सदस्य विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयी)	289-290
श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-शामली से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	290
श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-रायबरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	290-291
श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद-सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	291
श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	291
श्री कैलाश नाथ, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बलरामपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	292
श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद-जालौन से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	292-293
श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	293
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	293-294
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-आगरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	294-295

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री जयमंगल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-महराजगंज से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (व्यपगत)	295
श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-महराजगंज से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	295-296
श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद-सहारनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	296
श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	297
श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	297-298
श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	298
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	299
श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद-सोनभद्र से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	299
श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	300
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (व्यपगत)	300
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जालौन से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	300-301
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	301
श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-झांसी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	301
श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	302

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राजीव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मेरठ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	302
श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जालौन से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	302-303
श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	303
श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-खीरी से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	303
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	304
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	304
श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद-बस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयी)	304-305
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ तथा जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	305-306
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद-श्रावस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	306
श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बिजनौर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	306-307
श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-रायबरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	307
श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मिर्जापुर से सम्बन्धित 01 तथा जनपद-जौनपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (व्यपगत) ...	308
श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	308-309
श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	309

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्रीं श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	309-310
श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बहराइच से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)	310
श्री हंसुराम, सदस्य विधान सभा की जनपद-बलिया से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	310-311
श्री हरि ओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कासगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	311
श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	311
डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	311-312
श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद-प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	312
श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	313
श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद-सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	313-314
श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मथुरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	314
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद-झांसी से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ तथा जनपद-कन्नौज व आगरा से सम्बन्धित 01-01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	314-315
श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	315
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	315-317
जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के विकास खण्ड मोरना में कतिपय ग्रामों के मार्गों के निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में श्री चन्दन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	317-318

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-फिरोजाबाद के स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को पूर्ण क्षमता से शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	318-322
जनपद-रायबरेली में यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा एन0टी0पी0सी0 तापीय योजना के अन्तर्गत पुल/पुलियों के निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य	322-324
जनपद-मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारु रूप से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौहम्मद फहीम इरफान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	324-327
जनपद-अम्बेडकरनगर के कटेहरी बाजार (प्रतापपुर चमुर्खा) को नगर पंचायत बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...	327-330
जनपद-सहारनपुर के बजाज हिन्दुस्तान सुगर प्रा0 लि0 में गन्ना किसानों का बकाया धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार निम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री का केवल वक्तव्य... ...	330-331
नत्थियाँ	332-342

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2023 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य 365

1. अंकित भरती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अखिलेश यादव, श्री — मैनपुरी
5. अजय, श्री — गोण्डा
6. अजय कुमार, श्री — बागपत
7. अजय सिंह, श्री — बस्ती
8. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
9. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
10. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
11. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
14. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
15. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
16. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
17. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
18. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
19. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
20. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
21. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
22. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
23. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
24. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
25. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
26. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
27. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
28. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
29. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
30. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
31. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
32. अरमान खान, श्री — लखनऊ
33. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
34. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
35. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
36. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
37. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
38. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
39. अशरफ अली खान, श्री — शामली
40. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
41. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
42. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
43. आकाश सक्सैना (हनी), श्री — रामपुर
44. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
45. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
46. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
47. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
48. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
49. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई

50. आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', श्री लखनऊ
51. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
52. आशु मलिक, श्री सहारनपुर
53. इकबाल महमूद, श्री संभल
54. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
55. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
56. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
57. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
58. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
59. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
60. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
61. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
62. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
63. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
64. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
65. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
66. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
67. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
68. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
69. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
70. कैलाश, श्री चन्दौली
71. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
72. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
73. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
74. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
75. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
76. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
77. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
78. गुलाब देबी, श्रीमती सम्भल
79. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
80. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
81. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
82. चंदन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
83. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
84. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
85. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
86. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
87. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
88. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
89. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
90. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
91. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
92. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
93. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
94. जयमंगल, श्री महराजगंज
95. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
96. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
97. जाहीद, श्री भदोही
98. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
99. जियाऊर्रहमान, श्री मुरादाबाद
100. जी एस धर्मेश, डॉ0 आगरा
101. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
102. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
103. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
104. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
105. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
106. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
107. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
108. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
109. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
110. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
111. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
112. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
113. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
114. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया
115. दुधराम, श्री बस्ती

116. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
117. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
118. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
119. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
120. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
121. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
122. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
123. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
124. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
125. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
126. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
127. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री प्रयागराज
128. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
129. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
130. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
131. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
132. नाहिद हसन, श्री शामली
133. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
134. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
135. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
136. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
137. नील रतन सिंह, श्री वाराणसी
138. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
139. पंकज, श्री जौनपुर
140. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
141. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
142. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
143. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
144. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
145. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
146. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
147. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
148. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
149. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
150. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
151. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
152. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
153. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
154. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
155. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
156. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
157. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
158. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
159. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
160. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
161. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
162. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
163. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
164. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
165. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
166. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
167. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
168. बाबूराम, श्री पीलीभीत
169. बाबूलाल, श्री आगरा
170. बावन सिंह, श्री गोण्डा
171. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
172. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
173. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
174. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
175. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
176. बेदी, श्री गाजीपुर
177. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
178. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
179. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
180. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं

181. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
182. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
183. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
184. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
185. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
186. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
187. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
188. मनीष रावत, श्री सीतापुर
189. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
190. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
191. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
192. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
193. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
194. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
195. महबूब अली, श्री अमरोहा
196. महेन्द्र, श्री अमरोहा
197. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
198. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
199. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
200. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
201. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
202. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
203. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
204. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
205. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
206. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
207. मेघश्याम, श्री मथुरा
208. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
209. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
210. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
211. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
212. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
213. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
214. योगेश धामा, श्री बागपत
215. योगेश वर्मा, श्री खीरी
216. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
217. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
218. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
219. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
220. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
221. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
222. रमेश, श्री जौनपुर
223. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
224. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
225. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
226. रवि शर्मा, श्री झांसी
227. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
228. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
229. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
230. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
231. आर0के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
232. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
233. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
234. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
235. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
236. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
237. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
238. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
239. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
240. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
241. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
242. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
243. राजमणि, श्री प्रयागराज
244. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
245. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर

246. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
247. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
248. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
249. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
250. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
251. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
252. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
253. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
254. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
255. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
256. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
257. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
258. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
259. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
260. रामकेश निषाद, श्री बांदा
261. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
262. रामचन्द्र यादव, श्री अयोध्या
263. रामदुलार, श्री सोनभद्र
264. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
265. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
266. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
267. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
268. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
269. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
270. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
271. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
272. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
273. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
274. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
275. लकी यादव, श्री जौनपुर
276. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
277. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
278. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
279. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
280. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
281. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
282. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
283. विजयपाल (आढती), श्री हापुड़
284. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
285. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
286. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
287. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
288. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
289. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
290. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
291. विपुल दुबे, श्री भदोही
292. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
293. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
294. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
295. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
296. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
297. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
298. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
299. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
300. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
301. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
302. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
303. शशांक वर्मा, श्री खीरी
304. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
305. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
306. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
307. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
308. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
309. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली

310. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
311. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
312. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
313. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
314. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
315. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
316. संग्राम सिंह, श्री बलिया
317. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
318. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
319. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
320. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
321. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
322. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
323. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
324. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
325. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
326. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
327. सभाकुंवर, श्री देवरिया
328. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
329. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
330. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
331. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
332. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
333. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
334. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
335. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
336. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
337. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
338. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
339. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
340. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
341. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर
342. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
343. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
344. सुरेश राही, श्री सीतापुर
345. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
346. सुशांत सिंह, कुँवर बिजनौर
347. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
348. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
349. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री गाजीपुर
350. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
351. सैय्यदा खातून, श्रीमती सिद्धार्थनगर
352. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 मेरठ
353. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
354. सौरभ सिंह सोनू, श्री खीरी
355. स्वामी ओउमवेश, श्री बिजनौर
356. हंसु राम, श्री बलिया
357. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
358. हरिओम, श्री कासगंज
359. हरिप्रकाश वर्मा, श्री शाहजहांपुर
360. हरीश चन्द्र, श्री बदायूं
361. हरेन्द्र सिंह, श्री हापुड़
362. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री प्रयागराज
363. हाकिम लाल बिन्द, श्री प्रयागराज
364. हिमान्शु यादव, श्री बदायूं
365. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री आजमगढ़

नोटः- लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद), जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप), सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु') तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जिला पंचायतों एवं पंचायती राज विभाग में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवा नियमावली के सम्बन्ध में

***1-श्री अतुल प्रधान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला पंचायतों एवं पंचायती राज विभाग में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों की कोई सेवा नियमावली है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवा नियमावली बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जी हाँ। जिला पंचायतों में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों की सेवा नियमावली बनायी जायेगी।

पंचायती राज निदेशालय एवं इनके नियत्रंणाधीन कार्यालय मण्डलीय उप निदेशक (पं0)/जिला पंचायत राज अधिकारी में कम्प्यूटर आपरेटर का कोई पद सृजित न होने के कारण सेवा नियमावली बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रमोशन में व्यवस्था दी है कि सबको समान अवसर मिलेंगे। जिला पंचायत में एक पद कम्प्यूटर आपरेटर का होता है, वह पद 1997 में सृजित किए गए थे। लेकिन वर्तमान समय में जहाँ आप मान्यवर, सारी की सारी विधान सभा को और पूरे प्रदेश में ई-प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है, वहीं जिला पंचायत सहित सब जगह कम्प्यूटर आपरेटर को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि जब ड्राफ्टमैन, कनिष्ट लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को, सबको प्रमोशन मिल सकता है तो जो सबसे महत्वपूर्ण इस समय ई-गवर्नेस की बात चल रही है तो ऐसे में कम्प्यूटर आपरेटर को प्रमोशन क्यों नहीं ? मान्यवर, मेरा कहना यह है कि जब 2015 में कम्प्यूटर आपरेटर्स के लिए शासनादेश हुआ कि इनको भी प्रमोशन दिया जायेगा। लेकिन समस्त 75 के 75 जिलों में आज तक कोई प्रमोशन या उस शासनादेश के तहत् कोई लाभ कम्प्यूटर आपरेटर्स को नहीं मिल पाया। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि

क्या सरकार जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 की अनुसूची-क में जोड़ने का काम करेगी, यदि नहीं तो क्यों ? मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि 2015 में जारी शासनादेश का लाभ उस पद पर कार्य कर रहे लोगों को क्यों नहीं मिला या मिल रहा है ? इसके सम्बन्ध में क्या लोगों को कोई दिशा-निर्देश मिलेगा और मान्यवर, जिला पंचायतों में जो रिक्त पद पड़े हैं, चाहे वह कम्प्यूटर आपरेटर के हों या इसके अलावा और कोई हों, क्या सरकार उनको भी बैकलॉग के माध्यम से भरने का काम करेगी ? धन्यवाद।

लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही विस्तार से प्रश्न पूछा है और यह जिला पंचायत के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। जहाँ तक कम्प्यूटर आपरेटर के पद का सवाल है, सही है कि 2015 में एक जी0ओ0 निकला था, जिसके तहत तीन ग्रेड, पे-स्केल- ए, बी, सी में कम्प्यूटर आपरेटर पदों के जो लोग थे, उनके लिए कुछ प्राविधान हुआ था। मगर 2016 में ही उसी सरकार में उस पर रोक लगा दी गयी। अब जब विभिन्न जगहों से डिमाण्ड आई जिला पंचायतों से तो सरकार उस पर विचार कर रही है और जो मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि क्या नियमावली बनेगी, तो नियमावली बिल्कुल बनेगी और उसको जल्द बनाने का प्रयास करेंगे। मगर उसकी भी प्रक्रिया है कि कार्मिक वित्त नियोजन से राय लेकर उसके बाद कैबिनेट में जाएगी तो उसके बाद ही इसकी पूर्ति हो पाएगी तो मै मा0 सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार के संज्ञान में 97 से लेकर अब तक का पूरा प्रकरण है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो कम्प्यूटर ऑपरेटर हैं और जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं तो इसलिए इनको दृष्टिकोण में रखते हुए वह नियमावली बनाकर के उनको पे-ग्रेड और प्रमोशन के प्रावधान भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। दूसरा यह है कि जो पद खाली हैं उनके लिए जिला पंचायत में अभी रोक लगी हुई है। मगर जिला पंचायत स्वतंत्र हैं आउटसोर्सिंग से उनकी भर्ती करने के लिए।

श्री अध्यक्ष-

मेरे ख्याल से अतुल जी आपका पूरा उत्तर आ गया है जितने भी आपने प्रश्न पूछे थे।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिला पंचायत का जो पद है अध्यक्ष का वह पूरे जिले को कहीं न कहीं प्रभावित करता है और उसमें इस समय कर्मचारियों की कमी है। मान्यवर, बैकलॉग के माध्यम से या जितनी कमी है उनको अगर भर लें तो उससे आपकी नौकरियां भी लोगों को मिल जाएंगी और साथ ही साथ पूरे जिले में जो परेशानी या दिक्कतें इस समय आती हैं उसको भी कहीं न कहीं लाभ हो सके।

प्रदेश में दिनांक 15 मार्च, 2020 से दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 तक पंजीकृत अपराधिक घटनाओं के सम्बन्ध में

***2-श्री पंकज कुमार मलिक, श्री बेचई सरोज तथा श्री जगदीश नारायण-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 15 मार्च, 2020 से दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 तक लूट, डकैती, बलात्कार, महिला उत्पीड़न की कितनी-कितनी घटनाएं पंजीकृत हुई हैं ? क्या सरकार ने उक्त अपराधों को रोकने के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

इस सम्बन्ध में दिनांक 15 मार्च, 2020 से दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 तक पंजीकृत अभियोगों का विवरण निम्नवत् है :-

अपराध शीर्षक	पंजीकृत अभियोगों की संख्या
लूट	4026
डकैती	738
बलात्कार	6538
महिला उत्पीड़न	57755

जी हां।

प्रदेश में घटित लूट तथा डकैती की घटनाओं में शामिल अपराधियों के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की गयी है, जिसमें गैंगेस्टर अधिनियम, गुण्डा एक्ट एवं धारा-14(1) गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। साक्ष्य संकलन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए फुट एवं फिंगर प्रिन्ट, घटना के समय अभियुक्तों का लोकेशन, सी0सी0टी0वी0 फुटेज, घटना के समय अभियुक्त द्वारा छोड़े गये सामान आदि को कब्जे में लेकर इन साक्ष्यों का विवेचना में समावेश कर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण की जाती है।

जनपद लखनऊ में प्रदेश स्तरीय केन्द्रीय मास्टर कोआर्डिनेशन सेन्टर के रूप में एक वृहद् 'यू0पी0-112' काल सेन्टर की स्थापना की गयी है, जो प्रदेश के पूरे क्षेत्र में तत्काल पुलिस सहायता पहुचाने के उद्देश्य को निरन्तर प्राप्त कर रही है।

प्रदेश में प्रतिदिन सायं 60 मिनट भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग करायी जा रही है तथा बैंको, सर्राफा दुकानों इत्यादि के आस-पास खुलने एवं बन्द होने के समय पर प्रभावी ढंग से पुलिस गश्त क्रियान्वित की जा रही है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में बाल एवं महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम एवं उन अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध त्वरित गति से

विवेचना पूर्ण कर उन्हें सजा दिलाना है। भारत सरकार के इन्वेस्टीगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फार सेक्सुअल आफेन्स (आई0टी0एस0एस0ओ0) पोर्टल द्वारा इन विवेचनाओं की प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जाती है। माह अगस्त, 2022 में इन विवेचनाओं के निस्तारण में उत्तर प्रदेश राज्य सातवें स्थान पर था, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर सतत् प्रयासों द्वारा कुल दर्ज 76,459 अभियोगों के सापेक्ष 74,600 अभियोगों का निस्तारण करते हुए 97.61 प्रतिशत निस्तारण दर (डिस्पोजल रेट) के साथ उत्तर प्रदेश ने सम्पूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

वर्तमान सरकार द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में शीघ्र विचारण हेतु कुल 162 फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं पाक्सो सम्बन्धी अपराधों के लिए 218 एक्सक्लूसिव पाक्सो कोर्ट स्थापित किये जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में सजा का दर 59.1 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से 123 प्रतिशत अधिक है। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में उत्तर प्रदेश में सजा का दर पूरे देश में सर्वाधिक है।

महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान हेतु महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना की गयी है तथा विशेष अभियान 'मिशन शक्ति' चलाया जा रहा है। प्रदेश के समस्त थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है तथा 10378 महिला बीटों का सृजन किया गया है। जनपदों में 'एण्टी रोमियो दल' का गठन करते महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ वूमेन पावर लाइन 1090 क्रियाशील है जिस पर महिलाएं अपनी शिकायतें निःसंकोच एवं आत्मविश्वास के साथ दर्ज करवा रही हैं।

प्रदेश में अपराध तथा अपराधियों पर 'जीरो टालरेंस' के सिद्धान्त पर कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

विभाग की प्रभावी नीति के क्रियान्वयन के फलस्वरूप विगत 5 वर्ष 10 माह में इस प्रकार की घटनाओं में भारी कमी हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, कानून व्यवस्था का मामला बहुत गम्भीर है और जो सभी के सामने है। इलाहाबाद और कानपुर की घटना पर जो सवाल मैंने पूछा था मैं उसके संदर्भ में मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ और मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सवाल के जवाब में इन्होंने वैज्ञानिक विधिवत का जिक्र किया है। क्या सरकार बेतहाशा अपराध को रोकने के लिए सभी सेंसिटिव जगहों पर, भीड़ की जगहों पर, विद्यालयों पर, अस्पतालों पर, बस अड्डों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने और सभी जनपदों में फॉरेंसिक लैब बनाने का काम करेगी। दूसरा मेरा सवाल यह है कि 15 मार्च, 2020 से 22 दिसम्बर, 2022 के संदर्भ में मैंने प्रश्न पूछा और इनका जवाब आया है उसी पर मैं पूछना चाहता हूँ कि 1090 पर कितनी शिकायतें कुल दर्ज हुई हैं इस समय-सीमा के अन्तर्गत, कितनी सच पाई गई हैं और कितने पर क्या कार्यवाही

हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं। महिला उत्पीड़न के बड़ी संख्या में इन्होंने जो मुकदमें बताए हैं कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देश में सर्वाधिक मुकदमें महिला उत्पीड़न के हो सकते हैं। क्या सरकार विशेष महिला उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए अलग से कोई विशेष योजना बनाएगी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है साइबर क्राइम द्वारा महिलाओं के बढ़ते उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री बेचई सरोज-

अभी हमारे मलिक भाई ने जो बात रखी उससे मिली-जुली हमारी बात भी है।

श्री अध्यक्ष-

बड़हलगंज की उनके पास सूचना नहीं होगी वह पूछिए जो इन्होंने पूछा है पंकज जी ने वह सारे ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो नीति से सम्बन्धित है। आप अलग से पूछना चाहें तो अपने प्रश्न को पूछ लीजिएगा मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन कर लूंगा कि आपको उसकी जानकारी दे दें।

श्री बेचई सरोज-

मान्यवर, एक आई0टी0 स्कूल है जहां पर अधिक संख्या में वहां लड़कें पढ़ते हैं और वहां सी0सी0टी0वी0 या कैमरे की व्यवस्था होती, क्योंकि वहां भीड़ लगती है और उसी जगह पर बहुत बड़ी चोरी हुई, डकैती हुई, छिनैती हुई, चैन छीनी गयी, गाड़ी छिनी गई । अगर वहां सी0सी0टी0वी0 की व्यवस्था रही होती तो आज चोर, डकैत वहां गिरफ्तार हुए होते।

मान्यवर, अगर सी0सी0टी0वी0 की व्यवस्था रही होती तो आज डकैत, चोर गिरफ्तार हो गये होते यह भी हमारे मलिक भाई से मिला हुआ प्रश्न है। पूरे प्रदेश में इसी तरह से जहाँ पर भी भीड़ है, वहाँ पर व्यवस्था की जानी चाहिए । हम एक महिला के विषय में कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ एक करीवां गोपालपुर गाँव है । वहाँ पर एक महिला को काफी लोगों ने मिलकर मारा-पीटा और उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ अभी तक वह महिला अस्पताल में ही थी, लेकिन दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य इसको आप लिखकर दे दीजिए।

श्री जगदीश नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि जो आपका जवाब आया है उसमें 100 और 102 की बात की गयी है, जिसका यहाँ सेन्टर स्थापित है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आज की तारीख में 102 के लोग मौके पर जाते हैं, क्या उनकी मॉनीटरिंग वहाँ से सीधे होती है। वहाँ से मौके पर जाते हैं तो क्या सेण्टर पर बताया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न यह है। दूसरा मान्यवर, आज की तारीख में गाँवों में राजस्व विवाद या आबादी के विवाद बहुत बढ़ते जा रहे हैं। 102 के लोग सुलभ हैं लोग फोन करते हैं और 102 के लोग तुरन्त पहुँच जाते हैं। मैं मा0 मंत्री जी से

जानना चाहूँगा कि क्या राजस्व विवादों में या दीवानी न्यायालय सम्बन्धी जो विवाद हैं उसमें बिना सक्षम अधिकारी के 102 के अधिकारियों को उसको मौके पर रोकने का या बनवाने का पॉवर है कि नहीं है ? तीसरा प्रश्न यह है कि जब वह मौके पर जाते हैं और सम्बन्धित कोई पक्ष होता है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, क्या उनको अरेस्टिंग का पॉवर है कि नहीं है ?

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे मा0 सदस्यों ने जो कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रकट की है, तो हम आपको बता दें कि प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में आज सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में पहले के मुकाबले में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है।

(मेजों की थपथपाहट)

और हर तरह से सुधार हुआ है। आपने महिलाओं के सम्बन्ध में जो अपराध हुए हैं उसके बारे में जानकारी की। मैं आपको बता दूँ कि भीड़-भाड़ वाले इलाके में खास तौर से यह व्यवस्था है कि हम हर तरह से उसमें फुट पेट्रोलिंग करें और फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से लोगों में यह जानकारी भी रहे कि यदि किसी प्रकार का कोई अपराध घटित होता है, तो उसके बारे में सरकार सतर्क है और सरकार कार्यवाही जरूर करेगी और कार्यवाही करती भी है। मान्यवर, हमने इनको जो बाकायदा इन्होंने पूछा था कि डकैती, लूट और महिलाओं के सम्बन्ध में बलात्कार और महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके बारे में, इन चारों के बारे में हमने विशेष रूप से इनको अलग-अलग स्थिति की जानकारी भी दी है। फुट पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था है उसमें पुलिस थानों में प्रतिदिन सायंकाल के समय बाजारों, भीड-भाड़ वाले स्थानों पर, पुलिस द्वारा नियमित एवं प्रभावी फुट पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पेट्रोलिंग की मॉनीटरिंग हेतु एकीकृत फुट पेट्रोलिंग पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें प्रतिदिन जनपदों व थानों में की गई फुट पेट्रोलिंग की फोटो अपलोड कर उसकी समीक्षा की जाती है। इसके अलावा जो महिलाओं के सम्बन्ध में अपराध की बात कही है उसके बारे में कहना है कि हमने रोमियो स्क्वायड बनाया और रोमियो स्कवाइड का जो हमारे पास इस समय आंकड़ा है वह भी हम आपके सामने बताये देते हैं कि हमने हर तरह से इस बात की चिन्ता की है कि किसी भी तरीके से महिलाओं के सम्बन्ध में जो अपराध है .....

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 मंत्री जी, यह तो सब लिखा उत्तर आ गया है। मैंने जो अनुपूरक पूछे हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम आपके अनुपूरक के सम्बन्ध में ही बात कर रहे हैं कि जो महिला के सम्बन्ध में आपने पूछा है कि इसमें विशेष व्यवस्था क्या की गई है ? इसमें विशेष व्यवस्था यह है कि जबसे यह सरकार आई तब से ही विशेष व्यवस्था यह की गई कि अपराध को रोकने का

प्रिवेन्टिव और दूसरी तरफ किसी न किसी रूप में यदि वह अपराध करते हैं, तो हर तरह से उनको सजा दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। एंटी रोमियो स्क्वायड के सम्बन्ध में बताना है कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु सशक्तीकरण, एंटी रोमियो स्कवाइड, महिला सुरक्षा के दल का गठन कर अनवरत् दिनांक 22-03-17 से 10-02-23 तक 70,83,511 स्थानों पर चेकिंग की गयी तथा 2,20,17,197 व्यक्तियों को चेक किया गया। 17,980 अभियोग पंजीकृत किये गये। 25,127 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी। 88,25,966 व्यक्तियों को चेतावनी दी गयी। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण हेतु एण्टी रोमियो स्वायड, महिला सुरक्षा दल का गठन अनवरत् अभियान चलाया जा रहा है, ताकि यह अपराध न हो सकें। इसके साथ ही जो महिलाओं के खिलाफ अपराध पंजीकृत होते हैं, उसमें विशेष रूप से कार्यवाही भी की गयी है और उस कार्यवाही का परिणाम नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड हमारे पास है कि वर्ष 2021 में 59.1 प्रतिशत हमने सजा दिलायी। जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 26 प्रतिशत का है, यानि राष्ट्रीय स्तर पर जो औसत 2021 का है, उससे हमारा सजा दिलाने का औसत ज्यादा है। सजा से आदमी को यह भय लगता है कि अगर इस सरकार में किसी प्रकार का कोई अपराध किया तो हमको पनिशमेण्ट जरूर मिलेगी। यह अपने आप में सजा के डर को दर्शाता है। इसके साथ-साथ गैंगस्टर और गुण्डा एक्ट की कार्यवाही भी हमने बड़े पैमाने पर की है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि साइबर क्राइम द्वारा जो महिलाओं को सताया जा रहा है, उसमें क्या कार्यवाही करेंगे ? इसमें मैंने फॉरेन्सिक लैब के सम्बन्ध में कहा और सी0सी0टी0वी0 कैमरों के लिए भी कहा है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जहां आज सी0सी0टी0वी0 कैमरों की जरूरत है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सी0सी0टी0वी कैमरे बड़े पैमाने पर लग रहे हैं। साइबर क्राइम के सम्बन्ध में पहले बता दूँ कि इसमें एक अभियान चल रहा है। कहीं पर, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं है, जिस प्रकार से अपराध होते हैं, सरकार उससे आगे-आगे फोरसी करके, पहले से इस प्रत्याशा में कि अगर यह कल को होगा, तो यह हम करेंगे। इस प्रकार से ही कानून व्यवस्था पर नियंत्रण कर पाए और तभी प्रदेश की सरकार का परसेप्शन अच्छा बना है, जनता में भी, देश में भी और विदेश में भी। मान्यवर, 2020 में महिलाओं के मामलों में 535 सजा हुई, वर्ष 2021 में 1230 मामलों में सजा हुई, वर्ष 2022 में 2313 मामलों में सजा हुई। वर्ष 2020 के सापेक्ष 2022 में पॉक्सो मामलों में सजा दिलाने में 332 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा पॉक्सो मामलों में आरोप तय होने से निर्णय की अवधि तक मात्र एक माह में 2020 में 5 मामलों में सजा करायी गयी, वर्ष 2021 में 7 मामलों में सजा करायी गयी। वर्ष 2022 में 34 मामलों में सजा करायी गयी। बलात्कार में वर्ष 2020 में 177 मामलों में 2021 में

370 मामलों में, वर्ष 2022 में 671 मामलों में सजा करायी गयी। इस प्रकार वर्ष 2020 के सापेक्ष वर्ष 2022 में बलात्कार के मामले में सजा दिलाने में 280 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मान्यवर, यह अपने आप में दर्शाता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है, कितनी सेंसटिव है और उसी आधार पर यह कानून व्यवस्था की स्थिति हम बेहतर बना पाये। एक आँकड़ा हम आपको और खास तौर से देना चाहेंगे कि हमने इन लोगों के खिलाफ, जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, उन पर गैंगस्टर और गुण्डा एक्ट की कार्यवाही बड़े पैमाने पर की गयी है। इसमें वर्ष 2021 का आंकड़ा दें तो 3126 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी और गुण्डा एक्ट की कार्यवाही 34,379 लोगों के खिलाफ की गयी। वर्ष 2022 में 38 हजार 58 लोगों के खिलाफ गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी। गैंगस्टर अधिनियम में 4295 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी। यह अपने आप में दर्शाता है कि किसी भी तरह से हम अपराध के बारे में, जो जीरो टॉलरेन्स की नीति योगी सरकार ने घोषित की है, उसमें हम किसी प्रकार से लोगों को अपराध नहीं करने देना चाहते हैं। जहां पर भी अपराध होता है, तो हम हर तरह से उसको रोकने, प्रिवेन्टिव एक्शन भी लेते हैं और सजा भी दिलाने का काम बड़े पैमाने पर करते हैं। मान्यवर, जहां तक जो साइबर क्राइम की बात आयी है, उसमें अवगत कराना चाहूंगा कि यह 18 रेन्ज में जो साइबर पुलिस स्टेशन हैं, अभी तक केवल दो स्थानों पर यह पुलिस स्टेशन थे, एक लखनऊ में और एक नोएडा में, लेकिन अभी 16 स्थानों पर हमारी जितनी भी कमिश्नरी लेबिल हैं, उन सबमें साइबर थाने खोल दिये गये हैं। सभी प्रकार के लैब्स रेंज हेडक्वार्टर पर बनाने का प्रयास है। बेसिक फोरेंसिक जांचों के लिए लखनऊ हेडक्वार्टर में एडवान्स डिजिटल फोरेंसिक लैब्स की स्थापना की जा रही है।

इसके अलावा हमने अपना कन्विक्शन रेट आपको बता दिया है। हर तरह से, किसी भी एंगिल से आप देख लें, जितने भी पीछे की सरकारों के आंकड़े देख लें, पब्लिक परसेप्शन देख लें, सरकार ने हर तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने का जी-तोड़ प्रयास किया है और वह प्रयास सफल भी हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के जितने भी अपराधी हैं या तो वो प्रदेश छोड़ कर चले गये हैं, नहीं तो वह जेल में हैं। किसी की हिम्मत नहीं है किसी प्रकार का कोई अपराध खुलेआम कर सके, जहां पर अपराध किया गया तो अपराधियों को उसी भाषा में जवाब दिया गया और इसी प्रकार से आगे भी जीरो टॉलरेन्स की जो नीति है उसको हम पूरी तरह से परफार्म करेंगे, निभायेंगे और हर तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने का हमने जो बीड़ा उठाया है, उसमें रिजल्ट देंगे।

(श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

पूरे 15 मिनट हो गये हैं, डिबेट नहीं हो रही है। आपका जो उत्तर था, वह आ गया है। 15 मिनट से ज्यादा मैं एक प्रश्न पर नहीं दे सकता। मुझे सिर्फ 04 प्रश्न ही लेने हैं। आप लिखकर दे दीजियेगा।

प्रदेश में वर्तमान में रिक्त सहायक अध्यापकों की भर्ती के सम्बन्ध में

***3-श्री अनिल प्रधान-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 अप्रैल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2022 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि प्रदेश में वर्तमान में कितने पद शिक्षकों के खाली हैं तथा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संदीप कुमार सिंह)-

जी हाँ। दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2022 तक 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत 6696 अभ्यर्थियों के चयन/जनपद आवंटन की कार्यवाही की गयी है।

परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूल में 51,112 सहायक अध्यापक के पद रिक्त हैं। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री अनिल प्रधान-

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा बड़ा गुणगान किया जा रहा था कि प्राथमिक शिक्षा कैसे सुधर गयी और विद्यालयों में बहुत अच्छी व्यवस्था हो गयी और बच्चे पढ़ने जाने लगे। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि जब स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे, तो आप शिक्षा का स्तर कैसे सुधार पायेंगे, मेरा पहला सवाल है, जिस पर माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत 6696 अभ्यर्थियों का चयन अथवा जनपद आवंटन की कार्यवाही की गयी है। मान्यवर, मेरा यह पूछना है कि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र कब वितरित किये जायेंगे तथा रिक्त पदों पर विज्ञापन कब जारी किया जायेगा ? चूंकि 69000 शिक्षक भर्ती में जो सहायक अध्यापकों को नियुक्ति दी गयी थी उसमें विसंगति थी और ओ0बी0सी0 के आरक्षण में विसंगति थी, तो मंत्री जी यह बतायें कि आप कितने नये पद सृजित करेंगे, क्योंकि 69000 और 68500 शिक्षकों की भर्ती नहीं थी, बल्कि शिक्षामित्रों के संयोजन का मामला था। मेरे दूसरे अनुपूरक पर मंत्री जी का जवाब आया कि बेसिक स्कूल में शिक्षकों के 51,112 पद रिक्त हैं, लेकिन भर्ती के सम्बन्ध में सरकार का कोई भी विचार नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक वर्ष साढ़े 3 लाख प्रशिक्षणार्थियों को डी0एल0एड0 2022 के करवाया जा रहा

है, जबकि वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 डी0एल0एड0 प्रशिक्षु पहले से डी0एल0एड0 भर्ती की प्रतीक्षा में हैं। यानि लगभग 15 लाख अभ्यर्थी डी0एल0एड0 परीक्षा से उत्तीर्ण हैं, जिनमें 08 से 10 लाख टी0ई0टी0 उत्तीर्ण हैं। ऐसे प्रशिक्षकों की शिक्षक भर्ती सरकार कब निकालेगी ? इसको अवगत करा दें। मेरा तीसरा अनुपूरक है कि वर्ष 2016 में 12,400 शिक्षक की भर्ती हुई थी, जिसमें 6000 लोगों को नियुक्ति-पत्र दे दिया गया था।

सरकार बदलने के बाद उस पर जांच हुई थी, तो आधे को दे दिया गया और आधे अभ्यर्थी अभी बचे हैं, उनको नियुक्ति-पत्र कब दिया जायेगा ? मेरा आखिरी अनुपूरक है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में 17-18, अक्टूबर, 2021 को परीक्षा हुई जिसका परिणाम 17 नवम्बर, 2021 को आया तथा पुनः परिणाम 06 दिसम्बर, 2022 को जारी किया गया, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं की गयी, इन्हें कब तक नियुक्त किया जायेगा ? एक आखिरी बात मान्यवर, जनपद चित्रकूट में तैनात रहे पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री राजीव रंजन मिश्रा जी ने तमाम सारे जो भ्रष्टाचार किए थे उस पर 27 मई, 2022 को नियम-301 के तहत मैंने सूचना दी थी, जिस पर जिले से जांच हुई। ए0डी0एम0 और कोषाधिकारी द्वारा जांच की गयी उनकी, जिसमें उनको दोषी पाया गया। आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी। दुबारा विभागीय जांच होगी, जिसमें झांसी के अधिकारियों को तैनात किया गया, 31 दिसम्बर को रिटायर हो गये। इस विषय पर मैंने कई बार मंत्री जी से भी निवेदन किया और मिला भी, मेरा सरकार से सीधा सवाल है कि जीरो टॉलरेन्स के तहत क्या केवल बैकवर्ड, एस0सी0 और माइनॉरिटी के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, जो सत्ता पक्ष से जुड़े संरक्षित लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्या वह भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं ? इन विषयों पर मैं माननीय मंत्री जी का जवाब चाहता हूं।

श्री संदीप कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षकों के विषय में प्रश्न उठाया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बच्चों को पढ़ाने की जो व्यवस्था बनाई गई है, मुझे लगता है कि उनके समय में जो शिक्षा की व्यवस्था थी और आज के समय में जो बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पठन-पाठन की व्यवस्था बनाई गई है, उसमें जमीन-आसमान का अन्तर है। उस समय परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन के कार्य को छोड़ करके वहाँ बाकी अन्य सारे कार्य किये जाते थे, केवल पठन-पाठन नहीं होता था ।

श्री अध्यक्ष-

जो पूछा है, उसके ऊपर बता दीजिए। जो स्पेसिफिक पूछा है, उसके बारे में बता दीजिए।

श्री संदीप कुमार सिंह-

मान्यवर, मैं उत्तर पर ही आ रहा हूँ। माननीय सदस्य ने चिन्ता जताई है कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। मै माननीय सदस्य को

जानकारी देना चाहता हूँ कि वर्तमान में ये जो हमारे पद सृजित हैं, ये पद सृजित आज के समय के नहीं हैं, ये पुराने समय के हैं और पुराने छात्रों की संख्या के हिसाब से ये पद सृजित किये गये थे। आज वर्तमान में जो हमारे पास छात्रों की संख्या है और जो शिक्षकों की संख्या है, जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है, जो कि प्राइमरी में 1 शिक्षक पर 30 बच्चों का होता है और अपर प्राइमरी में 1 शिक्षक पर 35 बच्चों का होता है। वर्तमान में जो हमारे पास शिक्षक हैं, हमारे शिक्षामित्र, अनुदेशक और प्राइमरी के हमारे शिक्षक मिला करके हमारा जो पी0टी0आर0 रेसियो है, बच्चों और शिक्षक का रेसियो, इसको हम लोग पूरा करते हैं और वर्तमान में हमारे पास बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षक की कोई भी कमी नहीं है।

श्री अनिल प्रधान-

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के सहारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, तो आप उनको साढ़े सात हजार और दस हजार क्यों दे रहे हैं, उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं ? दूसरी बात मुझे यह कहना है कि जब आपके पास पद नहीं हैं, तो आप प्रत्येक साल लाखों बच्चों को डी0एल0एड0 क्यों करवा रहे हैं ? लगभग 15 लाख बच्चे जो डी0एल0एड0 किये हैं, जिसमें से 10 लाख बच्चे टी0ई0टी0 उत्तीर्ण हैं और आपके पास पद नहीं हैं, तो आप उनको क्यों डी0एल0एड0 करवा रहे हैं और उनको क्यों बेरोजगारी की ओर ढकेल रहे हैं ? तीसरा, मेरा स्पेसिफिक सवाल जनपद चित्रकूट के पूर्व बी0एस0ए0 के सम्बन्ध में है, उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई हो रही है ? लगभग 9 से 10 महीने होने जा रहे हैं, जनपद चित्रकूट में ए0डी0एम0 और कोषाधिकारी ने जाँच में उनको दोषी पाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ? सरकार के किस व्यक्ति का उनको संरक्षण मिल रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इसकी आपको जानकारी है तो बताइये।

श्री संदीप कुमार सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो एक विशेष बी0एस0ए0 के सम्बन्ध में जानकारी जाननी चाही है, वह मूल प्रश्न से अलग है, उसमें जो जाँच की कार्यवाही की जा रही है, उससे माननीय सदस्य को अवगत करा दूँगा। जहाँ तक माननीय सदस्य ने नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है, क्योंकि वर्तमान में पहले से दो नियुक्ति के प्रकरण अभी विभाग के अन्तर्गत चल रहे हैं, जिन पर माननीय न्यायालय का निर्णय आना बचा हुआ है। माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्णय आयेगा, उस अनुसार इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जायेगा । इसीलिए वर्तमान में कोई नई नियुक्ति की प्रक्रिया अभी विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन नहीं है और मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि विभाग के अन्तर्गत अभी शिक्षकों और छात्रों के अनुपात को देखते हुए कमी भी नहीं है।

प्रदेश में यातायात पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से किये जा रहे चालान पर रोक लगाने के सम्बन्ध में

***4-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यातायात पुलिस द्वारा ऑनलाइन चालान कराये जाने की क्या प्रक्रिया है ? क्या सरकार यातायात पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से किये जा रहे चालान पर रोक लगाने हेतु कोई योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित कराये गये बेवसाइट https//e.challan.parivahan.gov.in पर यातायात नियमों के उल्लंघन में पाये गये वाहनों का चालान एन0आई0सी0 द्वारा प्रदत्त मोबाइल एप के माध्यम से किया जाता है, जिसका सम्पूर्ण डाटा एन0आई0सी0 के सर्वर पर स्थापित होता रहता है।

एन0आई0सी0 द्वारा प्रदत्त मोबाइल एप एवं आई0टी0एम0एस0 वाले जनपदों में सी0सी0टी0वी0 कैमरों से प्राप्त फोटो के आधार पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में किया जाता है। चालान किये जाते समय मोबाइल एप के माध्यम से वाहन का फोटो खींचकर चालान की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पोर्टल वाहन एवं सारथी में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उल्लंघनकर्ता का नाम और पता स्वतः संरक्षित होता रहता है। चालान सम्बन्धी सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहन स्वामी के मोबाइल नम्बर पर जाता है।

प्रदेश के सभी जनपदों में यातायात नियमों/संकेतों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमित रूप से चेकिंग, चालान व शमन की कार्यवाही मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है। किसी भी उल्लंघनकर्ता का चालान करते समय एप में उल्लंघनकर्ता का फोटो भी अपलोड किया जाता है। दिनांक 03-06-2020 से मैनुअल चालान पूर्णतयाः बन्द कर दिया गया है। केवल ऑन लाइन चालान किये जाते हैं।

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 30-07-2020 में विभिन्न यातायात अपराधों के अन्तर्गत वसूल की जाने वाली धनराशि निर्धारित की गई है, जिसके अन्तर्गत चालानों के शमन की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करूँगा कि जनता से जुड़े इस विषय पर आपने हमको अनुपूरक पूछने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रश्न है कि जो मोबाइल के ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चालान हो रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, आज

ऑनलाइन चालान में एक बड़ी समस्या आ रही है कि आनलाइन, मोबाइल से फोटो खींच करके उसके ऊपर अर्थदण्ड कर दिया जाता है। यह अगले को नहीं मामूल होता है कि हमारी गाड़ी में क्या-क्या कमी बताई गई, क्या पेपर की कमी बताई गई और क्या लिख करके भेज दिया गया। बाद में उसे ऑनलाइन चालान आ जाता है, उसको वह रकम जमा करनी होती है। एक हमारे वहाँ क्षेत्र का ही व्यक्ति था, उसने एक मोटरसाइकिल 35 सौ रुपये में खरीदी थी। उसको टोटल 38 सौ रुपये का चालान गया और उसने वह गाड़ी फूँक दिया।

श्री अध्यक्ष-

35 सौ रुपये में कौन सी मोटरसाइकिल मिलती है ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, यह सदन की जानकारी में रहना जरूरी है कि एक चालान आया और मैं ले करके आया हूँ उसके ऊपर जो जुर्माना किया गया है। इसमें लिखा गया है कि हेलमेट अच्छी स्थिति में नहीं था, हेड लाइट नहीं जल रही थी, हार्न खराब प्रतीत होता है, ब्रेक कम लग रही थी, नम्बर प्लेट स्पष्ट नहीं थी, आर0सी0 फटी हुई है। चालान 3500 रुपये सेकेण्ड हैण्ड गाड़ी 1984 की कीमत 4 हजार रुपये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन चालान के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर वह किसी से गुस्सा हैं तो कहो हफ्ते में 5 बार चालान कर दें। तो क्या सरकार ऑनलाइन चालान जो मोबाइन से किये जाते हैं इसमें दण्ड आरोपित किये जाने पर वाहन मालिक को कोई परिपत्र या कोई नोटिस देंगे और उसको अपना जवाब या स्पष्टीकरण देने का मौका देंगे। दूसरा इस ऑनलाइन चालान के नाम पर जो गरीबों को छोटी-छोटी दिक्कतें हो रही हैं। क्या सरकार पुलिस विभाग को इस तरह के उत्पीड़न को रोके जाने का कोई निर्देश देगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय पाण्डेय जी ने जो प्रोसीजर पूछा था वह मैंने बता दिया है। अब सवाल यह है कि लगातार दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। जब दुर्घटना होती है तब पूछा जाता है कि साहब आपने कानून का पालन क्यों नहीं करवाया। तो उस समय यह था कि बचाव पक्ष में अगर मान लिया सरकार सचेत होती है तो कम-से-कम सरकार को यह करना चाहिए था, उसका सर्टीफिकेट जांचना चाहिए था। जब कोई अपराध हो जाता है तो उसके बाद उसका बचाव पक्ष वाला पहलू ज्यादा सतर्क हो जाता है। वह कहता है कि अगर साहब यह कर दिया होता तो शायद यह दुर्घटना नहीं होती। आखिरकार कहीं-न-कहीं पर हम लोग अपने आपको कानून का शासन मानेंगे या नहीं मानेंगे। सबसे पहला सवाल तो हमारा यह है। आपके सवाल के बारे में हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि बिना वजह किसी का चालान किया जा रहा हो ऐसा है नहीं। कहने के लिए कुछ भी कह दिया जाये। अब तो यह साढ़े तीन हजार

रुपये की मोटर साइकिल दिलवा रहे हैं। जो गाइड लाइन है उसमें 5 बातों के लिए चालान स्पेसीफाइड है। केवल हेलमेट के आधार पर या कहीं गलत तरीके से पार्किंग हो उसके आधार पर चालान किया जा रहा है। जो व्यवहारिक है हम बता दें ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। बिना हेलमेट के कितनी हेड इंजरी होती हैं। अगर अभी भी बाजार में देख लें तो स्वाभाविक है वह हेलमेट नहीं लगायेगा । आखिर कौन सा वह दिन आयेगा जिस दिन यह हेलमेट का प्रयोग अपने एक्सीडेंट को बचाने के लिए किया जायेगा। फिर एक्सीडेंट की फीगर्स दिखाते हैं कि साहब अगर आप लोग विजिलेंट होते तो साल में इतने एक्सीडेंट नहीं होते । ड्राइविंग टू व्हीलर विदाउट हेलमेट। फेलियोर टू यूज सेफ्टी बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग ऑर कैरीज पैसेंजर्स नॉट वियरिंग सेफ्टी बेल्ट, वाइलेशन ऑफ पार्किंग रूल्स, यूज ऑफ द हैण्ड कम्युनीकेशन डिवाइसेज व्हाइल ड्राइविंग फाल्ट नम्बर प्लेट आदि। यह सभी बातें हैं जिसके ऊपर चालान हो सकता है। अभी केवल हेलमेट के ऊपर चालान हो रहा है, जो व्यवहारिक स्थिति है। इसके साथ जब कभी भी सब-इन्स्पेक्टर को या ट्रैफिक इन्स्पेक्टर कोई चालान करता है और कोई आरोप लगाता है कि साहब आपने मेरा गलत चालान कर दिया।

पहले यह था कि साहब मेरे पास कागज नहीं है अब तो मोबाइल में फीड हो गया अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, आपका इन्श्योरेंस है तब आपका चालान नहीं होगा।

मान्यवर, इस पर खास तौर से एक बात हमारी सरकार ने की है। जो लोग चालान करते हैं, उनके पास एक बॉडी बॉण्ड कैमरा रहता है, ताकि जो भी निगोसिएशन हो, उस कैमरे में सेव हो जाए, ताकि कोई व्यक्ति यह न कह पाए कि हमसे अभद्र व्यवहार किया या हमको नाजायज परेशान किया। सरकार ने इस बात पर पूरी सावधानी बरती है कि किसी का हरेसमेंट न हो, कोई परेशान न हो, कोई उल्टा-सीधा उससे निगोसिएशन न करे, इस प्रकार की बातों को रोकने के लिए ये व्यवस्था की है। जहाँ तक कानून के पालन के लिए कई सारी आपत्तियाँ हैं, तो मान्यवर, हम क्षमा चाहेंगे। आखिरकार एक्सीडेंट को रोकना है, तो ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना जरूरी है, लेकिन किसी को हरेस करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है, ताकि कोई नाजायज परेशान न हो।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से सहमत हूँ। मैं मा0 मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि मैंने आपको जो दृष्टान्त दिया, हमारे पास उसके चालान के पेपर हैं, परन्तु मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस चालान के नाम पर जो हरेसमेंट हो रहा है, उस पर आपका एक निर्देश चला जाए कि इस तरीके के चालान के नाम पर लोगों का शोषण न हो। दूसरा, मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि आपने जिस कैमरे का जिक्र किया, क्या ये उत्तर प्रदेश के सभी ट्रैफिक सिपाहियों को, जो चालान काट रहे हैं, प्रोवाइड करा दिया गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, लगभग 25 से 30 हजार कैमरे उपलब्ध कराये गये हैं। दूसरा, किसी का हरेसमेंट न हो, इस सम्बन्ध में हम परिपत्र जारी करवा देंगे कि नाजायज तरीके से किसी को परेशान न किया जाए। जितनी सावधानी बरती जा सकती है, उतनी बरती जाए।

प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों के त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के सम्बन्ध में

***5-श्री अभय सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों के त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों के त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 व उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 की संगत धाराओं/नियमों में व्यवस्थाएं प्राविधानित हैं। उक्त के अतिरिक्त राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों के त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश दिनांक 28-12-2021, 09-09-2022 व दिनांक 18-11-2022 तथा शासनादेश दिनांक 27-3-2018 व 26-12-2022 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनका विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अभय सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गाँव में रहने वाले किसानों से सम्बन्धित है। हमारा प्रश्न था कि क्या राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों के त्वरित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सरकार की कोई गाइडलाइन है। उन्होंने कहा हाँ गाइडलाइन है और जो इन्होंने समय-समय पर शासनादेश और सकुर्लर भेजा है, उसकी एक प्रतिलिपि हमको दी है। मा0 अध्यक्ष जी, ये जो कुछ है सिर्फ एक साइक्लोस्टाइल के रूप में है। मान्यवर, गाँव में जो किसान रहते हैं, उनका मिलजुमला खाता होता है। एक खाते में 5-5, 7-7, 20-25 आदमी तक रहते हैं और उसके बाद बंटवारे को लेकर उनमें झगड़ा होता है और लगभग 80 प्रतिशत गाँवों में इसी को लेकर झगड़ा होता है कि खाते में हम भी हैं, हम इधर लेंगे, वो कहता है हम इधर लेंगे। उसमें लाठी-डंडा चलता है और फौजदारी हो जाता है। जो नई राजस्व संहिता,

---

† छापा नहीं गया।

2006 बनी है, जो वर्ष 2016 में लागू हुई। इस झगड़े को खत्म करने के लिए धारा-30 के अन्तर्गत उपधारा-2 है, जिसमें नियम बनाया गया है कि कानून-गो, लेखपाल, नायब तहसीलदार मौके पर जाएंगे और उसको देखेंगे, सारे पक्षों को बुलाएंगे, सहमति बनाकर, नक्शा बना करके दाखिल कर देंगे और माह, दो माह व तीन माह के अन्दर उसका निस्तारण कर देंगे, तो झगड़ा खत्म हो जायेगा। हम मा0 मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो 11 फरवरी, 2016 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 लागू हुई, क्या पिछले सात वर्षों में उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले/तहसील में धारा-30 की उपधारा-2 के अन्तर्गत कोई कार्रवाई की गयी। मा0 मंत्री जी पहले इसका जवाब दे दें, तत्पश्चात् हम दूसरा प्रश्न पूछ लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

मान्यवर, राजस्व संहिता, 2006 संशोधित राजस्व संहिता नियमावली, 2016 की संगत धारा और नियमों में व्यवस्था का प्रावधान है। जो राजस्व विवाद है, उनका समयबद्ध निस्तारण करने के लिए समय-समय पर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, जिसकी विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी है। इसमें समयबद्ध भी करने का निर्णय लिया गया है। धारा-70 (6) के मामले में 90 दिनों की अवधि के अन्दर निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। धारा-80 के विवाद में 45 दिनों के अन्दर निस्तारण करने का काम करेंगे। यदि समयावधि के अन्तर्गत उसका निस्तारण सम्भव नहीं है, तो आवेदक को कारण सहित अवगत भी कराएंगे। मान्यवर, इसी तरह जो दाखिल खारिज के मामले हैं, उसको भी 45 दिन के अन्दर निस्तारण करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है।

मान्यवर, इसी का परिणाम है कि इन्हीं प्रावधानों को लागू करने के बाद जहां 2016 में वादों के निस्तारण की स्थिति जो आयी थी 14,20,608 वाद 2016 में राजस्व अदालतों द्वारा किये गये थे। उसके सापेक्ष में वर्ष 2022 में 25,38,515 वाद एक साल के अन्दर निस्तारण करने का एक रिकार्ड कायम सरकार ने किया है, इसमें सरकार का पूरी तरह प्रयास है कि जो भी पीड़ित पक्ष हो उसमें समय पर न्याय मिले, गुणवत्तापूर्ण न्याय मिले और तुरन्त न्याय मिल सके, इसके लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है।

श्री अभय सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इस जवाब में मा0 मंत्री जी को जो लिख करके बता दिया गया है यह उसका ही बता दे रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत धारा-30 की उपधारा-2 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कितने मिलाजुला खातों का बंटवारा हुआ है किसी तहसील में ? वैसे ये इसका जवाब आज नहीं दे पायेंगे, क्योंकि इन्होंने यह सोचा ही नहीं होगा कि कोई पढ़ करके भी आयेगा । दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूँ कि वरासत का मामला,

दाखिल खारिज का मामला 45 दिन में कर देते हैं, वरासत का मामला कभी 50 दिन में किया हो तो, हमारे यहां एक सोहावल तहसील है वहां के तहसीलदार से रिपोर्ट ले लीजिए, अगर एक भी मामला किया हो 50 दिन में।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप सोहावल तहसील का मामला दिखवा लीजिएगा।

श्री अभय सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी कुछ सलाह भी है कि पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, हम इसलिए नहीं बैठें हैं कि हम आपकी आलोचना करें, हम इसलिए बैठे हैं कि हम चाहते हैं कि काम हमारे और आपकी बात-चीत से सुचारु रूप से हो। जैसे कि न्यायालय होते हैं, कोर्टें होती हैं, वहां पर अधिकारी सुबह 10:30 पर बैठ जाते हैं, लेकिन किसी भी चकबन्दी न्यायालय में या राजस्व सम्बन्धी न्यायालय में कोई अधिकारी 10:30 बजे नहीं बैठता सभी 12 बजे तक बैठते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे चकबन्दी का मामला होता है, तो चकबन्दी में एक नियम यह भी है कि चकबदी अदालतें गांव में जाएं और वहां अदालत लगायें और उसके एविडेंस लेकर उसका निस्तारण कर दें। लेकिन हम यह जानना चाहते है कि आज के समय में कितना ऐसा हो रहा है ? इसकी राजस्व में तो व्यवस्था है, तब इनको भी कुछ ऐसी व्यवस्था बना देनी चाहिए, एक नियम बना देना चाहिए कि 15 दिन में, 1 महीने में एक चकबन्दी न्यायालय चाहे सी0ओ0 को किसी गांव में जा करके बैठ करके वहां पर न्यायालय लगा दें और उस गांव का कम से कम 80 प्रतिशत मसला इससे निस्तारित हो जाएगा। तीसरी चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जो यह व्यवस्था है अगर इसको आप नहीं कहेंगे, हम जैसे न्यायालय में जाते हैं तो वहां लिखा होता है कि 'न्याय चला निर्धन की ओर' लेकिन जो स्थितियां बनी हुयी हैं वरासत दर्ज करने में और दाखिल खारिज कराने में, न्याय निर्धन की तरफ नहीं जाता है। न्याय तो इन्तजार करता है कि निर्धन हमारे यहां आये, सुविधा शुल्क दे तब उसको न्याय दें। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारी इस सलाह को मानिये और जो स्पेसिफिक प्रश्न आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले में इसका अनुपालन हुआ है, इसकी हमें जानकारी दीजिएगा और सोहावल तहसील के बारे में आप पता कर लीजिएगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, जो राजस्व संहिता, 2006 है यह लागू हुयी थी 2016 में उसको लागू करने में जो 36000 का चेंज किया था, इसमें यह किया गया था कि किसी भी किसान को, किसी भी गरीब को अधिकारियों के चक्कर न लगाना पड़े जैसे कि लेखपाल है, नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है यहां तक की एस0डी0एम के यहां भी किसानों को बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। वरासत चढ़ाने में सालों-साल का समय लगता है यहां तक कि वरासत करने

वाला शायद मर भी गया हो, चला भी गया हो, तब भी वरासत लागू नहीं हो पाती और इसके साथ-साथ जो भी रजिस्ट्री कराते हैं उनका दाखिल खारिज 45 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन न तो लेखपाल उसको चढ़ाता है न ही नायब तहसीलदार ध्यान देता है। यहां तक कि तहसीलदार के यहां भी दाखिल खारिज में बहुत देरी होती है। तो मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि अगर देरी होती है तथा ढिलाई कर रहे हैं तो उन अधिकारियों को अभी तक कितना दण्ड दिया है, किसी को मिला है दण्ड और अगर दण्ड नहीं मिला है तो क्या दण्ड दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के संशोधन की आपने चर्चा की है, उसमें निश्चित रूप से ये प्राविधान थे कि जो भी राजस्व अदालतें हैं वे समयबद्ध तरीके से मामलों का निस्तारण करेंगी और उनका कोटा भी माहवार तय किया गया था कि एक महीने के अन्दर निस्तारण कर दें। उसी के अन्तर्गत जो आपने 2016 में प्राविधान किया उसका हमारी सरकार ने एक्जीक्यूशन करते हुए पारदर्शिता के साथ पहली बार उत्तर प्रदेश में 305 पद एस0डी0एम0 न्यायिक के स्वीकृत किये जो केवल इसी तरह के वादों का निस्तारण करने का काम करेंगे। मुझे आज खुशी हो रही है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार पारदर्शिता के साथ, राजस्व के मामलों में समयबद्धता के साथ फैसले कराने के लिए चिंतित व प्रयासरत् है। उसी का परिणाम है कि एस0डी0एम0 न्यायिक के सृजित कुल 305 पदों में से 247 पद भरे जा चुके हैं और 55 पदों पर चयन व तैनाती तथा पदोन्नति की प्रक्रिया प्रचलन में है और हमारा यह भी प्रयास है कि जो भी अधिकारी न्याय देने में समयबद्धता व गुणवत्ता का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय अभय सिंह जी और आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने पूछा है, इसमें जो आपने समय-सीमा सभी के लिये तय की है, आपने बताया कि 90 दिन की समयावधि के बारे में। इसमें इस बात के लिए पुनः निर्देश चले जायं कि जो समय-सीमा है उसके अन्तर्गत ही उसका निर्णय हो जाये और इस बात की एकाउण्टबिल्टी हो जाए कि अगर उस समय सीमान्तर्गत नहीं होता है तो फिर उनकी जिम्मेदारी फिक्स हो जाये ।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कितने लोगों को दण्ड दिया, उसका जवाब नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना मंत्री जी के पास नहीं है। कृपया बैठिये।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों के अन्दर के मार्गों को सी0सी0 कराने हेतु

***6-श्री अखिलेश-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों के अन्दर के मार्गों को सी0सी0 कराने हेतु ग्राम पंचायतों के अलावा किसी अन्य योजना के तहत सी0सी0 कराये जाने की सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से लगभग रु0 14,666/- करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हो रही है। आवश्यकतानुसार अपने क्षेत्र में सी0सी0 रोड का निर्माण करा सकती हैं इसलिए सी0सी0 रोड निर्माण हेतु अतिरिक्त योजना की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अखिलेश-

माननीय अध्यक्ष जी, आज का मेरा सवाल उन 70 फीसदी आबादी के लिए है, जो गाँवों और कस्बों में रहती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 06 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज भी गाँवों में आने-जाने के रास्ते के लिए, जल निकासी के लिए और पुल-पुलिया के लिए दुश्वारियाँ बनी हुई हैं। हालात ये है कि बरसात के दिनों में न गाँव वाले बाहर आ पाते हैं और न बाहर का कोई व्यक्ति गाँव में घुस पाता है। मेरे प्रश्न का जो लिखित जवाब आया है उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से लगभग रु0 14,666/- करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हो रही है। आवश्यकतानुसार अपने क्षेत्र में सी0सी0 रोड का निर्माण करा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह जो आपने पढ़ा, यह लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री अखिलेश-

माननीय अध्यक्ष जी, हम यह पूछना चाहते हैं कि इस सरकार से पहले की जो सरकारें थीं, गाँवों में विकास कार्य कराने के लिए योजनायें बनाती थीं, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, समाजवादी पार्टी की सरकार में लोहिया समग्र विकास योजना और जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजनायें चलायी जाती थीं। हम यह कहना चाहते हैं कि जिन संस्थाओं को माननीय मंत्री जी ने गिनवाया है कि ये संस्थायें काम कर रही हैं, ये संस्थायें उस

सरकार में भी थीं। लेकिन विधायकों के प्रस्ताव पर साल भर में 4-5 लोहिया ग्राम तथा 10 ग्राम जनेश्वर मिश्र योजना के अन्तर्गत चयनित किये जाते थे और विधायकों के प्रस्ताव पर जब काम होते थे तो गाँव के लोगों को लगता था कि हमारा विधायक भी हमारे लिए कुछ कर रहा है या हमारे क्षेत्र की जानकारी रखता है। तो माननीय अध्यक्ष जी, हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की कोई योजना चला करके गाँवों को विकास कार्यों से संतृप्त कराने का काम सरकार करेगी ?

श्री जितिन प्रसाद-

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न किया है उसमें इन्होंने इच्छा जाहिर की है कि पहले गाँव के विकास के लिए कुछ ग्रामीण क्षेत्र की योजनायें होती थीं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, सिर्फ योजनाओं से काम नहीं चलता है, धरातल पर काम होना चाहिए और उसको दृष्टिगत रखते हुये सिर्फ 5-6 गाँव किसी जनप्रतिनिधि को दे दिये जाएं चयनित करने के लिए, उससे सबका भला नहीं होता है। हम सबको साथ लेकर प्रत्येक गाँव में विकास चाहते हैं।

मान्यवर, उसके तहत पहले जो प्राविधान था कि सिर्फ ग्राम पंचायत ही गांव के अन्दर काम करा सकती है। मगर 24 अगस्त, 2021 को एक शासनादेश जारी किया गया जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत भी गांव के अन्दर काम कराने के लिए उनको प्राविधान दिया गया। जहां तक धन की बात है इतना धन कभी नहीं आया होगा जो अब गांव के लिए दिया जा रहा है। चाहे वह केन्द्र सरकार द्वारा हो या राज्य सरकार द्वारा हो तो दोनों मिला करके प्रयास यही किया जा रहा है कि नियमों में छूट दी जाए सांसद, विधायक कभी भी चाहें गांव में काम करा सकते हैं मगर यह जो प्राविधान था जो पहले नहीं था सिर्फ ग्राम पंचायत ही काम करा सकती थी उसमें छूट दे दी गयी।

श्री अध्यक्ष-

श्री लालजी वर्मा जी आपको पता है कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ पूछने को नहीं है। सरकार ने कह दिया कि नहीं करा रहे हैं मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ पूछने को नहीं है। ठीक है वर्मा जी बोलिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो इन्होंने कहा कि चौदह हजार छह सौ छियासठ करोड़ की अधिक धनराशि उनको मिली है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि उनको शासन स्तर से अपनी योजनाओं की लायबिलिटी दे दी जाती है। जैसे पंचायत भवन बना, सचिवालय भवन बना उसमें कर्मचारी रखने का उसी दिन आयोग से वेतन दे दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

पहले तीन हजार करोड़ रु0 आता था अब चौदह हजार करोड़ रु0 आता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से बस इतना जानना चाहता हूँ कि जो प्रदेश सरकार उन पर धारित कर रही है अपनी योजनाओं के लिए क्या उसे वह छूट देने का काम करेगी। उनसे वेतन दिलवाया जा रहा है, तो उनके पास पैसा बच ही नहीं रहा है जिससे वह सी0सी0 रोड बनाएं। या तो उसका अतिरिक्त पैसा दें।

श्री अध्यक्ष-

इसमें जानकारी करके बताएंगे और इसको लिखकर देंगे। इसके लिए जानकारी नहीं है।

***7-श्री मौहम्मद फहीम इरफान**

[02-शुक्रवार के ताराकिंत प्र0सं0-13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विभाग द्वारा समय से कार्य न कराने के सम्बन्ध में

***8-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विभाग द्वारा समय से कार्य न कराने एवं लापरवाही से होने वाली फसलों की भारी तबाही तथा जनहानि से बचने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना अथवा नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतन्त्र देव सिंह)-

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग पिछले वर्षों की बाढ़ को ध्यान में रखते हुए सजग एवं तत्पर रहकर प्रो-एक्टिव एप्रोच के साथ समेकित दृष्टिकोण अपनाते हुए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सघन निरीक्षण कर बाढ़ पूर्व तैयारी करता है तथा सम्यक् विचारोपरान्त सिंचाई विभाग की स्थायी संचालन समिति से अनुमोदित बाढ़ परियोजनाओं को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार बाढ़ से पूर्व पूर्ण कराता है, जिससे बाढ़ से होने वाली क्षतियों को न्यून किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार 55वीं स्थायी संचालन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यवृत्त संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न पर अनुपूरक करने का अवसर दिया है।

[†] छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

इस समय कौन सी बाढ़ आई ?

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, बाढ़ क्षेत्र से ।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा ठीक है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से दो छोटे-छोटे सवाल करूंगा वैसे मा0 मंत्री जी ने विस्तार से अपना उत्तर दिया है और इस बात के लिए मैं मा0 मंत्री जी को बधाई भी देता हूँ कि 301 योजनाओं को इन्होंने अस्थायी समिति द्वारा जो चयन हुआ है, उसका इन्होंने इसमें डिटेल लिस्ट भी लगाया है। इसमें मेरा यह सवाल है कि क्या जो अस्थायी संचालन समिति ने जो 301 परियोजनाओं की अपने कमेटी द्वारा अप्रूव्ड की है जिसमें आप अध्यक्ष हैं तो क्या इसकी शासन से स्वीकृति जारी कर दी गई है और अगर स्वीकृति जारी कर दी गई है तो क्यों इसे बरसात से पहले इन कार्यों को पूर्ण करा लिया जाएगा यह पहला सवाल है। दूसरा है मा0 मंत्री जी कि बलिया जनपद में आपने सरयू और गंगा दोनों का जिक्र किया है और इसमें आपने टौंस नदी परियोजना का जिक्र किया है। क्योंकि हमारे यहां टौंस नदी भी बहुत प्रभावित करती है और कई बार इस टौंस नदी से प्रभावित गांवों के बारे में मैंने विभिन्न नियमों में इस सदन में लाने का भी प्रयास किया हूं, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है तो मैं आज इसमें यह चाहता हूँ कि जो यह टौंस नदी है इससे कुछ प्रभावित गांव हैं जैसे अतरसुआ है, कोडरा है, वेसवान है, प्रधानपुर है, मिरजापुर जेवेनिया है और लखुआ है, क्योंकि यह गांव जब प्रभावित हुए थे तो मैं हर साल बाढ़ में जाता हूँ तो लगभग 25 साल पहले ठोकर बने हैं जो पूरे तरह से अपने अस्तित्व में नहीं हैं और वह अपना अस्तित्व खो चुके हैं तो क्या इन ठोकरों का मरम्मत माननीय मंत्री जी कराने का विचार करेंगे और जो हमारे यहां टौंस नदी के बाढ़ का पानी फैलता है, टौंस नदी से बचाव के लिए गाजीपुर से रिंग बन्धा आता है उसका मैंने जब आँकलन किया कि हर साल पानी इन गांव में फैलता कैसे है, तो हम लोग नाव से गए तो उसमें 500 मीटर का एक पैच है जो दोनो बन्धों के बीच में रह गया है।

श्री अध्यक्ष-

उसको आप अलग से लिख कर दे दीजिएगा।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

मान्यवर, सिंचाई विभाग की योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। टेण्डर की प्रक्रिया भी हो चुकी है और मई जो उसका लक्ष्य रहता है पिछले बार भी लगभग हमारी जो योजनाएं थीं। पिछली बार भी वर्ष 2022-23 में हमारी लगभग 256 परियोजनाएं थीं। पहली बार व्यवस्थित

रूप से मैंने पूर्ण भी किया और पूर्ण होने से 3-5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ प्राप्त हुआ और इससे लगभग 26 लाख आबादी लाभान्वित हुयी। मा0 अध्यक्ष जी, पिछले 05 वर्षों में 883 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है जिससे 24-51 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि तथा 1-74 करोड़ आबादी लाभान्वित हुयी है। मा0 उमाशंकर जी ने टौंस नदी का जो विषय उठाया है, आप उसको लिख कर भी दे दीजिये, मैं एक बार उसको दिखवा लूंगा। किसानों के हित में जो भी होगा उसकी पूरी चिन्ता की जायेगी तथा किसानों को लाभ कैसे पहुँचे और किसान सुरक्षित कैसे रहें इसकी भी पूरी चिन्ता की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, धन्यवाद ।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

***9-डॉ0 संग्राम यादव (अनुपस्थित)-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण नीति वर्ष 2018 में लागू की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2018 में कितने जनपदों के शिक्षकों का स्थानान्तरण हुआ और कितने जनपदों में उक्त स्थानान्तरण नीति द्वारा किया जाना शेष है ? क्या सरकार प्राथमिक विद्यालयों का वर्ष 2023 में भी स्थानान्तरण नीति लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ। नीति आयोग द्वारा चिन्हित महत्वाकांक्षी जनपद बलरामपुर, बहराइच, चन्दौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र को छोड़कर अन्य जनपदों में अध्यापकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही की गयी है। किसी जनपद से स्थानान्तरण किया जाना शेष नहीं है।

वर्ष 2023 में स्थानान्तरण नीति लागू किये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य डॉ0 संग्राम यादव जी उपस्थित नहीं हैं।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा बलिया जनपद भी घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हम अगला प्रश्न संख्या-10 लेते हैं।

प्रदेश में बढ़ते साइबर जनित आर्थिक अपराध को रोकने के सम्बन्ध में

***10-श्री जियाउर्रहमान, श्री रवि शर्मा, श्री तुफानी सरोज, श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू तथा श्री पंकज-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश में बढ़ते साइबर जनित आर्थिक अपराध को रोकने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ? क्या सरकार उक्त अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष सेल गठित कर पुलिस को आधुनिक उपरकरण उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों की निगरानी प्रदेश के सभी जनपद, परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर सोशल मीडिया सेल द्वारा किया जाता है। जनपद, परिक्षेत्र एवं जोनल सोशल मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियों से सम्बन्धित ऐसे पोस्ट, जिनमें उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग किया जाता है, का संज्ञान लेकर सम्बन्धित जनपद के माध्यम से ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में साइबर जनित आर्थिक अपराध की रोकथाम के लिये प्रत्येक 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना की गयी है एवं प्रदेश के शेष 57 जनपदों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है। प्रदेश के साइबर वित्तीय अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु टोल फ्री नम्बर-1930 जारी किया गया है जो 24 घण्टे प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। इस टोल फ्री नम्बर पर आने वाली आर्थिक साइबर अपराध से सम्बन्धित शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुये साइबर अपराध में प्रयोग किये गये बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाता है जिससे अपराध से सम्बन्धित धनराशि अपराधी निकाल नही पाते हैं। प्रदेश के समस्त थानों को एनसीआरपी (नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) से जोड़ दिया गया है। साइबर वित्तीय अपराध की ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के थानों एवं साइबर क्राइम थानों द्वारा जांच कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाती है। प्रदेश के प्रत्येक थाने साइबर सेफ पोर्टल से जुड़ चुके हैं तथा साइबर अपराध में प्रयुक्त किये गये मोबाइल नम्बर व बैंक खातों को ब्लाक करने हेतु समय-समय पर साइबर सेफ पोर्टल के माध्यम से गृह मंत्रालय भारत सरकार को रिपोर्ट प्रेषित की जाती है।

साइबर क्राइम से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता हेतु प्रदेश के समस्त थानों पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है एवं प्रत्येक जनपद स्तर पर जनपदीय साइबर क्राइम सेल, परिक्षेत्रीय स्तर पर परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम सेल, जोन स्तर पर जोनल साइबर क्राइम सेल, राज्य स्तर पर साइबर क्राइम सेल गठित है। इन साइबर वित्तीय अपराधों पर प्रभावी अंकुश

लगाने हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में आम-जनमानस को साइबर अपराधों से जागरूक करने के लिये प्रत्येक माह के प्रथम बुद्धवार को साइबर जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। साइबर अपराध की विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण हेतु आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित तथा परिक्षेत्रीय साइबर थानों पर बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब एवं साइबर मुख्यालय पर एडवांस डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब के स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है, जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जियाउर्रहमान-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न किया था कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश में बढ़ते साइबर जनित आर्थिक अपराध को रोकने के लिये सरकार ने क्या योजना बनायी है ? मा0 मंत्री जी की तरफ से जवाब आया है कि प्रदेश के 75 जिलों में से 18 जिलों में साइबर थाने बना दिये गये हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के अन्दर बाकी जो 57 जिले हैं उनमें कब तक साइबर थाने बनकर शुरू करा दिये जायेंगे ? मान्यवर, मेरा मकसद है कि हम हर धर्म का तथा हर धर्म के लोगों का सम्मान करें। दूसरा मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के अन्दर ऐसे गैर जिम्मेदार लोग जिन्होंने आए दिन पेशा बना लिया है और वह हमारे धर्म के खिलाफ खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि अगर कार्यवाही की गयी है तो ऐसे कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है और आने वाले समय में अगर कोई ऐसा गलत कदम उठाता है, तो उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ? इसके अलावा मेरा एक और प्रश्न है कि बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके खिलाफ टिप्पणी की जाती है चाहे वह मीडिया की तरफ से हो, अगर सही है, तो हम समझते हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल कर देता है। अगर उनके खिलाफ गलत टिप्पणी की जाती है, जो कि उसके अन्तर्गत नहीं आता, तो क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी, कोई कदम उठायेगी ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अपने इन प्रश्नों का जवाब चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, मेरा विनम्र अनुरोध है कि जितने मा0 सदस्यों ने यह प्रश्न लगाया है उनमें से यदि कोई मा0 सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ ले, उसके बाद आप एक साथ उत्तर दे दें।

श्री पंकज-

मा0 अध्यक्ष जी, आज प्रदेश में साइबर अपराध की घटनाएं अत्यधिक हो गयी हैं। एक जनपद में एक दिन में लगभग पचासों साइबर की घटनाएं होती और एक जनपद में लगभग लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है। जो व्यक्ति साइबर अपराध से पीड़ित हो जाता है उसको एफ0आई0आर0 दर्ज कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा काफी लोगों की एफ0आई0आर0 भी दर्ज नहीं होती है। मा0 मंत्री जी से मेरा सवाल यह है कि क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने साइबर अपराधियों पर कार्यवाही करते हुये पीड़ितों का पैसा वापस कराने का काम किया गया ? मेरा दूसरा सवाल है कि क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शेष 57 जनपदों में साइबर क्राइम पुलिस थाने कब तक स्थापित हो जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप उत्तर दे दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं पहले मा0 सदस्य श्री जियाउर्रहमान के प्रश्न का और उसके बाद मा0 सदस्य श्री पंकज जी के प्रश्न का जवाब दे दे रहा हूँ। मा0 सदस्य ने पूछा कि बहुत सी भ्रामक सूचनाएं या इन्सल्टिंग बातें सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित की जा रही हैं, उसका खण्डन और उसमें कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ? वर्ष 2022 में सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों एवं आपत्तिजनक टिप्पणियों से सम्बन्धित पोस्ट का संज्ञान लेकर कुल 857 अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं जिनसे सम्बन्धित 655 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ जो 57 जिले हैं वहां पर थाना बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। जहां तक रिपोर्ट का सवाल है, तो इसमें एक व्यवस्था दी गयी है, 'डेडिकेटेड ट्विटर हैंडल' इसमें जो लोग पोस्ट डालते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है और प्रदेश के हर थाने में 5 लाख से अधिक 'व्हाट्सएप डिजटल वॉलिंटियर' बनाये गये हैं जिनके सहयोग से आपत्तिजनक टिप्पणियों पर रोकथाम के साथ-साथ भ्रामक खबरों का खण्डन कराया जाता है। जहां तक कार्रवाई का सवाल है, तो साइबर अपराधों में प्रदेश के थानों में कुल 5432 साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं 89 करोड़ 46 लाख रुपये की धनराशि बरामद की गयी है। जहां कहीं भी जिस प्रकार से हर जगह जितने भी हमारे कमिश्नरी हेड क्वार्टर हैं उसमें साइबर थाने खोले गये है और हर 1531 थानों में साइबर सेल की स्थापना की गयी है।

उन लोगों को लगभग, मैं आपको संख्या बता दूँ कि यह कोशिश की गयी कि सब जगह ट्रेड स्टाफ होना चाहिए जिसमें 1 लाख 92 हजार 800 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया, ताकि वह व्यक्ति जो थाने पर बैठे हैं वह प्रॉपर्ली सजेस्ट करें और अगर अपराध को रजिस्टर्ड करने की बात होती है, तो अपराध रजिस्टर करवायें जिससे आगे

की कार्यवाही जिस प्रकार से बाकी के केसों में होती है उस प्रकार से की जाय । सरकार पूरी तरीके से इस पर जागरूक है और हर तरह से इस बात की कोशिश कर रही है कि अगर किसी के साथ इस प्रकार का फ्रॉड होता है और उसकी सूचना अगर बैंकों से तुरन्त मिल जाये, तो इस प्रकार के केसेज में फ्रॉड को रोका भी जा सकता है, रोका भी गया है। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाये जा रहे हैं। लगभग 23 हजार से ज्यादा स्थानों पर अभी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाये गये हैं और सबसे ज्यादा इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। लोगों से लोग बहला फुसलाकर बैंक का नम्बर, एकाउन्ट का नम्बर पूछ लेते हैं और कभी बैंक का अधिकारी बनकर कभी किसी पुलिस का अधिकारी बनकर फोन करते हैं और भोले-भाले लोग जवाब दे देते हैं। जो अवेयरनेस सेन्टरर्स हैं वहां पर हर बुधवार को प्रत्येक पुलिस अधीक्षक को निर्देशित, किया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में पैमप्लेट बटवायें खासतौर से बैंकों में जितने भी एकाउन्ट होल्डर हैं उनको भी सूचना मिल जाये, बाकी लोगों को भी जितने स्कूल कॉलेज हैं, जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी लोगों को यह सूचित कर दिया जाए कि किसी प्रकार से इस प्रकार की जानकारी किसी गैर आदमी को न दी जाय। मैं समझता हूँ कि जितनी भी सावधानी बरती जा सकती है, बरती जा रही है। इसमें 1930 एक नम्बर है जिसे शिकायत करने के तौर पर घोषित किया गया है। जिस पर यदि आपको कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता तो इस नम्बर पर शिकायत करके सहायता मिल सकती है। इस पर 20 लाइनें 24 घण्टे चल रही हैं तथा इसको और आगे बढ़ाया जायेगा। 57 थाने खुलने की प्रक्रिया है, मैं समझता हूँ कि जल्दी ही इसको भी कार्यान्वित कर दिया जायेगा।

श्रीमती सैय्यदा खातून-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी एक शिकायत है कि पिछले एक महीने पहले मेरा फोन भी सोशल मीडिया के माध्यम से हैक कर लिया गया था जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियाँ एवं अश्लील फोटोज पोस्ट की जा रही थीं। हमें इसको कन्ट्रोल करने में एक माह का समय लग गया था। मान्यवर, जब हम लोगों के साथ इस तरह की घटनायें हो रही हैं, तो फिर और लोगों के साथ क्या हो रहा होगा ? मैं चाहती हूँ कि इस तरह की घटनाओं का खुलासा जल्द से जल्द होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

क्या आपने इसकी रिपोर्ट लिखवाई थी ?

श्रीमती सैय्यदा खातून-

मान्यवर, इसकी जानकारी मैंने प्रमुख सचिव, विधान सभा को भी दी थी।

श्री अध्यक्ष-

यह दुर्भाग्यपूर्ण है इसकी मा0 मंत्री जी जानकारी करेंगे और जिन्होंने यह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 सदस्या, आप एक कॉपी हमें दे दीजिए, जिसका हम संज्ञान लेकर आपको बाद में जवाब दे देंगे। इस सम्बन्ध में व्यवस्था भी है जिसका शिकायत नम्बर 1930 है एवं वेबसाइट है www.cybercrime.gov इसमें शिकायत दर्ज कराकर व्यक्ति की जो भी मदद हो सकती है की जाती है। ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन सभी लोगों को इसकी जानकारी हो जाए इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ। आपका जो व्यक्तिगत मामला है उस सम्बन्ध में पत्र हमें दे दीजिए उसको हम अलग से दिखवा लेंगे।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, लगभग डेढ़-दो महीने पहले मुरादाबाद में ऐसे ही एक साइबर क्राइम हुआ। जिसमें एक महिला के एकाउण्ट से एक लाख अस्सी हजार रुपये निकाल लिये गये। उसकी एफ0आई0आर0 उसी दिन लिखा दी गयी थी और मैंने गाजियाबाद, नोएडा में इसके अधिकारी जो एडीशनल एस0पी0 बैठते हैं। मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस सम्बन्ध में आपको कार्यवाही करके बतायेंगे। मुरादाबाद के जो आई0ओ0 हैं वह उनसे इस सम्बन्ध में कहते हैं कि आपके एक लाख अस्सी हजार रुपये गये हैं। आप पचास हजार रुपये मुझसे ले लीजिए और इस पर कम्प्रोमाइज कर लीजिए, खत्म कर दीजिए। यह तो बड़ा गलत मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आप इसको बताइये, इसका संज्ञान लेंगे।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, अगर आप कहें तो एफ0आई0आर0 की कापी उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

एफ0आई0आर0 की कापी आप दे दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आज अभी ही दे दें।

श्री जियाऊर्रहमान-

जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी आपने कहा कि महिला विधायक का सम्मान होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

उनकी बात आ गयी आप दूसरी बात कीजिए।

श्री जियाऊर्रहमान-

उस पर कार्यवाही की जा रही है, तो बाकी आम-जनता का क्या सूरत-ए-हाल होगा। यह आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

उसकी पूरी जानकारी कर ली जायेगी। कहां से हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। यह इतना आसान भी नहीं है। इण्टरनेशनल लेवल के ऊपर यह सब कुछ करना पड़ता है।

श्री जियाऊर्रहमान-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार डिजिटल टैक्नालॉजी की तरफ आगे बढ़ने के लिए कह रही है और जो ऑन लाइन पेमेन्ट की तरफ उनको करना चाहती है। मैं जानना चाहता हूँ जो गरीब, मजदूर लोग हैं जिनकी मेहनत की खून-पसीने की कमाई बैंक के अन्दर होती है और जब पढ़े-लिखों के साथ धोखा हो जाता है, तो गरीबों के साथ फ्रॉड होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? और अवेयर करने के लिए क्या कोई अभियान चलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

देखिये, अवेयर करने के लिए माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया। विषय यह है कि अगर वह पढ़ा-लिखा नहीं है, तो भी उसको यह पता है कि फंसा कैसे जा सकता है। अपने पैसे के बारे में सब लोग सावधान रहते हैं। चाहे पढ़ा-लिखा हो या न हो । सबके मोबाइल पर रोज दो-चार मैसेज आते हैं कि अपना ओ0टी0पी0 नम्बर नहीं दीजिए। कोई शेयर मत करिये। अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार भी चलाती है और सरकार के अलावा सरकार की विभिन्न एजेन्सियों के द्वारा मैसेज भी दिये जाते हैं। फिर भी आदमी करता है, तो उसमें उनको भी अवेयर करने की जरूरत है। सरकार ने जो भी जवाब दिया है, जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, की जायेगी।

***11-श्री पीयूष रंजन निषाद-**

[03-बुधवार के तारांकित प्रश्न सं0-22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्राथमिक स्कूलों में मानक के अनुरूप कक्षाओं का निर्माण कराकर शिक्षकों की तैनाती कराने के सम्बन्ध में

***12-डॉ0 रागिनी-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कतिपय प्राथमिक स्कूलों में कमरों के अभाव में एक या दो कमरों में ही सभी कक्षाओं की पढ़ाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप कक्षाओं का निर्माण कराकर शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ, कतिपय विद्यालयों में 1 या 2 कक्षों में कक्षायें संचालित हैं।

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 की संरचना की जा रही है। जनपदों से प्राप्त अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का प्रस्ताव समग्र शिक्षा की आगामी वर्षों की वार्षिक कार्य

योजना एवं बजट में किया जायेगा तथा प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति उपरान्त अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जा सकेगा। आर0टी0ई0 मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हैं, जिनकी यथावश्यकता तैनाती की जायेगी।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 रागिनी-

मान्यवर, आपका धन्यवाद आपने सवाल करने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल बेसिक शिक्षा मंत्री जी से था कि क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि कितने हमारे प्राथमिक स्कूल हैं जिसमें एक-दो कक्षा ही है और उनमें ही सारी कक्षायें चल रही हों। जिस पर उनका जवाब आया था कि जी हां। हमारे यहां एक-दो कक्षा में पूरी क्लासेज को चलाया जा रहा है। मान्यवर, इस जवाब से जनता को स्वयं में ही ठगा हुआ महसूस होता है। साथ ही साथ शिक्षा की इतनी सारी बातें हुईं और जब एक-दो कक्षा में ही सारी कक्षाओं को चला रहे हैं, तो यह सरकार की तरफ से एक इस तरीके का प्रोजेक्शन है कि आप शिक्षा को लेकर कितने जागरूक हैं ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जबकि उन्होंने ऑलरेडी यह बता दिया है कि न तो सरकार के पास बच्चों के लिए प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर है और साथ ही उनको सम्मानजनक तरीके से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि अधिकांश जगहों पर बच्चे आज भी टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ रहे हैं। चाहे वह भीषण गर्मी हो, चाहे ठण्ड हो, चाहे बरसात हो। अधिकांश जगह की इमारतें भी जर्जर हो चुकीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी क्योंकि मुझे डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है। सिर्फ जी हां बोल कर बताया गया है कि हमारे पास कम क्लासेज हैं और उन्हीं एक-दो क्लासेस में सारी की सारी क्लासेस को चलाया जाता है।

मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपके पास प्रॉपर डाटा है कि हमारे पास प्रदेश में कुल कितने स्कूल हैं जहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है। एक-दो-तीन क्लासेज में ही पूरा का पूरा स्कूल चलाया जा रहा है। साथ ही मैं यह भी पूछना चाहूंगी कि कितने प्राथमिक विद्यालय हैं जिनकी इमारतों की सिचुएशन जर्जर हो चुकी है, क्या उसका डाटा आपके पास है ? उसको आप कब तक ठीक करा देंगे ? जब तक आप उसको ठीक नहीं करा रहे हैं तब तक के लिए बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक तौर पर सुविधा या इन्तजाम किये हैं। जिससे उन बच्चों का समय जब तक आपकी इमारतों को बनाया जायेगा, वह व्यर्थ होगा। उसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहती हूँ कि आपके इन्फ्रास्ट्रक्चर का कोई मानक है, जिसके अनुसार बेसिक स्कूल को बनाना चाहिए ? अगर है, तो उसके अनुसार आप कब तक उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों को बना देंगे ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने विद्यालयों में कक्ष को लेकर अपनी चिंता जताई है, वर्तमान में प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के जितने भी विद्यालय हैं प्रत्येक विद्यालय में प्रदेश सरकार के

द्वारा आमूल-चूल परिवर्तन लाया गया है, मिशन कायाकल्प के अन्तर्गत अगर हम वर्ष 2017 से पहले के विद्यालयों के बारे में बात करें और उस स्थिति को देखें और आज की स्थिति को देखें तो मिशन कायाकल्प के अन्तर्गत 19 पैरामीटर्स पर आज हमारे परिषदीय विद्यालयों में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और हर एक मूलभूत सुविधा को जोड़ने की व्यवस्था की गयी है। जहां उस समय बच्चों के लिए टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं थी, क्लास रूम तो बहुत बड़ी बात थी और न पानी पीने की व्यवस्था थी और आज हर एक सुविधा को परिषदीय विद्यालय में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जो प्रश्न मा0 सदस्य ने उठाया है कि ऐसे विद्यालय हैं जहां पर जर्जर भवन हैं और जर्जर भवन होने के कारण इसकी प्रक्रिया पहले से ही गतिमान है, ऐसे जर्जर भवनों को चिन्हित करके उनके धवस्तीकरण की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है और जो बच्चे जर्जर विद्यालय के थे उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गयी है और बच्चों के पठन-पाठन का कार्य कहीं पर भी बाधित नहीं हो रहा है और ऐसे अभी जितने भी विद्यालय हैं प्रदेश भर में कई जगह ऐसी स्थिति है जहां पर छात्रों की संख्या 50 से 60 कई विद्यालयों में है, तो वहां पर दो या एक कमरों में पठन-पाठन का कार्य चल रहा है। प्रदेश भर में 823 विद्यालय ऐसे हैं जो हमारे एकल कक्ष में चल रहे हैं और 8160 विद्यालय ऐसे हैं जो दो कक्ष में चल रहे हैं लेकिन इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत कम है और पठन-पाठन का कार्य किसी भी तरह से बाधित नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पर भी इन विद्यालयों में कक्ष व टॉयलेट और पीने के पानी पर कार्य किया जा रहा है और 19 पैरामीटर्स पर जो हमारी सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है इसकी कार्रवाई गतिमान है और लगभग 90 प्रतिशत से भी अधिक हमारे विद्यालयों में 19 पैरामीटर्स को पूरा कर लिया है और आने वाले समय में इन सारी चीजों को भी पूरा करके हम शिक्षा के बेहतर स्तर को प्रदान करने में अपना पूरा योगदान देंगे।

डॉ0 रागिनी-

मान्यवर, मैं आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि अगर आप कह रहे है सारे पैरामीटर्स में हमारी सरकार और आपकी सरकार में जमीन-आसमान का फर्क आ चुका है और अगर हम प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों की बात करें तो क्या सरकार इस बात पर राजी होगी कि हम एक कमेटी का गठन करके जिसमें हमारे मेम्बर पक्ष व विपक्ष के भी हों और एक निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण करके देखा जाए कि उन स्कूलों की क्या सिचुवेशन है चाहे वह क्लासरूम हो या बेसिक सेनीटेशन हो या सरकार के जो भी पैरामीटर्स हों और उसको यहां पर रखा जाए। यह विषय सिर्फ आलोचना का विषय नहीं है। यह बेटरमेंट की तरफ सरकार को आगे बढ़ाकर कमेटी का गठन करना चाहिए। मैं मा0 मंत्री जी से चाहूंगी कि इसका उत्तर दें और साथ ही साथ जो अध्यापक तैनात हैं उनको हैल्थ या मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है तो मैं मा0 मंत्री जी से उसका भी अनुरोध करूंगी, जिस तरीके से बाकी विभागों में टीचर्स

को हेल्थ का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। यहां पर भी कैसलेस की सुविधा को भी प्रोवाइड कराकर लागू किया जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा था कि पहले के मुकाबले में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन हमने यह नहीं कहा कि सब कुछ ठीक हो गया। लोगों को इस बात का अहसास भी है और माननीय सदस्या जैसा कह रही हैं वैसा नहीं है। हमने कायाकल्प योजना के अन्तर्गत 1,34,000 से ज्यादा स्कूलों का जबर्दस्त सुधार किया है। पब्लिक इसी आधार पर बी0जे0पी0 के प्रति परसेप्सन बनाती है कि यह सरकार सुधार की तरफ काफी हद तक बढ़ी है। हम यह मानते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिये कमेटी की आवश्यकता नहीं है। मैं खास तौर से इसी बात को कोट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सरकार की मंशा है कि हम आगे भी हर तरह से बेसिक शिक्षा में जितना सुधार कर सकते हैं उतना करेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि हम 51,000 टीचर इसलिये नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब रेसियो पूरा हो गया है। शिक्षकों की नियुक्ति किए बगैर रेसियो पूरा होने का मतलब है कि छात्र संख्या घट गई है । अगर छात्र संख्या घट गई है तो ऐसा सुधार तो पूरी तरह बेमानी है।

(श्री महबूब अली, सदस्य द्वारा अनुपूरक पूछने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप बैठिये। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की योजना के सम्बन्ध में

***13-डॉ0 पल्लवी पटेल-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो प्रदेश के किन-किन जनपदों में कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने हेतु चिन्हित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ । शैक्षिक सत्र, 2018-19 एवं 2019-20 में प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में से कुल 14,000 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने हेतु चिन्हित किये गये, जिनमें से 13,250 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से छात्र-छात्राओं को शिक्षा दी जा रही है।

विवरण की प्रति संलग्न[†] है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ0 पल्लवी पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपने प्रश्न के सापेक्ष अनुपूरक पूछने का अवसर दिया, इस बावत मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैंने बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित जो प्रश्न पूछा उसमें माननीय मंत्री जी के विभाग से मुझे जो उत्तर मिला है उससे कुछ हद तक सन्तुष्ट होते हुए मैं अपने अनुपूरक की ओर बढ़ती हूँ। एक व्यक्ति के जीवन में आज पढ़ाई, दवाई और कमाई का संघर्ष है। व्यक्ति अपने छात्र जीवन में किस स्तर की और किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करता है वह उसका वर्तमान और भविष्य निर्धारित करता है और शायद इसीलिए बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिल्पी की संज्ञा दी गई है। बेसिक शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा है और जहां मातृ भाषा नहीं है वहां प्रादेशिक भाषा को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन यह भी सत्य है कि आज अंग्रेजी में शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम वार्तालाप का बहुत अहम बिन्दु बन चुका है। ऐसे में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मैंने सवाल किया था कि क्या प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की सरकार की कोई योजना है, जिसका उत्तर मुझे हाँ में मिलता है। मैंने प्रश्न किया कि इस योजना के सापेक्ष उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कितने विद्यालय हैं जहां पर आपने इस योजना को लागू किया है, उसका उत्तर भी मिला, लेकिन मेरी दुविधा यह है कि मुझे उत्तर में जो डेटा मिला है वह चार साल पुराना है। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूँगी कि आप मुझे इस योजना के सापेक्ष शैक्षिक सत्र, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 का डेटा देने की कृपा करें। मेरा दूसरा अनुपूरक है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट या परियोजना बनती है, तो उसका एक रोड मैप तैयार किया जाता है, उसका विधिवत रिव्यू होता है और उसकी डेडलाइन का निर्धारण होता है। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि क्या इस योजना से जुड़ी तमाम डिटेल रिपोर्ट डेडलाइन के साथ-साथ इस पटल पर रखने का कार्य करेंगे।

श्री संदीप कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले प्रश्न में माननीय सदस्य छात्रों की संख्या के बारे में बात कर रहे थे जिसका उत्तर नहीं आ पाया था। मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि 2017 से पहले जो भी सरकार रही है उनमें छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी। 2017 से लेकर आज तक छात्रों की संख्या देखें तो पहले जहां अभिभावकों का परिषदीय विद्यालयों से पूरी तरह से विश्वास उठ गया था तो आज उस विश्वास को दोबारा से कायम करते हुए जो छात्रों

[†] देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या-332-335 पर।

की संख्या गिरकर 1.40 करोड़ तक पहुँच गई थी और लगातार गिरती जा रही थी तो हमारी सरकार द्वारा आज छात्रों की संख्या को 1.91 करोड़ पर लाने का काम किया गया है। इसीलिए बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत हमेशा की तरह पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष विद्यालयों की स्थिति सुधर रही है और परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। मा0 सदस्य ने इंग्लिश मीडियम विद्यालयों के बारे में जानकारी चाही है तो वर्ष 2018-19 में 14000 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया गया था। जिसमें इस योजना को चलाया गया जिसके अन्तर्गत विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम से शिक्षा देने की व्यवस्था बनायी गयी। प्रश्न के साथ मैंने जानकारी दी है कि 13,250 विद्यालयों को प्रदेश भर में इंग्लिश मीडियम शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया गया । वहाँ पर इंग्लिश मीडियम पठन-पाठन का कार्य भी चल रहा है। लेकिन मा0 सदस्य ने चिंता जतायी कि और विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश की शिक्षा के साथ बच्चों को जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति, 2020 को लागू किया है उसके अन्तर्गत मातृभाषा को बढ़ावा देने का उसमें जोर दिया गया है। इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे हर एक परिषदीय विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो मीडियम है, जो पठन-पाठन का काम है चूंकि उसमें हमको मातृभाषा को बढ़ावा देना है। इसलिए मातृभाषा हिन्दी को वहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश हर एक विद्यालय में पढ़ायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय अब समाप्त हुआ।†

***14-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

[प्रश्न हटाया गया]

***15-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

[प्रश्न के वर्ग में परिवर्तन के कारण हटाया गया।]

माध्यमिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों एवं चपरासी के रिक्त पद के सम्बन्ध में

***16-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों एवं चपरासी के स्वीकृत पद के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर समय-सीमा निर्धारित कर नियुक्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† नोट :-नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न प्रश्न सं0-13 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती गुलाब देवी)-

वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों एवं चपरासी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0सं0	पदनाम	राजकीय		अशासकीय	
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	संस्था प्रधान	2373	1038	4512	3041
2	प्रवक्ता	9463	3957	22254	2522
3	सहायक अध्यापक	19300	6365	71684	16750
4	चतुर्थ श्रेणी (चपरासी)	6746	3132	42026	19874

निदेशालय के विभिन्न पत्रों से रिक्त पदों का अधियाचन मा0 लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। रिक्त पदों पर आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने के उपरान्त नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी (चपरासी) के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग से भरे जाने की व्यवस्था की गई है।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता।

दैवीय आपदा की सूचना अथवा सरकार की योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए तहसील स्तर पर डाटा सेण्टर की स्थापना के सम्बन्ध में

***17-श्री संदीप कुमार सिंह-**

क्या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दैवीय आपदा की सूचना अथवा सरकार की योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए तहसील स्तर पर डाटा सेण्टर की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आईटी एवं इले0 विभाग में तहसील स्तर पर डाटा सेन्टर की स्थापना की कोई योजना नहीं है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय लखनऊ में उ0प्र0 स्टेट डाटा सेन्टर

की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय वेबसाइट/पोर्टल की होस्टिंग आम-जनमानस तक त्वरित रूप से पहुँचाये जाने के दृष्टिगत करायी जाती है। उ0प्र0 स्टेट डाटा सेन्टर में प्रदेश के शासकीय विभागों/संस्थाओं का समस्त डाटा एकीकृत रूप से रखा जाता है।

***18-श्री मनोज कुमार पारस-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

***19-डा0 आर के वर्मा-**

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने/दोगुना किये जाने के सम्बन्ध में

***20-श्री राजपाल सिंह बालियान-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने/दोगुना किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-32599/2015, उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम आनन्द कुमार यादव में पारित आदेश दिनांक 25-07-2017 के क्रम में शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा शिक्षामित्रों का मानदेय बढाकर नियत रु0 10,000/- प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

अतारांकित प्रश्न

1-श्री पीयूष रंजन निषाद-

[03-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-207 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-जौनपुर के जलालपुर चौमुहानी से जलालगंज स्टेशन जाने वाली पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य कराने विषयक

2-श्री तुफानी सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के जलालपुर चौमुहानी से जलालगंज स्टेशन जाने वाली सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण जनसामान्य के आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिला पंचायत, जौनपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 विकास खण्ड जलालपुर में जलालपुर-वाराणसी मार्ग पर गोमती ग्रामीण बैंक जलालगंज रेलवे स्टेशन मार्ग का नवीनीकरण 700 मी0 की लम्बाई एवं 3.00 मी0 चौड़ाई में कार्य कराया गया था। वर्तमान में मार्ग क्षतिग्रस्त है। जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में उक्त कार्य की मरम्मत हेतु प्रस्ताव सदन में रखा जायेगा एवं सदन के निर्णयानुसार मार्ग की मरम्मत की कार्यवाही की जायेगी।

3-श्री प्रदीप कुमार यादव-

[03-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-209 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विगत 5 वर्षों में तालाबों की नीलामी से प्राप्त धनराशि प्रदेश के तहसील स्थित कोषागारों में जमा करने विषयक

4-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 5 वर्षों में तालाबों की नीलामी से प्राप्त कितनी धनराशि प्रदेश के तहसील स्थित कोषागारों में जमा हुई है तथा इसमें से कितनी धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को दी जा चुकी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विगत 05 वर्षों में तालाबों की नीलामी से रु0 1,38,69,33,004.00 की धनराशि कोषागारों में प्राप्त हुई, जिसमें से ग्राम पंचायतों को कुल रु0 36,63,15,988.00 की धनराशि प्रदान की गयी है ।

विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	कोषागारों में प्राप्त धनराशि (रुपये)	ग्राम पंचायतों को दी गयी धनराशि (रुपये)
2017-18	196904196.00	4840846.00
2018-19	191478611.00	61038666.00
2019-20	254614270.00	63639924.00
2020-21	407362142.00	94863311.00
2021-22	336573785.00	98365618.00

प्रश्न नहीं उठता।

5-श्री सचिन यादव-

[03-बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-210 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच के ब्लाक बलहा की ग्राम सभा गुरगुट्टा में चौकी से रमेश सोनकर के घर तक 500 मी0 रोड का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

6-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के ब्लाक बलहा की ग्राम सभा गुरगुट्टा में चौकी से रमेश सोनकर के घर तक 500 मी0 रोड का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बहराइच के ग्राम गुरगुट्टा में चौकी से रमेश सोनकर के घर तक दूरी 300 मीटर है, जो आन्तरिक गलियों से सम्बन्धित है। मार्ग पर पूर्व से खड़न्जा लगा है।

जिला पंचायत, बहराइच की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित होने के कारण उक्त कार्य का प्रस्ताव सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में पूर्व से लगे खड़न्जे पर लेपन निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत सदन के विचारार्थ रखा जायेगा। जिला पंचायत के सदन (बोर्ड) द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

7-श्री अतुल प्रधान-

[दिनांक 24-02-2023 को उत्तरित]

जनपद कानपुर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान अधिसूचना की चूक के कारण थाना बेकनगंज क्षेत्र में हुई हिंसा की घटना के लापरवाह पुलिस के आला अधिकारियों पर कार्यवाही कराने विषयक

8-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3 जून, 2022 को जनपद कानपुर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान अधिसूचना की चूक के कारण थाना बेकनगंज क्षेत्र में हुई हिंसा की घटना के लापरवाह पुलिस के आला अधिकारियों पर कोई कार्रवाई सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 3 जून, 2022 को कानपुर नगर थाना क्षेत्र बेकनगंज में अराजक तत्वों द्वारा अचानक पत्थरबाजी करने की सूचना प्राप्त होने पर कमिश्नरेट कानपुर नगर के अधिकारियों व पुलिस कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुँचकर त्वरित गति से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए परिस्थिति को बिना समय गंवाये नियंत्रित कर व्यापक रूप से फैल सकने वाली घटना को रोक दिया गया। इस सम्बन्ध में अभिसूचना/कार्यवाही अथवा किसी अन्य स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई चूक या लापरवाही नहीं पायी गयी।

प्रदेश में अधिकारियों की प्रोन्नत में बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के ही उनकी पोस्टिंग के प्रस्ताव मंत्रीगणों को प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई विषयक

9-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधिकारियों को प्रोन्नत (डीपीसी) करने की क्या प्रक्रिया है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि कतिपय विभागों में प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रोन्नत (डीपीसी) में बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के ही उनकी पोस्टिंग के प्रस्ताव मंत्रीगणों को प्रस्तुत कर दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

विभिन्न नियमावलियों एवं शासनादेशों के माध्यम से प्रदेश में अधिकारियों को प्रोन्नत करने की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वर्ष 2017 से 2022 तक नहरों, माइनरों, रजवाहो एवं ड्रेनों की सफाई के सम्बन्ध में

10-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से 21 दिसम्बर, 2022 तक किन-किन नहरों, माइनरों, रजवाहों एवं ड्रेनों आदि में कुल कितने किलोमीटर सिल्ट सफाई/खुदाई करायी गयी तथा उस पर कितना-कितना व्यय हुआ है एवं अभी उपरोक्त में कितने किलोमीटर सफाई/खुदाई हेतु शेष है ? क्या सरकार शेष बचे हुए नहरों, माइनरों, रजवाहों एवं ड्रेनों की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

सिचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से 21 दिसम्बर, 2022 तक नहरों पर सिल्ट एवं ड्रेनों की सफाई के कार्यो का विवरण निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष	नहरों की सिल्ट सफाई सम्बन्धित		ड्रेनों की सिल्ट सफाई सम्बन्धित	
	लम्बाई (किमी0 में)	व्यय (करोड़ रु0 में)	लम्बाई (किमी0 में)	व्यय (करोड़ रु0 में)
2017-18	27551.15	111.55	3403	35.61
2018-19	29487.21	102.82	6304	36.18
2019-20	46822.11	177.76	13271	124.59
2020-21	45942.26	160.14	12675	123.11
2021-22	50961.73	186.47	18780	218.00
2022-23	50522.66	7.14	9459	92.39

विभाग द्वारा प्रदेश में नहरों पर वर्ष 2017-18, 2018 19, 2019-20, 2020-21 वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में (दिनांक 21-12-2022 तक) क्रमशः धनराशि रु0 111.55, 102.82, 177.76, 160.14, 186.47 एवं 7.14 करोड़, सिल्ट सफाई कार्य में व्यय हुआ।

वर्ष 2022-23 में सिल्ट सफाई कार्यों के सम्पादन में रु0 186.55 करोड़ मात्र की व्यवस्था है, जिसमें दिनांक 21-12-2022 तक रु0 7.14 करोड़ मात्र व्यय हो चुका था। वर्तमान तक लगभग 82 करोड़ मात्र का व्यय हुआ है।

ड्रेनों पर सिल्ट सफाई कार्य में वर्ष 2017-18, 2018-19 2019-20, 2020-21 वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में क्रमशः धनराशि रु0 35.61, 36, 18, 124.59, 123.11, 218.00 एवं 92.39 करोड़ व्यय हुआ ।

विगत पाँच वर्षों में लगभग सभी चलित माइनरों व रजवाहों की कम से कम एक बार सफाई करायी जा चुकी है।

जी हाँ ।

विभाग में नहरों व ड्रेनों की सिल्ट सफाई प्रतिवर्ष की एक सतत् प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता एवं सफाई की आवश्यकतानुसार सिल्ट सफाई के कार्य कराये जाते है।

वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में केवल खरीफ में चलने वाली नहरों की सफाई प्रतिवर्ष दिनांक 15 अप्रैल से 15 जून तक एवं रबी की नहरों को प्रतिवर्ष दिनांक 15 अक्टूबर से दिनांक 15 दिसम्बर के मध्य सिल्ट सफाई कराये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

लोहिया आवास योजना की भांति कच्चे मकान से शत-प्रतिशत निजात दिलाने के लिए नीति की जानकारी के सम्बन्ध में

11-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण वासियों को लोहिया आवास योजना की भांति कच्चे मकान से शत-प्रतिशत निजात दिलाने के लिए सरकार ने कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विगत 5 वर्षों में कितने पक्के मकानों का निर्माण सरकार द्वारा कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकान में रह रहे लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018-19 से मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण संचालित है, जो कि पूर्णतया राज्य सहायतित है।

उपरोक्तानुसार।

विगत 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण को मिलाकर कुल 26.72 लाख आवास आवंटित किए गये हैं, जिसमें से 17.80 लाख आवास पूर्ण हो गये हैं।

उपरोक्त में से मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से अब तक 1.63 लाख आवास आवंटित किये गये, जिसके सापेक्ष 1.10 लाख आवास पूर्ण हो गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

12-श्री समरपाल सिंह-

[05-बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद के भवन निर्माण व अवस्थापना सुविधा (पेयजल, सड़क, अधिवक्ताओं के चेम्बर, फर्श आदि) हेतु कार्य योजना बनाने पर विचार करने विषयक

13-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद भवन निर्माण, अवस्थापना सुविधा (पेयजल, सड़क, अधिवक्ताओं के चेम्बर, फर्श आदि) हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद में 4 परिवार न्यायालय निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत जिला न्यायालय परिसर में लॉक-अप एवं गार्डरूम के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था लैकफेड से रु0 50.49 लाख का अनुमानित आगणन तैयार करा कर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। प्रश्नगत भवन के निर्माण हेतु मा0 उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त आगणन का तकनीकी परीक्षण करा कर धनराशि निर्गत की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

14-श्री पीयूष रंजन निषाद-

[बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-206 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय पुलिया के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

15-श्री संदीप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम दीघिया (चलंगा) एवं बरहा कला में बेलन नहर पर पुलिया काफी संकरा एवं जर्जर हालात में, जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलियों का चौड़ीकरण कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज की मेजा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम दिघिया (चलंगा) एवं बरहा कला में बेलन नहर प्रणाली की माण्डा राजवाहे का निर्माण कार्य वर्ष 1960 के दशक में कराया गया। ग्राम दिघिया में माण्डा राजवाहे के किमी0 9.55 पर स्वीकृत लम्बछिन्नक के अनुसार पुलिया निर्मित है। वर्तमान समय में पुलिया ठीक है, इस पर आवागमन हो रहा है। पुलिया की चौड़ाई 3.55 मीटर है। पुलिया को जोड़ने वाली सड़क जो ग्राम दिघिया से चलंगा होते हुए ढिलिया ग्राम को जाती है, की चौड़ाई मात्र 3.30 मीटर है, जबकि इस मार्ग पर निर्मित नहर पुलिया 3.55 मीटर चौड़ी है, जो आवागमन हेतु सुरक्षित है।

ग्राम बरहा कला में निर्मित पुलिया मेजा राजवाहा के किमी0 6.940 पर स्थित है। स्वीकृत एल सेक्शन के अनुसार उक्त स्थल पर पैदल पुलिया का निर्माण वर्ष 1960 के दशक में कराया गया था, जिसका कालान्तर में चौड़ीकरण करके पुलिया की चौड़ाई 1.80 मीटर से बढ़ाकर 3.30 मीटर किया जा चुका है। वर्तमान समय में पुलिया ठीक अवस्था में एवं आवागमन हेतु सुरक्षित है। यह पुलिया ग्राम आंधी से बरहा कला होते हुये ग्राम कुर्की कला को

जोड़ने वाली ग्रामीण मार्ग पर निर्मित है। इस मार्ग की चौड़ाई 3.30 मीटर है। वर्तमान समय में पुलिया ठीक अवस्था में है एवं आवागमन हेतु सुरक्षित है।

प्रदेश के विधान मण्डल के सदस्यों को अपने क्षेत्र के स्कूलों का निरीक्षण करने के सम्बन्ध में

16-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि प्रदेश के विधान मण्डल के सदस्यों को अपने क्षेत्र के स्कूलों का निरीक्षण करने का अधिकार है ? यदि हाँ तो किस नियम के अन्तर्गत ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 में विभागीय अधिकारियों द्वारा स्कूलों का निरीक्षण करने की व्यवस्था है। जनप्रतिनिधि के रूप में अवस्थापना सुविधाओं तथा व्यवस्था का निरीक्षण किये जाने पर कोई रोक नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के सभी रजवाहों की सफाई के सम्बन्ध में

17-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के सभी रजवाहों की सफाई हो चुकी है ? यदि हां, तो सफाई कराने में कितनी धनराशि खर्च हुई है और कितने का आवंटन हुआ था ? क्या सरकार उक्त विवरण को सदन के पटल रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ ।

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर की नहरें खरीफ फसली नहरें हैं, जिनकी सिल्ट सफाई खरीफ फसली 1430 के पूर्व माह मई, जून, 2022 में करायी गयी है।

आंवटित धनराशि रु0 19.24 लाख तथा व्यय धनराशि रु0 17.25 लाख।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में भूमिगत जल सुधार हेतु योजना के सम्बन्ध में

18-श्री स्वामी ओउमवेश-

प्रभावी क्या जल शक्ति मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में भूमिगत जल सुधार हेतु सरकार कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में विकास खण्ड-जलीलपुर, नूरपुर तथा हल्दौर के आंशिक अथवा पूर्ण भाग आते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नवीनतम भू-जल संसाधन आंकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार विकास खण्ड-जलीलपुर को क्रिटिकल, विकास खण्ड-नूरपुर को सेमी क्रिटिकल तथा विकास खण्ड-हल्दौर को सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

प्रदेश में भू-जल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं नियमन किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 प्रख्यापित है। अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम चरण में समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर तथा द्वितीय चरण में समस्त सरकारी सहायता प्राप्त भवनों एवं नियमानुसार निजी क्षेत्रों के भवनों को अच्छादित करते हुए रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित किये जाने का प्राविधान है।

सरकार द्वारा भूमिगत जल सुधार हेतु निरन्तर सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं यथा चेकडैम/तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार, वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण इत्यादि ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड मुरसान के ग्राम पंचायत खरगू में श्मशान के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में

19-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विकास खण्ड मुरसान के ग्राम पंचायत खरगू में श्मशान भूमि पर जलभराव के कारण दाहसंस्कार करने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त श्मशान का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण कराते हुए जलभराव की समस्या का निराकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद-हाथरस के विकास खण्ड-मुरसान की ग्राम पंचायत खरगू में श्मशान की भूमि सिंचाई विभाग के नाले के किनारे स्थित है, उक्त सिंचाई विभाग के नाले की पटरी बहुत नीची व टूटी हुई है, जिसके कारण बरसात के दिनों में आंशिक भाग में जल भराव हो जाने के कारण दाह-संस्कार करने में परेशानी होती है।

जी हां।

प्रश्नगत कार्य को जिला पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-हाथरस के सादाबाद तहसील में तहसीलदार और कनूनगो लेखपाल द्वारा फसल चक्र बदले जाने पर किसानों की भूमि की पैमाइश और मेड़बन्दी के सम्बन्ध में

20-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के सादाबाद तहसील में तहसीलदार और कनूनगो, लेखपाल द्वारा फसल चक्र बदले जाने पर किसानों की भूमि की पैमाईश और मेड़बन्दी नहीं करायी जा रही है ? क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जाँच कराकर उक्त कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

नियमानुसार भूमि की पैमाइश और मेड़बन्दी करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में विद्यालयों की मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में

21-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में विक्तीय वर्ष 2019-2020 से मार्च, 2022 तक हाई स्कूल व इण्टरमीडियट कालेज के नवीन मान्यता के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने विद्यालयों को मान्यता दी गयी है और कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष को मान्यता देगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हां।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में विक्तीय वर्ष 2019-2020 से मार्च, 2022 तक हाई स्कूल के नवीन मान्यता हेतु 03 विद्यालयों, इण्टरमीडिएट के नवीन मान्यता हेतु 02 विद्यालयों तथा इण्टरमीडिएट वर्ग विषय की मान्यता हेतु 04 विद्यालयों कुल-09 विद्यालयों द्वारा मान्यता हेतु आवेदन किया गया था। मान्यतार्थ आवेदित-09 विद्यालयों में से 07 विद्यालयों को मान्यता प्रदान कर दी गयी है। शेष 02 विद्यालयों को मान्यता हेतु मानकों की पूर्ति न करने के कारण मान्यता नहीं प्रदान की गयी है।

जनपद बिजनौर के जिन दो विद्यालयों को मान्यता नहीं प्रदान की गयी है यदि उनके मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तों के अनुसार आवेदन किया जाता है, तो परिषद् द्वारा उनके मान्यता आवेदन पर विनियमानुसार विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया गोपाल नगर, वशिष्ठनगर, शिवाल मठिया आदि गांवों को घाघरा नदी की कटान से बचाने के सम्बन्ध में

22-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया गोपाल नगर, वशिष्ठनगर, शिवाल मठिया आदि गांव घाघरा नदी की कटान से प्रभावित हैं ? क्या सरकार उक्त गांवों को बचाने के लिए कटान रोधी कार्य करायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत गोपाल नगर, वशिष्ठनगर, शिवाल मठिया आदि ग्राम डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में आते हैं तथा डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में कटान रोधी कार्य तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य नहीं होने के कारण अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया, भुवाल, छपरा, नौरंगा से लेकर चक्की नौरंगा को गंगा नदी की भीषण कटान से बचाने हेतु रिंग बांध के निर्माण के सम्बन्ध में

23-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया, भुवाल, छपरा, नौरंगा से लेकर चक्की नौरंगा के लगभग 5000 आबादी गंगा नदी की भीषण कटान से प्रभावित हो रही है ? क्या सरकार रिंग बांध का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी के दायें किनारे पर भुवाल छपरा, नौरंगा से लेकर चक्की नौरंगा स्थित है। उक्त ग्राम नदी के डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में स्थित है। डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में कटान रोधी कार्य तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य नहीं होने के कारण अनुमन्य नहीं है। वर्तमान में ग्राम एवं आबादी पूरी तरह सुरक्षित है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया देवपुर मठिया में बाढ़ के समय में पम्प लगाकर पानी की निकासी कराये जाने के सम्बन्ध में

24-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया देवपुर मठिया रेगुलेटर से नदी के पानी रिसाव होने व पानी की निकासी न होने के कारण काफी फसलें बर्बाद होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बाढ़ के समय में पम्प लगाकर पानी की निकासी करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत देवपुर मठिया रेगुलेटर सरयू नदी के दायें तट पर स्थित तुर्तीपार श्रीनगर तटबन्ध के किमी0 74.400 पर स्थित है। वर्तमान में रेगुलेटर पूरी तरह से क्रियाशील है तथा रेगुलेटर में रिसाव नहीं है। बरसात में सरयू नदी का जल स्तर बढ़ने पर रेगुलेटर बन्द कर दिया जाता है, ताकि नदी का पानी कन्ट्री साइड में न जाय। रेगुलेटर के फाटक बन्द होने पर बरसात के पानी से फसलें प्रभावित होती हैं। नदी में पानी का जल स्तर कम होने पर रेगुलेटर खोल दिया जाता है, जिससे पानी नदी में चला जाता है तथा जल जमाव की समस्या समाप्त हो जाती है।

आवश्यकता नहीं।

उपरोक्तानुसार

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड कोइली मुहालताल व पशुहारी सखईल ताल से जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में

25-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड कोइली मुहालताल व पशुहारी सखईल ताल के जलभराव के कारण हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

अत्यधिक वर्षा होने पर ही जलभराव के कारण फसलें प्रभावित होती हैं।

जल निकासी हेतु पम्पिंग की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम दीघिया के सड़क का चौड़ीकरण/नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

26-श्री संदीप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम दीघिया (शुक्ला बस्ती)में राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला के घर के मार्ग बेलन नहर के बन्धे पर पक्की सड़क काफी संकरी एवं जर्जर हालात में है, जिसके कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है ? क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण/नवीनीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम दीघिया (शुक्ला बस्ती) में राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला के घर के मार्ग बेलन नहर के बन्धे पर पक्की सड़क का 320 मीटर लम्बाई व 03 मीटर चौड़ाई में सड़क निर्माण पूर्व में जिला पंचायत द्वारा कराया गया था, जिसमें से 145 मीटर की लम्बाई में सड़क मरम्मत योग्य है।

अतः उक्त मार्ग के 145 मीटर लम्बाई में सड़क का मरम्मत/नवीनीकरण किये जाने हेतु विक्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए नियमानुसार निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत, सदन की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। सदन से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त निर्माण कार्य कराया जायेगा।

प्रदेश में शौचालयों के निर्माण के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में

27-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में शौचालयों के निर्माण के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शौचालयों का निर्माण करा दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि उक्त हेतु कितनी धनराशि का आवंटन जनपदवार किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रदेश में प्रथम चरण में 21806648 शौचालयों के निर्माण के सापेक्ष शत-प्रतिशत निर्माण करा लिया गया है। द्वितीय चरण में 1621409 शौचालयों के सापेक्ष 1030447 शौचालय, इस प्रकार कुल 2,28,27,095 शौचालयों का निर्माण हो चुका है। शेष शौचालयों का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत रुपये 2540527.52 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता।

सभी विभागों के प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष की सूची, जिसमें उनके ई-मेल आइडी का उल्लेखन हो उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

28-श्री दीनानाथ भाष्कर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सभी विभागों के प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष की सूची, जिसमें उनके ई-मेल आइडी का उल्लेखन हो उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसके माध्यम से विधान सभा सदस्य सम्बन्धित को ई-मेल के द्वारा सूचना का आदान-प्रदान कर सके ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सूची उपलब्ध करायेगी ? क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त व्यवस्था की निगरानी किसी अधिकारी के द्वारा की जाती है या कोई नोडल अधिकारी इस ऑनलाइन व्यवस्था का समन्वय करता है ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

ऐसी कोई सूची सचिवालय प्रशासन विभाग में उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता !

प्रश्न नहीं उठता।

विक्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में प्रदेश के रोगियों के इलाज हेतु मुख्य मंत्री राहत कोष से जारी की गयी धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

29-श्री महबूब अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में प्रदेश के रोगियों के इलाज हेतु कितनी धनराशि मुख्य मंत्री राहत कोष से जारी हुई तथा उक्त धनराशि में से कितनी धनराशि अस्पतालों से किन कारणों से वापस हुई है ? क्या सरकार उक्त कोष से मरीजों की वित्तीय मद की समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से मरीजों के इलाज हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में क्रमशः रु0 275.72 करोड़ तथा रु0 398.87 करोड़ की धनराशि अस्पतालों को स्वीकृत की गयी है। मरीज की मृत्यु होने, मरीज के द्वारा अस्पताल परिवर्तित करने, इलाज हेतु स्वीकृत धनराशि में से व्यय हेतु अवशेष होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में अस्पतालों द्वारा क्रमशः रु0 23.07 करोड़ तथा रु0 25.87 करोड़ की धनराशि वापस की गयी है।

उ0प्र0 विवेकाधीन कोष नियमावली, 1999 यथासंशोधित 2006 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विवेकाधीन कोष से दी जाने वाली आर्थिक सहायता/अनुदान प्रत्येक प्रकरण की आवश्यकता, तात्कालिकता एवं औचित्य के आधार पर दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा अन्तर्गत ग्राम पंचायत काँथा में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में सरकारी धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में

30-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा अन्तर्गत ग्राम पंचायत काँथा में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में सरकारी धनराशि के दुरुपयोग किये जाने में तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत को दोषी पाया गया था ? उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव के आदेश दिनांक 23-03-2021 द्वारा सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत से दुरुपयोगित सरकारी धनराशि की वसूली किये जाने हेतु आदेश दिये थे, परन्तु दिनांक 21-12-2022 तक दोषी अधिकारियों से सरकारी धनराशि की वसूली नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी धनराशि की वसूली नहीं करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव के पत्र दिनांक 21-01-2023 द्वारा प्रभारी अधिकारी संग्रह, उन्नाव को वसूली किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

मृतक के नाम पर शासकीय धनराशि आवंटित करते हुए अवैध शौचालय निर्माण के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

31-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम काँथा के मोहल्ला रमना में निजी भूमि खाता सं0 02325, खसरा सं0-2288, 2292 क्षे0 0.5820 हे0 क्षे0-0.0760 हे0 का वाद वर्ष 2015 से विचाराधीन होते हुए भी वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थानीय अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु लगभग 06 वर्ष पूर्व दिवंगत हो चुके छोटेलाल के नाम शासकीय धनराशि आवंटित करते हुए उपरोक्त भूमिधरी की निजी भूमि पर उक्त अवैध शौचालय का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार

इसके लिए दोषियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए भूमिधरी की निजी भूमि पर निर्मित उक्त अवैध शौचालय को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

छोटेलाल के नाम से भूमि न होने के बावजूद उस जमीन पर स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत रुपये 12000 खर्च करते हुए शौचालय निर्माण कराया गया था। उक्त के दृष्टिगत रुपये 12000 की वसूली सुनिश्चित की जा चुकी है तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। जहां तक शौचालय के हटाने का प्रश्न है मौके पर गाटा संख्या-2288 एवं 2292 में शौचालय के अलावा अन्य मकान भी बने हुए हैं एवं इस सम्बन्ध में प्रकरण सिविल कोर्ट मैं लम्बित है। अतः इसमें प्रशासनिक रूप से कोई कार्यवाही किया जाना विधि संगत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत काँथा में वर्ष 2016-21 तक कराये गये विकास कार्यों की जानकारी के सम्बन्ध में

32-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत काँथा में वर्ष 2016-21 तक कराये गये विकास कार्यों की संयुक्त जाँच कमेटी द्वारा जाँच किये जाने पर सम्बन्धित ग्राम सचिवों को सम्बन्धित सरकारी अभिलेखों को गायब करने का दोषी पाया था ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव के पत्र दिनांक 16-08-2022 द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत काँथा द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त प्रकरण संयुक्त जाँच कमेटी के नामित जाँच द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त प्रकरण संयुक्त जाँच कमेटी के नामित जाँच अधिकारी को प्रेषित किया गया ? यदि हां, तो जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव दिनांक 16-08-2022 द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अभिलेखों की संयुक्त जाँच कमेटी द्वारा स्थलीय परीक्षण/सत्यापन किया गया ? यदि हां, तो सरकार वर्ष 2022 की उक्त जाँच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला-उन्नाव की तहसील बीघापुर के ग्राम बारा हरदो में सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराते हुए इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में

33-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव की तहसील-बीघापुर के अन्तर्गत ग्राम बारा हरदो में सरकारी भूमि गाटा संख्या-443, रकबा 0.126 हे0 पर मयंक वर्मा,

उ0 नि0 एवं शशांक वर्मा पुलिसकर्मी एवं उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा जबरन अवैध कब्जा कर बाउण्ड्री का निर्माण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराते हुए इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम- बारा हरदो, परगना-भगवन्तनगर, तहसील-बीघापुर जनपद उन्नाव में स्थित गाटा सं0-443 क्षे0 0.1260 हे0 जो राजस्व अभिलेखों में नवीन परती के रूप में दर्ज है, जिसके जुज भाग 0.025 हे0 पर लगभग 10 वर्ष पूर्व पक्की नींव भरकर साहबदीन पुत्र फक्ते व अरूणेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल तथा श्रीमती सरोज पत्नी स्व0 अवधेश कुमार द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। उक्त अवैध अतिक्रमणियों में से श्रीमती सरोज पत्नी स्व0 अवधेश कुमार, निवासी-ग्राम- बारा हरदो, परगना-भगवन्तनगर, तहसील-बीघापुर, जनपद उन्नाव की निवासिनी है, जो मयंक वर्मा, उप निरीक्षक एवं शशांक वर्मा, पुलिस कर्मी की पारिवारिक सदस्य (माता) हैं।

प्रश्नगत प्रकरण में अवैध अतिक्रमणियों के विरुद्ध जांचोपरान्त उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 के अन्तर्गत बेदखली का वाद मा0 न्यायालय तहसीलदार बीघापुर में योजित है, जिसकी वाद सं0-टी-202210690503517 है। उक्त अवैध निर्माण को तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा नींव स्तर पर ही रुकवा दिया गया। उसके उपरान्त उक्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है और न ही वर्तमान में कोई निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त प्रकरण में न्यायालय के निर्णय के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के थाना रेढ़र के निवासियों को बुरी तरह से पीटने के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के सम्बन्ध में

34-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के थाना रेढ़र में दिनांक 04-06-2022 को विभू चौहान, प्रिन्स कटोरे, नन्नू राजा आदि, निवासीगण रेढ़र को पुलिस कर्मियों द्वारा बुरी तरह से पीटे जाने के विरुद्ध दिनांक 05-06-2022 को थाना रेढ़र में एन0सी0आर0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो अब तक किन-किन दोषी पुलिस कार्मियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

प्रकरण में दोषी उ0नि0 मयंक वर्मा को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही के क्रम में दिनांक 05-01-2023 को पदच्युत (बर्खास्त) कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा निर्गत वसूली के प्रमाण-पत्र संख्या-11599/यू0पी0 रेरा/वसूली/2022-23, दिनांक 27-09-2022 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

35-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र संख्या-11599/यू0पी0 रेरा/वसूली/2022-23, दिनांक 27-09-2022 जिलाधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है एवं इसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

सचिव, उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-11599/यू0पी0 रेरा/वसूली/2022-23, दिनांक 27-09-2022 द्वारा मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, द्वितीय तल, शापिंग स्क्वायर-2, सेक्टर-डी, सुशान्त गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ के विरुद्ध रु0 3,07,989.00 का वसूली प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया गया है। उक्त वसूली प्रमाण-पत्र, वसूली की कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय अमीन को दिनांक 09-02-2023 को प्राप्त कराया गया। क्षेत्रीय अमीन द्वारा मांग-पत्र (आर0सी0 प्रपत्र-36) बाकीदार फर्म को दिनांक 13-02-2023 को तामील कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अतुल अवस्थी पुत्र स्व0 नवल किशोर अवस्थी, एस0 एस0-1/454-455 सेक्टर ए, सीतापुर रोड योजना अलीगंज, थाना मड़ियांव, जनपद लखनऊ का शस्त्र लाइसेंस के सम्बन्ध में

36-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गृह पुलिस अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन, दिनांक 08-10-2022 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-09-2022 जो कि श्री अतुल अवस्थी, पुत्र स्व0 नवल किशोर अवस्थी, एस0 एस0-1/454-455 सेक्टर-ए, सीतापुर रोड योजना अलीगंज, थाना मड़ियांव, जनपद लखनऊ का शस्त्र लाइसेंस को आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

शासन के पत्र संख्या-वीआईपी-68/छः-पु-5-2022, दिनांक 18-10-2022 के अनुपालन में जिलाधिकारी, लखनऊ के आदेश दिनांक 13-02-2023 द्वारा आवेदक का शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-कानपुर, तहसील सदर के ग्राम मेहरबान सिंह का पुरवा में रास्ते को अवैध निर्माण कराते हुए भू-माफियाओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के सम्बन्ध में

37-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के सदर तहसील के ग्राम मेहरबान सिंह का पुरवा में आराजी संख्या-958, 962 तथा 973 में भू-माफियाओं द्वारा अवैध नव निर्माण कराये जाने से आम रास्ता तथा सरकारी नाली बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आराजी एवं रास्ते को अवैध नव निर्माण से मुक्ति कराते हुए भू-माफियाओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम-मेहरबान सिंह का पुरवा, तहसील सदर, कानपुर नगर की वर्तमान खतौनी सन् 1428 फ0 से 1433 फ0 के खाता संख्या-100 में आराजी संख्या-958, रकबा 0.3380 हे0, 962 रकबा 0.0200 हे0 व 973 रकबा 0.3380 हे0 कुल 03 किता रकबा 0.8190 हे0 भूमि खातेदार हरदेव सिंह पुत्र राम गोपाल, निवासी मेहरबान सिंह का पुरवा मजरा-मौजा गुजैनी, परगना व तहसील-कानपुर नगर के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त आराजियों में अभिलेखों में कोई आम रास्ता या सरकारी नाली अंकित नहीं है, सम्पूर्ण आराजियां खातेदार की संक्रमणीय भूमिधर दर्ज भूमियाँ हैं। उक्त आराजियों में कोई आम रास्ता या सरकारी नाली अंकित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-बांदा के तहसील-बबेरू के ग्राम पंचायत-सांडा के मुख्य मार्ग से अवधेश कहाँर के घर से सुबेन्द्र पासवान के घर तक लगभग 100 मी0 कच्चे मार्ग को पक्का करने के सम्बन्ध में

38-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के तहसील बबेरू के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सांडा के मुख्य मार्ग से अवधेश कहाँर के घर से सुबेन्द्र पासवान के घर तक लगभग 100 मी0 कच्चे मार्ग पर गन्दे पानी का जमाव बना रहता है, जिससे निवासियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग

को सी0सी0 निर्माण एवं मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायत की अनुपूरक योजना में सम्मिलित कर 02 माह में करा दिया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के गांव ऐमनपुर में जूनियर हाई स्कूल की चहारदीवारी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

39-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के गांव ऐमनपुर में जूनियर हाई स्कूल की चहारदीवारी न होने के कारण छात्र-छात्राओं को पढ़ाई करने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो उक्त स्कूल की चहारदीवारी का सरकार निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के गांव ऐमनपुर में जूनियर हाई स्कूल की चहारदीवारी न होने के कारण छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में परेशानी नहीं होती है। जूनियर हाई स्कूल ऐमनपुर के चहारदीवारी निर्माण हेतु समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में प्रस्ताव किया जायेगा।

प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति के उपरान्त चहारदीवारी निर्माण का कार्य बजट की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में जून, 2021 से नवम्बर, 2022 तक इण्टरलॉकिंग, आर0सी0सी0 रोड, पक्की नाली, पुलिया इत्यादि कार्य से सम्बधित विवरण को उपलब्ध कराये जाने की मांग

40-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में जून, 2021 से नवम्बर, 2022 तक इण्टरलॉकिंग, आर0सी0सी0 रोड, पक्की नाली, पुलिया इत्यादि कार्य कहां-कहां तथा कितने-कितने कराये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कार्यों के लिए अलग- अलग कितनी-कितनी

धनराशि आहरित/भुगतानित की गयी ? क्या सरकार उक्त कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम पंचायत-त्रिपुरारपुर में जून, 2021 से नवम्बर, 2022 तक इण्टरलॉकिंग, आर0सी0सी0 रोड, पक्की नाली, पुलिया इत्यादि के 26 कार्य कराये गये, जिनका विवरण संलग्न है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जी हाँ ।

(सूची संलग्न† है।)

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के अन्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज शिवसत प्रतापगढ़ के निर्माण की गुणवत्ता सम्बन्धी जाँच

41-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माणाधीन हैं ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के अन्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज शिवसत प्रतापगढ़ विगत लगभग 6 वर्षों से निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि उक्त के निर्माण प्रारम्भ से दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 तक उक्त के निर्माण की गुणवत्ता सम्बन्धी जाँच जनपद स्तरीय एवं किसी एकेडमिक इन्स्टीट्यूट से निर्माण व निर्माण सामग्री से सम्बन्धित कुल कितनी जांच कराई गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

जी हाँ।

कुल 08 इंजीनियरिंग कालेज निर्माणाधीन हैं।

जी हाँ।

कुल 18 जांचें।

जी हां। विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† देखिए नत्थी (ख) आगे पृष्ठ सं0-336-337 पर।

† छापा नहीं गया।

प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था के सम्बन्ध में

42-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त से सम्बन्धित आदेश का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ ।

उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली, 1975 के पैरा-10 में निम्नवत् प्राविधानित है :-

मान्यता प्राप्त स्कूल प्रत्येक अध्यापक तथा कर्मचारी को दिनांक 01 जुलाई, 1975 से वही वेतनमान, महंगाई भत्ता तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता देगा जो परिषद् के समान पदधारक अध्यापकों तथा कर्मचारियों को दिया जाता हो । वेतन का भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में फोन नेटवर्क एवं इन्टरनेट नेटवर्क से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क टावर लगाये जाने हेतु कार्य योजना की जानकारी

43-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फोन नेटवर्क एवं इन्टरनेट नेटवर्क से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क टावर लगाये जाने पर सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मोबाइल टावर्स/दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है, अतः इस प्रयोजन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गई है। मोबाइल टावर्स/दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार की नीतियों एवं निर्देशों के अन्तर्गत मोबाइल टावर्स/दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनियों द्वारा की जाती है। यद्यपि इस कार्य में प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान किया जाता है।

उक्त के क्रम में दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना एवं विकास हेतु राइट ऑफ-वे अनुमोदन समयबद्ध रूप से प्रदान किये जाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किया गया है।

राइट ऑफ-वे अनुमतियों के लिए आवेदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है तथा इस सेवा को निवेश-मित्र पोर्टल से एकीकृत करके जनहित गारण्टी ऐक्ट से भी जोड़ दिया गया है।

आवेदनों के निस्तारण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित 60 दिनों की अवधि के सापेक्ष प्रदेश सरकार द्वारा आवेदन की तिथि से 45 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है।

राइट ऑफ-वे अनुमतियों के लिए लम्बित आवेदनों की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की योजना हेतु माननीय मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन से उत्तर प्रदेश (पूर्वी) दूरसंचार सर्किल के अन्तर्गत 129 स्थलों तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) दूरसंचार सर्किल के अन्तर्गत 97 स्थलों अर्थात् कुल 226 स्थलों पर 200 वर्गमीटर ग्राम सभा की भूमि जिला प्रशासन के माध्यम से चिन्हित कर मोबाइल टावर्स के निर्माण के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियो को निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

महन्त शिवदास उदासीन इण्टर कालेज, सादात, गाजीपुर को अनुमन्यता निर्गत करने के सम्बन्ध में

44-श्री पंकज कुमार मलिक-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के आतारांकित प्रश्न संख्या-180 के उत्तर के क्रम में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महन्त शिवदास उदासीन इण्टर कालेज, सादात, गाजीपुर को अनुमन्यता निर्गत करने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-2302/15-05-2022-1600 (244)/2015, दिनांक 28-11-2022 के क्रम में निदेशालय के पत्रांक (अर्थ 1)/5293/2022-23, दिनांक 01-12-2022 द्वारा आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर को निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आख्या/अभिलेख का विवरण प्राप्त कर अनुमन्यता निर्गत करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण में रिट याचिका संख्या-12695/2000 चन्द्रभान यादव बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर एवं अन्य मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त रिट याचिका के

अन्तिम निस्तारण तक याची श्री चन्द्रभान यादव, सहायक अध्यापक, श्री महन्त शिवदास उदासीन इण्टर कालेज, सादात, गाजीपुर के प्रश्नगत अवशेष भुगतान हेतु अनुमन्यता निर्गत किये जाने पर विचार किया जाना नियम संगत नहीं होगा ।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी के ग्राम अकबालपुर में गाटा संख्या-154/0062 हे0 पर न्यायालय अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) द्वारा वाद संख्या-डी 202114360004255/2021, दिनांकित 19-05-2022 के आदेश के दाखिल तजवीजसानी विषयक

45-श्री पंकज कुमार मलिक-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के आतारांकित प्रश्न संख्या-196 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी के ग्राम अकबालपुर में गाटा संख्या-154/0062 हे0 जो कि अभिलेख में चकमार्ग खाते की भूमि है, पर न्यायालय अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) द्वारा वाद संख्या-डी 202114360004255/2021, दिनांकित 19-05-2022 के आदेश के दाखिल तजवीजसानी वाद पर निर्णय ले लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्णय के क्रम में मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं ।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जौनपुर के न्यायालय में तजवीजसानी विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

46-श्री प्रसन्न कुमार-

[02-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-209 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवीन डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जानकारी

47-श्री अनिल प्रधान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद चित्रकूट के कर्वी (चित्रकूट) ब्लॉक अन्तर्गत ग्राम मुकुन्दपुर में राज्यपाल के नाम आवंटित भूमि लगभग 10 बीघे में डिग्री कॉलेज की स्थापना कराए जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

अवगत कराना है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत 01 राजकीय कन्या महाविद्यालय जमालपुर, मिर्जापुर प्रस्तावित है।

जी नहीं।

जनपद चित्रकूट में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के लिये ग्राम मुकुन्दपुर में प्लाट नं0-570/1, रकबा 0.3140 हे0, प्लाट नं0-570/2मि0, रकबा 0.211हे0, कुल 0.5250 जिला प्रशासन द्वारा पुनर्ग्रहीत की गयी। राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु मानकानुसार भूमि पर्याप्त न होने के कारण ग्राम मुकुन्दपुर के ही ग्रामीणों द्वारा आराजी नं0-563 मि0, रकबा-1.750 हे0 को स्वेच्छापूर्वक दान स्वरूप महाविद्यालय के पक्ष में जरिये बैनामा दस्तावेज भूमि उपलब्ध करायी गयी है, किन्तु पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जिस पर लागत अधिक आने को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पाही में गाटा सं0-848, रकबा 1.000 हे0 निःशुल्क भूमि चिन्हित कर खतौनी सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा आच्छादित ग्राम पाही में राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना हो चुकी है तथा यह महाविद्यालय बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय को संघटक महाविद्यालय के रूप में संचालित करने हेतु हस्तान्तरण किया जा चुका है, जिसमें कक्षायें संचालित हैं। ग्राम मुकुन्दपुर, जनपद चित्रकूट के कर्वी ब्लॉक में अवस्थित है तथा उक्त ब्लॉक में 02 राजकीय महाविद्यालय, जिसमें से एक संघटक महाविद्यालय है तथा 06 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने का अवसर नहीं है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की योजना के सम्बन्ध में

48-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन निम्नवत् विश्वविद्यालय/राजकीय अनुदानित इंजीनियरिंग कालेज संचालित हैं :-

1-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।

2-उ0 प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।

3-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मैनपुरी ।

4-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज।

5-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर।

6-उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, नोएडा।

उक्त के अतिरिक्त एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना/निर्माण हेतु कम से कम 10 एकड़ भूमि तथा लगभग 50.00 करोड़ की लागत अनुमानित है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट/मांग के माध्यम से धनराशि व्यवस्थित करायी जानी होगी। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किये जाने की योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

जनपद चित्रकूट में सैनिक स्कूल की स्थापना करने के सम्बन्ध में

49-श्री अनिल प्रधान-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में सैनिक स्कूल की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

उ0प्र0 में पूर्व से चार सैनिक स्कूल यथा कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ, मैनपुरी, झांसी तथा अमेठी में संचालित हैं तथा जनपद-गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजकीय विद्यालय/सहायता प्राप्त विद्यालय/गैर सरकारी संगठन इत्यादि सहित इच्छुक विद्यालय को पी0पी0पी0 मॉडल पर सैनिक स्कूल में परिवर्तित किये जाने हेतु पोर्टल http://sainikschool.ncog.gov.in पर प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

उक्त पोर्टल पर जिलाधिकारी के माध्यम से आवेदनोपरान्त मानक पूर्ण करने पर उपयुक्तता के आधार पर सैनिक स्कूल के रूप में परिवर्तित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जनपद-सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड डुमरियागंज के ग्राम अगया के चौराहे से लेकर डी0 डी0 पाण्डेय के घर तक जर्जर मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में

50-श्रीमती सैय्यदा खातून-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड डुमरियागंज के ग्राम अगया के चौराहे से लेकर डी0 डी0 पाण्डेय के घर तक का मार्ग जर्जर

होने के कारण आमजन को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड-डुमरियागंज के ग्राम अगया के चौराहे से लेकर डी0डी0 पाण्डेय के घर तक के मार्ग की सड़क काफी पुरानी है। उक्त मार्ग के नव निर्माण का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव अनुमोदित होने के उपरान्त नव निर्माण कार्य कराया जायेगा।

51-श्री अमिताभ बाजपेई-

[02-बुधवार के अतारंकित प्रश्न सं0- 202 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र शेखपुर में ब्लॉक मुख्यालय/ब्लॉक क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए राजकीय डिग्री कॉलेज बनाने हेतु कार्य योजना के सम्बन्ध में

52-श्री हिमान्शु यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायू के विधान सभा क्षेत्र शेखपुर में ब्लॉक मुख्यालय/ब्लॉक क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए राजकीय डिग्री कॉलेज बनाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र शेखपुर में उच्च शिक्षा प्राप्त किये जाने हेतु पर्याप्त महाविद्यालय हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं में 04 राजकीय महाविद्यालय, 03 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 29 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र शेखपुर के 10 किमी0 की परिधि में 02 राजकीय महाविद्यालय, 02 सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं 07 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत नये महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद आजमगढ़ में दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के निर्माण के उपरान्त छोड़ी गई जमीन को किसान के नाम दर्ज कराने के सम्बन्ध में

53-श्री अखिलेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड सठियांव से सम्बन्धित चीनी मिल आयुक्त श्री लक्ष्मीकान्त नागर के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-3954 ए0सी0/18(6)/775/73, दिनांक 6 अगस्त, 1974 के अनुपालन के

क्रम में भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा चीनी मिल निर्माण में छोड़ी गई जमीनों को प्रतिकर न दिए जाने के बावजूद भी किसानों की भूमि उनके नाम दर्ज नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड सठियांव, आजमगढ़ द्वारा कोई भी अधिग्रहीत भूमि छोड़ी नहीं गयी है एवं समस्त अधिग्रहीत भूमि भू-लेख में चीनी मिल के नाम दर्ज हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

परिषदीय विद्यालयों में समय से निःशुल्क पुस्तकों का वितरण न हो पाने के दोषियों के विरुद्ध कृत कार्रवाई की जानकारी

54-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषदीय विद्यालयों में निशुल्क किताबों का वितरण करने हेतु किताबों की आपूर्तिकर्ता प्रकाशकों द्वारा समय से पुस्तक आपूर्ति न किए जाने से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य में ढिलाई बरतने वाले प्रकाशकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ!

समय से पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति न करने वाले मुद्रकों/प्रकाशकों के विरुद्ध शासनादेश दिनांक 01-02-2018 के बिन्दु संख्या-6 में विहित व्यवस्था के अनुक्रम में जनपद स्तर पर गठित जनपदीय सत्यापन समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

उक्त के क्रम में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिनांक 16-02-2023 को समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

55-श्री मोहन वर्मा-

[दिनांक 27-02-2023 को उत्तरित]

56-श्री मोहन वर्मा-

[प्रश्न हटाया गया]

प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अन्तर्गत पूर्णतः क्षतिग्रस्त आवास/भवन हेतु अनुदान धनराशि के बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में

57-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अन्तर्गत पूर्णतः क्षतिग्रस्त आवास/भवन पर रु0 95,000 की अनुदान धनराशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रु0 करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

भारत सरकार के आदेश संख्या-33-03/2020 एन0 डी0 एम0-1, दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 द्वारा विभिन्न अधिसूचित आपदाओं से क्षति (जनहानि/पशुहानि/मकान क्षति/फसल क्षति) के सापेक्ष निर्धारित मानक एवं दरों के अनुसार राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता राशि 95,100 रु0 से बढ़ाकर 1,20,000 रु0 कर दी गयी है।

अधिसूचित आपदाओं से होने वाली क्षतियों के सापेक्ष अनुग्रह सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई व्यवस्था/मानक निर्धारित नहीं है।

58-श्री संदीप सिंह-

[02-सोमवार के अतारांकित प्र0 सं0-169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश की तहसीलों में निर्धारित अवधि पूर्ण कर चुके लेखपालों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

59-श्री संदीप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की तहसीलों में नियुक्त लेखपालों की एक ग्राम सभा में तैनाती का कार्यकाल निर्धारित है ? यदि हां, तो एक ग्राम सभा में तैनाती की निर्धारित अवधि पूर्ण कर चुके लेखपालों को चिहिन्त कर उनका स्थानान्तरण सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ

जी हाँ।

शासन के पत्र संख्या-1250/1-9-2004-116 एल0सी0/2002, दिनांक 21-06-2004 के बिन्दु सं0-4 में उल्लिखित है कि लेखपाल एक लेखपाल क्षेत्र में अधिकतम 3 वर्ष तथा तहसील में 10 वर्ष रह सकते है।

वार्षिक स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-8/2022/सा0-119/सैंतालिस-4-2022-(1/3/96), दिनांक 13-05-2022 द्वारा समूह 'ग' के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त पटल/क्षेत्र परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत करछना में अग्निशमन केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में

60-श्री पीयूष रंजन निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत करछना में अग्निशमन केन्द्र (फायर स्टेशन) बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद प्रयागराज के तहसील करछना में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों एवं सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत उक्त अग्निशमन केन्द्र की स्थापना वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद-बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम नैथला में लिंक मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

61-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम नैथला में लिंक मार्ग से पोखर तक का रास्ता जर्जर होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 350 मी0 है। उक्त मार्ग पर सी0सी0 व नाली का निर्माण कराये जाने में लगभग रु0 25.00 लाख व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 में प्राप्त होने वाले अनुदानों के सापेक्ष कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है। प्रश्नगत कार्य को वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में शामिल करने हेतु जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्ताव रखा जायेगा एवं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

62-श्री संदीप कुमार चौधरी-

[दिनांक 22-02-2023 को उत्तरित]

विधान सभा मछलीशहर में अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 एवं अप्रैल, 2022 से 23-12-2022 तक नहरों की सफाई विषयक

63-डॉ0 रागिनी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, जौनपुर को सम्बोधित पत्रांक-293, दिनांक 03-11-2022 को विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 एवं अप्रैल, 2022 से 23-12-2022 तक नहरों

की सफाई विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं, अपितु पत्रांक-292, दिनांक 03-11-2022 प्राप्त हुआ है, जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, जौनपुर के पत्रांक-2845/सि0 खं0 जौनपुर/प्रा0 अनु0/सिल्ट, दिनांक 06-12-2022 द्वारा मा0 सदस्य विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर, जौनपुर को समस्त बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करा दी गयी है तथा दिनांक 22-01-2023 को वांछित सूचना ई-मेल (dr.raginisonkar@ gmail.com) पर भी प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की कार्य योजना की जानकारी

64-डॉ0 रागिनी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मुख्य मार्ग से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों का निर्माण एवं पठन-पाठन का कार्य किया जाता है। विद्यालयों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की कोई कार्य योजना सम्प्रति बेसिक शिक्षा विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी लगाने के सम्बन्ध में

65-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी लगाकर ग्रामीण को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ। 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चॉदपुर के ग्रामों सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में नमामि गंगे परियोजना के तहत ग्रामीण अंचल में पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में

66- श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में नमामि गंगे परियोजना के तहत ग्रामीण अंचल में पाइप लाइन बिछाने हेतु खड़न्जा एवं सी0सी0 रोड तोड़ दिये हैं तथा कुछ स्थानों पर तोड़े जा रहे हैं जिससे लोगों को आवागमन में समस्या का सामना कर पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त रास्तों को समय-सीमा निर्धारित कर मरम्मत करयेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ । पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु तोड़े जा रहे खड़न्जे एवं सी0सी0 रोड को बिछायी गयी वितरण प्रणाली की हाईड्रोलिक टेस्टिंग किये जाने के उपरान्त पूर्व निर्मित सड़क की स्थिति तक यथाशीघ्र पुनर्निर्माण हेतु सम्बन्धित को निर्देश दे दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

67-श्री स्वामी ओउमवेश-

[बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया के घाघरा नदी में बाढ़ से हुए कटान से प्रभावित ग्रामीणों को जमीन क्रय करके बसाने के सम्बन्ध में

68-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा और घाघरा नदी से बाढ़ से हुए कटान से प्रभावित ग्रामीणों को जमीन क्रय करके बसाने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी के कटान से तहसील बैरिया के ग्राम सभा उदई छपरा व गोपालपुर के कटान से प्रभावित ग्रामीणों को मौजा मानसिंह छपरा

के गांव सभा की आ0नं0-383, रकबा 0.376 हे0 भूमि आवंटित कर पट्टा उपलब्ध करा दिया गया है तथा तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम गंगापुर के नवीन परती के आ0नं0 265, रकबा 0.093 हे0 भूमि पुनर्वास हेतु आरक्षित की गयी है तथा मौजा गंगापुर के आ0नं0-165, 166, 160, 159, 199, 200 व आ0नं0-910 के सहखातेदारों से 0.686 हे0 भूमि क्रय की गयी है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में घाघरा (सरयू) नदी के कटान से प्रभावित ग्रामीणों में 03 परिवार ग्राम रेवती में, 09 परिवार ग्राम चाई छपरा में, 30 परिवार ग्राम गोपालनगर अपनी निजी जमीन पर तथा 14 परिवार ग्राम सुरेमनपुर में सरकारी जमीन में मकान/ झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं। इनको जमीन क्रय कर बसाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी के दूसरे छोर पर स्थित चक्की नवरंगा को बाढ़ से बचाने के सम्बन्ध में

69-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी के दूसरे छोर पर स्थित चक्की नवरंगा को बाढ़ से बचाने की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह

जी नहीं।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी के दूसरे किनारे पर स्थित चक्की नवरंगा नदी के डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में स्थित है। नदी का जल स्तर बढ़ने से पानी फैलता है तथा जल स्तर कम होने पर स्वतः नदी में चला जाता है। डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु कोई कार्य योजना तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य नहीं होने के कारण अनुमन्य नहीं है।

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा की तहसील तिलहर में निर्माणाधीन कस्तूरबा गांधी कन्या आवासीय विद्यालय में अधोमानक सामग्री लगाकर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

70-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा की तहसील तिलहर में निर्माणाधीन कस्तूरबा गांधी कन्या आवासीय विद्यालय में अधोमानक सामग्री लगाकर निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर उक्त का जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

प्रश्नगत निर्माणाधीन कस्तूरबा गांधी कन्या आवासीय विद्यालय के उच्चीकरण हेतु छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त निर्माण की गुणवक्ता जांच जनपदीय समिति द्वारा दिनांक 15-02-2023 को की गयी है, जांच में कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण-पत्र के सापेक्ष निर्माण कार्य प्रथम दृष्टया संतोषजनक पाया गया। निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का निर्माण स्थल से सैम्पल लेते हुए केन्द्रीय प्रयोगशाला, लोक निर्माण विभाग, बरेली को भेजा गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्नगत निर्माण की गुणवक्ता जांच जनपदीय समिति से करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर में वर्ष 2022-23 में स्वीकृत बाढ़ परियोजनाओं ग्राम भुण्डा हरवंशपुर विकास खण्ड खुदागंज, तहसील तिलहर में बाढ़ परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के जांच के सम्बन्ध में

71-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2022-23 में स्वीकृत बाढ़ परियोजनाओं ग्राम भुण्डा हरवंशपुर, विकास खण्ड खुदागंज, तहसील तिलहर में कितनी धनराशि अवमुक्त हुई व कितनी व्यय हुई है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता के कारण परियोजना से बनी होकर देवहा नदी में कट गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर उक्त प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद शाहजहाँपुर में वर्ष 2022-23 में ग्राम भुण्डा हरवंशपुर, वि0ख0 खुदागंज तहसील तिलहर में कोई बाढ़ परियोजना स्वीकत नहीं हुई। विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत देवहा नदी के बांयें तट पर स्थित ग्राम मुण्डा हरिवंशपुर (नौगवा), सहबाजपुर एवं मीरपुर आदि ग्राम समूह की सुरक्षा हेतु कटान निरोधक कार्य की परियोजना' स्वीकृत हुई, जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 मे रु0 70.55 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई तथा समस्त धनराशि कार्यों के सापेक्ष व्यय की गयी है।

परियोजना के समस्त कार्य वर्ष 2022 की बाढ़ काल से पूर्व मानक व विशिष्टियों के अनुसार गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करा लिये गये थे, जो समस्त सुरक्षित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार

जनपद-शाहजहांपुर ग्राम परौर, विकास खण्ड व तहसील कलान में वित्तीय वर्ष 2022-23 मे स्वीकृत बाढ़ परियोजना में बनी ठोकरों में अनियमितता की जाँच विषयक

72-श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 मे स्वीकृत बाढ़ परियोजना में ग्राम परौर वि0ख0 व तहसील कलान, जनपद शाहजहांपुर में कितनी धनराशि अवमुक्त हुई व कितनी व्यय हुई है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त परियोजना में अनियमितता के कारण बाढ़ के दौरान परियोजना से बनी ठोकरें रामगंगा नदी में कट गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर उक्त प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद शाहजहाँपुर में वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत बाढ़ परियोजना में ग्राम परौर, वि0ख0 व तहसील कलान, जनपद शाहजहाँपुर में कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं हुई। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 'जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम परौर विकास खण्ड व तहसील कलान, जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत रामगंगा नदी के दाँयें किनारे पर स्थित परौर, ककोरा तथा मंजा आदि ग्राम समूह की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की एक परियोजना' स्वीकृत हुई थी, जिस पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोई धनराशि अवमुक्त नहीं हुई।

परियोजना के समस्त कार्य वर्ष 2021 की बाढ़ काल से पूर्व मानक व विशिष्टियों के अनुसार गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करा लिये गये थे, जो समस्त सुरक्षित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत ग्राम नवादा दरोबस्त में बाढ़ परियोजना अन्तर्गत बनी ठोकरों की जांच के सम्बन्ध में

73-श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत ग्राम नवादा दरोबस्त में बाढ़ परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है ? क्या सरकार को जानकारी है कि बाढ़ के दौरान परियोजना से बनी ठोकरें देवहा नदी में बह गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर उक्त की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 'जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत देवहा नदी के दांयें तट पर स्थित ग्राम नवादा दरोबस्त खेड़ा एवं बहेड आदि ग्राम समूह की सुरक्षा हेतु कटान

निरोधक कार्य की एक परियोजना' स्वीकृत हुई, जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 124.04 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

परियोजना के समस्त कार्य वर्ष 2022 की बाढ़ काल से पूर्व मानक व विशिष्टियों के अनुसार गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करा लिये गये थे, जो समस्त सुरक्षित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में ओबीसी, एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक समाज की जनसंख्या के आधार पर उन्हें सुरक्षा विभाग में प्रतिनिधित्व देने हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में

74-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ओबीसी, एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक समाज की जनसंख्या के आधार पर उन्हें सुरक्षा विभाग में प्रतिनिधित्व देने की सरकार कोई नीति निर्धारण करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान में उ0प्र0 लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम (यथासंशोधित), 1994 के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों को राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर क्रमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

इटावा की तहसील जसवन्त नगर के ग्राम नगला की गाटा संख्या-1235, 1236, 1238 एवं 1216 पर भू-माफियाओं के कब्जा के सम्बन्ध में

75-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा की तहसील जसवन्त नगर के ग्राम नगला की गाटा संख्या-1235, 1236, 1238 एवं 1216 किसके नाम दर्ज है तथा वर्तमान में उक्त पर कौन व्यक्ति काबिज है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त भूमि पर भू-माफियाओं का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त करवाकर उसके वास्तविक स्वामियों को सौंपेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद-इटावा की तहसील-जसवन्तनगर में नगला नाम से तीन राजस्व ग्राम हैं, जिनके नाम क्रमशः नगला रामसुन्दर, नगला सलहदी व नगला तौर हैं, जिसमें राजस्व अभिलेख खसरा-खतौनी के अनुसार नगला सलहदी व नगला रामसुन्दर में गाटा संख्या-1235, 1236, 1238 एवं 1216 अंकित नहीं है ।

राजस्व ग्राम नगला तौर की गाटा संख्या-1235, 1236, 1238 एवं 1216 का विवरण निम्न प्रकार है :-

1-गाटा सं0-1235 रकवा 0.1860 हे0 पर खातेदार सत्यवीर सिंह, निवासी ग्राम आदि बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर खातेदार काबिज है ।

2-गाटा सं0-1236 रकवा 0.2300 हे0 पर खातेदार श्रीमती दाखश्री, निवासी ग्राम आदि बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर खातेदार काबिज है ।

3-गाटा सं0-1238 रकवा 0.2230 हे0 पर खातेदार श्रीमती दाखश्री, निवासी ग्राम आदि बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर खातेदार काबिज है।

4-(i) गाटा सं0-1216/1 रकवा 0.1250 हे0 नवीन परती के रूप दर्ज है, मौके पर उक्त भूमि पर सार्वजनिक प्रयोग हेतु रास्ता बना हुआ है।

(ii) गाटा सं0-1216/2 रकवा 0.0570 हे0 भूमि पर खातेदार अवनीश कुमार पाठक, निवासी ग्राम आदि सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर खातेदार काबिज है ।

वर्तमान में उक्त गाटा संख्याओं पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा उक्त भूमि पर किसी भू-माफिया का कब्जा नहीं है ।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आगरा की ब्लाक जैतपुर की ग्राम पंचायत पारना के ग्राम फकीरे की मडैया को एक ही जनपद से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में

76-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की ब्लाक जैतपुर की ग्राम पंचायत पारना के ग्राम फकीरे की मडैया इटावा/आगरा दोनों जनपदों से सम्बद्ध होने के कारण गांव के निवासियों को अभिलेखीय असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम फकीरे की मडैया को किसी एक ही जनपद से सम्बद्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-1344/एक-5-2015-49/2015, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 द्वारा मजरा फकीरे की मड़ैया को तहसील बाह जनपद आगरा तहसील जसवन्तनगर जनपद इटावा में सम्मिलित किया गया है।

जिलाधिकारी आगरा के पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2023 में उल्लिखित है कि 'जनपद आगरा की ब्लॉक जैतपुर की ग्राम पंचायत पारना के ग्राम फकीरे की मड़ैया के राजस्व सम्बन्धित अभिलेख प्रमाण-पत्र तहसील जसवन्त नगर जनपद इटावा से जारी किये जाते हैं'।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की ब्लाक असोहा के अन्तर्गत बछौरा विकास कार्यों हेतु कमेटी गठन विषयक

77-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की ब्लाक असोहा के अन्तर्गत बछौरा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग/गबन के आरोप सिद्ध होने पर थाना पुरवा में मुकदमा सं0-0513 भा0द0प्रा0 की धारा-409 के अन्तर्गत दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 को पंजीकृत है यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पंचायत में विकास कार्य करवाने हेतु एक कमेटी का गठन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की नदियों की सफाई कार्य में विगत 05 वर्षों में व्यय की गयी धनराशि का विवरण

78-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित नदियों की सफाई का कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों (2017 से 2022 तक) में कौन-कौन सी नदियों की सफाई कराई गयी तथा उन पर कितना-कितना धन व्यय किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में एल0टी0 ग्रेड पर नियुक्त सहायक अध्यापकों की पदोन्नति की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

79-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने राजकीय विद्यालयों में एल0टी0 ग्रेड पर नियुक्त सहायक अध्यापकों की पदोन्नति की गई है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है ग्रेड पे- 4600 पर नियुक्त कतिपय सहायक अध्यापकों

को एक पदोन्नति का ग्रेड-पे छोड़ कर सीधे ग्रेड पे-5400 प्रदान करा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

प्रदेश के राजकीय हाई स्कूलों में सृजित प्रधानाध्यापक पदों पर सेवा नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार पुरुष शाखा में कुल 98 एवं महिला शाखा में कुल 86 राजकीय विद्यालयों में कार्यरत एल0टी0 ग्रेड सहायक अध्यापाकों को पदोन्नति प्रदान की गयी है एवं तत्समय पुरुष शाखा में कुल 21 पद एवं महिला शाखा में कुल 99 पद शेष रह गये थे।

हाँ।

पदोन्नतियां नियमानुसार की गयी हैं। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कनिष्ठ पद पर कार्यरत एल0टी0 ग्रेड सहायक अध्यापकों को प्रवक्ता के पद पर प्रोन्नति देने के स्थान पर सीधे राजपत्रित प्रधानाध्यापकों के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में

80-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने राजकीय विद्यालयों में कनिष्ठ पद पर कार्यरत एल0टी0 ग्रेड सहायक अध्यापकों को प्रवक्ता के पद पर प्रोन्नति देने के स्थान पर सीधे राजपत्रित प्रधानाध्यापकों के पदों पर पदोन्नति की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

प्रदेश के राजकीय हाई स्कूलों में सृजित प्रधानाध्यापक पदों पर सेवा नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार पुरुष शाखा में कुल 98 एवं महिला शाखा में कुल 86 राजकीय विद्यालयों में कार्यरत एल0टी0 ग्रेड सहायक अध्यापकों को सीधे राजपत्रित प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है।

हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुल्हीपुर में श्मशान भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के सम्बन्ध में

81-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुल्हीपुर में गाटा सं0-664ग कुल रकबा 0.810 एयर व

गाटा सं0-683 कुल रकबा 0.632 एयर जो कि हिंदू श्मशान भूमि के खाते में दर्ज है, पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ? क्या सरकार उक्त अतिक्रमित श्मशान भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-उन्नाव की ब्लॉक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बछौरा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग व गबन के आरोप के सम्बन्ध में

82-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की ब्लॉक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बछौरा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग व गबन के आरोप में थाना पुरवा में मुकदमा संख्या-0513 भारतीय दण्ड विधान की धारा-409 के अन्तर्गत 15 अक्टूबर, 2022 को एवं सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा-2 व 3 के अन्तर्गत 23-07-2021 को मुकदमा संख्या-0238 मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था ? यदि हाँ, तो क्या गबन सहित सभी आरोपों में दोषी ग्राम प्रधान को निलम्बित करते हुए कार्य-संचालन समिति बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

डॉ0 अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्रैल, 2018 से 17-11-2022 तक व्यय धनराशि में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में

83-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के डॉ0 अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्रैल, 2018 से 17-11-22 तक कितना बजट की धनराशि व्यय की गई है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त में भ्रष्टाचार किया गया है ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

जी हाँ।

अप्रैल, 2018 से दिनांक 17-11-2022 तक डॉ0 अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैण्डीकैप्ड, उत्तर प्रदेश, कानपुर को वेतन, गैर वेतन एवं पुनरीक्षित वेतन मद में कुल रु0 9,25,29,500.00 का बजट आवंटित किया गया है, जिसके सापेक्ष संस्थान द्वारा दिनांकरू 17-11-2022 तक कुल धनराशि रु0 9,20,67,633.00 का व्यय किया गया है।

डॉ0 अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी फॉर हैण्डीकैप्ड, उत्तर प्रदेश, कानपुर को आवंटित बजट के सापेक्ष संस्थान द्वारा व्यय उन्हीं मदों में किया गया है, जिसके लिए धनराशि आवंटित की गयी थी । संस्थान द्वारा व्यय की गई सभी धनराशियों का चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से ऑडिट कराकर उसकी ऑडिट रिपोर्ट वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जिसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/भ्रष्टाचार नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पर भ्रष्टाचार के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में

84-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पर भ्रष्टाचार के आरोपों के प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के नियुक्ति प्राधिकारी, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उ0प्र0 हैं। सम्प्रति प्रश्नगत प्रकरण में उच्च शिक्षा विभाग के स्तर से कोई जांच विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-चित्रकूट के रसिन बांध से बांध में पानी पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट फार कन्स्ट्रक्शन आफ बाण गंगा बरुआ डैम लिंक कैनाल को मंजूरी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में

85-श्री अनिल प्रधान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2022-23 में कितने नए लिंक कैनाल का निर्माण कार्य प्रस्तावित है ? क्या सरकार बताएगी कि जनपद चित्रकूट के रसिन बांध से बरुवा बांध में पानी पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ बाण गंगा बरुवा

डैम लिंक कैनाल का गठन किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परियोजना को मंजूरी प्रदान कर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में वर्ष 2022-23 में किसी भी नये लिंक कैनाल का निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है।

जी हाँ।

परियोजना फिजिबिल होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

86-[प्रश्न हटाया गया]

87-[प्रश्न हटाया गया]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर अन्तर्गत गांवों/घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के सम्बन्ध में

88-श्री सुभाष त्रिपाठी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर अन्तर्गत गांवों/घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से 30 अप्रैल, 2017 से 30 मार्च, 2022 तक किन-किन ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी के निर्माण कार्य कब-कब पूर्ण किया गया है ? क्या ये सभी चालू हालत में हैं तथा बिना किसी बाधा के घरों में पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो ऐसी कौन-कौन सी पानी की टंकी हैं जिनका उक्त अवधि में निर्माण कराकर चालू करा दिया गया था वर्तमान में खराब है ? क्या सरकार इन्हें ठीक कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत दिनांक 30 अप्रैल, 2017 से 30 मार्च, 2022 तक वित्तीय वर्षवार विवरण क्रमशः निम्नलिखित पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया गया है :-

1-वित्तीय वर्ष 2017-18 में 06 पाइप पेयजल योजनाएं यथा-पुरैनी, लालपुर जलालपुर, करमुल्लापुर, लौकाही, सिंहपुर एवं बालापुर ।

2-वित्तीय वर्ष 2018-19 में 05 पाइप पेयजल योजनाएं यथा-गुल्हरिया गाजीपुर, करैला शहबाजपुर, आदिलपुर, लालपुर एवं झुरीकुईयां।

3-वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10 पाइप पेयजल योजनाएं यथा-देवीदासपुर, बिराहिमपुर भिल्हौरा, बिबियापारा, इच्छापुर, रायगढ़ बेहड़ा, अलहियापुर, बरूही, बब्बा, भैंसहा एवं हुजूरपुर।

4-वित्तीय वर्ष 2020-21 में 07 पाइप पेयजल योजनाएं यथा-कटका मरौठा, धरमपुर गाजीपुर कोड़री, धनपारा, जगता जलालपुर, पूरेजैता एवं लक्खारामपुर ।

उपरोक्त 28 पाइप पेयजल योजनाओं में से 18 पाइप पेयजल योजनाएं क्रमशः लालपुर, जलालपुर, लौकाही, आदिलपुर, झुरीकुईया देवीदासपुर, बिबियापारा, इच्छापुर, रायगढ़ बेहड़ा,अलहियापुर, बरूही, भैंसहा, हुजूरपुर, धरमपुर, गाजीपुर कोड़री, धनपारा, जगता जलालपुर, पूरेजैता तथा लक्खारामपुर चालू हालत में और बिना किसी बाधा से घरों में पानी पहुंच रहा है।

विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत 10 पाइप पेयजल योजनाओं यथा-बालापुर, सिंहपुर, करमुल्लापुर, बिराहिमपुर भिलौरा, कटका मरौठा, पुरैनी, गुल्हरिया गाजीपुर, बब्बा, करैला शहबाजपुर एवं लालपुर का निर्माण कराकर उक्त अवधि में चलाई गयी थी, परन्तु उक्त पाइप पेयजल योजनाओं के ग्रामों में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण एवं नाली निर्माण इत्यादि होने के कारण पाइप लाइन एवं योजना के कुछ घटकों के क्षतिग्रस्त होने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक समस्त कार्य पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर अन्तर्गत मार्च, 2017 के पूर्व गांवों/घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से की टंकी निर्माण की जानकारी

89-श्री सुभाष त्रिपाठी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर अन्तर्गत मार्च, 2017 के पूर्व किन-किन गांवों/घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से पानी की टंकी का निर्माण कराकर चालू कर पानी की सप्लाई की जा रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि ऐसी कौन-कौन सी पानी की टंकियां है जो वर्तमान में खराब हैं ? क्या सरकार इन्हें ठीक कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में मार्च, 2017 के पूर्व विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम पयागपुर एवं सोहरियावां तथा विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत सहरालमपुर पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराकर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को संचालन एवं रख-रखाव हेतु हस्तगत की जा चुकी है।

जनपद बहराइच के ग्राम बालापुर, सिंहपुर, करमुल्लापुर, बिराहिमपुर भिलौरा, कटका मरौठा, पुरेनी, गुल्हरिया गाजीपुर, बब्बा, करैला शहबाजपुर, लालपुर में निर्मित पानी की टंकियां आंशिक रूप से खराब हैं।

'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 2024 तक रेट्रोफिटिंग एवं पुनर्गठन की कार्यवाही कराकर शुद्ध पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर की टंकियों की पाइप लाइन खराब होने से सप्लाई बाधित होने के जांच के सम्बन्ध में

90-श्री सुभाष त्रिपाठी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर अन्तर्गत गाँवों/घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गयी पानी की टंकियों की पाइप लाइन खराब होने से सप्लाई बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त टंकियों को चिन्हित किया है ? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी पानी की टंकियां हैं जहां पाइप लाइन खराबी या फट जाने से पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार खराब पाइपों के सप्लाई व लगाने की जांच कराते हुए पानी की सप्लाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर अन्तर्गत गांवों/घरों में निर्मित 31 पाइप पेयजल योजनाओं में से 11 पाइप पेयजल योजनाएं सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण के कारण पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण आंशिक रूप से बाधित है।

जी हाँ ।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में नवनिर्मित सड़कों/सड़क चौड़ीकरण एवं नाली निर्माण के कारण बालापुर, सिंहपुर, करमुल्लापुर, बिराहिमपुर भिलौरा, कटका मरौठा, पुरैनी, गुल्हरिया गाजीपुर, बब्बा, करैला शहबाजपुर, सहसलमपुर एवं लालपुर पाइप पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है।

उपरोक्त पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण पाइप की सही गुणवत्ता के अनुसार कराया गया था, परन्तु योजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित ग्रामों में नवनिर्मित सड़कों एवं सड़क चौड़ीकरण के कारण पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनका चिन्हिकरण करा लिया गया है। उक्त चिन्हित योजनाओं का जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पुनर्गठन कर जलापूर्ति कराया जाना लक्षित है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक समस्त कार्य पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्रामों में चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त कब्जा परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में

91-श्री सुभाष त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत वर्ष 2005 से सितम्बर, 2022 तक किन-किन राजस्व ग्रामों की चकबंदी प्रक्रिया कब-कब पूरी हुई है ? क्या ऐसे सभी ग्रामों की जिनकी चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है उनमें कब्जा परिवर्तन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से ग्राम हैं जिनकी चकबंदी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब तक कब्जा परिवर्तन शेष है ? क्या सरकार उक्त ग्रामों में समय सीमा निर्धारित कर कब्जा परिवर्तन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में वर्ष 2005 से माह सितम्बर, 2022 तक कुल 74 राजस्व ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण करायी गयी है।

जी हां।

कब्जा परिवर्तन हेतु कोई भी ग्राम शेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता है।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ एवं राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा विगत 7 वर्षों में वर्षवार आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में

92-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ एवं राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा विगत 7 वर्षों में वर्षवार आवंटित धनराशि के सापेक्ष मदवार व्यय धनराशि का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हां।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा का पद वर्ष 2019 में सृजित किया गया था। इसके पूर्व राज्य परियोजना निदेशक द्वारा ही कार्यक्रम का संचालन किया जाता था। विगत 7 वर्षों में वर्षवार आवंटित धनराशि के सापेक्ष मदवार व्यय धनराशि का विवरण संलग्न[†] है।

[†] छापा नहीं गया।

प्रश्न नहीं उठता।

छापा नहीं गया।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी में बिहार साइड में बसे गांव भुवाल छपरा, नवरंगा ग्राम को कटान से बचाने के सम्बन्ध में

93-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी में बिहार साइड में बसे गांव भुवाल छपरा, नवरंगा ग्राम को कटान से बचाने हेतु बांध बनाकर बोल्डर से पिच कराने की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में गंगा नदी में बिहार साइड में बसे गांव भुवाल छपरा, नवरंगा नदी के डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में स्थित है। डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में कटान रोधी कार्य तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य नहीं होने के कारण अनुमन्य नहीं है।

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के नगर पंचायत कटरा में स्थित प्राथमिक विद्यालयों एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में काया कल्प योजना के अन्तर्गत इण्टर लाक एवं बाउण्ड्री का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

94-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के नगर पंचायत कटरा में स्थित प्राथमिक विद्यालयों एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत इण्टर लाक एवं बाउण्ड्री का निर्माण नहीं कराया गया है ? तथा मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत निम्न स्तर का खाना दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप सिंह-

नगर पंचायत कटरा में अवस्थित कुल 07 परिषदीय विद्यालयों में से 01 उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा को छोड़कर सभी विद्यालयों में वर्तमान में चहारदीवारी उपलब्ध है। विद्यालयों में इण्टरलॉकिंग कार्य वर्तमान में आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधा सम्बन्धी निर्धारित 19 पैरामीटर के अन्तर्गत लक्षित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मिड-डे-मील में निम्न स्तर का भोजन दिये जाने सम्बन्धी सम्प्रति कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है।

जनपद बलरामपुर में खेतों में बाढ़ के पानी को निकालने के लिये नहरों/नालों में साइफन के निर्माण के सम्बन्ध में

95-श्री पल्टूराम-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में विगत दिनों आयी भीषण बाढ़ के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गयी और वर्तमान में किसानों की खेतों में बाढ़ का पानी जमा होने के कारण रबी फसल की बुआई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के खेतों से पानी निकालने हेतु विभिन्न नहरों/नालों में साइफन का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता !

जनपद बलरामपुर में माह अक्टूबर में नदियों में आये भारी जल प्रवाह के कारण भीषण बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसके कारण जल प्लावन की स्थिति से आंशिक रूप से फसलें क्षतिग्रस्त हुईं तथा रबी फसल की बुआई में भी समस्या उत्पन्न हुई। सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहरों एवं नालों पर जल निकासी हेतु आवश्यकतानुसार पूर्व से ड्रेनेज क्रासिंग्स/साइफन्स निर्मित है तथा समय-समय पर स्थान विशेष पर आवश्यकतानुसार ड्रेनेज क्रासिंग/साइफन का निर्माण किया जाता है ।

जनपद बलरामपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जलापूर्ति हेतु पाइप डालने में खोदी गयी सड़कों/रास्तों को ठीक कराने के सम्बन्ध में

96- श्री पल्टूराम-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जनपद बलरामपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल-हर घर नल योजना में कार्यदायी संस्था द्वारा ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व अन्य विभागों से बनी सड़कों को पाइप डालने हेतु खोद दिया गया है जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं ? क्या सरकार उक्त खोदी गयी सड़कों/रास्तों को कार्यदायी संस्था से ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बलरामपुर में 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के हर घर जल योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों को कराये जाने के दौरान सड़कों की खुदाई की गयी है।

पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी जा रही सड़कों के यथाशीघ्र पुनर्निर्माण हेतु सम्बन्धित को निर्देश दे दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला में राप्ती नदी-भड़रिया तटबंध के निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में

97-श्री पल्टूराम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला में राप्ती नदी-भड़रिया तटबंध के निर्माण में किसानों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किसानों को वर्तमान तक नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को उनकी अधिग्रहीत भूमि की मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला में राप्ती नदी के किनारे निर्माणाधीन बलरामपुर-भड़रिया तटबंध के निर्माण की परियोजना हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित स्थानीय कृषकों से स्पष्ट सहमति का पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जाए एवं तद्नुसार परियोजना आगामी मुख्य समिति में प्रस्तुत की जाए।

उक्त के अनुपालन में परियोजना आगामी मुख्य अभियन्ता समिति में प्रस्तुत की जायेगी तथा परियोजना के स्वीकृत होने के उपरान्त ही मुआवजे से सम्बंधित अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में संचालित गर्म काँच की भट्ठियों को दृष्टिगत रखते हुये अग्निशमन विभाग में अनिवार्य अवस्थापना सुविधाओं के बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

98-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में संचालित गर्म काँच की भट्ठियों को दृष्टिगत रखते हुये अग्निशमन विभाग में फायर बिग्रेड की गाड़ियों की संख्या

बढ़ाये जाने सहित अन्य आवश्यक अनिवार्य अवस्थापना सुविधाओं के बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान में जनपद फिरोजाबाद के अग्निशमन विभाग में उपलब्ध फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ/उपकरण निम्नवत् है :-

1-फोम टेण्डर-02

2-वाटर टेण्डर टाइप-बी बड़ा (क्षमता 4500-5000 ली0)-01

3-वाटर टेण्डर टाइप-बी छोटा (क्षमता 2000-2500 ली0)-04

4-वाटर मिस्ट वन टनर क्षमता 400 ली0-02

5-महेन्द्रा बोलेरो कैम्पर-03

6-हाईबैक पैक बुलेट मोटर साइकिल-01

7-पोर्टेबुल पम्प 60 जीपीएम-03

8-एम्बुलेन्स विंगर-01

अग्निशमन सुविधाओं को बढ़ाये जाने के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग में फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ/उपकरण/संयंत्रों सहित क्रय किया जाना है, जिनके सापेक्ष अग्निशमन सुविधा हेतु जनपद फिरोजाबाद को उपलब्धता के आधार पर फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ आवंटित की जाएंगी।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा के आगरा शहर में सिंचाई विभाग की मघटई, दयालबाग, पार्क माइनर जमीन को कब्जा मुक्त कराने के सम्बन्ध में

99-श्री बाबूलाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा शहर में सिंचाई विभाग की मघटई, दयालबाग, पार्क माइनर आदि की अरबों रुपयों की जमीनों पर अवैध कब्जे कर लिए गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन को कब्जा मुक्त कराकर उक्त हेतु जिम्मेवारों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

मघटई माइनर एवं दयालबाग माइनर की कुछ भूमि पर अवैध कब्जे हैं परन्तु पार्क माइनर पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

जी हाँ ।

अतिक्रमण हटवाये जाने हेतु कार्यवाही प्रशासन/पुलिस की सहायता से प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में आगरा शहर के बीच में अरबों रुपयों की जॉन्स मील की सरकारी जमीनों (नगर निगम, नजूल एवं नहर विभाग) को अवैध कब्जा से मुक्त कराने व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

100-श्री बाबूलाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में आगरा शहर के बीच में अरबों रुपयों की जॉन्स मील की सरकारी जमीनों (नगर निगम, नजूल एवं नहर विभाग)पर पक्की बिल्डिंगें बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन को कब्जा मुक्त कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

प्रश्नगत सम्पत्ति सम्बन्धी प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत जिलाधिकारी, आगरा के आदेश दिनांक 29-07-2020 के द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता में जाँच कमेटी का गठन किया गया। जाँच कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 15-12-2020 के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या-53334/2021 राजेन्द्र प्रसाद जैन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य तथा रिट याचिका संख्या-9336/2022 हेमेन्द्र अग्रवाल उर्फ चुनमुन बनाम उ0प्र0 राज्य के साथ ही सिविल न्यायालय में भी वाद विचाराधीन है । साथ ही आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा, कानपुर के स्तर पर भी जाँच प्रचलित है ।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा की विधान सभा छाता के थाना कोसी कलां में दर्ज एफ0आई0आर0 संख्या-416 के सम्बन्ध में

101-श्री बाबूलाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 06-09-2022 का पत्र संख्या 775/वि0फ0/फा0सि0/2022 जो जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र छाता के कस्बा कोसीकलां के थाना कोसी कलां में दिनांक 02-06-2018 को एफ0आई0आर0 संख्या-0416 जिसमें सरकारी जमीन खसरा संख्या-1119, 1122, 1634 पर अवैध कब्जा को हटाने विषयक हैं प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

थाना कोसीकलां जनपद मथुरा पर वादी श्री उमेश चन्द्र अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् कोसीकलां द्वारा मु0अ0सं0 416/18 धारा 188/447 भादवि व 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम बनाम प्रहलाद सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप, निवासी हताना कोसीकलां जनपद मथुरा के विरुद्ध सरकारी पोखर पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के सम्बन्ध में दिनांक 02-06-2018 को पंजीकृत कराया गया, दौराने विवेचना उक्त अभियोग में अभियुक्त चरन सिंह पुत्र लालाराम, निवासी राजागढ़ी, थाना कोसीकलां, जनपद मथुरा का नाम प्रकाश में आया जो पोखर उक्त की बगल में स्थित मोतीमहल होटल का मालिक है। राजस्व निरीक्षक के बयानों के आधार पर अभियुक्त चरन सिंह द्वारा सरकारी पोखर के आंशिक भाग में पक्की बाउन्ड्री, लैट्रीन, बाथरूम व जीना बनाकर पार्क के रूप में कब्जा किया होना पाया गया। उपरोक्त अभियोग में नामित अभियुक्त प्रहलाद सिंह की घटना में संलिप्तता न पाये जाने पर नामजदगी गलत की गयी तथा प्रकाश में आये अभियुक्त चरन सिंह उपरोक्त पर धारा-41 (क) सीआरपीसी का नोटिस तामील कराते हुए आरोप पत्र 642/18 दिनांक 13-09-2018 माननीय न्यायालय में प्रेषित करते हुए विवेचना समाप्त की गयी, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सोहांव के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगहरा में चकबन्दी की प्रक्रिया पूर्ण करने के सम्बन्ध में

102-श्री संग्राम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सोहांव के अन्तर्गत ग्राम सभा गंगहरा में चकबन्दी कि प्रक्रिया विगत 20 वर्षों से प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त चकबन्दी की प्रक्रिया को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, बलिया की आख्या दिनांक 14-02-2023 के अनुसार ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है।

जी हां।

जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, बलिया द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम में बन्दोबस्त भू-चित्र के अभाव में तथा ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया को लेकर कृषकों के मध्य आपसी गुटबन्दी व घोर विरोध होने के कारण चकबन्दी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत ग्राम को उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक किये जाने की कार्यवाही चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

जनपद रायबरेली के अन्तर्गत सभी विकास खण्डों में लम्बे अर्से से खराब इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रि-बोर कराने विषयक

103-श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 111/05/07/022 जो विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर, जनपद रायबरेली के अन्तर्गत सभी विकास खण्डों वि0ख0 हरचन्दपुर, खीरों, संताव, लालगंज के सभी ग्राम सभाओं में काफी लम्बे अर्से से इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्प खराब हैं की मरम्मत एवं रि-बोर कराने विषयक है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर जनपद-रायबरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड- हरचन्दपुर, खीरों, संताव एवं लालगंज के सभी ग्राम सभाओं में स्थापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की मरम्मत/रि-बोर करा दिया गया हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में 2020 में कार्यदायी संस्था जिला पंचायत रायबरेली द्वारा सिविल लाईन चौराहे के निकट एक मार्केट के निर्माण के सम्बन्ध में

104-श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में 2020 में कार्यदायी संस्था जिला पंचायत रायबरेली द्वारा सिविल लाईन चौराहे के निकट एक मार्केट का निर्माण जिला पंचायत परिसर के ऊपरी तल पर गोरा बाजार एवं रफी अहमद किदवई (हाथी पार्क) में भवन निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिला पंचायत द्वारा सिविल लाईन चौराहे के निकट दुकानों के निर्माण हेतु बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कराकर शासन से स्वीकृति उपरान्त दुकानों का निर्माण वर्ष 2017 में कराया गया है। तदोपरान्त जिला पंचायत की आय के दृष्टिगत बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कराकर दुकानों के ऊपरी तल पर छत किराये पर दिया गया है एवं रफी अहमद किदवई (हाथी पार्क) में पूर्व में बनी जर्जर कैण्टीन के स्थान पर कैण्टीन का निर्माण कार्य कराया गया है। प्रश्नगत कार्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के अनुसार जिला पंचायत के स्वामित्व की भूमि पर हुआ है।

किस बिन्दु पर जाँच अपेक्षित है, स्पष्ट नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कस्बा सैंथल में एम0एस0डी0पी0 के तहत निर्मित कराये गये जी0टी0आई0 कालेज का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में

105-डा0 एम0 पी0 आर्य-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कस्बा सैंथल में एम0एस0डी0पी0 के तहत निर्मित कराये गये जी0टी0आई0 कालेज का संचालन कराये जाने की योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा एम0एस0डी0पी0 योजना के तहत जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कस्बा सैंथल में जी0टी0आई0 कॉलेज के नाम से किसी संस्थान का निर्माण नहीं कराया गया है। अतः उक्त कॉलेज का संचालन प्रारम्भ कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

वस्तुतः जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कस्बा सैंथल में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व नाम एम0एस0डी0पी0) के तहत राजकीय पालीटेक्निक भवन का निर्माण कार्य अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में बाढ़ से बचाव हेतु कतिपय ग्राम पंचायतों में रेगुलेटर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

106-डॉ0 हृदय नारायण पटेल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी जो बाढ़ ग्रस्त इलाका होने के कारण हजारों एकड़ जमीन व फसल खराब हो जाती है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि इससे बचाव हेतु दिनांक 20-04-22 को दो रेगुलेटर ग्राम पंचायत पिहार में छोटी सरयू पर बने बांध पर नाला क्रासिंग पर रेगुलेटर तथा ग्राम पंचायत सहनूपुर में महुला गढ़वल बांध पर रेगुलेटर लगाने के लिए उ0 प्र0 शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल कार्यवाही कराकर रेगुलेटर का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं, मात्र नदी एवं तटबंध के मध्य की डूब क्षेत्र की जमीन व फसलें ही बाढ़ से प्रभावित होती हैं।

ग्राम पंचायत में सिंचाई विभाग द्वारा कोई भी तटबंध निर्मित नहीं है। बिना तटबंध के रेगुलेटर गेट का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है । ग्राम पंचायत सहनूपुर में महुला गढ़वल

बांध के किमी0 37.100 पर 08 अदद गेट का रेगुलेटर निर्मित है तथा वर्तमान में उक्त कैचमेंट एरिया में नये रेगुलेटर गेट के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के रौनापार बाजार में फायर स्टेशन के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

107-डॉ0 हृदय नारायण पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के रौनापार बाजार में फायर स्टेशन का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी में अग्निशमन केन्द्र महराजगंज के आवासीय/अनावासीय भवन का निर्माण कर क्रियाशील/संचालित अवस्था में है, जो रौनापार बाजार तहसील सगड़ी से लगभग 23 किमी0 की दूरी पर स्थित है। अग्निशमन केन्द्र, महराजगंज से ही सगड़ी के रौनापार बाजार एवं आस-पास की अग्नि दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के बचाव हेतु बंधे का निर्माण करने विषयक

108-डॉ0 हृदय नारायण पटेल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में अधिकांश क्षेत्र में बाढ़ के कारण फसल खराब हो जाती है ? क्या सरकार उक्त हेतु कार्यवाही कराकर उपरोक्त बंधे का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तटबंध पूर्व से ही विद्यमान है, मात्र नदी एवं तटबंध के मध्य की डूब क्षेत्र की फसलें ही बाढ़ से प्रभावित होती हैं।

जनपद झांसी की बड़वार झील भरने से किसानों की डूबी हुयी भूमि का मुआवजा दिलाये जाने विषयक

109-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की बड़वार झील भरने से किसानों की डूबी हुयी भूमि का मुआवजा दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0 105321, दिनांक 25 नवम्बर, 2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

वर्ष 2022-23 में तहसील टहरौली क्षेत्रान्तर्गत बड़वार झील में अधिक पानी आने पर/अतिवृष्टि से कुल 08 गांव के 1692 कृषकों की खरीफ की फसल प्रभावित होने से इन सभी कृषको को रु0 0117.39 लाख की धनराशि नियमानुसार फसल क्षतिपूर्ति के रूप मे उनके खातों में अन्तरित की जा चुकी है। प्रश्नगत डूब क्षेत्र की भूमि का मुआवजा दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की ब्लाक पुरवा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत त्रिपुरापुर में हैण्डपम्पों की मरम्मत व रि-बोर हेतु व्यय की गई धनराशि का ब्योरा सदन के पटल पर रखने की मांग

110 श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय सत्र 2022 के प्रथम मंगलवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 185 के उत्तर के सन्दर्भ में जनपद उन्नाव की ब्लाक पुरवा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत त्रिपुरापुर में जिन 38 हैण्डपम्पों की मरम्मत में रु0 1,43,092/- एवं 10 हैण्डपम्पों के रि-बोर में रु0 2,73,890/- की धनराशियां व्यय की गयी है तथा उक्त रि-बोर वाले हैण्डपम्प किन-किन स्थानों पर अधिष्ठापित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड पुरवा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत- त्रिपुरापुर में 38 हैण्डपम्पों की मरम्मत के स्थल की सूची एवं 10 हैण्डपम्पों के रि-बोर के स्थल की सूची संलग्न है।[†]

[†] देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ सं0-338-340 पर

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियों के सम्बन्ध में

111-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियों को आवंटित किए गये हैं और कितने लाभार्थी प्रतीक्षारत हैं ? क्या सरकार उक्त लाभार्थियों को समय सीमा निर्धारित कर आवास आवंटित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 04 विकास खण्डों की ग्राम पंचायतें समाहित हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक पात्र परिवारों को उपलब्ध कराये गये आवासों का विकास खण्ड वार विवरण निम्नवत है :-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	विकास खण्ड में विधान सभा क्षेत्र गरौठा की सम्मिलित ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल आवंटित किये गये आवासों की संख्या	प्रतीक्षारत आवासों की संख्या
1	मोंठ	67	4438	101
2	बामौर	53	3863	235
3	गुरसराय	38	2835	40
4	चिरगांव	13	1161	-
	योग :	171	12297	376

प्रतीक्षारत लाभार्थियों को आवास दिया जाना भारत सरकार से अग्रिम निर्देश/लक्ष्य प्राप्त होने पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली के उप जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 14-12-2017 को दिये गये आदेश द्वारा गाटा संख्या-182 को ग्राम सभा बहेड़ी में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में

112-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बरेली के उप जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 14/12/2017 को दिये गये आदेश द्वारा गाटा संख्या-154, 157, 159, 160, 161,

162, 163, 164, 165, 166, 168,169,170, 176, 182, 199 एवं 200 संख्याओं में से 182 न0 को ग्राम सभा बहेड़ी में सम्मिलित कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो किस आधार पर ? क्या जिलाधिकारी द्वारा जारी विक्रय-पत्र में संशोधन का अधिकार उप जिलाधिकारी को है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त विक्रय-पत्र के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में वर्ष 2015 से वाद लम्बित है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त आदेश जारी किये जाने से पूर्व मा0 उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त की गयी ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? क्या यह सही हैं कि गाटा संख्या-182 को ग्राम सभा में सम्मिलित किये जाने पर विक्रय-पत्र के मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ेगा ? यदि हाँ, तो क्या उक्त विक्रय प्रमाण-पत्र को संशोधित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

उक्त आदेश दिनांक 14-12-2017 के विरुद्ध योजित निगरानी में राजस्व परिषद् द्वारा दिनांक 30-01-2018 को आदेश पारित करते हुए उप जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किया गया है। वर्तमान में गाटा संख्या-182 के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् के समक्ष वाद विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या-137/2015 चन्द्र प्रकाश बनाम उ0प्र0 राज्य व 15 अन्य को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09-09-2015 के द्वारा निस्तारित किया जा चुका है ।

जिलाधिकारी, बरेली द्वारा जारी किये गये विक्रय प्रमाण-पत्र दिनांक 16-05-2015 के विरुद्ध श्री चन्द्र प्रकाश द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के निस्तारण हेतु वाद को आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली को प्रति प्रेषित किया गया।

आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा श्री चन्द्र प्रकाश खंडूजा की आपत्तियाँ ग्राहय न होने के कारण समुचित सुनवाई के उपरान्त निरस्त करते हुए निस्तारण किया गया।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या में स्थित थाना कुमारगंज के ग्राम बलारमऊ, तहसील मिल्कीपुर निवासिनी अनारकली पत्नी स्व0 खिलाड़ी को मृतक दिखाकर उसकी भूमि को हड़पने के सम्बन्ध में

113-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या में स्थित थाना कुमारगंज के ग्राम बलारमऊ, तहसील मिल्कीपुर निवासिनी अनारकली पत्नी स्व0 खिलाड़ी का दिनांक

05-11-22 को सम्पूर्ण समाधान दिवस पर शिकायती प्रार्थना पत्र सं0 30090322 तथा दिनांक 11-11-2022 का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अयोध्या को प्रेषित पत्र जो कि प्रार्थिनी को मृतक दिखाकर उसकी भूमि को कतिपय व्यक्तियों द्वारा हड़पने के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके कार्यवाही करने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 08-03-2022 व दिनांक 05-11-2022 को तहसीलदार मिल्कीपुर द्वारा दिनांक 15-11-2022 को निरस्त किया गया और अनारकली का नाम खतौनी में पूर्ववत् कायम हो गया है। साथ ही तहसीलदार मिल्कीपुर के आदेश के क्रम में दिनांक 14-02-2023 को थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या पर मु0अ0सं0-80/2023 धारा-419/420/467/468/471 भादवि बनाम-रामलली पत्नी शिव प्रसाद निवासी ग्राम बलारमऊ थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर के ग्राम ऐत्मादसराय में 2010-11 में निर्माणाधीन महिला डिग्री कॉलेज को पूर्ण करने के सम्बन्ध में

114-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर के ग्राम ऐत्मादसराय में 2010-11 में निर्माणाधीन महिला डिग्री कॉलेज 10 वर्ष बीत जाने के उपरान्त तैयार नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त महिला डिग्री कॉलेज को समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर के ग्राम ऐतमादपुर में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का निर्माण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया जा रहा है। परियोजना की स्वीकृत लागत रु0 477.50 लाख थी जो प्राप्त हो गयी है तथा उसका व्यय हो चुका है। वर्ष 2018 में पुनरीक्षित आगणन के अनुसार परियोजना की कुल लागत रु0 852.35 लाख है। परन्तु पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत न होने तथा अन्य धनराशि प्राप्त न होने के कारण कार्य बन्द है। उक्त परियोजना में कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0, यूनिट-25 जल निगम, अलीगढ़ है।

उपर्युक्तानुसार।

जी हां।

02 वर्ष ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर के ग्राम जसनावली कला में सुबोध के खेत से बलवीर सिंह के खेत तक जर्जर मार्ग का नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में

115-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर के ग्राम जसनावली कला में सुबोध के खेत से बलवीर सिंह के खेत तक का मार्ग जर्जर होने के कारण आम जनता को आने जाने में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग कच्चा मार्ग है, जिसकी लम्बाई 1.00 किमी0 है। उक्त मार्ग पर मिट्टी/खडंजा निर्माण कराये जाने में लगभग रु0 24.00 लाख व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 में प्राप्त होने वाले अनुदानों के सापेक्ष कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है। प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में शामिल करने हेतु जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जायेगा एवं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर के ग्राम हीरापुर पजाये में ऋषि पैलेस से बिजेन्द्र सिंह के घर तक मार्ग नव निर्माण कराने विषयक

116-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर के ग्राम हीरापुर पजाये में ऋषि पैलेस से बिजेन्द्र सिंह के घर तक का मार्ग जर्जर होने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। ग्राम हीरापुर पजाये में ऋषि पैलेस से बिजेन्द्र सिंह के घर तक मार्ग लगभग 180 मी0 ग्राम पंचायत की आबादी के अन्दर है।

प्रश्नगत कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायत की अनुपूरक योजना में सम्मिलित कर 02 माह में पूर्ण करा लिया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर के ग्राम गिनीरा शेख में मेन मार्ग से शमशान घाट तक के जर्जर भाग का नव निर्माण कराने विषयक

117-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर के ग्राम गिनीरा शेख में मेन मार्ग से शमशान घाट तक का मार्ग जर्जर स्थिति में होने के कारण आम जनता को शमशान घाट तक आने जाने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 1.00 किमी0 है। उक्त स्थल पर पुराना खड़न्जा लगा हुआ है, जो कि जर्जर स्थिति में है। मार्ग की मरम्मत में लगभग रु0 15.00 लाख व्यय होने का अनुमान है। वर्तमान में जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 में प्राप्त होने वाले अनुदानों के सापेक्ष कार्य-योजना स्वीकृत हो चुकी है। प्रश्नगत कार्य को आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य-योजना में शामिल करने हेतु जिला पंचायत की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जायेगा एवं सदन द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

श्री शीतल प्रसाद गुप्ता की प्रारूपकार से संगणक के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में

118-श्री महेंद्र नाथ यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सिंचाई विभाग के अधिष्ठान 6 ख अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 798/ई-6ख/ संगणक/प्रोन्नति /लखनऊ, दिनांक 15 सितम्बर, 2020 द्वारा शीतल प्रसाद गुप्ता की पदोन्नति उपरान्त (पदस्थापना/राजसात) विभाग द्वारा की गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ। श्री शीतल प्रसाद गुप्ता की प्रारूपकार से संगणक पद पर प्रोन्नति सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिष्ठान-6ख अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-798/ई-6ख/ संगणक/प्रोन्नति, दिनांक 15 सितम्बर, 2020 द्वारा की गयी। तत्पश्चात् इनके स्वयं के अनुरोध पर कार्यालय ज्ञाप सं0-1991/ई-6ख/संगणक, दिनांक 10-02-2023 द्वारा राजसात किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

119-श्री पंकज कुमार मलिक-

[02-सोमवार के अतारांकित प्र0सं0-168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बरेली के थाना प्रेमनगर में दर्ज एफ0आई0आर0 नम्बर 0229 दिनांक 30-06-2022 के सम्बन्ध में

120-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के थाना प्रेमनगर में दर्ज एफ0आई0आर0 नम्बर-0229, दिनांक 30-06-2022 जोकि घर का ताला तोड़ कर चोरी करने के सम्बन्ध में है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

दिनांक 30-06-2022 को वादी श्री संजीव कुमार सक्सेना पुत्र स्व0 एम0 एल0 सक्सेना नि0 255, गांधीपुरम गुप्ता नर्सरी के पास थाना-प्रेमनगर, जनपद-बरेली के द्वारा अपनी पुत्रवधू सिद्धि सक्सेना व उसके परिजनों के विरुद्ध थाना-प्रेमनगर पर मु0अ0सं0-229/22 धारा-454, 380 भादवि बनाम सिद्धि सक्सेना आदि 07 नफर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही से ज्ञात हुआ कि वादी श्री संजीव कुमार के द्वारा दिनांक 04-03-2021 को थाना कोतवाली, जनपद-बरेली पर मु0अ0सं0-76/21 बनाम 452, 323, 504, 506 भादवि बनाम सिद्धि सक्सेना आदि के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 29-04-2021 को श्रीमती सिद्धि सक्सेना के द्वारा थाना तल्लीताल, जनपद-नैनीताल, उत्तराखण्ड में मु0अ0सं0-22/21 धारा-498ए, 354, 506, 504 भा0द0वि0 व 3/4 द0प्र0अधि0 बनाम संजीव सक्सेना आदि 04 नफर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। प्रतिवादी सिद्धी सक्सेना के द्वारा अपने पति शिवम सक्सेना के विरुद्ध मा0 न्या0 परिवार न्या0 नैनीताल में 125 द0प्र0सं0 के तहत वाद सं0-90/21 दायर किया गया था। दिनांक 29-10-2022 को वादी श्री संजीव सक्सेना के समधी राजेश सक्सेना के द्वारा थाना तल्लीताल, जनपद- नैनीताल, उत्तराखण्ड में मु0अ0सं0-64/22 धारा-420, 468, 471 भा0द0वि0 बनाम संजीव सक्सेना व शिवम सक्सेना के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है। दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं। मुकदमा उपरोक्त में कोई साक्ष्य प्राप्त न होने के कारण अभियोग की विवेचना में दिनांक 30-12-2022 को अन्तिम रिपोर्ट सं0-122/22 किता कर विवेचना समाप्त की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पी0ई0टी0 परीक्षा-2022 के लिए आवेदन का विवरण सदन के पटल पर रखने विषयक

121-श्री महबूब अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने अभ्यर्थियों ने पी0ई0टी0 परीक्षा-2022 के लिए आवेदन किया तथा सरकार को उनसे फीस के रूप मे कितनी

धनराशि प्राप्त हुयी हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET)-2022 हेतु 37,63,444 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया, जिसके सापेक्ष कुल 37,58,209 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किये गये। उक्त परीक्षा में फीस के रूप में कुल रु0 60,91,86, 170.00 (साठ करोड़ इक्यानबे लाख छियासी हजार एक सौ सत्तर रूपये) की धनराशि प्राप्त हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के सम्बन्ध में

122-श्री अनिल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 2018 को सरकार संपन्न कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हॉ। उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मेसर्स टाटा कन्सल्टेंसी के माध्यम से दिनांक 22 व 23/12/2018 को आयोजित सम्मिलित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी (स0क0) एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक (सामान्य चयन) परीक्षा में प्राप्त गम्भीर शिकायतों के दृष्टिगत आयोग द्वारा दिनांक 24-03-2021 को लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त परीक्षा को निरस्त कर दिया गया।

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षा की शुचिता के दृष्टिगत लिये गये निर्णय एवं विषयगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के अनुक्रम में उक्त परीक्षा को यथाशीघ्र कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज, प्रतापगढ़ और लखनऊ के कतिप्रय विद्यालयों द्वारा उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का निर्धारण) अध्यादेश 2018 के विपरीत अभिभावकों से अधिक शुल्क वसूली के के सम्बन्ध में

123-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का निर्धारण) अध्यादेश 2018 लागू है ? यदि हां, तो उक्त का अनुपालन के विपरित जनपद प्रयागराज, प्रतापगढ़ और लखनऊ के कतिपय विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से अधिक शुल्क वसूलने की जानकारी सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वे

कौन-कौन से विद्यालय हैं तथा उक्त विद्यालय के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ एवं लखनऊ से प्राप्त आख्या के अनुसार विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से अधिक शुल्क लेने की शिकायत संज्ञान में नहीं आई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में फसलों के अवशेषों को खेतों में जलाकर निस्तारित करने के विरुद्ध दर्ज अपराधी मुकदमों को वापस लेने के सम्बन्ध में

124-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में धान, गन्ना आदि की फसलों के अवशेषों को किसानों द्वारा खेतों में जलाकर निस्तारित करने पर उनके विरूद्ध दर्ज अपराधी मुकदमों को वापिस लेने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

उक्त प्रकरण से सम्बन्धित कोई मुकदमा विधान सभा, चाँदपुर में पंजीकृत नहीं हुआ है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में चकरोड़ को अवैध कब्जे से मुक्त करने के सम्बन्ध में

125-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में किसानों की चकबन्दी में छूटी चकरोड़ को कतिपय दबंग व्यक्तियों ने काट कर अपने खेत में मिलाकर कब्जा कर लिया है ? क्या सरकार जांच/सर्वे कराकर उक्त अवैध कब्जों को हटवाकर चकरोड़ बनवाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में सरकारी नलकूपों की संख्या, उनकी अवस्था व खराब नलकूपों को ठीक कराकर चालू कराने के सम्बन्ध में

126-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में कितने सरकारी नलकूप हैं एवं उनमें से वर्तमान में कितने नलकूप खराब हैं और कितने चालू अवस्था में हैं ? क्या सरकार खराब नलकूपों को ठीक कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड हल्दौर में 10 राजकीय नलकूप, विकास खण्ड-जलीलपुर में 95 राजकीय नलकूप एवं विकास खण्ड-नूरपुर में 14 राजकीय नलकूप, इस प्रकार कुल 119 राजकीय नलकूप संचालित है।

साप्ताहिक नलकूप बन्दी दिनांक 02-02-2023 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के विकास खण्ड हल्दौर में 01 राजकीय नलकूप एवं जलीलपुर में 03 राजकीय नलकूप, इस प्रकार कुल 04 राजकीय नलकूप यांत्रिक दोष से अस्थायी रूप से खराब एवं 115 राजकीय नलकूप चालू अवस्था में हैं।

राजकीय नलकूपों का विद्युत एवं यांत्रिक दोष से अस्थायी रूप से बन्द होना एवं चालू कराया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। यांत्रिक दोष से बन्द राजकीय नलकूपों को विभागीय मानकों के अनुसार निर्धारित अवधि में ठीक कर सिंचाईरत कर दिया जाता है। विद्युत दोष से अस्थायी रूप से राजकीय नलकूपों को ठीक कराये जाने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर राजकीय नलकूपों को चालू कराये जाने की कार्यवाही की जाती है।

उपर्युक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के थाना कोतवाली चाँदपुर के ग्राम पंचायतों में मार्च, 2022 में एवं अप्रैल-मई, 2022 के मध्य लगे गैंगेस्टर एक्ट का विवरण

127-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के थाना कोतवाली चॉदपुर के अन्तर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों में मार्च, 2022 में एवं अप्रैल, मई, 2022 के मध्य कितने लोगों पर धारा 107, 116, 151 और गैंगेस्टर एक्ट लगायी गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के थाना कोतवाली चाँदपुर के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में मार्च, 2022 में एवं अप्रैल, मई, 2022 के मध्य लोगों पर लगायी गयी धारा 107,116,151, और गैंगेस्टर एक्ट का विवरण निम्नवत् है :-

थाना	अवधि	107/116 व्यक्तियों की संख्या	151 की कार्यवाही में व्यक्तियों की संख्या	गैंगेस्टर एक्ट के व्यक्तियों की संख्या
चाँदपुर	मार्च, 2022	230	26	0
चाँदपुर	अप्रैल, 2022	211	26	0
चाँदपुर	मई, 2022	286	18	0
कुल योग :		**727**	**70**	**0**

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में प्राथमिक विद्यालयों व जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति विषयक

128-श्री स्वामी ओउमवेश

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में प्राथमिक विद्यालयों व जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह

जी हाँ।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर दिनांक 10 अप्रैल, 2023 तक पदोन्नति एवं कार्यमुक्त तथा उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने के लिए दिनांक 29-04-2023 तक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर याचिका संख्या 36240/2015 तपेश्वर राम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया लम्बित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड गौरा के राजस्व ग्राम पंचायत कनेवरा पूरे खुशहाली की गाटा संख्या-848 की सरकारी भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराने विषयक

129-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड गौरा के राजस्व ग्राम पंचायत कनेवरा पूरे खुशहाली की खसरा गाटा संख्या-848 की क्षेत्रफल हेक्टेयर-0.0120 जोकि चकमार्ग के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज पर भू-माफियाओं का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गाटे संख्या की सरकारी भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

ग्राम-कनेवरा पूरे खुशहाली, तहसील-रानीगंज, जनपद-प्रतापगढ़ की गाटा संख्या- 848 क्षे0 0.012हे0 भूमि पर गुलाब चन्द्र पाण्डेय पुत्र अजुग नरायन पाण्डेय द्वारा कच्चा मकान सहन आदि बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है जिसके सम्बन्ध में राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार रानीगंज में बेदखली का वाद विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर अन्तर्गत गाँवों/घरों में पानी की टंकियां ठीक कराकर पानी सप्लाई के सम्बन्ध में

130-श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर अन्तर्गत गाँवों/घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से कतिपय पानी की टंकियां जिनका वर्षों पूर्व निर्माण कार्य पूर्ण कर चालू दिखाया गया है वर्तमान तक चालू नही हो पाई हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त क्षेत्र में ऐसी कौन-कौन सी पानी टंकियां है जो चालू होने के समय से ही खराब है ? क्या सरकार उक्त टंकियों को ठीक कराकर घरों में पानी सप्लाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के 50 राजस्व ग्रामों हेतु निम्नलिखित 31 पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण पूर्ण कराकर संचालन प्रारम्भ कराया गया :-

1-मार्च, 2017 के पूर्व 03 पाइप पेयजल योजनाएं क्रमशः पयागपुर, सोहरियावां एवं सहसलमपुर।

2-वित्तीय वर्ष 2017-18 में 06 पाइप पेयजल योजनाएं क्रमशः पुरैनी, लालपुर जलालपुर, करमुल्लापुर, लौकाही, सिंहपुर एवं बालापुर।

3-वित्तीय वर्ष 2018-19 में 05 पाइप पेयजल योजनाएं क्रमशः गुल्हरिया गाजीपुर, करैला शहबाजपुर, आदिलपुर, लालपुर एवं झूरीकुईयां।

4-वर्ष 2019-20 में क्रमशः देवीदासपुर, बिराहिमपुर, भिल्हौरा, बिबियापारा, इच्छापुर, रायगढ़ बेहड़ा, अलहियापुर, बरूही, बब्बा, भैसहा एवं हुजूरपुर।

5-वित्तीय वर्ष 2020-21 में 07 पाइप पेयजल योजनाएं क्रमशः कटका मरौठा, धरमपुर, गाजीपुर कोड़री, धनपारा, जगता जलालपुर, पूरेजैता एवं लक्खा रामपुर।

उपरोक्त 31 पाइप पेयजल योजनाओं में से 23 पाइप पेयजल योजनाएं सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को हस्तगत की गयीं थी, परन्तु बाद में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण एवं नाली निर्माण होने के कारण पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण 11 पाइप पेयजल योजनाएं क्रमशः बालापुर, सिंहपुर, करमुल्लापुर, बिराहिमपुर भिलौरा, कटका मरौठा, पुरैनी, गुल्हरिया गाजीपुर, बब्बा, करैला शहबाजपुर, लालपुर एवं सहसलमपुर में जलापूर्ति बाधित है।

जी हाँ ।

''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक समस्त कार्य पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के पी. डी. पाण्डेय इण्टर कालेज सोनैसा में प्रवक्ता भूगोल शिव कुमार ओझा के दिनांक 01.07.1992 को तदर्थ प्रधानाचार्य होने एवं पुनः उ0प्र0 मा0शि0 सेवा चयन आयोग से उसी विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर चयनित हो जाने के उपरान्त रिक्त प्रवक्ता भूगोल को प्रवक्ता समाजशास्त्र में बदलकर श्री राकेश कुमार पाण्डेय को स्थाई करने की जांच विषयक

131-श्री अभय सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रथम बार प्रवक्ता पद एवं उसके सापेक्ष विषय का निर्धारण हो जाने के बाद संस्था प्रबन्ध तन्त्र को प्रवक्ता पद के प्रति विषय परिवर्तन का अधिकार शिक्षा निदेशक (मा0)उ0प्र0 के अनुमति के पूर्व है ? यदि नहीं, तो रसूलाबाद, जनपद अयोध्या के पी0डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज सोनैसा में प्रवक्ता भूगोल शिव कुमार ओझा के दिनांक 01-07-1992 को तदर्थ प्रधानाचार्य होने एवं पुनः उ0प्र0मा0शि0 सेवा चयन आयोग से उसी विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर चयनित हो जाने के उपरान्त रिक्त प्रवक्ता भूगोल को किस नियम के अनुसार प्रवक्ता समाजशास्त्र में बदलकर श्री राकेश कुमार पाण्डेय को प्रवक्ता समाजशास्त्र पर स्थाई कर दिया गया है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

प्रबन्धतन्त्र को विषय परिवर्तन का अधिकार नहीं है।

जी हाँ ।

निदेशालय के पत्रांकः सामान्य (1) तृतीय/14286/2022-23 दिनांक 14-02-2023 द्वारा प्रकरण की जाँच कर जाँच उपलब्ध कराये जाने हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, देवीपाटन मण्डल, देवीपाटन को निर्देश दिये गये हैं।

उक्तवत!

जनपद अयोध्या में रसूलाबाद के पी0डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज सोनैसा के प्रबन्धतन्त्र द्वारा ग्राम हैसा परगना अमसिन तहसील सदर के भूमि गाटा सं0 01 (नाला) तथा गाटा सं0-02 (सरकारी स्कूल) की भूमि पर अवैध कब्जा करके विद्यालय संचालित करने के सम्बन्ध में

132-श्री अभय सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को सरकारी भूमि पर भवन निर्माण कराकर विद्यालय संचालन करने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 को मान्यता बनाये रखने हेतु प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या जनपद अयोध्या रसूलाबाद के पी0डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज सोनैसा के प्रबन्धतन्त्र द्वारा ग्राम हैसा परगना अमसिन तहसील सदर के भूमि गाटा सं0 01 (नाला) तथा गाटा सं0 02 (सरकारी स्कूल) की भूमि पर अवैध कब्जा करके विद्यालय संचालित करने पर सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 (डी) तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-13 (क) तथा 13 (ख) के अन्तर्गत उक्त विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के पी0डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज सोनैसा रसूलाबाद में प्रधानाचार्य द्वारा नियम विरुद्ध नियुक्त किये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

133-श्री अभय सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर दिनांक 06-01-2011 के पश्चात् चयन व नियुक्ति किये

जाने पर राजकोष से वेतन भुगतान होने का आदेश शासन स्तर पर निर्गत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या जनपद अयोध्या के पी0डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज सोनैसा रसूलाबाद में प्रधानाचार्य द्वारा नियम विरुद्ध नियुक्त किये गये चतुर्थ श्रेणी कतिपय कर्मियों की नियुक्तियों की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी, नहीं।

जी, हॉ।

निदेशालय के पत्रांक सामान्य (1) तृतीय/14285/2022-23 दिनांक 14-02-2023 द्वारा प्रकरण की जाँच कर जाँच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु मण्डीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, देवीपाटन मण्डल, देवीपाटन को निर्देश दिये गये हैं।

उक्तवत ।

पी0डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज सोनैसा पो0 रसूलाबाद अयोध्या में माह सितम्बर, 2005 के पूर्व नियुक्त/कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सम्बद्ध प्राइमरी के शिक्षकों को बिना प्रशिक्षण के भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

134-श्री अभय सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी में शिक्षकों की नियुक्ति में प्रशिक्षण से मुक्त होने का नियम माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 या अन्य सम्बन्धित अधिनियमों में प्रख्यापित रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि पी0डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज सोनैसा, पो0 रसूलाबाद अयोध्या में माह सितम्बर, 2005 के पूर्व नियुक्त कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सम्बद्ध प्राइमरी के शिक्षकों को बिना प्रशिक्षण के भुगतान देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ ।

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी में शिक्षकों की नियुक्ति में प्रशिक्षण से मुक्ति का प्राविधान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 में नहीं है, अपितु शासनादेश संख्या-1747/79-6-03-22(17)/02 दिनांक 09 दिसम्बर, 2003 द्वारा दिनांक 31-12-2003 को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा सेवा 02 वर्ष शेष रहने वाले अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी थी ।

इस सम्बन्ध में मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, देवीपाटन मण्डल से जाँच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

135-श्री मौहम्मद फहीम-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद अयोध्या स्थित तहसील मिल्कीपुर में संचालित राजकीय बालिका विद्यालय टकसरा में अध्यापकों की नियुक्ति विषयों व छात्रों की संख्या विषयक

136-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या स्थित तहसील मिल्कीपुर में संचालित राजकीय बालिका विद्यालय टकसरा में कितने अध्यापकों की नियुक्ति हुयी है और विद्यालय में किन-किन विषयों की पढ़ाई हो रही है तथा छात्रों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

राजकीय बालिका विद्यालय टकसरा में प्रवक्ता-6, सहायक अध्यापक-02, कुल-08 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है।

विद्यालय में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान विषय के प्रवक्ता कार्यरत हैं तथा भूगोल, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र प्रवक्ता का पद रिक्त है एवं समाजिक विज्ञान तथा संस्कृत के सहायक अध्यापक तैनात हैं तथा हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा वाणिज्य के पद रिक्त हैं।

260

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर वीरांगना ऊदा देवी पासी के सम्मान में विश्वविद्यालय अथवा मेडिकल कालेज बनाने की मांग

137-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में आजादी के सिलसिले देश में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के महान पावन पर्व के सुअवसर पर सरकार वीरांगना ऊदा देवी पासी के सम्मान में कोई शिक्षण संस्थान (विश्वविद्यालय अथवा मेडिकल कालेज) बनाने की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

वर्तमान में वीरांगना ऊदा देवी पासी के सम्मान में कोई विश्वविद्यालय अथवा मेडिकल कालेज/मेडिकल शिक्षण संस्थान बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पेयजल की समस्या के निवारण हेतु जनपदों में इंडिया मार्क-2 हैन्डपम्प लगवाने की मांग

138-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पेयजल की समस्या के निवारण हेतु जनपदों में इंडिया मार्क-2 हैन्डपम्प लगवाने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर नल से जल योजना संचालित है। पंचायतीराज विभाग द्वारा पूर्व में लगाये गए हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रि-बोर का कार्य कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अयोध्या स्थित ईटगांव थाना इनायब नगर के निवासी मृतक बालक राम कोरी के परिवार को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में

139-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या स्थित ईटगांव थाना इनायत नगर के निवासी बालक राम कोरी आयु 38 वर्ष की थी, दिनांक 20-08-22 को आवारा सांड़ के मारने से मृत्यु हो गयी ? क्या सरकार मृतक परिवार को 5 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी हाँ।

मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत मृतक बालक राम की पत्नी द्वारा प्रस्तुत दावा जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। दावाकर्ता के बैंक खाते में स्वीकृत धनराशि 5 लाख रुपये अन्तरित कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अयोध्या सहित पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को राहत राशि देने की मांग

140-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष में जनपद अयोध्या सहित प्रदेश में वर्षा कम होने के कारण किसान अपने खेतो में धान की रोपाई नही कर पाये हैं ? यदि हां,

तो क्या सरकार जनपद अयोध्या सहित पूरे प्रदेश को सूखा घोषित कर किसानों को राहत राशि देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में मानसून 2022-23 में (15 जून से 30 सितम्बर) 72 प्रतिशत वर्षा दर्ज की गयी है। प्रदेश का बड़ा क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्र होने के कारण कम वर्षा का बुआई पर प्रभाव नहीं पड़ा । कृषि विभाग की सूचना के अनुसार दिनांक 31-8-2022 तक धान की रोपाई 97.93 प्रतिशत रही है। प्रदेश में 15 जून से 15 अक्टूबर तक 678.9 मिमी वर्षा रही जो कि प्रदेश की औसत वर्षा का 88.34 प्रतिशत है।

जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार (जनपद अयोध्या सहित) प्रदेश में कम वर्षा के कारण फसलों में 33% या उससे अधिक फसल क्षति नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के सूखा मैनुअल 2016 में उल्लिखित मानकों के अनुसार वर्ष 2022 में जनपद अयोध्या सहित प्रदेश का कोई भी जनपद सूखा की श्रेणी में नहीं है।

141-[प्रश्न हटाया गया]

जनपद फिरोजाबाद में हैंडपंप री-बोर कराये के सम्बन्ध में

142-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में कितने हैण्डपम्प रि-बोर किये जाने है ? क्या सरकार उक्त हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने हेतु कोई कार्यवाही कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद-फिरोजाबाद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक कुल 2227 हैण्डपम्प रि-बोर कराये गये हैं। हैण्डपम्प का खराब होना व रि-बोर कराना एक सतत् प्रक्रिया है, जो लगातार चलती रहती है। ग्रामवासियों की मांग पर ग्राम पंचायतों द्वारा हैण्डपम्पों के रि-बोर की कार्यवाही प्राथमिकता तय करते हुए बजट की उपलब्धता के आधार पर करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में नामांकन विहीन बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन कराने के सम्बन्ध में

143-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में प्रवेश हेतु योग्य कितने बच्चे वर्तमान में विद्यालयों में नामांकन विहीन हैं ? क्या सरकार नामांकन

विहीन बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन परिषदीय विद्यालयों में कराने की योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

विद्यालयों में प्रवेश हेतु योग्य, किन्तु नामांकन विहीन आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन/नामांकन हेतु वर्ष 2022-23 में किये गये हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के लगभग 3.33 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल पाये गये, जिन्हें निकटतम विद्यालयों में आयुसंगत कक्षाओं में नामांकित कराने का कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश के समस्त 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कराने हेतु विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर 'स्कूल चलो अभियान' तथा शारदा कार्यक्रम के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 6-14 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों को चिन्हांकित कर उन्हें विद्यालयों में आयुसंगत कक्षाओं में नामांकित कराया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना की चकबन्दी प्रक्रिया में की गई लापरवाही की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

144-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के अन्तर्गत बुढ़ाना बांगर दक्षिण में चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान उक्त ग्राम के किसानों की 15 हेक्टेयर भूमि कम पड़ जाने के कारण चकबन्दी विभाग द्वारा चौगामा नहर परियोजना के अन्तर्गत नहर की भूमि आवंटित कर दी गयी है ? क्या सरकार चकबन्दी प्रक्रिया में की गई लापरवाही एवं त्रुटिपूर्ण कार्य की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जीं, नहीं।

ग्राम में प्रचलित चकबन्दी योजना में कृषकों द्वारा सिंचाई की सुविधा हेतु नहर की मांग की गयी। इस सम्बन्ध में दिनांक 30.04.2003 को उप संचालक चकबन्दी, मुजफ्फरनगर व अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग व अवर अभियन्ता सिंचाई विभाग व कृषकों के मध्य यह निर्णय लिया गया कि चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान कृषकों की सिंचाई की सुविधा हेतु नहर हेतु भूमि दी जायेगी । कृषकों की भूमि पर बनाये जाने वाली नहर में जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल/मालियत की पूर्ति चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान कृषकों से होने वाली कटौती/बचत भूमि/ग्राम समाज भूमि से की जायेगी ।

प्रस्तावित चकबन्दी योजना निर्मित करते समय कुल 3.25 प्रतिशत की कटौती करते हुए सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा कुल 81 गाटों में क्षेत्रफल 15.1969 हे0 भूमि नहर हेतु आवंटित कर दी गयी। जिन कृषकों की मूल जोत की भूमि नहर के नाम आवंटित की गयी उन कृषकों को उनकी भूमि की मालियत के सापेक्ष चक प्रदिष्ट कर दिये गये।

चकबन्दी विभाग द्वारा सिंचाई विभाग अथवा चौगामा नहर की कोई भूमि कृषकों को आवंटित नहीं की गयी है तथा ऐसा किये जाने की भविष्य में भी कोई सम्भावना नही है।

चूंकि चौगामा नहर अथवा सिंचाई विभाग की कोई भूमि किसी भी कृषक को आवंटित करने का कोई प्रकरण प्रकाश में नही आया है, इसलिए किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक अथवा अपेक्षित नही है ।

प्रश्न ही नही उठता है।

उपरोक्तानुसार।

145-श्री राजपाल बालियान-

[03-बुधवार के अतारांकित प्र0 सं0-211 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अयोध्या मण्डल में विद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से नियम विरुद्ध विनियमितीकरण/स्थायीकरण करने वाले संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मण्डल की जांच स्तर के सम्बन्ध में

146-श्री अभय सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 17 जुलाई, 1992 से अध्यापक पद पर अल्पकालिक तथा तदर्थ रूप से चयन करने की व्यवस्था किस प्रकार की गई थी ? क्या सरकार बतायेगी कि अयोध्या मण्डल में विद्यालय प्रबन्धतन्त्रों द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से दिनांक 07 अगस्त, 1993 से 30 दिसम्बर, 2000 तक चयनित एवं नियुक्त तथा मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम/अन्तिम आदेश से वेतन प्राप्त करने वाले तदर्थ अध्यापक स्थापित विधि व्यवस्था के अनुसार चयनित व नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण में नियम विरुद्ध रूप से विनियमितीकरण/स्थायीकरण करने वाले संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मण्डल के विरुद्ध शासन स्तर पर जांच समिति गठित कर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ ।

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम-1982 (यथासंशोधित) 1992 के प्रवृत्त होने की तिथि 14-07-1992 से रिक्त पदों के सापेक्ष तदर्थ आधार पर नियुक्ति करने का अधिकार जनपद स्तर पर गठित समिति को प्रदान किये गये। अल्पकालिक रिक्ति के सापेक्ष नियुक्ति का अधिकार प्रबन्धतंत्र में निहित रहा, जिन्हें चयन बोर्ड अधिनियम की धारा-16 एवं धारा-33 (ड), जो दिनांक 30-12-2000 से प्रवृत्त माना गया, समस्त नियुक्तियाँ चयन बोर्ड के माध्यम से कराये जाने का प्राविधान किया गया।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या को जाँच अधिकारी नामित करते हुए जाँच के निर्देश दिये गये हैं।

उक्तवत्।

जाँच गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में महिला माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने विषयक

147-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में महिला माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद कौशाम्बी की आख्यानुसार जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में राजकीय बालिका इण्टर कालेज सिराथू, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, कड़ा, पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माडल इण्टर कालेज केसारी, राजकीय हाई स्कूल अफजलपुरवारी, राजकीय हाई स्कूल कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय कशिया तथा राजकीय हाई स्कूल राला, कौशाम्बी अवस्थित हैं।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

148-श्री पंकज पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत कुल कितनी सड़कें स्वीकृत हुई है तथा

वर्तमान में उक्त सड़कों के निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण देते हुए सड़कों का निर्माण निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कुल 04 सड़कें स्वीकृत हैं, जिसमें 03 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका हैं तथा 01 सड़क पर निर्माण कार्य प्रगति में है।

वित्तीय वर्ष	पैकेज सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)	कार्य पूर्ण करने की तिथि
2020-21	यूपी 37101	टी02, बी0जे0 किमी0 8 निभापुर से उचौरा	5.70	13-05-2022
2020-21	यूपी 37128	मुंगराबादशाहपुर से बेलवार मुंगराबादशाहपुर बेलवार रोड	7.00	21-10-2022
2020-21	यूपी 37129	मुंगराबादशाहपुर बेलवार रोड किमी0 13 से भीलमपुर	5.00	21-05-2022
2020-21	यूपी 37144	टी02, ए0जी0 किमी0 57 रायपुर से पवारा रोड वाया सेमरिया	6.60	कार्य पूर्ण करने की तिथि 22-04-2023 है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के विभिन्न ग्राम सभाओं के मजरों में स्थापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को ठीक कराने विषयक

149-श्री पंकज-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के विभिन्न ग्राम सभाओं के मजरों में स्थापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों में से ग्राम सभावार खराब हैण्डपम्पों को चिन्हित कर ठीक कराकर सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र, मुंगराबादशाहपुर के विभिन्न ग्राम सभाओं के मजरों में स्थापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों में से ग्राम सभावार खराब हैण्डपम्पों को चिन्हित

कर ठीक करा दिया गया हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	विधान सभा में बादशाहपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड का नाम	वि0ख0 के अन्तर्गत ग्रा0प0 में स्थापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की संख्या	स्थापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों में से खराब हैण्डपम्पों की संख्या	ठीक कराये गये पम्पों की संख्या	अवशेष हैण्डपम्पों की संख्या
1	मुंगराबादशाहपुर	9802	2753	2753	0
2	सुजानगंज	6860	1328	1328	0
3	मछलीशहर	1512	500	500	0

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के ग्राम सभा हाजीपुर एवं आराजी देवारा करखिया में चकों का रकबा मूल चकों से बढ़ा देने की जांच कराने विषयक

150-डॉ0 हृदय नारायण पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के ग्राम सभा हाजीपुर एवं आराजी देवारा करखिया में कुछ लोगों के द्वारा चकबन्दी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलकर चकों का रकबा मूल चकों से बढ़ा देने के उपरान्त जांच होने पर 70 प्रतिशत मामले फर्जी बढ़ोत्तरी पाये जाने के कारण 1989 ई0 चकबन्दी प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है तथा हाजीपुर में सन 1983-84 व आराजी देवारा करखिया में 1984-85 में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हुई जो अभी तक पूर्ण न होने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चकबन्दी कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम हाजीपुर में प्रस्तावित चकबन्दी योजना का जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 12-03-1989 को हुआ था। तत्पश्चात् अभिलेखों की जांच में अनियमिततायें पाये जाने के कारण चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 19-11-1990 द्वारा प्रस्तावित चकबन्दी योजना को निरस्त कर इस ग्राम को सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर पुनः चक निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था। अद्यतन ग्राम का चक सृजन कार्य पूर्ण हो गया है। ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया निरस्त नहीं की गयी है।

ग्राम आराजी देवारा करखिया के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चकबन्दी प्रक्रिया को लेकर ग्रामवासियों के प्रबल विरोध के कारण वर्ष 1993 से चकबन्दी प्रक्रिया अवरुद्ध थी। दिनांक 26-12-2019 को ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने विषयक बैठक की गयी, जिसमें ग्रामवासियों द्वारा मांग की गयी कि ग्राम का विनिमय अनुपात (मालियत) लगभग 32 वर्ष पूर्व का होने के कारण स्थल पर हुये भौतिक परिवर्तन के दृष्टिगत पुनः विनिमय अनुपात

निर्धारित कर चक सृजन की कार्यवाही की जाय। तत्क्रम में जोत चकबन्दी आकार पत्र-2क तैयार किया जा रहा है। ग्राम आराजी देवारा करखिया की चकबन्दी प्रक्रिया निरस्त नहीं की गयी है।

जी हां।

जी हां।

दोनों ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया कार्य योजना के अनुसार आगे बढ़ायी जा रही है। उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम कम्पोजिट करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

151-डॉ0 रागिनी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी जौनपुर को सम्बोधित जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम कम्पोजिट स्कूल करने विषयक पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम कम्पोजिट स्कूल करने एवं कतिपय अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक जिलाधिकारी, जौनपुर को सम्बोधित एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर को पृष्ठांकित मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 12-08-2022 में वांछित सूचनायें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर के पत्र दिनांक 15-02-2023 द्वारा मा0 सदस्य को उपलब्ध करा दी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत नहर सफाई हेतु योजना बनाने विषयक

152-डॉ0 रागिनी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत नहर सफाई हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? क्या सरकार समय सीमा अन्तर्गत नहर सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

विवरण संलग्न[†] है।

समय-सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के ग्राम सैदपुर बुजुर्ग तहसील बहेड़ी के गाटा संख्या-182 के विक्रय पत्र को संशोधित करने के संम्बध में

153-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के जिलाधिकारी बरेली द्वारा ग्राम सैदपुर बुजुर्ग तहसील बहेड़ी की गाटा सं0 154, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 176, 182, 199 एवं 200 का विक्रय पत्र दिनांक 16 मई, 2015 को जारी किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त गाटों में से गाटा सं0-182 को उपजिलाधिकारी बहेड़ी, जिला बरेली द्वारा मु0सं0 टी 2017121311052877 में अपने आदेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 द्वारा ग्राम सभा में सम्मिलित कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त आदेश के कारण गाटा संख्या 182 के विक्रय पत्र के मूल्याकंन पर प्रभाव पड़ेगा ? यदि हाँ, तो क्या उक्त गाटा संख्या 182 के विक्रय पत्र को संशोधित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी हाँ।

उक्त आदेश दिनांक 14-12-2017 के विरुद्ध योजित निगरानी में राजस्व परिषद् द्वारा दिनांक 30-01-2018 को आदेश पारित करते हुए उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किया गया है। वर्तमान में गाटा संख्या-182 के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् के समक्ष वाद विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के जे0 पी0 एन0 इण्टर कालेज को राजकीय इण्टर कालेज के रूप में संचालित कराने विषयक

154-डा0 एम0 पी0 आर्य-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के जे0 पी0 एन0 इण्टर कालेज को राजकीय इण्टर कालेज के रूप में संचालित कराये जाने की सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ सं0-341-342 पर

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

शासनादेश संख्या-106/15-8-2020-3001 (3)/2019, दिनांक 27 फरवरी, 2020 से जे0 पी0 एन0 इण्टर कालेज नवाबगंज बरेली आच्छादित नहीं है।

प्रदेश में मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से गम्भीर बीमारियों के इलाज हेतु गरीबों के लिए एक वित्तीय वर्ष में सहायता धनराशि के सम्बन्ध में

155-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से गम्भीर बीमारियों के इलाज हेतु गरीबों के लिए एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार एवं कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की जाती है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि सहायता राशि प्राप्त होने में विलम्ब के कारण इलाज न होने से कभी-कभी मरीज की हालत गम्भीर हो जाती है अथवा मृत्यु भी हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सहायता राशि कम से कम समय में दिलाये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली, 1999 (यथासंशोधित) के अनुसार विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता/अनुदान विवेकानुसार दिए जाने की व्यवस्था है।

जनपद मुजफ्फरनगर व शामली सहित प्रदेश के निजी माध्यमिक विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश के सम्बन्ध में

156-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर व शामली सहित प्रदेश के निजी माध्यमिक विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश हेतु आरक्षण देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

प्रदेश के निजी माध्यमिक विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

प्रदेश में राजकीय शिक्षक संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष तथा महामंत्री एवं संगठन का कार्यकाल के सम्बन्ध में

157-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय शिक्षक संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष तथा महामंत्री एवं संगठन का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित है क्या सरकार

बतायेगी कि वर्तमान में कार्यरत संगठन का कार्यकाल किस वर्ष गठित किया गया है ? क्या सरकार उक्त संगठन के वर्तमान प्रान्तीय अध्यक्ष तथा महामंत्री का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

02 वर्ष

वर्तमान में राजकीय शिक्षक संघ का कोई संगठन वैधानिक रूप से अस्तित्व में नहीं है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

158-श्री पंकज कुमार मालिक-

[02-बुधवार को अतारांकित प्रश्न संख्या-201 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों को 12वीं शासी निकाय में अनुमोदित मॉडल मानव संसाधन (एच0आर0) पॉलिसी का लाभ दिलाने विषयक

159-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों को 12वीं शासी निकाय में अनुमोदित मॉडल मानव संसाधन (एच0आर0) पॉलिसी का लाभ सरकार दिलाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 12वीं शासी निकाय में अनुमोदित मानव संसाधन नियमावली के अनुसार ही सेवाप्रदाता कर्मियों को मानदेय, अवकाश, एफ0एल0टी0ए0 आदि की सुविधा दी जा रही है। मानव संसाधन नियमावली में वार्षिक इन्क्रीमेंट दिये जाने का प्रावधान केवल थीमेटिक एक्सपर्ट हेतु अनुमन्य किया गया था। वर्तमान में थीमेटिक एक्सपर्ट पद नाम से कोई मिशन कर्मी मिशन में कार्यरत नहीं है। मिशन के संविदा कार्मिकों को वार्षिक वेतनवृद्धि दिये जाने का वित्तीय नियमों में प्राविधान नहीं है। अतः मिशन के कार्मिकों को वार्षिक वेतनवृद्धि दिया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या स्थित तहसील मिल्कीपुर के परसवा ग्राम में संचालित राजकीय बालिका महाविद्यालय के सम्बन्ध में

160-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या स्थित तहसील मिल्कीपुर के परसवा ग्राम में संचालित राजकीय बालिका महाविद्यालय में कितने अध्यापक

नियुक्त हैं तथा इनकी नियुक्ति किस आधार पर हुयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त महाविद्यालय में किन विषयों की पढ़ाई हो रही है तथा छात्रों की संख्या क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

अवगत कराना है कि जनपद अयोध्या स्थित तहसील मिल्कीपुर के परसवां ग्राम में राजकीय महिला महाविद्यालय, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत संघटक महाविद्यालय के रूप में संचालित है, जिसमें वर्तमान में संविदान्तर्गत 03 शिक्षक नियुक्त हैं।

उक्त महाविद्यालय में वर्तमान में 08 विषय यथा हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, अंग्रेजी, समाजशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र की पढ़ाई हो रही है तथा कुल छात्रों की संख्या-59 है।

विवरण उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

161-श्री चंदन चौहान-

[03-बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-208 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बिजनौर के विद्यालयों में अध्यापक व छात्र का मानक पूर्ण करने की विषयक कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में

162-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति अध्यापक व छात्रों की संख्या का निर्धारित मानक क्या है ? क्या सरकार ने उक्त विद्यालयों में अध्यापक व छात्र का मानक पूर्ण करने की कोई योजना बनायी है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्राविधानानुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35:1 निर्धारित है।

(1) जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 578 अध्यापकों एवं 286 शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 22:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है।

(2) जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 261 अध्यापकों एवं 43 अनुदेशकों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के नारखी ब्लाक एवं टूण्डला ब्लाक डार्क जोन/अतिदोहित श्रेणी में जल परियोजना बना कर पयेजल आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में

163-श्री मनीष असीजा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के नारखी ब्लाक एवं टूण्डला ब्लाक डार्क जोन/अतिदोहित श्रेणी में आते हैं ? क्या सरकार अवगत है कि उक्त ब्लाकों के भू-गर्भ जल में अत्यंत हानिकारक फ्लोराइड पाया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कारणों से पीने के पानी की परेशानी का सामना करने को मजबूर क्षेत्रीय नागरिकों की उक्त समस्या के समाधान हेतु सतही जल परियोजना बना कर पयेजल आपूर्ति करायेगी यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित भू-जल संसाधन आंकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार जनपद- फिरोजाबाद के नारखी ब्लाक एवं टूण्डला ब्लाक अतिदोहित श्रेणी (डार्क जोन)में वर्गीकृत किये गये हैं।

जी हाँ।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सतही जल आधारित परियोजनाओं का निर्माण कर पेयजल आपूर्ति करायी जायेगी ।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सतही जल आधारित परियोजनाओं का निर्माण कर पेयजल की आपूर्ति वर्ष 2024 तक कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बस्ती स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन करवाने के सम्बन्ध में

164-श्री महेंद्र नाथ यादव-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन निर्धारित समय अवधि के बीत जाने के बाद भी आरम्भ नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

जी हाँ। भूमि का आंशिक भाग विवादित होने के कारण निर्माण बाधित रहा था।

जी हाँ।

परियोजना निर्माणाधीन है। निर्माण का कार्य अतिशीघ्रपूर्ण होने पर कालेज संचालित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

165-श्री उमर अली खान-

[दिनांक 24-02-2023 को उत्तरित]

कानपुर नगर के तहसील सदर में ग्राम हाजीपुर पोस्ट भारू ब्लाक बिधनू की अराजी संख्या 137 चारागाह की भूमि भू-माफियाओं से मुक्त कराने विषयक

166-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के तहसील कानपुर सदर में ग्राम हाजीपुर पोस्ट भारू ब्लाक बिधनू की अराजी संख्या 137 चारागाह की भूमि पर भू-माफियाओं का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को चिन्हित करके भू-माफियाओं से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के सदर तहसील में विकास कार्यों को गति प्रदान करने हेतु निर्माणाधीन नई तहसील का कार्य प्रारम्भ कराने विषयक

167-श्री जै किशन साहू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के सदर तहसील में विकास कार्यों को गति प्रदान करने हेतु निर्माणाधीन नई तहसील का कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त तहसील के रुके हुए निर्माणाधीन कार्यों को प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

तहसील सदर गाजीपुर के नवीन अनावासीय व आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु मानकीकृत लागत क्रमशः रु0 340.26 लाख व रु0 264.23 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को अवमुक्त की जा चुकी है।

जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्वीकृत धनराशि से माह जनवरी, 2018 में कार्य प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में जी0एस0टी0 लागू होने के कारण एवं सामग्री की दरों में वृद्धि होने की स्थिति में कार्य आवंटित धनराशि से पूर्ण न होने के दशा में रुका हुआ है।

उक्त पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2023 में उल्लिखित है कि तहसील के अनावासीय व आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच त्रिस्तरीय कमेटी द्वारा करायी जा रही है। कमेटी द्वारा कार्यदायी संस्था यू0 पी0 आर0 एन0एन0 से अभिलेख जाँच हेतु माँगा जा रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा अभी अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया है। इस प्रकार पूर्व में कराये गये कार्यों की जाँच करायी जा रही है। जाँच प्रचलित है। जाँच पूर्ण होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद फिरोजाबाद के तहसील जसराना में चार बड़ी नहरों में होने वाली दुर्घटनाओं में जनमानस के बचाव हेतु स्थाई रूप से गोताखोरों की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में

168-श्री सचिन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के तहसील जसराना में चार बड़ी नहरों में होने वाली दुर्घटनाओं में जनमानस के बचाव हेतु स्थाई रूप से गोताखोरों की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद फिरोजाबाद के तहसील जसराना में चार बड़ी नहरों में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए स्थाई गोताखोर उपलब्ध नही है। स्थाई गोताखोर नियुक्त करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। इन नहरों में होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए स्थानीय गोताखोरों एवं पी0ए0सी0 पुलिस बल की फ्लड कम्पनी की मदद से बचाव एवं राहत कार्य किया जाता है।

169-श्री सचिन यादव-

[दिनांक 27-02-2023 को उत्तरित]

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में हर घर नल योजना के अन्तर्गत कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में

170-श्री सचिन यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में हर घर नल योजना के अन्तर्गत कार्यों को पूर्ण करने की तय समय सीमा क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान में इन कार्यों की प्रगति की क्या स्थिति है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजनाओं से वर्ष 2024 तक आच्छादित किया जाना है। उक्त के क्रम में जनपद फिरोजाबाद के समस्त ग्रामों को वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

जनपद फिरोजाबाद के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत पेयजल योजना के डी0पी0आर0 तैयार करा लिए गए हैं। सम्प्रति उनके अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अमृत सरोवर का विवरण सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

171-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने अमृत सरोवर दिनांक 30-11-2022 तक पूर्ण रूप से बनाए जा चुके हैं एवं कितने अमृत सरोवरों का निर्माण अधूरा है तथा कितने अमृत सरोवर के कार्य का भुगतान अवशेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

अमृत सरोवर पोर्टल पर प्रदर्शित रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30-11-2022 तक कुल 8558 अमृत सरोवर पूर्ण रूप से बनाये जा चुके हैं एवं कुल 7251 अमृत सरोवर का निर्माण अधूरा है तथा मनरेगा वेबसाइट पर दिनांक 30-11-2022 को प्रदर्शित रिपोर्ट के अनुसार कुल 12922 अमृत सरोवर के कार्य का भुगतान अवशेष है, जिसमें श्रमांश का भुगतान किया जा चुका है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक व जूनियर स्तर के विद्यालयों को निश्चित अवधि में मान्यता दिलाने जाने विषयक

172-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक व जूनियर स्तर की मान्यता हेतु कितने विद्यालयों के प्रार्थना-पत्र विभिन्न जिलों में वर्तमान में लम्बित हैं ? क्या सरकार मानक पूर्ण करने वाले विद्यालयों को किसी निश्चित अवधि में मान्यता दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

प्रदेश में प्राथमिक व जूनियर स्तर की मान्यता हेतु 559 आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

शासनादेश संख्या-64/अड़सठ-3-2021-840/2020, दिनांक 11-02-2021 द्वारा पूर्व में ही समयावधि निर्धारित की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

173-[प्रश्न हटाया गया]

जनपद गोण्डा विकास खण्ड कटरा बाजार में क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित कराये गये सामुदायिक शौचालयों की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

174-श्री बावन सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा विकास खण्ड कटरा बाजार में क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्मित कराये गये सामुदायिक शौचालयों की जांच विषयक उपनिदेशक (पं0) देवीपाटन मण्डल गोण्डा के पत्रांक-917/30नि0पं/जांच/2022-23, दिनांक 24 दिसम्बर, 2022 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड कटरा बाजार जनपद गोण्ड को आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

शिकायतों की दो सदस्यीय जांच कमेटी [उप निदेशक (पं0), देवीपाटन मण्डल, गोण्डा एवं अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-2, जनपद गोण्डा] द्वारा जांच की गयी है। जांच में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु जांच आख्या आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा को प्रस्तुत कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शत-प्रतिशत ग्रामों में बारात घर बनाने की कार्य योजना विषयक

175-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने ग्रामों में बारात घर स्थापित हैं ? क्या प्रदेश के शत-प्रतिशत ग्रामों में बारात घर बनाने हेतु सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान में पंचायती राज विभाग में बारात घर निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों, कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की तर्ज पर विद्यार्थियों की भी बायोमेट्रिक उपस्थिति की योजना के सम्बन्ध में

176-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों, कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की तर्ज पर विद्यार्थियों की भी बायोमेट्रिक उपस्थिति की योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था की गयी है। विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति की योजना बनायी जायेगी।

उक्तानुसार।

पी0डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज सोनैसा पोस्ट रसूलाबाद जनपद अयोध्या के मान्यता प्रत्याहरण कार्यवाही पूर्ण करने विषयक

177-श्री अभय सिंह-

द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-112 के उत्तर के क्रम में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज सोनैसा, पोस्ट रसूलाबाद, जनपद अयोध्या के मान्यता प्रत्याहरण कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा-16 (डी) तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-13 (क) तथा 13 (ख) के अन्तर्गत उक्त विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षकों के विनियमितीकरण की जांच विषयक

178-श्री अभय सिंह-

द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न-113 के उत्तर के क्रम में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक दिनांक 14-09-22 द्वारा शिक्षकों के विनियमितीकरण की जांच सम्बन्धी प्रकरण में जांच पूर्ण

कर ली गई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

उक्तवत्।

जाँच की कार्यवाही गतिमान है।

पी0 डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज सोनैसा, रसूलाबाद, अयोध्या के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

179-श्री अभय सिंह-

द्वितीय सत्र 2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न-112 के उत्तर के क्रम में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् प्रयागराज उ0प्र0 के किस-किस विनियमों के अनुसार पी0 डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज सोनैसा, रसूलाबाद, अयोध्या के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा-16(डी) तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-13(क) तथा 13(ख) के अन्तर्गत उक्त विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

संयुक्त शिक्षा निदेशक, अयोध्या द्वारा नियम विरुद्ध किये गये 69 तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की जांच

180-श्री अभय सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न 85 तथा 86 के उत्तर के क्रम में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त शिक्षा निदेशक, अयोध्या मण्डल द्वारा वर्ष 2021-22 में विनियमित किये गये 69 तदर्थ शिक्षक, उ0प्र0 मा0 शिक्षा से आ0 (कठिनाइयों का निवारण) आदेश 1981 अथवा उ0प्र0 मा0 सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा-18 के अनुसार नियुक्त नहीं है जो केवल मा0 न्यायालय के अन्तरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे है को तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या द्वारा नियम विरुद्ध रूप से विनियमित करने सम्बन्धी प्रकरण सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया के गड़वार थाना अन्तर्गत ग्राम बहादुरपुर कारी में सरकारी जमीन पर कब्जा रोकने गई पुलिस टीम पर हुए हमले की जांच

181-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के गड़वार थाना अन्तर्गत ग्राम बहादुरपुर कारी में सरकारी जमीन पर कब्जा रोकने गई पुलिस टीम पर 31 अक्टूबर, 2022 को हुए हमले की घटना सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो उक्त घटना की जांच से सम्बन्धित प्रमुख तथ्य सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

दिनांक 30-10-2022 को ग्राम बहादुरपुर कारी थाना गड़वार, जनपद-बलिया स्थित ग्राम समाज की भूमि पर वर्तमान ग्राम प्रधान सहित अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हनुमान जी की मूर्ति रखकर बिना किसी परमीशन के अवैध रूप से ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किये जाने का प्रयास किया गया, जिस पर उसी गाँव के कुछ लोगों को आवासीय पट्टा हुए हैं। पट्टाधारकों द्वारा मूर्ति रखे जाने का विरोध किया जा रहा था। सूचना के आधार पर थाना गड़वार की पुलिस मौके पर पहुँची, जिस पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना गड़वार पर मु0अ0सं0-346/2022 धारा-147/148/149/323/504/506/427/188/324/332/333/336/186/353/30/120 भादवि व 2/3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 7 सीएलए ऐक्ट विरुद्ध 36 नामजद अभियुक्तों सहित 30-40 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। नामजद अभियुक्तों में से दिनांक 31-10-2022 को 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा 10 नामजद अभियुक्त मा0 न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर वाया मा0 न्यायालय जेल भेजे गये थे। अभियोग की विवेचना अपराध शाखा, जनपद-बलिया द्वारा सम्पादित की जा रही है। अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य संकलन व गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद वाराणसी के लक्सा थाने में तैनात दरोगा को गोली मारकर सरकारी पिस्टल छीनने सम्बन्धी घटना पर कृत कार्रवाई की जानकारी

182-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 08 नवम्बर, 2022 को जनपद वाराणसी के लक्सा थाने में तैनात दरोगा को गोली मारकर सरकारी पिस्टल छीनने के प्रकरण

की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटना से जुड़े प्रमुख तथ्यों तथा की गई कार्रवाई का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

उ0नि0ना0पु0 अजय कुमार यादव, जो थाना लक्सा, कमिश्नरेट वाराणसी में तैनात थे, दिनांक 08-11-2022 को सायंकालीन अपने नवनिर्मित मकान मनियारीपुर थाना-रोहनियां, कमिश्नरेट वाराणसी पर जा रहे थे कि मोटर साईकिल पर सवार 03 अज्ञात बदमाशों ने उ0नि0ना0पु0 अजय कुमार यादव को गोली मारकर उनकी सरकारी पिस्टल, कारतूस व अन्य सामान छीन लिया। इस सम्बन्ध में उ0नि0ना0पु0 अजय कुमार यादव द्वारा थाना रोहनियां कमिश्नरेट वाराणसी पर मु0अ0सं0-404/22 धारा-394/307 भादवि पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त मुकदमें के अनावरण व सरकारी पिस्टल की बरामदगी हेतु पुलिस आयुक्त, वाराणसी द्वारा एस0आई0टी0 का गठन करते हुए सर्विलांस प्रभारी क्राइम ब्रान्च एवं अन्य पुलिस टीमों को निर्देशित किया गया तथा विवेचना सी0सी0टी0वी0 फुटेज व सर्विलांस के सहयोग से यह तथ्य प्रकाश में आया कि बिहार जेल से न्यायिक हिरासत से फरार अभियुक्त रजनीश सिंह, मनीष सिंह व लल्लन सिंह पुत्रगण शिवशंकर सिंह, निवासी ग्राम आनन्द गोलवा, थाना-मोहीउद्दीन नगर जनपद समस्तीपुर, बिहार द्वारा घटना कारित किया गया है ।

दिनांक 21-11-2022 को पुलिस बल द्वारा अभियुक्त लल्लन सिंह, मनीष सिंह व रजनीश सिंह को गिरफ्तार करने हेतु घेराबन्दी की गयी। पुलिस बल को देखकर अभियुक्त उपरोक्त ने अपने गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस बल के ऊपर फायर किया। पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गयी, जिसमें अभियुक्त मनीष सिंह व रजनीश उपरोक्त घायल हो गये तथा मौके से अभियुक्त लल्लन सिंह फरार हो गया। घायल अभियुक्त मनीष सिंह व रजनीश सिंह को उपचार हेतु पंडित दीन दयाल उपाध्याय, राजकीय अस्पताल वाराणसी में भेजा गया। उपचार के दौरान अभियुक्त मनीष सिंह व रजनीश सिंह की मृत्यु हो गयी। मृतक मनीष सिंह के पास से उ0नि0ना0पु0 अजय कुमार यादव से लूटी गयी सरकारी पिस्टल 9 एमएम ब्राउनिंग, जिसका नं0 15338655 है, बरामद हुआ था तथा मृतक अभियुक्त रजनीश सिंह के पास से 01 अदद 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ था । मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना बड़ागांव में मु0अ0सं0-486/22 धारा-307 भादवि व 3/7/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत है। फरार अभियुक्त लल्लन सिंह की गिरफ्तारी हेतु 01 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है तथा मा0 न्यायालय से एनबीडब्लू प्राप्त कर लिया गया है।

इस प्रकार घटना का सफल अनावरण करते हुये लूटी गयी सरकारी पिस्टल बरामद कर ली गयी है, शेष वांछित अभियुक्त लल्लन की गिरफ्तारी व साक्ष्य संकलन के दृष्टिगत विवेचना प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ नगर में निर्बाध यातायात संचालन हेतु कारगर उपाय किये जाने के सम्बन्ध में

183-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर में बढ़ते वाहनों की संख्या तथा ट्रैफिक पुलिस बल की कमी के कारण नागरिकों को भारी ट्रैफिक जाम से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार निर्बाध यातायात संचालन हेतु कोई कारगर उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

महानगर मेरठ की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिये निम्नलिखित उपाय/प्रयास किये गये हैं :-

'वर्तमान में जनपद मेरठ में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये यातायात निरीक्षक-06, टीएसआई-27, हे0कां0-100 व आरक्षी (पुरुष/महिला)-112 व होमगार्ड/पीआरडी-260 जवानों की ड्यूटी 53 स्थानों पर 02 पालियों में तैनात कर यातायात का सफल संचालन किया जाता है। यातायात व्यवस्था के संचालन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। शहर में 09 स्थानों पर नो एन्ट्री प्वाइन्ट चिन्हित किये गये हैं। इन पर प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 10 बजे तक शहर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। इसका पालन कराने के लिये पर्याप्त यातायात पुलिस बल इन स्थानों पर तैनात किया गया है। जिन वाहनों के द्वारा नो एन्ट्री का उल्लघंन किया जाता है उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।'

राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत जनपद मेरठ शहर की यातायात को सुदृढ़ व सुनियोजित करने हेतु आई0टी0एम0एस0 (इन्टीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के अन्तर्गत मेरठ नगर के 09 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल के आधार पर ही यातायात का संचालन किया जाता है। जो वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके विरुद्ध आई0टी0एम0एस0 के माध्यम से चालान की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के समस्त विकास खण्डों के लघु व सीमान्त किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु निःशुल्क बोरिंग के सम्बन्ध में

184-श्री बेचई सरोज-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के समस्त विकास खण्डों के लघु व सीमान्त किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु निःशुल्क बोरिंग सुविधा दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में कितने किसानों को उक्त सुविधा दी गई है एवं कितने किसानों को उक्त सुविधा दिये जाने की

कार्यवाही लम्बित है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधीन लघु सिंचाई द्वारा जनपद आजमगढ़ के क्रिटिकल श्रेणी में चिन्हित विकास खण्डों (सठियांव व पल्हनी) को छोड़कर शेष समस्त विकास खण्डों के लघु व सीमान्त किसानों को निःशुल्क बोरिंग की सुविधा दी जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में लघु व सीमान्त किसानों को सिंचाई हेतु निःशुल्क बोरिंग की सुविधा वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार प्रदान की गयी है :-

वर्ष	सामान्य जाति	अनुसूचित जाति	योग
2018-19	713	301	1014
2019-20	1425	472	1897
2020-21	683	302	985
2021-22	793	457	1250
कुल योग	**3614**	**1532**	**5146**

उक्त अवधि में इच्छुक एवं पात्र लाभार्थी का कोई प्रार्थना-पत्र लम्बित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

कोई प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के ब्लाक दुधही में तैनात खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

185-श्री मोहन वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के ब्लाक दुधही में तैनात खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जाँच विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-ख-7 नं0 56272 तथा ख-7 नं0 56273 दिनांक 07-12-2022 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हां।

शासन के पत्र दिनांक 11-01-2023 द्वारा मण्डल आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से शिकायती पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जांच किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड गौरा के राजस्व ग्राम पंचायत कनेवरा पूरे खुशहाली में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

186-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड गौरा के राजस्व ग्राम पंचायत कनेवरा पूरे खुशहाली की खसरा गाटा संख्या-848 का क्षेत्रफल हेक्टेयर-0.0120 जोकि चकमार्ग के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है, पर भू-माफियाओं का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गाटे संख्या की सरकारी जमीन भू-माफियाओं से कब्जा मुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

ग्राम-कनेवरा पूरे खुशहाली, तहसील-रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ की गाटा संख्या-848 क्षे0- 0.0120 भूमि पर गुलाब चन्द्र पाण्डेय पुत्र अजुग नरायन पाण्डेय द्वारा कच्चा मकान सहन आदि बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है जिसके सम्बन्ध में राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार रानीगंज में बेदखली का वाद विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर की तहसील चाँदपुर में चकबन्दी द्वारा छोड़े गये चकरोडों को दबंगों से मुक्त कराने विषयक

187-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर की तहसील चाँदपुर में चकबन्दी द्वारा छोड़े गये चकरोडों को दबंगों से मुक्त कराने तथा कितने किसानों द्वारा अपनी बैनामों की जमीन दंबगों से मुक्त कराने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितनो पर कार्यवाही हुई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

दिनांक 01 जनवरी, 2023 से चकरोड पर कब्जे के सम्बन्ध में कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुईं तथा सभी शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है ।

बैनामों की जमीन को दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में कुल 05 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 04 शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है । शेष 01 शिकायत के सम्बन्ध में न्यायालय जूनियर डिवीजन, चाँदपुर के समक्ष वाद विचाराधीन है ।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में हर घर नल योजना के अन्तर्गत ग्रामों में पानी की टंकी व पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में

188-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में हर घर नल योजना के अन्तर्गत किन ग्रामों में पानी की टंकी व पाइप लाइन बिछाने का कार्य संचालित है तथा उक्त कार्य को पूर्ण करने की समयावधि क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के 02 विकास खण्ड-जलीलपुर एवं नूरपुर के आंशिक क्षेत्र में फेज-2 के अन्तर्गत 61 ग्राम पंचायतों के 105 राजस्व ग्रामों में तथा फेज-3 के अन्तर्गत 100 ग्राम पंचायतों के 173 राजस्व ग्रामों में पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त योजनाओं को मार्च, 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली 1994 के नियम-3(1) में निर्वाचन याचिका हेतु प्रतिभूति धनराशि जमा किए जाने के सम्बन्ध में

189-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के नियम-3(1) में निर्वाचन याचिका हेतु प्रतिभूति धनराशि किस प्रकार जमा किए जाने का प्रावधान है ? क्या उक्त प्रतिभूति धनराशि के चालान का खाता शीर्ष अथवा सम्बन्धित ग्राम पंचायत के निजी खाते में जमा करने की युक्ति बताने वाला आदेश सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ

उ0प्र0 पंचायत राज (निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के नियम-3 में निम्नवत् प्रावधान है :-

निर्वाचन याचिका (1) अधिनियम की धारा-12 ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन पर उस सब डिवीजनल अधिकारी के समक्ष जिसकी अधिकारिता के भीतर सम्बद्ध ग्राम पंचायत पड़ती है, उस दिन से जब प्रश्नगत चुनाव का परिणाम घोषित किया जाए, 90 दिन के भीतर

प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें वह आधार या वे आधार जिसके कारण प्रतिवादी के चुनाव पर प्रश्न किया गया है, विनिर्दिष्ट होंगे और उसमें परिस्थितियों का सारांश होगा जिसके आधार पर प्रश्न किया जा रहा है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आवेदन पत्र तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसके साथ एक कोषागार चालान यह प्रदर्शित करने के लिए न लगा हो कि पचास रुपए की धनराशि प्रतिभूति के रूप में सम्बद्ध ग्राम पंचायत के निजी खाते में जमा कर दी गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-1185/रा0नि0आ0अनु0-4/2000 दिनांक 07 जुलाई, 2000 से प्रधान ग्राम पंचायत और सदस्य ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत के वैयक्तिक खाते, क्षेत्र पंचायत प्रमुख/सदस्य तथा अध्यक्ष जिला पंचायत/सदस्य जिला पंचायत के लिए लेखा शीर्षक 8443-सिविल जमा (121) को प्रभावी किया गया था, जिसे वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-01/2018/ए-1-53ए0जी0/दस-2017-10 (50)/2011, दिनांक 04 जनवरी, 2018 द्वारा बन्द कर दिया गया है।

प्रश्नगत लेखाशीर्षक में संशोधन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 में दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार त्रिस्तरीय परीक्षण के दिये जाने के सम्बन्ध में

190-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 में दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार त्रिस्तरीय परीक्षण के जरिए दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त त्रिस्तरीय परीक्षण के लिए जारी किए निर्देश की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्या आगामी चुनाव से पूर्व त्रिस्तरीय परीक्षण उपरान्त अन्य पिछड़ा वर्ग को पंचायतों में आरक्षण सरकार सुनिश्चित करेगी ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में निर्धारित आरक्षण व प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सम्पन्न कराए गए हैं।

उपरोक्तानुसार।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप आगामी निर्वाचन में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में परिषदीय विद्यालयों में मानक के अनुसार छात्र व अध्यापक की संख्या के सम्बन्ध में

191-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान में छात्रों तथा नियमित अध्यापकों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि आर0टी0ई0 अधिनियम के मानक अनुसार 30 छात्रों पर एक अध्यापक का मानक उक्त विद्यालयों में पूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार चांदपुर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या 19206 तथा अध्यापक संख्या 578 है।

विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 578 शिक्षक तथा 286 शिक्षामित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 22:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है।

विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में विगत वर्ष 2021-2022 में साड़ों के मारने, नदी में डूबने आदि में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में

192-श्री स्वामी ओउमवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में विगत वर्ष 2021-2022 में साड़ों के मारने, नदी में डूबने, आकाशीय बिजली गिरने, विद्युत तार टूटने तथा सड़क दुर्घटना में कितनें लोगों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार उक्त मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में विगत वर्ष 2021-22 में गंगा नदी में डूबने से तथा विद्युत तार टूटने से 01-01 व्यक्ति की तथा सरकारी बस से सड़क दुर्घटना में 05 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। सांड़ के मारने तथा आकाशीय बिजली गिरने से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

[†] छापा नहीं गया।

गंगा नदी में डूबने से तथा विद्युत तार टूटने से मृतकों के परिजन को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।

सरकारी बस से सड़क दुर्घटना में मृत 05 व्यक्तियों के परिजनों को नियमानुसार आर्थिक सहायता मजिस्टीरियल जांच के उपरान्त पात्र पाये जाने पर परिवहन विभाग द्वारा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न पुलिस लाइन एवं पुलिस थानों में पुलिस कर्मियों के बने आवासों तथा बैरक का कायाकल्प करने के सम्बन्ध में

193-श्री अरमान खान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर सहित प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए बने हुए अधिकांश आवास जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण पुलिस कर्मी बड़ी कठिनाई से रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के विभिन्न पुलिस लाइन एवं पुलिस थानों में पुलिस कर्मियों के आवासों तथा बैरक का कायाकल्प करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पुलिस कर्मियों के आवासीय व्यवस्था को बेहतर बनाये जाने हेतु भवनों के अनुरक्षण/मरम्मत कराने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित कर प्रदेश के जनपदों को प्रेषित किया गया है। विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनपद/इकाइयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों की मरम्मत, रंगाई-पुताई आदि कार्य हेतु लगभग 03 गुना धनराशि रु0 154.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष जनपद/इकाइयों को उनकी आवश्यकतानुसार अनुदान आवंटित किया गया है। पुलिस विभाग में अधिष्ठापित थानों के पुराने एवं जर्जर भवनों के मरम्मत, रंगाई-पुताई एवं अनुरक्षण आदि कार्य निरन्तर किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के बेहतर आवासीय/अनावासीय सुविधा हेतु निष्प्रयोज्य भवनों का ध्वस्तीकरण एवं नये भवन यथा हास्टल, बैरक, पुलिस लाइन, ट्रांजिट हॉस्टल आदि का निर्माण कराया जा रहा है । वर्तमान में पुलिस विभाग में धनराशि रु0 510.52 करोड़ की लागत के कुल 440 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा धनराशि रु0 2166.49 करोड़ की लागत के कुल 373 भवनों का निर्माण कार्य प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों में मानक के अनुरूप कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के अध्ययन/बैठने की व्यवस्था के सम्बन्ध में

194-डा0 पल्लवी पटेल तथा श्री पंकज-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के अनुपात में अध्ययन/बैठने का कक्षों में मानक क्या है ? क्या

सरकार कक्षों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को बैठने की व्यवस्था का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

भारत सरकार की समग्र शिक्षा की गाइड लाइन्स में कक्षा-कक्षों के सम्बन्ध में निम्नवत् मानक निर्धारित हैं :-

(अ) अतिरिक्त कक्षा-कक्ष छात्र नामांकन के आधार पर स्वीकृत किये जायेंगे ।

(ब) प्राथमिक विद्यालयों हेतु इंगित छात्र कक्षा-कक्ष अनुपात 30:1 है।

ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत विद्यालयों हेतु निर्धारित पैरामीटर्स में छात्रों हेतु फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत लगभग 14 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था की जा चुकी है। शेष विद्यालयों हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

भारत सरकार की समग्र शिक्षा की गाइड लाइन्स में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों हेतु फर्नीचर की सुविधा देने का प्रावधान है तथा अब तक 27,167 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था की जा चुकी है। उक्त गाइड लाइन्स में प्राथमिक विद्यालयों हेतु फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों को पूर्व की सेवाओं का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में

195-श्री पंकज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निदेशालय के आदेश सं0-1540 दिनांक 26-02-2020 के द्वारा कुल कितने वर्कचार्ज कार्मिकों को अपनी पूर्व की सेवाओं का लाभ दिया गया है तथा कितनों को लाभ दिया जाना शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखते हुए यह भी बतायेगी कि शेष वर्कचार्ज कार्मिकों को पूर्व की सेवाओं का लाभ प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

पत्रांक-1540 दिनांक 26-02-2020 के द्वारा रिट याचिका सं0-8148 /1990 के साथ क्लब की गयी समस्त रिटों में 29वां नम्बर पर अवस्थित सन्दर्भित कार्मिक की रिट सं0-2364/1991 भी सम्मिलित थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के निर्णय दिनांक 21-07-1993 के अनुपालन में सम्बन्धित कार्मिक की नियुक्ति वर्ष नवम्बर, 1994 को संशोधित कर दिनांक 21-07-1993 से अस्थायी नियुक्ति मानते हुये कनिष्ठ सहायक के पद पर अनुमति प्रदान की गयी ।

उक्त कार्यालय पत्रांक-1540, दिनांक 26-02-2020 द्वारा अन्य किसी कार्मिक को उक्त लाभ दिया जाना अवशेष नहीं है।

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-386/79-वि-1-21-1-क-39-20, दिनांक 05-03-2021 ''उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021'' प्रभावी होने के कारण वर्कचार्ज कार्मिकों को पूर्व की सेवाओं का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

196-[प्रश्न हटाया गया]

197-[प्रश्न हटाया गया]

स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष/कर्मचारियों की कार्य करने की अवधि को 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने की मांग

198-श्री महबूब अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एन आई ऐक्ट धारा (138) वाली अदालत/प्राधिकरण के अध्यक्ष की अधिवर्षता आयु 70 वर्ष की भाँति स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष/कर्मचारियों की कार्य करने की अवधि को भी 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्र सरकार के द्वारा वर्ष 2003 में प्रख्यापित स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य नियम और शर्तें) नियम, 2003 के प्रस्तर-4(2) में प्राविधान है कि स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष और अन्य सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली स्कॉलरशिप को पुनः चालू करने की मांग

199-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राएं अध्ययन करते हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्व की भांति कक्षा 1 से 8 तक दी जाने वाली स्कॉलरशिप को पुनः चालू करने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी हाँ ।

परिषदीय, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पुस्तकें एवं जूते-मोजे, स्कूल बैग एवं अन्य स्टेशनरी के क्रय हेतु धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के खाते में सीधे भेज दी जाती हैं। कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप दिये जाने की कोई योजना सम्प्रति विद्यमान नहीं है ।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के गांव भडौली में बाल्मीकि मंदिर से लेकर जसवीर सिंह के घर तक सी0सी0 रोड के निर्माण के सम्बन्ध में

200-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के गांव भडौली में बाल्मीकि मंदिर से लेकर जसवीर सिंह के घर तक लगभग 300 मीटर सी0सी0 रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण आम-जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग को आर0ई0डी0 विभाग द्वारा सी0सी0 मार्ग बनाया गया है। मार्ग के मध्य में पाइप लाइन डाले जाने के कारण संदर्भित मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त मार्ग की लम्बाई 300 मी0 है। उक्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने में लगभग रु0 15.00 लाख व्यय होने का अनुमान है। वर्तमान में वर्ष 2022-23 में प्राप्त होने वाले अनुदानों के सापेक्ष कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है। प्रश्नगत कार्य को वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में शामिल करने हेतु जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जायेगा एवं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के गांव ज्ञान लोक में मंदिर के पास से नंदू की डेरी तक सीसी रोड निर्माण के सम्बन्ध में

201-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर, विधान सभा क्षेत्र सदर के गांव ज्ञान लोक में मंदिर के पास से नंदू की डेरी तक लगभग 250 मीटर सी0सी0 रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण आम-जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग वर्तमान में कच्चा मार्ग है एवं खराब स्थिति में है। उक्त मार्ग की लम्बाई 250 मी0 है। मार्ग पर सी0सी0 व नाली का निर्माण कराये जाने में लगभग रु0 24.00 लाख

व्यय होने का अनुमान है। वर्तमान वर्ष 2022-23 में प्राप्त होने वाले अनुदानों के सापेक्ष कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है। प्रश्नगत कार्य को वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में शामिल करने हेतु जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जायेगा एवं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर के ग्राम सिखेड़ा में शाहपुर कला सम्पर्क मार्ग के पास से संजय के खेत तक का जर्जर रास्ते के निर्माण के सम्बन्ध में

202-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर के ग्राम सिखेड़ा में शाहपुर कला सम्पर्क मार्ग के पास से संजय के खेत तक का रास्ता जर्जर होने के कारण आम जनता को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग वर्तमान में पूर्णतः कच्चा मार्ग है, जिस पर जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं। उक्त मार्ग की लम्बाई लगभग 500 मी0 है । मार्ग पर मिट्टी/खड़न्जा का निर्माण कराये जाने में लगभग रु0 12.00 लाख व्यय होने का अनुमान है। वर्तमान वर्ष 2022-23 में प्राप्त होने वाले अनुदानों के सापेक्ष कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है। प्रश्नगत कार्य को वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में शामिल करने हेतु जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जायेगा एवं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के समस्त मण्डल मुख्यालयों को भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय से आच्छादित करने पर विचार करने की मांग

203-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन-कौन से मण्डल मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय की सुविधा से वंचित हैं ? क्या सरकार समस्त मण्डल मुख्यालयों को भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय से आच्छादित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश के 13 मण्डल मुख्यालय यथा सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झाँसी, अयोध्या, प्रयागराज, बाँदा, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती एवं गोण्डा भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय की सुविधा से वंचित हैं।

जी हाँ।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लेखपालों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में

204-श्री सचिन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लेखपालों के कुल कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार की इन रिक्त पदों को भरने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में दिनांक 31-01-2023 तक लेखपालों के कुल 12,697 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

राजस्व परिषद् के पत्र दिनांक 04-01-2022 द्वारा लेखपालों के रिक्त 8085 पदों का अधियाचन उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया गया है। आयोग के स्तर से मुख्य परीक्षा करायी जा चुकी है। अन्तिम परिणाम प्रतीक्षित है। अद्यतन चयन वर्ष 2022-23 तक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन सभी मण्डलों से प्राप्त कर उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में ग्रामीण पेयजल मिशन योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्पों के पानी के परीक्षण में पाये जा रहे प्रदूषित पानी सुधार के सम्बन्ध में

205-श्री सचिन यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में ग्रामीण पेयजल मिशन योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्पों के पानी के परीक्षण में पाये जा रहे प्रदूषित पानी के सुधार हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद फिरोजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के पानी में अशुद्धियां पाये जाने के दृष्टिगत जनपद फिरोजाबाद के समस्त ग्रामों को सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है। जनपद फिरोजाबाद के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में लोअर गंगा कैनाल (जनपद एटा) से सतही स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु डी0पी0आर0 तैयार करा लिये गए हैं एवं उक्त के अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद न्यायालय फिरोजाबाद में अधिवक्ताओं की संख्या के सापेक्ष चेम्बरों का निर्माण कराने विषयक

206-श्री सचिन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के जनपद न्यायालय में अधिवक्ताओं की संख्या के सापेक्ष उनके बैठने हेतु चेम्बरों की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो

क्या सरकार जनपद न्यायालय फिरोजाबाद में अधिवक्ताओं की संख्या के सापेक्ष चेम्बरों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जनपद न्यायालय फिरोजाबाद के न्यायालय परिसर में 100 अधिवक्ता चेम्बर का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है।

भूमि की उपलब्धता एवं बार एसोसियेशन आदि की मांग पर निर्भर है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्रस्ताव प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झाँसी में मूंगफली एवं अदरक की पर्याप्त पैदावार को देखते हुए जनपद में उक्त उपजों को प्रसंस्कृत एवं संरक्षित करने हेतु उद्योग स्थापित किये जाने विषयक

207-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झाँसी में मूंगफली एवं अदरक की पर्याप्त पैदावार को देखते हुए जनपद में उक्त उपजों को प्रसंस्कृत एवं संरक्षित करने हेतु जनपद में उद्योग स्थापित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

निजी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा कृषि एवं खाद्य उत्पादों के मूल्य सम्वर्धन तथा प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने हेतु उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 का प्रख्यापन किया गया है। जिससे प्रदेश के समस्त जनपद आच्छादित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत परसौंजा में राजू ठाकुर के पुरवा से साधुशरण सिंह के मकान तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में

208-श्री अनिल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत परसौंजा में राजू ठाकुर के पुरवा से साधुशरण सिंह के मकान तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत परसौंजा, विकास खण्ड चित्रकूटधाम कर्वी में राजू ठाकुर के पुरवा से साधुशरण सिंह के मकान तक कच्चा सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 300 मीटर एवं

चौड़ाई लगभग 12 फुट है। प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु दिनांक 14-02-2023 को ई-निविदाएं आमंत्रित की गईं, जिसमें अनुबन्ध के उपरान्त प्रश्नगत निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रदेश में स्टार्ट-अप के अन्तर्गत भारत सरकार से उद्योगों या कम्पनियों को बिना गारण्टी के 10 करोड़ रुपये तक का कर्ज देने की योजना के सम्बन्ध में

209-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्टार्ट-अप के अन्तर्गत भारत सरकार से उद्योगों या कम्पनियों को बिना गारण्टी के 10 करोड़ रुपये तक का कर्ज देने की कोई योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत कर्ज की पात्रता के बिंदु का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना से प्रदेश में अब तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

पात्र स्टार्ट-अप्स को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों द्वारा ऋण प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारण्टी देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 'स्टार्ट-अप्स हेतु ऋण गारण्टी स्कीम' दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचित की गई है।

इस स्कीम के अन्तर्गत अधिकतम गारण्टी कवर प्रति ऋण प्राप्तकर्ता 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।

स्टार्ट-अप्स के लिए ऋण गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए किसी कम्पनी के पात्रता मानदण्ड निम्नानुसार हैं, जिसमें किसी कम्पनी को 1-समय-समय पर जारी राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार डीपीआईआईटी के द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप होना चाहिए, और 2-ऐसे स्टार्ट-अप्स जो स्थिर राजस्व प्रवाह के चरण में पहुंच गए हैं, जैसा कि 12 महीने की अवधि में लेखा परीक्षित मासिक विवरणियों से मूल्यांकित किया गया है, ऋण वित्तपोषण के लिए उत्तरदायी होंगे, और 3-स्टार्ट-अप किसी ऋणदाता/निवेशकर्ता संस्थान के प्रति चूककर्ता नहीं होना चाहिए और आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं होना चाहिए, और 4-ऐसे स्टार्ट-अप जिनकी पात्रता गारण्टी कवर के उद्देश्य हेतु सदस्य संस्था द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

प्रश्नगत सूचना उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के उद्योग सम्वर्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग से दिनांक 15-02-2023 को अनुरोध किया गया है, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, हमारा अतारांकित प्रश्नों में प्रश्न संख्या-138 लगा है। मैंने उसमें पूछा था कि क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के

ग्रामीण अंचलों में पेजयजल की समस्या के निवारण हेतु जनपदों में इंडिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगवाने की व्यवस्था सरकार करेगी ? मान्यवर, सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर नल से जल योजना संचालित है। पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्व में लगाये गए हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रि-बोर का कार्य कराया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें व्यवस्था क्या है ? आपने प्रश्न किया उसका उत्तर आ गया। आपने साफ-साफ पूछा उन्होंने साफ-साफ बता दिया।

श्री अवधेश प्रसाद-

एक मिनट, मान्यवर, मैंने हैण्डपम्प लगाने के लिए पूछा था इन्होंने रि-बोर के लिये कहा है। तो यह क्या हो रहा है। यह नई परम्परा है कि सवाल कुछ पूछा जाता है और उत्तर कुछ और दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

उसके लिए उचित फोरम है। उसमें दीजिए ।

[12:21] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 फरवरी, 2023 को कुल 87 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिसमें 18 मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्रीमती अलका सिंह की जनपद हरदोई की विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में कतिपय पुलियों का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती अंजुला माहौर की जनपद हाथरस की सदर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक सासनी में एक महाविद्यालय स्थापित कराए जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री शिवपाल सिंह यादव की गत 2020 में हुए टोक्यो पैरालम्पिक प्रतियोगिता में सफल हुए प्रतियोगियों के स्टाफ को सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री रमाशंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत अहरौरा में नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के अन्तर्गत ग्राम उभई असदूनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री आशु मलिक की जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड पुवांरका के अन्तर्गत ग्राम मुगलमजरा से छपपुरा पीपल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना डा0 शिव प्रताप यादव की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत परसा पलईडीह, विकास खण्ड गैसड़ी में निर्माणाधीन पालीटेक्निक का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में सीवर के सफाई कराने हेतु तथा सफाई हेतु लगे मोटरों की क्षमता बढ़ाये जाने के हेतु है, नवीं सूचना श्री संग्राम सिंह की

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना में बाढ़ खण्ड की इकाई में सहायक अभियन्ता के पद को भरे जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री प्रेम सागर पटेल की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवा की निचलौल तहसील में भू-माफिया द्वारा कब्जा की जमीन को मुक्त करने तथा कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती मनीषा अनुरागी की जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ की ग्राम पंचायत मस्कारा को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री विशम्भर सिंह यादव की उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त वैयक्तिक सहायक का पी0एफ0 भुगतान न होने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण की जनपद जौनपुर के जाफराबाद के अन्तर्गत प्रधानपुर कुसिया नेवधिया मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के ब्लाक सैया में ग्राम भिड़ावाली से मंगल नगर तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी में कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेन्सी अवनी परिधि द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री गुलाम मोहम्मद की प्रदेश के अल्पसंख्यक घोषित विद्यालय में नीति बनाकर नयी नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलन्दशहर सदर तहसील से चीलघर तिराहे तक रोड का चौड़ीकरण निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है तथा अट्ठारहवीं सूचना श्री विरेन्द्र कुमार यादव की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा सरयां, ब्लाक सदर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :-

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री अभय सिंह, श्री बाबूलाल, श्री राम खिलाड़ी सिंह, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती पूनम संखवार, श्रीमती अनुपमा जायसवाल, श्री विनोद शंकर अवस्थी, श्री जियाउर रहमान बर्क, श्री बेदी, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, डा0 सुरभी, श्री पल्टूराम, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री बाबूराम पासवान, श्री सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी, श्री मनीष रावत, श्री चेतराम, श्री राजीव तरारा, श्री अशरफ अली खां, डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 राजेश्वर सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, श्री राजीव कुमार सिंह ''बब्बू भैया'', श्री संदीप सिंह, डा0 आर0 के0 पटेल, श्री बम्बा लाल, डा0 मनोज कुमार प्रजापति, श्री देवेन्द्र कुमार निम, श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री अनिल कुमार, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री राकेश कुमार गोस्वामी, श्री अशुतोष शुक्ला, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री अरमान खान, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री गणेश चन्द्र, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री ज्ञान तिवारी, श्री पूरन प्रकाश, श्री ब्रज भूषण राजपूत, श्री स्वामी ओउमवेश, श्री कैलाश नाथ शुक्ला, श्री गौरी शंकर वर्मा,

श्री अनिल प्रधान, श्री मोहम्मद ताहिर, श्री त्रिभुवन दत्त, डॉ0 रागिनी सोनकर, श्री लालजी वर्मा, श्री उमाशंकर सिंह, श्री निर्मल वर्मा, श्री मौहम्मद फहीम इरफान, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री बिपुल दुबे, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री हरिओम वर्मा, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी, श्री रमेश सिंह, डा0 नीरज बोरा, श्री मदन भैया, श्री तस्लीम अहमद तथा श्री राजीव गुम्बर।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएँ पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अलका सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सण्डीला जनपद हरदोई के अन्तर्गत मुख्य मार्गो की निम्नलिखित पुलियों का निर्माण कराना अति आवश्यक है। आये दिन आवागमन में असुविधा तथा दुर्घटना होती रहती है । उक्त मार्ग निम्नवत् हैं :-

1-ग्राम भोगीपुर मजरा महुआडांडा में भोगीपुर टिठई मार्ग पर पुलिया निर्माण।

2-भरावन चौराहे के पास भरावनगंज मार्ग पर पुलिया निर्माण।

3-ग्राम चेचरी मजरा अतरौली में पश्चिम की ओर मार्ग पर पुलिया निर्माण।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद हाथरस की सदर विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक सासनी में एक महाविद्यालय स्थापित कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अंजुला माहौर

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-78, हाथरस सदर, जिला-हाथरस के ब्लॉक-सासनी में एक महाविद्यालय की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में महाविद्यालय न होने के कारण यहां के छात्र-छात्राओं को दूर-दराज के इलाके में शिक्षा ग्रहण करने हेतु जाना पड़ता है। इस ब्लॉक की आबादी लगभग ढाई लाख है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद यहां पर कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। जनहित में ब्लॉक-सासनी में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक है ।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गत वर्ष 2020 में टोक्यो पैरा ओलम्पिक प्रतियोगिता में सफल हुए प्रतियोगियों के स्टाफ को सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्री शिवपाल सिंह यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान पैरालम्पिक प्रतियोगिता में भाग लेकर देश का नाम रोशन करने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाडियों और उनके साथ गये कोच व फिजियोथेरेपिस्ट एवं अन्य स्टाफ को सम्मान दिये जाने की ओर दिलाना चाहता हूँ। जैसे कि ज्ञातव्य हो कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने हेतु कोच की नियुक्ति होती है, उसी प्रकार उन खिलाड़ियों को पूरी तरह फिट रखने व चोटों से बचाव के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह खिलाड़ी के साथ पूरे समय उपस्थित रहता है। गत 2020 में टोक्यो में हुये पैरालम्पिक प्रतियोगिता में सफल हुये खिलाड़ियों व उनके कोच को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा सम्मान राशि देकर सम्मानित करने की घोषणा की गयी थी और फिजियोथेरेपिस्ट व अन्य स्टाफ को नजरअंदाज कर दिया गया है। इस उपेक्षात्मक निर्णय से फिजियोथेरेपिस्ट व अन्य स्टाफ के बीच घोर निराशा व रोष व्याप्त है तथा सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से माँग करता हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट व सम्बद्ध स्टाफ को भी सम्मानित राशि प्रदान की जाय।]

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत अहरौरा में नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमा शंकर सिंह-

[मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र-399, मड़िहान, जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड राजगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल काफी बड़ा है, जिसका कुछ भाग 50 किमी0 से अधिक है। दूरी अधिक होने के कारण क्षेत्रवासियों को अपने कार्यों के निष्पादन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों द्वारा काफी समय से राजगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल की अधिकता को देखते हुए अहरौरा में विकास खण्ड बनाये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने के कारण क्षेत्रवासियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। जनहित में राजगढ़ एवं उससे लगे विकास खण्डों के क्षेत्रफल को काटकर एक नया विकास खण्ड अहरौरा में बनाया जाय ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए राजगढ़ एवं उससे लगे विकास खण्डों के क्षेत्रफल को काटकर एक नया विकास खण्ड अहरौरा में बनाये जाने हेतु कारवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के अन्तर्गत ग्राम उभई असदनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह राठौर-

[मान्यवर अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-103, अलीगंज, जनपद-एटा के विकास खण्ड अलीगंज के अन्तर्गत ग्राम उभई असदनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाया जाना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि इस ग्राम सभा के निवासियों को प्राथमिक चिकित्सा हेतु दूर-दराज के क्षेत्र में जाना पड़ता है ।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड पुवांरका के अन्तर्गत ग्राम मुगल मजरा से छपपुरा पीपल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्री आशु मलिक-

[मान्यवर आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड पुवांरका अन्तर्गत ग्राम मुगलमजरा से लेकर छपपुरा पीपल तक सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 3.00 किमी0 है जो बिल्कुल कच्चा है जिससे कई गांवों का सम्पर्क मार्ग है नेवादा, चन्द्रौली व मुगलमजरा का बाईपास है। मार्ग कच्चा होने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी असुविधा होती है। उक्त मार्ग का पक्का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। उक्त मार्ग का निर्माण न होने से स्थानीय जनता में रोष एवं आकोश व्याप्त है ।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़क का पक्का निर्माण कराये जाने हेतु सरकार से कारवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत परसा पलईडीह, विकास खण्ड गैसड़ी में निर्माणाधीन पॉलीटेक्निक का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 शिव प्रताप यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी, जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत परसा पलईडीह, वि0ख0 गैसड़ी में उक्त पालीटेक्निक का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जिससे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस पिछड़े क्षेत्र में नौजवान तकनीकी शिक्षा से वंचित हैं। इस पालीटेक्निक के अधिकांश भाग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, कुछ भाग शेष रह गया है जिससे उक्त पालीटेक्निक में शिक्षण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। यह जनहित एवं लोक महत्व का विषय है तथा स्थानीय छात्र-छात्राओं के भविष्य से जुड़ा प्रकरण है। उक्त पालीटेक्निक का निर्माण पूर्ण कराकर शिक्षण प्रारम्भ न किये जाने से लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से उपरोक्त पालीटेक्निक का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में सीवर की सफाई कराने हेतु तथा सफाई हेतु लगे मोटरों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद आजमगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 1972-73 में सीवर लाइन बनी थी। काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त सीवर लाइन जाम हो गयी है जिसके कारण शहर के अन्दर प्रदूषित गन्दा पानी बह रहा है, हर्रा की चुंगी में प्रदूषित पानी भरने से लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा सफाई नहीं की जा रही है, बलरामपुर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है जो टौंस नदी में पानी को बाहर फेंकने का काम करता है उसमें जो मोटरें इत्यादि मशीनें लगी हुई हैं उनकी क्षमता कम होने के कारण प्रदूषित पानी को खींचकर टौंस नदी में नहीं गिरा पा रही हैं। सीवर लाइन की सफाई कराया जाना व सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में लगी हुई मोटरों की क्षमता बढ़ायी जाय। प्रदूषित गन्दा पानी को लेकर आम-जनमानस में सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्त्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल क्षमता बढ़ाये जाने एवं सीवर लाइन का कचरा निकाल कर सफाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना में बाढ़ खण्ड की इकाई में सहायक अभियन्ता के पद को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्री संग्राम सिंह-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद बलिया के मेरे विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्रफल बाढ़ के मौसम में बाढ़ से प्रभावित हो जाता है जिसके बचाव के लिए सिंचाई विभाग द्वारा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया में बाढ़ खण्ड की इकाई स्थापित है, जिसमें सहायक अभियन्ता के पद विगत वर्षों से रिक्त हैं तथा जनपद का अधिकांश क्षेत्रफल 2 नदियां घाघरा एवं गंगा में आने वाली बाढ़ से प्रभावित हो जाता हैं, के दृष्टिगत शासन द्वारा बाढ़ खण्ड बलिया में सहायक अभियन्ता के रिक्त पद के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से जनहित/कार्यहित में श्री श्रवण कुमार प्रियदर्शी, सहायक अभियन्ता (सिविल), बाढ़ खण्ड, कुशीनगर (तृतीय उपखण्ड) को दिनांक 06-01-2022 को स्थानान्तरित करते हुए बाढ़ खण्ड, बलिया में तैनाती देने के लिए आदेश दिया गया है। परन्तु एक वर्ष बीत जाने के बाद भी श्री श्रवण कुमार प्रियदर्शी द्वारा धन बल का प्रभाव दिखाते हुए शासन के आदेश की अवहेलना करते हुए बाढ़ खण्ड, कुशीनगर में 8 वर्षों से कुण्डली मार कर गोल-माल कर रहे हैं, जिससे जनपद के बाढ़ प्रभावित जनता में भारी आक्रोश है, जिस कारण बाढ़ खण्ड कुशीनगर (तृतीय उपखण्ड) से स्थानान्तरित, सहायक अभियन्ता श्री श्रवण कुमार प्रियदर्शी को कार्यमुक्त कराकर नवीन तैनाती स्थान जनपद-बलिया के बाढ़ खण्ड में किया जाना जनहित/कार्यहित में अति आवश्यक है ।

अतः लोक महत्व के इस अवलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवा की निचलौल तहसील में भू-माफिया द्वारा कब्जा की गयी जमीन को मुक्त कराने तथा कठोर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम सागर पटेल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा की निचलौल तहसील के अन्तर्गत टाऊन एरिया निचलौल में, सैयद जावेद अली शाह उर्फ मियां जिला गोरखपुर की जमींदारी भी थी। वर्ष 1972 में चकबन्दी प्रक्रिया चालू हुआ था तब जमींदार की भूमि को भू-माफिया आविद अली खान पुत्र राहतुल्ला खान, ग्रामवासी मुहल्ला महाशय, नगर पंचायत निचलौल ने आराजी संख्या-729, 134, 801, 1415, 1812, 2887 फर्जी रूप से इन्द्राज कराया एवं करमहिया ग्राम पंचायत, तहसील निचलौल में ही फर्जी रूप से खाता नं0-141 व 142 को अपने नाम जंगल की जमीन कराया है। यह भू-माफिया है तथा जमीनों में फर्जीवाड़ा किया है। जनहित में इसकी जाँच कराकर इसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त भू-माफिया के जमीन फर्जीवाड़े के कृत्यों की जाँच जिलाधिकारी, महराजगंज से कराकर फर्जी तरीके से अपने नाम कराये गये जमीन को सरकार के पक्ष में दर्ज किये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ ग्राम पंचायत मस्करा को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध मे नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्रीमती मनीषा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड के जनपद-हमीरपुर की विधान सभा क्षेत्र राठ की ग्राम पंचायत मस्करा की आबादी लगभग 22000 से भी ज्यादा है। यह क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित मानक को पूर्ण कर लिया गया है जिसकी समस्त सूचना जिला प्रशासन द्वारा पत्रावली के द्वारा शासन को उपलब्ध करा दी गयी है, जो काफी लम्बे समय से लम्बित है और इस ग्राम पंचायत को अभी तक नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिया गया है, जिस कारण से जनहित के कार्य तेज गति से नहीं हो पा रहे हैं। जनहित में जनपद हमीरपुर की विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मस्करा को नगर पंचायत बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त वैयक्तिक सहायक का पी0एफ0 भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर सिंह यादव-

[मान्यवर, उ0प्र0 सिंचाई एवं जल संसाधान अनुभाग-07 के पत्र संख्या-270/21-27-सिं0-07-21(6)/21, दिनांक 08 अप्रैल, 2021 के द्वारा सेवानिवृत्त वैयक्तिक सहायकों का पी0एफ0/ग्रेच्युटी का ब्याज सहित भुगतान कराये जाने की ओर मा0 सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मान्यवर जिन कार्मिकों का प्रकरण है 30 नवम्बर, 2011 को सेवानिवृत्त वैयक्तिक सहायक हैं। उक्त प्रकरण एक दशक से अधिक का है और सम्बन्धित विभाग की लापरवाही के कारण आज तक उपरोक्त का भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे सम्बन्धित कार्मिक मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान हैं, सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा लगातार उक्त का भुगतान कराये जाने हेतु सम्बन्धित को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता रहा है, किन्तु खेद का विषय है कि सम्बन्धित विभाग की लोक सेवा में कार्यरत कार्मिकों के प्रति कोई रुचि नहीं है, जिससे सम्बन्धित कार्मिकों में भारी रोष व्याप्त है।

अतः मा0 सदन के माध्यम से उ0प्र0 सिंचाई एवं जल संसाधान अनुभाग-07 के पत्र संख्या-270/21-27-सिं0-07-21(6)/21, दिनांक 08 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित संबंधित कार्मिकों का पी0एफ0/ग्रेच्युटी का ब्याज सहित भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-जौनपुर के जाफराबाद के अन्तर्गत प्रधानपुर कुसिया, नेवढ़िया मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र जाफराबाद के अन्तर्गत प्रधानपुर, कुसिया, नेवढ़िया मार्ग जो ओ0डी0आर0 घोषित हुआ है, इसके चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव शासन में लम्बित है। अब तक उस पर धन अवमुक्त नहीं हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के ब्लाक सैया में ग्राम भिड़ावली से मंगल नगर तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-92, खैरागढ़, जनपद आगरा के ब्लाक सैया में ग्राम भिड़ावली से मंगल नगर तक लगभग 02 किमी0 रोड का नव निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। वहां पर लगभग 500 की आबादी है, आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है, जिससे आम-जनता को काफी कठिनाई होती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी में कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसी अवनी परिधि द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चौधरी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा नकुड़, जनपद सहारनपुर क्षेत्र में राजकीय मेडिकल कालेज, पिलखनी क्रियाशील है, इस मेडिकल कालेज में आउटसोर्सिंग का कार्य अवनी परिधि एनर्जी एवं कम्यूनिकेशन प्रा0लि0 नाम की कम्पनी कर रही थी, जिसके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच के लिये मैंने शासन को पत्र लिखा था। तद्क्रम में विशेष सचिव के द्वारा जाँच भी की जा चुकी है। परन्तु अभी तक उक्त जाँच रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के अल्पसंख्यक घोषित विद्यालय में नीति बनाकर नयी नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गुलाम मौहम्मद-

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1920 के चेप्टर नं0-2 सेक्शन-17 में पिछली सरकारों ने संशोधन कर अल्पसंख्यक घोषित संस्थाओं में प्रबन्ध समितियों को प्राप्त नियुक्ति के अधिकार पर रोक लगा दी गई, जो संविधान की धारा-30 अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार अपनी शैक्षिण संस्थाओं को स्थापित करना और संचालित करने का अधिकार का हनन किया गया है तथा इसके नतीजे में न तो प्रबन्ध समिति ही प्रधानाचार्य व अध्यापकों की नियुक्ति कर पा रही है और न ही इन अल्पसंख्यक घोषित विद्यालय में कोई नीति बनाकर नियुक्तियों का रास्ता खोला जा रहा है। जिसकी वजह से इन कालेजों में अध्यापकों की संख्या वर्ष दर वर्ष घटती जा रही है। जिससे छात्रों की शिक्षा पर खराब प्रभाव पड़ रहा है, ये पूरे प्रदेश के धार्मिक/भाषायी/अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के भाविष्य से जुड़ी एक गम्भीर समस्या है।

अतः मा0 महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर सदर तहसील से चीलघर तिराहे तक रोड का चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि सदर तहसील से चीलघर तिराहे तक रोड का चौड़ीकरण कराने का कष्ट करें, इस रास्ते की लम्बाई लगभग 5 किमी0 है, ये रास्ता पूरी तरह दयनीय स्थिति में है, इस रोड पर जाम की स्थिति रहती है, जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस रोड का चौड़ीकरण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः जनहित में उपरोक्त रोड़ का चौड़ीकरण, निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। इस क्षेत्र की जनता आपकी सदैव अभारी रहेगी।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा सरयां, ब्लाक सदर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध मे नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर, जनपद गाजीपुर अन्तर्गत ग्राम सभा सरयां, ब्लाक सदर में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुल निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। बाढ़ के दिनों अथवा सामान्य दिनों में काफी घूम कर बाजार जाना पड़ता है। आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल उपरोक्त पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

[12:26] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी की है कि सदन में सरकार द्वारा औचित्य के प्रश्नों पर व्यवस्था दिए जाने के बाद भी निर्देश का अनुपालन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, जो सुनी जायेगी।

सरकार द्वारा औचित्य के प्रश्नों पर व्यवस्था दिये जाने के बाद भी निर्देश का अनुपालन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, नियम-300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को आपने हमें पढ़ने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रत्येक सत्र में सदन के भीतर औचित्य के प्रश्नों पर आप द्वारा व्यवस्था दी जाती है, सरकार द्वारा इसका संज्ञान लेने की बात भी कही जाती है, परन्तु उपवेशन के समाप्त होने के साथ ही औचित्य का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है, न तो कोई कार्यवाही की जाती है और न ही सम्बन्धित मा0 सदस्य को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाता है। जिससे सदन के भीतर दिया गया आश्वासन निरर्थक सिद्ध होता है। 18वीं विधान सभा के औचित्य के प्रश्नों को देखें तो कहीं-न-कहीं सदन और विधान सभा से जुड़े मुद्दों पर आप द्वारा व्यवस्था दी गयी, परन्तु कोई भी कार्यवाही तथा सुधार नहीं दिखाई देता है। सदनों में प्रश्नों का गलत जवाब, नियमों की सूचना पर भ्रामक उत्तर तथा सदन में दिए गये समयबद्ध आश्वासन को पूरा न करना सदन के प्रति सरकार की उदासीनता को दिखाता है। आप द्वारा औचित्य के प्रश्नों पर व्यवस्था दी जाती है, जिसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आपके द्वारा सदन में उत्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सहमति प्रदान की गयी है। परन्तु आज भी स्थिति वही है। आपके निर्देश पर प्रश्नकाल में तो कुछ सम्बन्धित अधिकारी आ जाते हैं, लेकिन शाम की चर्चा में कभी-कभी हमारे अधिकारीगण उपस्थित नहीं रहते हैं। आपसे अनुरोध है कि 18वीं विधान सभा के औचित्य के प्रश्नों पर मा0 अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश की एक बार फिर समीक्षा कराते हुए समेकित कार्यवाही से इस सदन को अवगत करा दिया जाए। इस औचित्य के प्रश्न पर मैं आपसे समयबद्ध व्यवस्था की मांग करता हूँ।

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मा0 सदस्य पाण्डेय जी तो यह सोचते हैं कि सदन में चाहे नियम-56 हो, चाहे नियम-300, चाहे प्रश्न हों। दूसरे दिन उन्हीं को सबसे ज्यादा महत्व मिले तो मुख्य सचेतक महोदय हम तो आपको वैसे भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और आप सदन का समय क्यों खराब कर रहे हैं। आज भी तीन पुलिस के आई0जी0 स्तर के अधिकारी, अधिकारी दीर्घा में उपस्थित थे और इसके अलावा श्री नील रतन और दीक्षित जी पूरे बजट पर बैठे रहे हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

शाम 4 बजे के बाद कोई अधिकारी नहीं था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

शाम 4 बजे तो मेरी ब्रीफिंग चल रही थी, उस समय का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, उस समय हमारी विशेषाधिकार समिति की बैठक चल रही थी, उसके बाद साढ़े चार बजे से लेकर सवा छः बजे तक मेरी ब्रीफिंग चल रही थी तो उस वक्त तो नहीं कह सकता लेकिन जब सवा छः बजे मैं आया था तो दोनों अधिकारी यहां मौजूद थे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

लेकिन चार बजे के बाद कोई अधिकारी मौजूद नहीं था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन मान्यवर, जिस दिन से आपने निर्देश दिया है उसका पूरी तरीके से पालन करने के लिए हमने बोल भी दिया है और अभी भी हमारे प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य जो पहले एल0आर0 रहे हैं, वे इस समय भी बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि कोई अधिकारी नहीं बैठता है। आप स्वयं देख लीजिए, इस समय भी बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने कल देखा है कि सवा छः बजे जब मैं आया तब दोनों अधिकारी बैठे थे और बजट के समय पर पूरे टाइम पर वही दोनों लोग बजट में मेन भूमिका अदा करते हैं श्री नील रतन एवं श्री दीक्षित जी, ये दोनों ही विशेष सचिव हैं, ये दोनों ही बैठे थे, इसलिए कम-से-कम इतनी ज्यादती तो मत करिए। मान्यवर, यह नियम-300 में नहीं आता है और हम निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस किसी का भी विषय होगा उससे सम्बन्धित अधिकारी उस समय उपस्थित रहेगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय मंत्री जी, जो भ्रामक उत्तर आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपके पास निदेश है, आप नियम-166 के अन्तर्गत भी लिखकर दे सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार से उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास व्यवस्था है। अगर सबसे ज्यादा व्यवस्था के प्रश्न पर कोई खड़ा होता है तो आप ही खड़े होते हैं तो हर चीज के लिए तो आपको अधिकार मिला हुआ है और उसके बाद भी सदन का समय नियम-300 में खराब कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठिए ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इनसे भी कहा जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ये हर समय हर बात के लिए कहते हैं और इनकी बात का सबसे ज्यादा संज्ञान लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

इनकी पार्टी के लोग भी इस बात का संज्ञान लेते हैं। यह नियम-300 में नहीं आता है, इसे अग्राह्य करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-03 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-04।

[12:31] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

हम कार्य-स्थगन की सूचना लेते हैं, आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा और अन्य सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। पहली सूचना प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री पंकज मलिक एवं श्री लालजी वर्मा जी की है। कोई एक माननीय सदस्य इस पर बोल दें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता महंगाई से पीड़ित है। जनता से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने नियम-56 के अन्तर्गत हमें अपनी बात रखने का पार्टी की ओर

से अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महंगाई के जिस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हम यहां खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप चर्चा नहीं कर रहे हैं आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

जी मान्यवर, अपनी बात को रखने के लिए खड़े हुए हैं। यह समस्या कोई सत्तापक्ष या विपक्ष, आलोचना या विरोध से सम्बन्धित नहीं है। यह समस्या आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता से सम्बन्धित है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई लगातार तेजी से बढ़ती चली जा रही है, चाहे वह खाने-पीने की वस्तु हो, चाहे रोज दिनचर्या में काम करने वाली वस्तुएं हों, चाहे बिल्डिंग मैटेरियल का सवाल हो, महंगाई की मार से आज आम आदमी और गरीब आदमी सबसे ज्यादा पीड़ित है। हम आज देखें तो इसी महंगाई के कारण आज पारिवारिक क्लेश, आत्महत्या की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं कहीं-न-कहीं परोक्ष व अपरोक्ष रूप आपस में जुड़ी हुई है और लगातार इनमें वृद्धि हो रही है। हमने जिक्र किया दिनचर्या में काम आने वाली वस्तुओं का, अगर हम देखें पिछले वर्षों में तो वर्ष 2015 से 2022 के बीच में तो जो अरहर की दाल 75 रुपये प्रति किलो में थी, वह आज 120 रुपये प्रति किलो में बिक रही है, लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। सरसों का तेल जो 102 रुपये में था, आज 190 रुपये में है, लगभग 39 प्रतिशत की वृद्धि है। जो दूध 30 रुपये का था, आज 50 रुपये का है, 40 प्रतिशत की वृद्धि है। आलू 5 रुपये की जगह 10 रुपये का बिक रहा है, 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। प्याज 10 रुपये की जगह पर 20 रुपये का है, 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। पेट्रोल 71 रुपये 41 पैसे की जगह 96.72 का बिक रहा है, लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि है। डीजल 56 रुपये 71 पैसे की जगह पर 89 रुपये 62 पैसे का बिक रहा है, लगभग 27.4 प्रतिशत की वृद्धि है। गैस सिलेण्डर जो अभी 3-4 साल पहले 928 का था, वह आज 1053 रुपये का है, लगभग 26.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। अगर हम सीएनजी पर जायें जो 38 रुपये 15 पैसे के स्थान पर 75 रुपये 61 पैसे का बिक रहा है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि है। सीमेंट 300 की थी, आज 400 में बिक रही है। सरिया 3800 रुपये कुन्तल थी, आज 7500 रुपये कुन्तल बिक रही है, लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि है। ईंट 4200 की आज 6000 में बिक रही है, लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि है। मौरंग 3500 की जगह 6000 में बिक रही है, 45 प्रतिशत की वृद्धि है। बजरी 2200 के स्थान पर 3000 रुपये में बिक रही है, जो लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि है।

अगर मान्यवर, आज हम देखें और यह मान लें कि किसी व्यक्ति की औसत आय 12 से 14 हजार रुपये प्रतिमाह है, खासकर मध्य क्षेत्र का रहने वाला मध्यम श्रेणी का और कमजोर और गरीब व्यक्ति का। अगर उसकी आय हम 12 से 15 हजार मान लें तो आज

उसका खर्च क्या आ रहा है ? आज अगर हम देखें, उसके 02 बच्चे हैं तो पति-पत्नी मिलाकर 04 लोग होते हैं और अगर हम खाने का 50 रुपये से भी हम गुणा करें तो 200 रुपये प्रतिदिन उसके खाने का व्यय आ रहा है और अगर माह से गुणा करें तो लगभग 6 हजार रुपये आ रहा है। यह कम से कम हम बता रहे हैं। अगर 02 बच्चे हैं और उसकी पढ़ाई पर खर्च हो रहा है तो दो से ढाई हजार रुपये उनकी ड्रेस, कापी, किताब और पढ़ाई का खर्च। अगर उसने एक कमरे का भी कोई मकान किराये पर ले रखा है और औसत किराया 3 हजार रुपये मान लें। अगर हम आकस्मिक खर्च हटा रहे हैं, मान लें कि वह साइकिल से आता-जाता है, तब भी मान्यवर, यह खर्च 16,300/- रुपये आ रहा है। तो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति और आम व्यक्ति कैसे जीवन जीने का काम करेगा और आज खासकर जब बच्चे के जन्म लेने से ले करके और उसकी मृत्यु तक के सामानों पर जीएसटी है और जीएसटी छोटी रकम नहीं है, आज जीएसटी में बड़ी रकम जा रही है। तो आम आदमी और मध्यम श्रेणी का व्यक्ति कैसे जीवन-यापन कर रहा है, यह निश्चित रूप से आज चिन्ता का विषय भी है और विचार करने का भी विषय है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ, आज एक आम आदमी क्या कह रहा है ?

'जिन्दगी की तन्हाई लिखूँ, पर अपनों की रुसवाई लिखूँ,
बढ़ती हुई महंगाई लिखूँ या अपनी घटती हुई कमाई लिखूँ।'
यह आम आदमी कह रहा है।
'दिल उतना नहीं रोया तन्हाई में, दिल जितना रो रहा है आज महंगाई में।'

मान्यवर, आज यह परिस्थितियाँ हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि आलोचना का यह विषय नहीं है, केवल विरोध करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। मान्यवर, चाहे इधर के सदस्य हों, चाहे उधर के सदस्य हों, हमने आज आम आदमी की कमाई जो बतायी है और उसका खर्च बताया है, आज आम आदमी किस तरीके से जीवन जी रहा है और यह बढ़ती हुई महंगाई आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसलिए मान्यवर, हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का जहाँ हम ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, वहीं इस पर अलग से चर्चा कराये जाने का हम आग्रह और अनुरोध भी करने का काम करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

माननीय अध्यक्ष जी, 22 आवश्यक वस्तुएँ हैं, जिनके बारे में समय-समय पर जब महंगाई बढ़ती है तो केन्द्र सरकार निर्देश जारी करती है और राज्य सरकारें उसके हिसाब से उन पर छापेमारी, चेकिंग आदि की कार्यवाही करती है। यह केंद्र सरकार के ऊपर है और उन्हीं के अधीन है। जहां तक दो-तीन बातें मुख्य रूप से हमें कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के खर्च की बात अभी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने आपके सामने ही कही थी। 1 करोड़ 92 लाख

छात्रों को मुफ्त स्वेटर, कपड़े, मोजे, जूते और किताबें सारी चीजें फ्री में दी जाती हैं। महंगाई रोकने के लिए आपने जो दालों के रेट के भाव बताए मैं चुनाव से पहले गांव में गया था वहां एक बुजुर्ग बैठे थे बुजुर्ग ने स्वाभाविक तौर पर कहा कि भईया मोदी, योगी जुग-जुग जिएं। मैंने समझा की बाबा नाराज हैं मैंने कहा कि ऐसी क्या बात है कोई नाराजगी है क्या तो उन्होंने कहा कि यह नाराजगी नहीं है पिछले तीस साल में मैंने गुड़, चने की रोटी नहीं खाई अब तो मोदी और योगी चना खिला रहे हैं। मान्यवर पूरे प्रदेश में क्या कभी बांटा गया है चना, लेकिन हमने बांटा है चना हमारी सरकार ने बांटा है चना। मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूँ और आपको मालूम भी है कि हमने 1 करोड़ 75 लाख मुफ्त में गैस के सिलेण्डर घर-घर पहुंचाए हैं।

मैंने दो दिन पहले भी कहा था जब आदरणीय डॉ0 रागिनी जी ने सवाल पूछा था तो उस समय भी मैने यह बात कही थी कि हमारे देश में जब पहली बार मैं यहां हाउस में आया सन् 1985 में तो मा0 स्पीकर महोदय ने लिखकर दिया तब मुझे गैस का सिलेण्डर मिला कि ये विधायक हैं इनको सिलेण्डर मिलना चाहिए । जब स्पीकर महोदय के कहने पर एम0एल0ए0 को गैस सिलेण्डर मिलता था तो आज 1 करोड़ 75 लाख बिना कहे गैस सिलेण्डर घर-घर पहुंचाए है। 15 करोड़ उपभोक्ताओं को मुफ्त राशन दिया है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कोरोना के दौरान कहा कि कोई फॉरमेल्टी की आवश्यकता नहीं जो हमारे उत्तर प्रदेश के बाहर लोग रहते थे और वापस आए हैं उनके लिए तुरन्त मौके पर ही राशन कार्ड बना दिया जाए हमने 35 लाख राशन कार्ड बनाए हैं। अब यदि आप बात करते हैं तो मैं यह भी बता देता हूँ मान्यवर, राजस्थान में 31 रुपये पेट्रोल पर वैट लगता है, वहां पेट्रोल का भाव है 108 रुपये 48 पैसे। उत्तर प्रदेश में उसका लगभग आधा 19 रुपये 36 पैसे वैट लगता है और पेट्रोल का भाव है 96 रुपये 97 पैसे, झारखण्ड में 22 रुपये वैट लगता है पेट्रोल पर और पेट्रोल का भाव है 99 रुपये 84 पैसे। बिहार में 23 रुपये 58 पैसे वैट लगता है पेट्रोल पर और वहां पेट्रोल का भाव है 107 रुपये 24 पैसे हमारे यहां पेट्रोल का भाव है 96 रुपये 97 पैसे। वेस्ट बंगाल में 25 रुपये लगता है पेट्रोल पर वैट और पेट्रोल का भाव 106 रुपये 3 पैसे है। हमारे यहाँ पेट्रोल का भाव है 96.97 रुपये। आप यदि डीजल में देखें तो मैं बता हूँ कि हमारे यहाँ जो वैट लगा है 17.08 रुपये, राजस्थान में वैट लगा है 19 रुपये, झारखण्ड में वैट लगा है 22 रुपये, वेस्ट बंगाल में वैट लगा है 17 रुपये और अब मैं आपकी ही बात कहे देता हूँ तो आप भी जरा सुन लो। आपकी सरकार में पेट्रोल पर वैट लगता था 26.80 रुपये, आपकी सरकार में 26.80 रुपये टैक्स था, उसे हमने घटाकर 19.36 रुपये किया है, हमने 19.36 रुपये कम किया है। आपकी सरकार में डीजल पर टैक्स था 17.48 रुपये जिसको हमने घटाकर 17.08 रुपये किया है। ये आपकी सरकार का टैक्स है तो अब आप स्वयं इससे अन्दाजा लगा लीजिए कि हमने तो आपके टैक्सों को घटाया है, यही हमारी सरकार के हक में है। इसलिए मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अब वह समय आ गया है कि

दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज काहु नहिं व्यापा। अब कोई आदमी यहाँ भूख से नहीं मरता, अब कोई विद्यार्थी यहाँ नंगे पैर पढ़ने नहीं जाता, अब कोई विद्यार्थी यहाँ बिना किताब के नहीं पढ़ता। मान्यवर, इसलिए इसको अग्राह्य किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी को सुना, मैंने मा0 मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, मैं इसको अग्राह्य करता हूँ। दूसरी सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह जी की है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, यहाँ सरकार द्वारा झूठी बात बोली जा रही है, इसलिए मैं और मेरा दल सरकार की इस बात और महंगाई के मुद्दे पर दो मिनट के लिए सदन का बहिष्कार करते हैं।

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के श्री मनोज कुमार पाण्डेय अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, क्या आप भी बहिर्गमन कर रहे हैं।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं वापस आ जाऊँगा।

श्री अध्यक्ष-

दो मिनट में तो हम आगे बढ़ जाएँगे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं रुका हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इसका मतलब सब लोग बहिर्गमन नहीं कर रहे हैं। अब मा0 सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह जिन्होंने बहिर्गमन नहीं किया है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बहिर्गमन करके वापस आ गया हूँ। मान्यवर, थोड़ा सदन व्यवस्थित हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

अपने पीछे से सदन व्यवस्थित करवाओ न, आप सीनियर लीडर हो सदन व्यवस्थित करवाओ।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

आप सदन व्यवस्थित करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

सदन व्यवस्थित हो गया।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

और मैं बहिर्गमन करके आ भी गया। मा0 अध्यक्ष जी, आपने कार्य-स्थगन के हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, मैं कोई राजनैतिक बात नहीं करूँगा, कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूँगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से केवल इतना अनुरोध करूँगा कि मेरी पूरी बात सुन लें और जो न्याय कहता हो, जिससे गरीब को न्याय मिल सकता हो, जिससे गरीब की जान बच सकती हो, जिससे समाज में रहने वाले सामान्य नागरिक की अपराधियों से रक्षा हो सके, सरकार मेरी बात सुनने के बाद ऐसा कोई कदम उठाए। मैं अभी कल हमारे क्षेत्र में गौरीगंज विधान सभा क्षेत्र में एक कोतवाली पड़ती है मुसाफिरखाना। मुसाफिरखाना कोतवाली के अन्तर्गत एक ग्राम पंचायत भद्दौर आती है। भद्दौर में रहने वाले सुरेश यादव जो तहसील में जिलेदार/संग्रह अमीन थे, उनका भतीजा जो पूर्व में प्रधान था, अबकी बार उसकी माता जी प्रधान हैं, इससे पहले उसके भाई बी0डी0सी0 थे, यह राजनैतिक परिवार है, उसकी हत्या हो जाती है। डबल हत्या होती है और हत्या किस प्रकार से की जाती है, चिन्तनीय विषय यह है। ये चार-पाँच लोग अपनी बोलेरो गाड़ी से लगभग रात के सवा आठ, साढ़े आठ बजे जा रहे थे, मुसाफिरखाना कस्बे से लगभग पाँच किलोमीटर दूर उनका घर है। पूरे रास्ते में कई बड़े गाँव हैं, जैसे दादरा, सरईयाँ, गोनईयाँ आदि बड़ी आबादी से घिरे हुए गाँव हैं। ये बड़ी आबादी 7-8 हजार आबादी के गाँव हैं। उस रास्ते से वे जाते हैं, एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है। पहले दो मोटर साइकिल से अपराधियों द्वारा उनकी बोलेरो को घेरने का काम किया जाता है कॉसिंग के पास और उनके ऊपर अटैक करने का प्रयास होता है तो वे अपनी बोलेरो की स्पीड तेज कर देते हैं। सामने एक डिग्री कॉलेज है, डेढ़ किलो मीटर ओवर टेक करने के बाद भट्ठे के पास जहाँ पर 40-50 की संख्या में मजदूर हमेशा रहते हैं, काम करते हैं। वहाँ उस बोलेरो के आगे अपनी मोटर साइकिल को खड़ी करने का प्रयास करते है और बोलेरो न रोकने पर जब वे अपनी बोलेरो नहीं रोकते, बृजेश यादव उसको चला रहे थे, सुरेश यादव उसमें बैठे, तीन नौजवान उसमें और बैठे थे। जब वे बोलेरो नहीं रोकते हैं तो बम से उस बोलेरो पर हमला किया जाता है। उस बोलेरो पर बम से हमला होता है और जब बम से हमला होता है तो हड़बड़ाकर वे गाड़ी रोक देते हैं और अपराधी मोटर साइकिल से उतर कर 25 राउण्ड गोलियाँ चलाकर दोनों की हत्या कर देते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, इस घटना में 25 राउण्ड गोलियाँ चलती हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, हत्या तो हुई, यह दुर्भाग्य है कि मेरे कार्यकर्ता, मेरे समर्थक इस प्रदेश में रहने वाले एक नागरिक की हत्या हुई है, पूर्व प्रधान की हत्या हुई हैं, प्रधान के पुत्र की हत्या हुई है और एक सरकारी कर्मचारी की हत्या हुई है। लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात

यह है कि लगभग चार-पाँच साल पहले उसी सुरेश यादव पर जानलेवा हमला होता है उसके सीने पर गोली लगती है और उसको ट्रॉमा सेण्टर में भर्ती कराया जाता है। समय से उसको उपचार मिल जाता है तो इसलिए उसकी जान बच जाती है। एक बार यह अटैक उस पर होता है, तब से वह लगातार सुरक्षा की गुहार लगाता है कि उसको सुरक्षा मिल सके। इसके लिए मैं डी0एम0 और एस0पी0 से एवं जिले के अन्य अधिकारियों से सम्पर्क करता हूँ, लेकिन उसका एक शस्त्र लाइसेंस तक नहीं बनाया जाता। मेरे द्वारा अथक प्रयास किया जाता है, तीन-तीन बार उसकी शस्त्र लाइसेंस की फाइल जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुँचाई जाती है, लेकिन उसका लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाता। जबकि धारा-307 में मामला लिखे जाने के बाद अपराध पीड़ित कोटे से उसका शस्त्र लाइसेंस निर्गत हो जाना चाहिए था। पंचायत चुनाव में उसके ऊपर दूसरा जानलेवा हमला होता है। एक मुस्लिम बिरादरी के व्यक्ति की उसमें हत्या होती है, साथ ही आठ लोगों को लाठी-डण्डों से पीट-पीट कर अधमरा कर दिया जाता है। जिनका मेडिकल कॉलेज के अपेक्स ट्रॉमा में, पी0जी0आई0 के ट्रॉमा सेण्टर में और सरकारी अस्पतालों में इलाज होता है।

श्री अध्यक्ष-

आप सारा इतिहास मत बताइए, इसी घटना पर बताइए।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कहीं और से किसी दूसरी घटना की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है और उसके साथ पीछे क्या-क्या हुआ है, उसको उजागर करना मेरा दायित्व भी बनता है और सदन में बैठे सभी लोगों के संज्ञान में लाने का भी मेरा दायित्व बनता है और आपको उसका संज्ञान लेना भी चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, जब उसमें सात-आठ लोगों की हत्या हो जाती है, सात-आठ लोगों को चोटिल कर दिया जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और उसके बाद उसमें सुरेश यादव के खिलाफ मुकदमे लिख दिए जाते हैं। केवल इसलिए मुकदमे लिख दिए जाते हैं बड़ी धाराओं में कि वह मृतक व्यक्ति के साथ, उसके परिवार के साथ खड़ा हो जाता है। मैं आपसे इसमें केवल इतना कहना चाहता हूँ। मैं इस पर चर्चा की मांग भी करता हूँ और सरकार से अनुरोध भी करता हूँ कि मृतक परिवार के भरण पोषण की सरकार कोई व्यवस्था करे। सुरेश यादव के बच्चे छोटे हैं, उसके परिवार में सरकारी नौकरी थी, सुरेश यादव सरकारी कर्मचारी था, उसके परिवार में एक नौकरी की व्यवस्था करें और कम से कम 4-5 करोड़ रुपये के अनुदान की व्यवस्था उसके परिवार के लिए की जाए। मैं इसकी मांग करता हूँ और चर्चा की भी मांग करता हूँ।

साथ ही एक मांग और करता हूँ कि लगातार मैं उस क्षेत्र से विधायक हूँ, मैं लगातार जिले के डी0एम0, एस0पी0 आदि अधिकारियों से उसकी सुरक्षा की गुहार लगाता हूँ। मैं स्वयं

एक साल पहले जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को जाकर बताता हूँ कि इसकी हत्या हो जाएगी, जेल में साजिश हो रही है। लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया जाता तो मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इसमें कम से कम रिटायर्ड सीनियर आई0ए0एस0 और रिटायर्ड सीनियर आई0पी0एस0 की एक तीन सदस्यीय टीम गठित कराके इस प्रकरण की जाँच होनी चाहिए कि क्यों एक व्यक्ति पर तीन-तीन बार जानलेवा हमला होता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। जिले में बैठे अधिकारी इसका संज्ञान नहीं लेते हैं और जिले में बैठे अधिकारी शासन तक इस बात को क्यों नहीं पहुँचाते और क्यों उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करते हैं ? मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं इस पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह जी ने अपने क्षेत्र की घटना के बारे में बताया, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। दोनों के बीच में पहले से ही जिस प्रकार की रंजिश बताई जाती है, उसी के कारण यह घटना घटी है। मान्यवर, इसमें क्राइम तहरीर पर क्राइम नम्बर-30/2023 दर्ज है, जो मृतक के भाई हैं दुर्गेश यादव उनकी नं0-30/2023 धारा 147, 148, 149 और 302 आई0पी0सी0 बनाम जलालुउद्दीन खाँ, मुइनुद्दीन खाँ पुत्र जलालुउद्दीन, राहुल यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव, संजय यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव, वशीर खाँ, निवासी ग्राम भद्दौर, थाना मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी तथा दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। सुरेश यादव और बृजेश यादव के शव को पोस्टमार्टम हेतु मर्चुअरी भेजा गया है। मान्यवर, मा0 सदस्य ने यह माँग की है, वैसे भी मान्यवर, आपके माध्यम से हम यह पूरे सदन का आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूरी तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ इसमें विवेचना होगी और जो आपने अपेक्षा की है कि किसी सीनियर अधिकारी के द्वारा हो। हम यह आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की निगरानी में या एडिशनल पुलिस अधीक्षक की निगरानी में इसकी हम विवेचना करवा लेंगे और हर तरह से दूध का दूध और पानी का पानी होगा और यह हम आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री राकेश प्रताप सिंह जी को सुना, मैंने मा0 मंत्री जी को सुना, उन्होंने उत्तर दे दिया है। मा0 सदस्य सन्तुष्ट हैं। यह नियम-56 में नहीं आता है, इसको अस्वीकार करता हूँ। बाकी तीन सूचनायें जिसमें से श्री ओम प्रकाश जी की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के सम्बन्ध में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। श्री कमाल अख्तर की मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के किसानों के मुआवजे के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। अब मा0 नेता विरोधी दल को बोलना है।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी के खड़े होकर बोलने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 रिजवी साहब आप क्या कह रहे हैं ?

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, हमारा भी नियम-56 में लगा है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 में मा0 सदस्य जियाउद्दीन रिजवी की सूचना पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया जाता है। अब बजट पर चर्चा जारी रहेगी मा0 श्री अखिलेश यादव जी ।

(सदस्य श्री ओम प्रकाश के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने के प्रयास पर)

आपकी सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है। जैसा सुबह आपने तय किया था, वही किया। श्री कमाल अख्तर जी की सूचना पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 सदस्य ओम प्रकाश जी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 70 से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं। यदि अध्यक्ष जी आप अनुमति दें तो उनको सुन जरूर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

किसमें जेल जा चुके हैं ?

श्री ओम प्रकाश-

दो मिनट सुन लें, मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने अनुरोध किया है।

श्री अध्यक्ष-

मैं सुनूँगा नेता प्रतिपक्ष ने कहा है तो मैं 100 प्रतिशत सुनूँगा, जो मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, मैं उसका पूरा संज्ञान लूँगा और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। 70 लोग किसमें जेल गये हैं बताइये, उसको हम सुन लें। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने अभी बताया कि 70 लोग जेल जा चुके हैं आप उस पर बताइये ।

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, जो पुलिस दरोगा की भर्ती है। मा0 अध्यक्ष जी, यह हमारी व्यवस्था है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर...

श्री अध्यक्ष-

पुलिस दरोगा की भर्ती नियम-56 में नहीं आती है फिर भी मैनें आपका ध्यान आकर्षित करने का काम किया।

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें आप यदि पूरे मामले का संज्ञान ले लें तो अब तक की यह ऐतिहासिक धांधली की परीक्षा हुई है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए आपकी सूचना को स्वीकार कर लिया है। मैंने सूचना अस्वीकार नहीं की है।

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, 9534 लोगों की भर्ती हुई है।

श्री अध्यक्ष-

यह तात्कालिक भी नहीं है और पर्टीकुलर भी नहीं है। यह मामला कई वर्षों से चल रहा है। यहाँ कोर्ट के अन्तर्गत भी चल रहा है।

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, जब आप पूरी बात पढ़ेंगे और पूरी बात को सुनेगें तो आप सोच सकते हैं कि यह सरकार की सबसे धांधली, गंदा और घिनौना परीक्षा का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आप इसको कल दीजिएगा तो उसको हम देखेंगे। कल दे दीजिए अब आज नहीं । आज नेता प्रतिपक्ष ने बोलना है। आप कल दे दीजिएगा । यदि ग्राह्यता में होगी तो कल जरूर ले लूँगा ।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, यह पूछ लीजिए मा0 सदस्य यह बताना चाहते हैं कि कितने सेकेण्ड में कितने आनर्सर लिख दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

जब आप पूरा डीटेल बताएंगे तो उस पर चर्चा हो जाएगी। अगर आपको जवाब चाहिए तो जवाब के लिए सरकार के पास भेजने हेतु मैंने उसे स्वीकार नहीं किया था। मा0 नेता प्रतिपक्ष मेरा निवेदन है कि मा0 ओम प्रकाश जी की अगर मैंने सुबह सूचना स्वीकार कर ली होती, मैंने दो सूचनायें सुनने के लिए स्वीकार की थीं तो उसका सरकार से जवाब आ गया होता। सुबह मेरा प्रयास होता है कि मैं 10:00 बजे बैठ जाऊँ और सवा दस तक मैं

इसका निस्तारण कर दूँ क्योंकि सम्बन्धित विभाग में जब तक जाएगा और वहाँ से जब तक उत्तर नहीं आएगा, तब तक मंत्री जी के पास उसका उत्तर नहीं होता है। मैं नेता विरोधी दल का पूरा सम्मान करते हुए, उसे सुनने के लिए तैयार हूँ लेकिन उसका जवाब भी तो आना चाहिए। जवाब के लिए मैंने कहा ही नहीं था तो जवाब आया नहीं होगा । जब जवाब नहीं आया होगा तो उसको सुनने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, 59 सेकेण्ड में 60 क्वेश्चन हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

आजकल बड़ा तेज जमाना है उसी के हिसाब से होते हैं। अब क्या हुआ किस संदर्भ में हुआ, जब तक संदर्भ सामने नहीं आएगा तब तक बात नहीं की जा सकती है।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, इसमें ऑलरेडी एफ0आई0आर0 दर्ज है।

श्री अध्यक्ष-

एफ0आई0आर0 कब दर्ज हुई थी ?

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, यह एफ0आई0आर0 वर्ष 2021 में दर्ज हुई है।

श्री अध्यक्ष-

वर्ष 2021 के बाद अब 2023 आ गया, तात्कालिक नहीं है न, तो कल सुन लेंगे। जब वर्ष 2021 में एफ0आई0आर0 दर्ज हुई और 2022 के बाद अब 2023 आ गया है, दो साल पहले की यह सूचना है, तात्कालिक सूचना नहीं है।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, इसमें जांच हो रही थी ।

श्री अध्यक्ष-

श्रीमन, आप स्वयं कह रहे हैं कि वर्ष 2021 में एफ0आई0आर0 लिखी गयी और नियम-56 जब आप पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे कि किसी भी तात्कालिक घटना के ऊपर, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको कल सुनूँगा, उसके लिए जिद नहीं करिए ।

(श्री सचिन यादव के अपने स्थान से अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नो सचिन, प्लीज सिट डाउन। माननीय नेता प्रतिपक्ष।

[01:00] वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

*** नेता विरोधी (श्री अखिलेश यादव)-**

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पर बोलने का मौका दिया है। सरकार का यह 7वाँ बजट है और सदन में जब कभी भी बजट पेश होता है तो सरकार यही कहती है कि सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ा बजट सरकार पेश कर रही है। पहले भी सरकार ने कई बजट पेश किये हैं और इतने बजट पेश करने के बाद भी जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, वह कई पैरामीटर्स में अभी सुधरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में 2 संस्थाओं के जो उत्तर प्रदेश के मानक हैं, डेटा आया है, वह मैंने पेश किया था। सरकार उसको स्वीकार नहीं कर रही थी। अपने बजट भाषण को शुरू करने से पहले नीति आयोग की जो रिपोर्ट वर्ष 2020-2021 की है, उसमें यू0पी0 की रैंकिंग क्या है, इसे मैं जरूर रखना चाहूंगा। वर्ष 2023-24 का बजट दिशाहीन बजट है जिसमें न वर्तमान की समस्याओं का सुलझाव है, न भविष्य का रास्ता । डबल इंजन की सरकार ने किसानों को यह वादा किया कि आय दोगुनी होगी। न किसानों की दोगुनी आय का कोई भविष्य दिखता है, न रोजगार है और न उसका विचार दिखायी दे रहा है। इससे जो सपना पूरे देश को और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाया जा रहा है कि 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी। यदि सरकार 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना देख रही है तो सरकार को नीति आयोग का जो सतत् विकास लक्ष्य वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट है, उसमें यू0पी0 कहां स्टैण्ड करता है, वह जरूर देखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, और तब यह जरूर देखना चाहिए कि एक बार दिन-रात विधान सभा चलाकर यह साबित करने की कोशिश की कि जो यू0एन0 के सस्टेनुबल गोल्स हैं, उन पर उत्तर प्रदेश की सरकार काम करेगी और दिल्ली की सरकार सहयोग करेगी । उस समय सरकार ने जो दिन-रात माननीय सदस्यों को जगाकर इसी सदन में बहस की थी यदि सही मायने में उन चीजों पर काम किया होता और अपने बजट को खर्च किया होता, विभागों को बजट दिया गया होता तो नीति आयोग को ऐसा नहीं कहना पड़ता । उनका पहला मानक, नो पॉवर्टी, जिसमें 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश नीचे से चौथे नम्बर पर है। यह जो आँकड़े मैं देने जा रहा हूँ यह मेरे नहीं हैं, जो आप लोग काम करते होंगें, वही नीति आयोग को पहुँचता है। जीरो हंगर, भुखमरी समाप्त करने में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 5वें नम्बर पर है। गुड हेल्थ एण्ड वेल बीइंग में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश नीचे से दूसरे नम्बर पर है। क्वॉलिटी एजुकेशन में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 18 वें नम्बर पर है। जेण्डर

---

† दिनांक 27-02-2023 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इक्वॉलिटी में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 14वें नम्बर पर है। क्लीन वॉटर एण्ड सेनीटेशन, 28 राज्यों की सूची में 20वें नम्बर पर है। एफोर्डेबल एण्ड क्लीन एनर्जी में हम 14वें नम्बर पर स्थान रखते हैं। डीसेन्ट वर्क एण्ड इकॉनामिक ग्रोथ, सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश 21वें नम्बर पर है। इण्डस्ट्री इनोवेशन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश 17वें नम्बर पर है, टू रीड्यूज इनइक्वेलिटी, समानता में कमी में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश अन्तिम पायदान पर है। यहां जरूरी है कि सरकार को समाजवादी सिद्धांत को समझना होगा। सबका साथ सबका विकास या राम राज्य बिना समाजवाद के सम्भव नहीं है। सस्टेनबल सिटीजन कम्युनिटीज में उत्तर प्रदेश 14वें नम्बर पर हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एण्ड प्रोडेक्शन में उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर हैं क्योंकि एक बार सरकार के ही एक माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम कृत्रिम बारिश करायेंगे । क्लाइमेट एक्शन में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 5वें पायदान पर है। लाइफ बिलो वाटर, वित्त मंत्री जी हो सकता है कि कुछ और सोच रहे हों, लाइफ बिलो वाटर, जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन है ही नहीं, सीमा ही नहीं है, इसलिए पैरामीटर की दिक्कत ही नहीं है, लिखा ही नहीं आपका, आप कुछ लिख रहे थे इसलिए मैंने पढ़ दिया। लाइफ फुल लैण्ड में उत्तर प्रदेश 20वें नम्बर पर है। पीस जस्टिस एण्ड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन्स में उत्तर प्रदेश 8वें नम्बर पर है। जब नीति आयोग के ये आंकड़े बताते हों, 6 बजट आपने पेश किये हों, 7वां बजट आपका है तो हम कहां खड़े हैं इसके बारे में सरकार को जरूर बताना चाहिए कि आखिरकार हम इन पैरामीटर्स में कैसे बेटर होंगे। मैं नीति आयोग की रिपोर्ट और उस दिन मैंने डेटा जो पढ़ा था उसकी रिपोर्ट, इण्डिया टूडे की रिपोर्ट, तीनों रिपोर्टों को अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से टेबिल करना चाहता हूं। फिर सरकार कहती है कि इन्वेस्टमेंट आयेगा और उन्होंने सपना देखा कि इस बार 33 लाख करोड़ के एम0ओ0यू0 किये गये हैं, लेकिन उन्होंने लगभग 19 हजार के एम0ओ0यू0 किए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये तस्वीर जो मेरे हाथ में आयी है वह सबने देखी होगी। हालांकि तस्वीर नहीं दिखा सकते लेकिन यह बड़ा मामला है इसलिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। ये टी0वी0 पर चली, सोशल मीडिया पर चली, अखबारों में छपी, न जाने कितना इसके लिए खर्च किया गया होगा। गमलों पर तो खर्च हुआ था, सफाई में खर्च हुआ था। आज एक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि जहां पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई वहां 20 दिन से सफाई नहीं हुई और जितने गमले, जितनी सजावट थी वह सब समाप्त हो चुकी है, सब खत्म हो गया, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हवा में 19 हजार एम0ओ0यू0 दिखाये गये थे और 33 लाख हवा में दिखाये गये थे। ये सबका सब इन्वेस्टमेंट हवा में ही दिखायी दे रहा है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और सरकार बगल में बैठे नेता सदन यह मानते हैं कि वन ट्रिलियन की इकानॉमी हासिल कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम विपक्ष की तरफ से सरकार से पहला प्रश्न मेरा यही है कि जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश की ग्रोथ है, जो नेशनल स्टेटिस आफिस, मिनिस्ट्री आफ स्टेटिक्स एण्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का डेटा कहता है, उसमें हमें क्या जी0डी0पी0 चाहिए होगी ? हमारी

ग्रोथ क्या हो, फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में 2021-22 में उन्होंने कहा कि 16.8 हमारी ग्रोथ रेट रहे, करेन्ट प्राइज पर, जो बजट स्पीच में है।

जो 2017-18 और 2021-22 की एवरेज ग्रोथ रेट है, वह 7.8 परसेण्ट है, इस सरकार का डेटा बताता है। मुझे यह बताते हुए खुशी है और वही मिनिस्ट्री के डेटा को बताते हुए कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, उस समय की जो एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ जी0डी0पी0 थी, वह 12.25 परसेण्ट थी, आपकी एवरेज ग्रोथ रेट उससे 5 परसेण्ट कम है। फिर कहते हैं कि हम 2023-24 में 19 परसेण्ट तक लेकर जायेंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी और नेता सदन से जानना चाहूँगा कि इसकी सोर्स क्या है ? हमसे तो हर चीज की सोर्स पूछी जाती है। कम से कम 19 परसेण्ट कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए आपके सोर्स क्या हैं ? फिर 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को पाने के लिए जो आपका लक्ष्य 2026-27 में है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि आपको 34 परसेण्ट की ग्रोथ रेट चाहिए। 34 परसेण्ट की ग्रोथ रेट कैसे सम्भव है ? जो आपका 6 साल का ट्रैक रिकार्ड है, वह आपकी ग्रोथ रेट कहाँ पर ले जा रहा है और अगले चार साल में उत्तर प्रदेश क्या उम्मीद कर सकता है। मैं तो बधाई दूँगा और आप जो सहयोग चाहें 34 परसेण्ट हासिल करने के लिए, हम आपके साथ खड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहूँगा, मुख्य मंत्री जी का अपना कोई इकोनॉमिक एडवाइजर होगा, उसको बदल देना चाहिए और अगर आपको कोई गुमराह करे, इकोनॉमिक एडवाइजर आपको गुमराह करे, जो आपको सही सच्चाई न बताता हो, उस आर्थिक सलाहकार का आप क्या करोगे ? नेता सदन जरूर बतायें कि आप 34 परसेण्ट कैसे हासिल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ कि हम समाजवादियों का घोषणा-पत्र ले लें, ये 34 परसेण्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसको हासिल करने के लिए, बड़ी बुद्धि की बात हो रही थी, बहुत बुद्धि है, जाने कहाँ बुद्धि है। अध्यक्ष महोदय, हालाँकि मुझे नहीं पता कि बुद्धि वर्ड अनपार्लियामेण्ट्री है या पार्लियामेण्ट्री है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे बतायें कि बुद्धि वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। एक संस्था को हायर किया गया है, केवल मुख्य मंत्री जी को, सरकार को झूठ बताने के लिए, सच्चाई से दूर रखने के लिए, झूठ इज अनपार्लियामेण्ट्री। आप 200 करोड़ रुपये दे रहे हैं कि डेटा को कैसे मैनेज किया जाये, जो आपने सच नहीं बोला कि हम 34 परसेण्ट हासिल कैसे करें। उस 34 परसेण्ट को साबित करने के लिए आप 200 करोड़ एक कम्पनी को दे रहे हैं। 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए आप 200 करोड़ खर्च कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो 6 साल में नहीं कर पाये, उन्हें 200 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इनके आर्थिक सलाहकार फेल, इतनी बड़ी कॉम्पीटेंट अधिकारी फेल, आपका प्लानिंग कमीशन फेल, आपका वित्त विभाग फेल, 200 करोड़ रुपये दे करके डिलॉयड कम्पनी से आप सुझाव लेंगे। सदियों सदियों से बनी संस्थाओं को आपने धक्का मार दिया। फिर सरकार कहती है कि 4.2 परसेण्ट अनइम्प्लॉयमेंट रेट है। जिस तरह गन्ने में गुमराह करते हैं। हम जितने भी विपक्ष के सदस्य हैं, वह यह पूछते हैं कि बकाया कितना है ? सरकार कहती है कि

हमने इतना पे कर दिया है। हम सभी माननीय सदस्य सरकार से यह जानना चाहते हैं कि बकाया कितना है ?

मान्यवर, कहते हैं हमने इतने लाख पे कर दिया। इसी तरह आप कहते हैं कि अनइम्प्लॉयमेंट रेट 4.2 प्रतिशत, यह एम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं हो सकता, रोजगार और नौकरी का डेटा नहीं हो सकता। अगर सच्चा आंकड़ा सरकार को बताना है तो एम्प्लॉयमेंट रेट बताना चाहिए एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है सरकार का और अगर यह बात 4.2 प्रतिशत की है या माननीय सदस्य जितने भी अपने क्षेत्र में जाते होंगे तो क्या उन्हें बेरोजगार नहीं दिखाई दे रहे होंगे, उनके क्षेत्र में बेरोजगारी नहीं है सबको नौकरी मिल गई। इसलिए सरकार को एम्प्लॉयमेंट रेट बताना चाहिए और जो विभागों में नौकरियाँ खाली पड़ी हैं वह सरकार कब भरेगी। अगर सरकार बताती है जो मैं आँकड़े पेश कर रहा हूँ वह सी0एम0आई0 का है। उसी का आँकड़ा देख लीजिये। क्या एम्प्लॉयमेंट रेट जो समाजवादियों की सरकार में था उससे आप नीचे गये हैं कि नहीं गये हैं। अगर हम सी0एम0आई0 का डेटा देखेंगे तो वर्ष 2017 से 2022 के बीच में आपके यहाँ गिरावट हुई है लोग हताश हो करके बैठ गये, नौजवान निराश हो करके बैठ गया और इतनी न उम्मीदी कभी नहीं थी जितनी न उम्मीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई। लोग नौकरियाँ और रोजगार की तरफ नहीं जा रहे हैं।

अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर सीमा की सुरक्षा पर आपको नौजवान को भेजना है जिसे वर्दी पहन करके सम्मान की बात हो उसे परमानेंट नौकरी चाहिए। पुरानी नौकरी जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस अग्निवीर जैसी व्यवस्था के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। सरकार जहाँ सपने दिखा रही है ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्री के लोगों का स्वागत कर रही है। वहीं एम0एस0एम0ई0 का क्या दोष है। जो सबसे ज्यादा नौकरी दे रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है। इन्वेस्टमेंट मीट में आये कूपन को ले करके बड़ी खातिरदारी हुई, कूपन बांटे गये। जब इन्वेस्टर्स लंच के लिए कम पड़ गये तो कूपन फ्री बंटे जिसको टाई पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके कूपन हासिल करके लंच कर लें, यह स्थिति थी। जो एम0एस0एम0ई0 है उसके लिये क्या किया। यह बड़े उद्योगपति पहले भी आये थे। आखिरकार जो एम0एस0एम0ई0 के लिए जो होना चाहिए था, सरकार ने क्या किया और सरकार बता रही है कि न जाने कितने कारखाने लग गये हैं, कितना फाइनेंस हो गया है। उनको बैक फाइनेंस नहीं दे रही है। अगर इनकी सरकार में एम0एस0एम0ई0 लगी है तो बिजली का कितना कनेक्शन लिया उन्होंने । केवल डेटा पर बता देना कि इन्होंने एम0यू0 कर लिया। यह सच्चाई से दूर होगा। जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं बताया जायेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना आप इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पायेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल है। एग्रीकल्चर हमारे नेशनल से विलो जा रही है और कम-से-कम जो फसलें पैदा हों उनकी एम0एस0पी0 सरकार दे । क्या सरकार ने एम0एस0पी0 दी है। अभी जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं वह जानते होंगे आलू की फसल चौपट हो गई है। किसान को जो कीमत मिलनी

चाहिए थी वह नहीं मिल पा रही है। इन्होंने घोषणा-पत्र में कहा था कि एक हजार करोड़ रुपये रखे जा रहे हैं कुछ फसलों को खरीदने के लिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो पोटैटो बेल्ट है आज तक सरकार ने आलू की कितनी खरीद की है। यह सरकार कम-से-कम आँकड़े हम लोगों के पास रख दे। ओ0डी0ओ0पी0 बहुत फेमस सरकार ने पूरा का पूरा प्रचार ओ0डी0ओ0पी0 वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट एक लम्बी सूची है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पास ओ0डी0ओ0पी0 की एक लम्बी सूची है। सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटीफाई किया है कि वहाँ पर कितना बजट दिया जायेगा, कितना ओ0डी0 ओ0पी0 में काम होगा। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर पूरे प्रदेश के जितने भी मा0 सदस्य बैठे है। मैं जानना चाहता हूँ कि आगरा में लेदर प्रोजेक्ट के लिए क्या बजट दिया है ? अलीगढ़ के ताले एवं हार्डवेयर के लिए कितना बजट दिया गया ? अम्बेडकरनगर हमारे बुनकरों से भरा पड़ा है। समाजवादी सरकार में उनको जो सुविधाएं मिलती थीं, वह सभी सुविधाएं उनसे छीन ली गयीं। ओ0डी0ओ0पी0 में कहा गया कि टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स को हम बढ़ावा देंगे। सरकार बताए कि टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स के लिए क्या बजट दिया है ? औरैया में फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग में देशी घी । हमारे मा0 सदस्य यहाँ बैठे हैं, कृपया बताएं कि देशी घी के लिए क्या बजट दिया गया है ? अयोध्या में जैग्री के लिए आपने क्या बजट दिया ? बलरामपुर में फूड प्रोसेसिंग के लिए कितना बजट दिया गया ? भदोही कार्पेट/दरी के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ कितना बजट दिया ? वही इन्फ्रास्ट्रक्चर, जो समाजवादी सरकार में बना था, उसके अलावा सरकार ने वहाँ पर क्या दिया ? फिरोजाबाद में ग्लास के लिए बजट क्या था ? हमीरपुर में शूज के लिए बजट क्या था, बांदा के लिए बजट क्या था, झांसी के साफ्ट ट्वॉयज के लिए आपने क्या बजट दिया ?

अध्यक्ष महोदय, कन्नौज परफ्यूम 'इत्र' के लिए जाना जाता है। पता नहीं सरकार को खुशबू से क्या नफरत है ? मा0 सदस्य ने कहा कि छापा पड़ गया। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पूछ लिया। अध्यक्ष महोदय, जिस पर छापा पड़ा था, वह भारतीय जनता पार्टी का आदमी था।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

अध्यक्ष महोदय, मैं मा0 सदस्य से कहूँगा कि अध्यक्ष जी से मिल लें, क्योंकि कानपुर के जिस उद्योगपति पर छापा मारा गया था, उससे समाजवादियों का कोई रिश्ता नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था, समाजवादी लोग कैसे बदनाम हों, समाजवादियों पर कैसे आरोप लगे, इसलिए वह छापा मारा गया और गलती डिजिटल इंडिया की थी ? क्योंकि जिसने 'इत्र' और परफ्यूम को लांच किया था, उसका नाम भी पी0 जैन है, वह भी कन्नौज का रहने वाला है, उसी मोहल्ले का है, उसका भी कारोबार कानपुर और मुम्बई में है। डिजिटल इंडिया में पता नहीं कम्प्यूटर में क्या दिखाई दिया कि जिसके यहाँ छापा मारना था, उसके यहाँ छापा नहीं मारा, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसी के यहाँ छापा मार दिया और अपनी खीझ मिटाने के लिए इन्होंने पुनः उसके ऊपर छापा मारा। ये छापा मार सरकार है।

मा0 अध्यक्ष महोदय, ये कोई नई चीज नहीं है, जो दिल्ली में रहता है, वही छापा मारता है। पहले भी सरकारें थीं, ये भी सरकारें हैं। कम से कम बी0जे0पी0 के लोगों ने कांग्रेस पार्टी से कुछ अच्छा सीखा है। कांग्रेस पार्टी भी छापा मारती थी। बी0जे0पी0 ने कम से कम कांग्रेस के रास्ते पर चलने का काम किया है। मा0 अध्यक्ष जी, बहुत नये-नये मा0 सदस्य जीत कर आये हैं, उनको कांग्रेस का पुराना इतिहास पढ़ना चाहिए। मेरठ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स का बजट क्या है ? तो आखिरकार ओ0डी0ओ0पी0 का इतना प्रचार क्यों है। जब आप उसके लिए बजट नहीं दे रहे हैं और जो वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में है, उसकी सच्चाई उत्तर प्रदेश कब तक जानेगा ? इससे पहले जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, जिसमें लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एम0ओ0यू0 साइन हुए। अध्यक्ष महोदय, देश के सब वे उद्योगपति आए, जो दूसरी इन्वेस्टमेंट मीट में आए थे, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के मित्र उद्योगपति नहीं आए...

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने शेम-शेम बोले)

कहां दो नम्बर का प्रचार हो रहा था, भारत को गर्व होता कि भारत का एक उद्योगपति दुनिया में नम्बर एक पर पहुंच गया है, हमें भी गर्व होता। हम भी कहते कि हमारा उद्योगपति इतना अच्छा करोबारी है कि दुनिया के नम्बर एक पर है, दुनिया के बड़े-बड़े उद्योगपतियों को उसने पछाड़ दिया है। मान्यवर, केवल एक रिपोर्ट ने कहां दुनिया के दूसरे नम्बर के और अब दुनिया के किस नम्बर पर है कोई नहीं जानता है कि कहां पर है। अध्यक्ष महोदय, मित्र की पहचान तभी होती है जब बुरा वक्त आता है। क्या बी0जे0पी0 ने अपने मित्र को छोड़ दिया है ? कम से कम इस इन्वेस्टर मीट में तो मित्र आते और अगर मित्र को छोड़ दिया तो हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं वह एक्सप्रेस-वे से कैसे लखनऊ आयेंगे। जो मॉडल आपने अपनाया क्या आपका वह एक्सप्रेस-वे बन जायेगा ? जिस मॉडल पे आप उन उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में लेकर आये क्या उस मॉडल से आपकी सड़क बन जायेगी और मुझे खुशी है इस बात की क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहता था कि अगर आप स्पीड को बढ़ा देंगे और जब मैंने किसी भी 4 लेन एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया होगा तो मैं यह जरूर कहता था और मैं अमरीका की एक कहावत बोलता था। अभी रोड ट्रांसपोर्ट सरफेस मिनिस्टर आए थे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में अमरीका से बेहतर सड़कें बना देंगे, या अमरीका के बराबर का इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा।

मैं यह बात कहता था कि अमरीका ने सड़कें बनायी हैं और अमरीका को सड़कों ने बनाया है और मैंने हमेशा कहा कि 'इफ यू केन डबल दी स्पीड, ट्रिपल दी इकोनॉमी' नेता सदन शायद यह बात आपकी समझ में आ गयी होगी जो मैंने कही है और आपका एक्सप्रेस-वे कैसा बना है, पूरी गाड़ी अन्दर चली गयी लोग बड़ी मुश्किल से बाहर निकले थे। अगर मुझे वह वीडियो मिल जाता तो शायद दुनिया में देखने को मिलता कि असली शूटिंग यह होती है और जो बात एक्सप्रेस-वे की है वह कैसे बनेगा वह मॉडल क्या था, उस मॉडल पर क्या आपका गंगा एक्सप्रेस-वे बन जायेगा ? जो आपने समय तय किया है क्या वह एक्सप्रेस-वे तब तक बन जायेगा ? जिस मॉडल पर आपने दिया है अपने मित्र उद्योगपति को, मुझे लगता है कि

नहीं बन पायेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ और मेरा सुझाव है कि दिल्ली की सरकार को और मुझे लगता है कि दिल्ली वाले कम सुनते होंगे आपकी और अगर यह मेरी बात गलत है तो आप बताओ कि दिल्ली वालों ने आपको किस एक्सप्रेस-वे के लिए बजट दिया है। यह मौका है कि आप अपना एक्सप्रेस-वे दिल्ली वालों को दे दो और दिल्ली वालों से बजट लेकर बनवा लो, नहीं तो यह बनने वाला नहीं है। क्योंकि जिनको आपने दिया उनके साथ तो आप खड़े ही नहीं हैं। मैं केवल एक्सप्रेस-वे की बातें नहीं कर रहा हूँ जो समाजवादी सरकार में काम हुए थे, इनका पिछली बार का पी0डब्ल्यू0डी0 का बजट रु0 27 हजार 470 करोड़ का था और खर्च हुआ कितना, यह केवल रु0 7 हजार 570 करोड़ हुआ। इसको मैं 30 प्रतिशत मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी मिलेगी, ऐसे हमें जी0डी0पी0 की 34 प्रतिशत ग्रोथ रेट मिलेगी ? समाजवादियों ने केवल एक्सप्रेस-वे नहीं बनाये थे To double the speed, tripple the economy के लिए। अगर नोएडा में एलीवेटेड सड़क की जरूरत थी तो एलीवेटेड सड़कें बनी हैं, नोएडा को गाजियाबाद से जोड़ने के लिए, नोएडा के अन्दर ट्रैफिक को ईज आउट करने के लिए। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मैट्रो समाजवादी सरकार की है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। गाजियाबाद की एलीवेटेड सिंगल पेयर सिक्स लेन एलीवेटेड रोड अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। पिछले 06 साल में अगर कहीं एलीवेटेड सड़क बनायी हो तो सरकार हमें बतायें।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

जिस समय वह बनी थी, वह देश की इकलौती सड़क थी । नेता सदन सिंगल पेयर सिक्स लेन सड़क कहीं तो बना देते ? हम पर तो बुद्धि नहीं है, हम तो एक ही बना पाये। हम तो कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में कोलकाता, मुम्बई, बंगलौर, चेन्नई व हैदराबाद में सिंगल पेयर सिक्स लेन एलीवेटेड रोड जितनी गाजियाबाद में रिकॉर्ड टाइम में बनायी थी, पूरे देश में कहीं नहीं बनी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन से पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने 06 साल के कार्यकाल में एक भी एलीवेटेड सड़क बनायी हो तो हमें बता दें। हम पर तो बुद्धि नहीं है, आप पर तो बहुत है। अगर बनायी हो तो बता दें, अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

कल बतायेंगे।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, अगर बनायी हो तो बता दें, मैं बैठ जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आज आप बोलो, वह कल बतायेंगे।

श्री अखिलेश यादव-

केवल यह दो सड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरठ से करनाल फोर लेन सड़क समाजवादी सरकार की बनी हुई है (मुजफ्फरनगर से देवबंद, देवबन्द से सहारनपुर, मुरादाबाद से सम्भल अमरोहा तक जुड़ा है, बरेली से बदायूँ, बरेली से उत्तराखण्ड। एन0डी0 तिवारी जी हमारे पूर्व मुख्य मंत्री रहे, मैंने उनके नाम पर घोषणा की थी कि उनके नाम पर 'पं0 नारायण दत्त तिवारी फोर लेन मार्ग', लखनऊ से मलिहाबाद हो करके हरदोई से शाहजहाँपुर फोर लेन, सीतापुर से लखीमपुर फोर लेन, एटा-करौली से लेकर मैनपुरी और मैनपुरी से लेकर इटावा तक फोर लेन। आपके शिकोहाबाद से लेकर बेवर तक फोर लेन, कन्नौज-तिर्वा से लेकर विधूना तक फोर लेन, छिबरामऊ से लेकर सौरिख फोर लेन, बहराइच से श्रावस्ती फोर लेन, गोण्डा से बलरामपुर आर0सी0सी0 की सड़क बनायी थी जिससे अगले 30-40 वर्षों तक वह टूटे नहीं। रामनगर से गोण्डा वाली फोर लेन सड़क, आपके देश की सबसे खराब सड़क कालपी से हमीरपुर फोर लेन, उरई-जालौन से लेकर ओल्ड औरैया फोर लेन, आजमगढ़-मऊ फोर लेन, आजमगढ़-जौनपुर-इलाहाबाद फोर लेन, बावतपुर एअरपोर्ट से लेकर भदोही फोर लेन, सोनभद्र-बनारस फोर लेन की सड़कें बनायीं....

(प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं)

जब ये सड़कें बनती हैं तब बजट खर्च होता है। अरे! आपके पास तो डबल इंजन है, क्या दोनों इंजन एक-दूसरे से टकरा रहे हैं ? आप क्यों नहीं सड़क डिजाइन कर पाये, आपको किसने रोका था ? मैं तो कहूँगा अध्यक्ष महोदय, 06 साल के अन्दर यू0पी0 बजट के हेड से आपने फोर लेन सड़क बनायी हो तो आप हमें बता दो ?

(प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

(नेता विरोधी दल अपने आसन पर बैठ गये।)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर।)

श्री अध्यक्ष-

वह कल बतायेंगे। आप लोग शान्त रहें। कल सही तरीके से जवाब आयेगा ।

श्री अखिलेश यादव-

जबाव आयेगा, फिर हमें मौका मिलेगा। अभी तो केवल डेवलपमेंट पर बात हो रही है। मैं अभी एन0एच0ए0आई0 की बात नहीं कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्टेट बजट के फोर लेन हेड पर बात कर रहा हूँ और हो सकता है कि इस समय मेरे दिमाग में कुछ बात न आ रही हो फोर लेन की वह शायद एक भी नहीं बनाई है अगर एक भी बनाई हो तो बता दीजिए कि स्टेट हेड से क्या बनाया है। स्टेट बजट के एन0एच0ए0आई0 से मैंने कहा कि देश में एक्सप्रेस-वे के लिए बजट मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा लोक सभा के सांसद यू0पी0 जिताता है। लेकिन एक्सप्रेस-वे के लिए बजट

उत्तर प्रदेश को नहीं मिलता है। वह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ने के लिए सड़कें बनाई गई थीं जिससे कि कम से कम हमारा मोबिलिटी फास्ट हो जाए। बिजली सप्लाई के लिए सरकार में जो पॉवर प्लांट बनाए गए थे उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज का 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट समाजवादियों की देन है एटा में जवाहरपुर समाजवादियों की देन है 3X660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो बन करके तैयार हो जाएगा दो हजार मेगावाट के लगभग बिजली मिलेगी।

ललितपुर में एम0ओ0यू0 बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार का था, लेकिन बहुत सारे एन0ओ0सी0 उसमें नहीं मिले थे अगर उस प्रोजेक्ट को दो हजार मेगावाट को किसी ने आगे बढ़ाया है तो समाजवादी लोगों ने आगे बढ़ाया है। चाहे इलाहाबाद के हों, चाहे प्राइवेट प्लांट हों, चाहे एन0टी0पी0सी0 का हो, समाजवादी सरकार में आगे बढ़े, अनपरा का बढ़ा तो आज जो बिजली बन रही है वह समाजवादियों की देन है, भारतीय जनता पार्टी बताए कौन सा नया प्लांट इन्होंने अपने कार्यकाल में शिलान्यास करके उद्घाटन कर दिया हो कोई उद्घाटन किया हो तो बताइए। यह है इन्फ्रास्ट्रक्चर यह हमारे स्टेट को ग्रोथ पर ले जाएगा। पुलिस हेडक्वार्टर समाजवादियों की देन है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग आप देखते होंगे बहुत ऐतिहासिक शानदार बनी है, जो डायल 100 बनाया गया था रिस्पॉन्स सिस्टम वह वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम था और मैंने पहले ही जब भाषण दिया था उस समय ही मैंने कहा था कि जिस तरीक से दुनिया में दूसरे देश अपनी पुलिस को इक्विप्ड करते हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर से उस तरीके से पुलिस को इक्विप्ड किया, डायल 100 डिजाइन किया और उस समय के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको विदेश भेजा जिससे वह सीख करके आएं कि आखिरकार काम कैसे करते हैं। वह सीख करके आए और डिजाइन किया उसके बाद यू0पी0 को वन ऑफ द बेस्ट डायल 100 सिस्टम मिला। इस सरकर ने केवल यह किया डायल 100 को डायल 112 कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के सामने हूबहू सा दिखता हुआ फ्रन्ट ऐलिवेशन लोक भवन का है मुझे याद है उस समय जो हमारे नये गवर्नर थे उन्होंने कहा कि इस तरह के नाम एनेक्सीज या सचिवालय या उस तरह के नाम व दूसरे तरह के नाम हैं कोई दूसरा नाम रखा जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि देश के सबसे बड़े कवि आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से मैंने नाम पूछा उन्होंने लोक भवन बताया और लोक भवन नाम उसका रखा गया सामने जहाँ मुख्य मंत्री जी बैठते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी नहीं पूछा और न कभी जानना चाहा, क्योंकि उस स्थान पर तो जनता बैठाती है वह बिल्डिंग कैसी बनी है जो उस हॉल में आता होगा और यह मुख्य मंत्री के लिए है कोई मेरे लिए नहीं है और न ही किसी और के लिए है जो मुख्य मंत्री बनेगा उसके लिए है वह, कि अगर मुख्य मंत्री ऑडीटोरियम में कार्यक्रम करना चाहें तो वह कार्यक्रम कर सकता है, ऑडिटोरियम में कोई प्रेजेन्टेशन करना चाहे वह कर सकता है। आपके पास दूसरी जगह नहीं थी कि अगर आप कोई बड़ा इवेन्ट शोकेस करें तो आपको वैसा ऑडिटोरियम

सरकार का मिल जाएगा। उसके बराबर का अगर कोई ऑडिटोरियम है तो बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के नाम पर लोहिया यूनिवर्सिटी में बना है वह भी नेता जी ने बनवाया था और यह लोक भवन वाला मैं तो कहता हूँ नेता सदन को हम तो चार साल आने वाले नहीं हैं आपके यहां बदला बदली हो सकती है हम तो चार साल आने ही वाले नहीं हैं। 27 में चुनाव होगा कम से कम जे0पी0एन0आई0सी0 ऑडिटोरियम तो बना ही देते। जैसे और जगह आपने अपनी पट्टियाँ लगवा ली हैं नाम लिखवा लिया है उसमें भी नाम लिखा लो, क्योंकि वह ऑडिटोरियम अगर बन करके तैयार हो जाता समय से तो मैं दावा कर सकता हूँ वह विज्ञान भवन से ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी वाइज यह ऑडिटोरियम आपके उत्तर प्रदेश के पास होता।

अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मीट करते तो जो इन्वेस्टर्स आते उनको भी लगता कि वह किस जगह पर बैठे हैं। मुझे याद है कि बनारस में एक 'रूद्राक्ष' ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ था। वह ऑडिटोरियम 1200 की कैपेसिटी का है, लेकिन उसका न जाने कितना प्रचार किया गया। यह जो जे0पी0एन0आई0सी0 का ऑडिटोरियम है उसमें गाड़ी पार्किंग की कैपेसिटी 1200 है तो समझ लीजिये ऑडिटोरियम कितना बड़ा होगा...

(विपक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

मुझे कोई शिकायत नहीं है कि आपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा वहाँ लगायी है। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उन्हें अकेले मत खड़ा करो। उनके नाम पर उसी जगह पर शिलान्यास की हुयी यूनिवर्सिटी आप 06 साल में नहीं बना पाये और वह यूनिवर्सिटी कहाँ चल रही है। नेता सदन, राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट के नाइन्थ फ्लोर पर चल रही है, नाइन्थ फ्लोर पर जाइये। बताइये, 06 साल में आप एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाये। मा0 अध्यक्ष महोदय, नेता सदन को अपनी यूनिवर्सिटी बनानी थी, क्योंकि खुद चांसलर बनना था तो वह एक साल में बन गयी तो सरकार की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकती। लोक भवन तो अच्छा ही लगता होगा। मैं जब टेबल को देखता हूँ तो लगता है कि समाजवादियों की खरीदी हुयी टेबल पर आप दस्तखत कर रहे हैं।

(इस मध्य किसी सदस्य द्वारा बीच में कुछ टोका-टाकी करने पर)

वह बात बाद में आयेगी अभी नहीं। मान्यवर, मैं नेता सदन का भाषण सुन रहा था कि हम सबका कुछ न कुछ योगदान है तो स्वीकार करें कि पूरे देश में अब तो और भी मुख्य मंत्री ऑफिसेज बना रहे हैं, लेकिन कोई भी मुख्य मंत्री होता तो पूरे देश में मुख्य मंत्री ऑफिस में काम करने के लिये अगर सबसे अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर कहीं का होता तो उत्तर प्रदेश का होता। हालाँकि पेड़-पौधों से आपको कोई बहुत रुचि नहीं है। आपको गमलों से रूचि है। गमले लगाये, लेकिन सूख गये, चोरी हो गये। पता चला कि करोड़ों के गमले चोरी हो गये और जिन्होंने गमले चोरी किये उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हो गयी। आप कम से कम समाजवादियों जैसा काम करते। आप मुख्य मंत्री आवास में फ्लॉवरिंग करते हुये पेड़ देखते होंगे, लेकिन आप

उन पेड़ों का नाम नहीं जानते होंगे। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं दावा कर सकता हूँ कि नेता सदन उन पेड़ों का नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनको पेड़ों से रुचि कम है। एक-एक पेड़ पसन्द करके लगाया गया और अगर आप गवर्नर हाउस से थोड़ा-सा घूम जायेंगे, वहाँ पर आज कल जो पेड़ फ्लॉवरिंग कर रहे हैं, उनमें जो पर्पिल फ्लॉवरिंग आ रही है वह टवुविया का पेड़ है और आपके यहाँ पर जो पेड़ पिंक और यलो फ्लॉवरिंग करता होगा, जिसकी पत्तियाँ हट जाती हैं, वह क्रोशिया का पेड़ है। समाजवादियों ने जो पेड़-पौधे लगाये वह आज भी फ्लॉवरिंग कर रहे हैं, लेकिन इनके गमले सब सूख गये। हालाँकि जो जनेश्वर मिश्र पार्क तथा लोहिया पार्क बना है, हमें उम्मीद है कि यह सरकार भी कोई न कोई पार्क बनायेगी और अगर पार्क नहीं बनायेगी तो किसी का नाम ही बदल देगी। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि कुकरैल नाले पर रिवर फ्रंट बनेगा। नाले पर रिवर फ्रंट कहाँ बनता है ? नाले का पानी तो साफ किया जाता है।)

मा0 अध्यक्ष महोदय, नेता सदन अपना पुराना प्रेस नोट निकलवा सकते हैं और देख सकते हैं। जनेश्वर मिश्र पार्क अथवा अन्य पार्कों की जो दुर्दशा है उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आपने पेड़ कटवाये लगवाये नहीं । मैं यह बात इसलिये उठा रहा हूँ कि डबल इंजन की सरकार है, आपको पेड़ नहीं काटने पड़ते। कैन्टोन्मेंट की दोनों सड़कें जो आप ओ0डी0ओ0पी0 की होर्डिंग्स से छिपा रहे थे अथवा कभी कुछ और लगा करके उसके पीछे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे तथा अर्जुनगंज होकर इन्वेस्टर्स मीट के लिये जो सड़क जाती है, मा0 अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि इस सड़क को सिक्स लेन विद साईकिल ट्रैक बनाने के लिये मैंने प्रस्ताव दिया था। डिफेन्स मिनिस्ट्री से पूरे मिनट्स तक तैयार हो गये थे और अधिकारियों के बीच में लेकिन एक-दूसरे को जो लैण्ड ट्रांसफर होनी थी उसका भी फैसला हो गया था, जैसे ही सरकार चली गयी आज तक वह सड़क चौड़ी नहीं हो पायी है। शायद अगर पुराना काम देखा होता और आगे बढ़ाया होता तो आपको होर्डिंग्स से कुछ छिपाना नहीं पड़ता। न आप की कमाण्ड वाली सड़क बन पायी और न ही अर्जुनगंज वाली सड़क बन पायी। इसलिए जितने भी वी0आई0पी0 आए उनको आपने छिपा दिया, होर्डिंग के पीछे की चीजें आपने छिपा दी, क्योंकि होर्डिंग के पीछे कुछ था ही नहीं। अगर पीछे कुछ होता तो शायद इन्हें होर्डिंग न लगानी पड़ती। बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेज के दावे हो रहे हैं और मेडिकल कॉलेज के दावे ऐसे हो रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर हो गया हो । स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं बची है। दुःख होता है जब अखबारों में तस्वीरें छपती हैं कि आज इस अस्पताल से मरीज लौटा दिया गया, आज यहां पर ऑक्सीजन नहीं मिली, आज यहां पर गन्दगी थी, बिजली नहीं है, टॉर्च में इलाज चल रहा है, डाक्टर नहीं था, नर्स नहीं थी, वार्ड ब्वाय ने इंजेक्शन लगा दिया। ऐसी तमाम खबरें हैं जो अखबारों में देखने को मिलती हैं। कोई पिता अपने परिवार के सदस्य को, पुत्र को कैसे ले जा रहा है, कोई अपनी बूढ़ी माँ को किसमें रख कर ला रहा है। आखिरकार इस सरकार ने स्वास्थ्य का क्या कर दिया है ? लखनऊ की ओ0पी0डी0 बता देना

आपकी उपलब्धि नहीं हो सकती और यह आपने सरकारी उपलब्धि बतायी है, सरकार के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की। अगर यहां पर इतनी ओ0पी0डी0 है तो सोचिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी ओ0पी0डी0 कितनी होगी ? और मुझे तो लगता है जिस तरह से यह पी0पी0पी0 मोड पर मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं, इस सरकार की नियत और मंशा यही है कि स्वास्थ्य विभाग सरकार के हाथों में न रहे यह प्राइवेट हाथों में चला जाए। अगर स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो गरीब इलाज कहां से करायेगा। जो एम्बुलेंस 102, 108 चलाई गयीं थीं और जो अत्यधिक मेडिकल चीजों से लैस थीं आखिरकार समय पर क्यों नहीं पहुँच रही हैं ? आप फोन करते रहिए, एम्बुलेंस पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी कुछ पता नहीं है। कई मरीज अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। सरकारी अस्पताल चाहे लोहिया इंस्टिट्यूट हो, चाहे पी0जी0आई हो, चाहे के0जी0एम0यू0 हो और चाहे बलरामपुर हो इसकी ओ0पी0डी0 तो आपको पता है, लेकिन कभी प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स की ओ0पी0डी0 आप देखोगे तो आपको दुःख होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश का खासकर ईस्ट यू0पी0 का पूरा का पूरा मरीज लखनऊ की तरफ भागता चला आ रहा है। कई बार हमने देखा है, हम लोगों ने खुद सिफारिश की है लोग कहते हैं कि पी0जी0आई0 में बेड दिलवा दो और अगर पी0जी0आई0 में बेड नहीं मिलता है तो मेदान्ता में दिलवा दो। क्या प्राइवेट अस्पताल में ईलाज हो पायेगा ? मेदान्ता हॉस्पिटल जो आप लखनऊ में प्राइवेट देख रहे हैं वह अगर किसी की देन है तो वह नेता जी और समाजवादी सरकार की देन है। किसी और की देन नहीं है, अगर नेता जी जमीन न दिलवाते तो यह अस्पताल न बन पाता। जो आपको टाउनशिप दिखायी दे रही है, हाईटेक सिटी दिखायी दे रही है वह नेता जी की देन है यह जो टाउनशिप बड़ी वाली दिखायी दे रही है जिसको आप सभी इन्वेस्टर्स को दिखा रहे थे और कह रहे थे कि लैण्ड बैंक है हमारे पास, यह सब है। यह हाईटेक सिटी का कॉनसेप्ट हाईटेक सिटी की प्लानिंग अगर किसी के समय आई है तो वह नेता जी के टाईम पर आई थी, वही आपको दिखायी दे रही है और वहीं पर मेदान्ता अस्पताल है। बगल में लुलू मॉल, नेता सदन गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। प्रदेश को अच्छा लगता अगर स्टेरिंग आपके हाथ में होती । आप स्टेरिंग पर नहीं थे, आप बगल में बैठे थे। लुलु मॉल वह समाजवादियों की देन थी उसकी वजह से लुलु मॉल लखनऊ में दिखायी दे रहा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रदेश की पूरी स्टेरिंग को संभाल रहे हैं।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैंने गलत नहीं कहा है। मैंने यह कहा कि बगल में न बैठे होते और स्टेरिंग खुद हाथ में लिए होते। इकोनॉमी का एडवाइजर बता रहा है कि 34 प्रतिशत ग्रोथ रेट हो जाएगी और आपको डिलायड हायर करना पड़ रहा है, 200 करोड़ रुपये देने पड़ रहे है। आपको 200 करोड़ नहीं देने पड़ते। लुलु मॉल और आपके यहां का नवीन मार्केट मैं चाहता था

कि पार्किंग से लेकर अच्छा बन जाए, सुन्दर बन जाय । कम से कम लोग आयें, कुछ समय गुजारें। शॉपिंग करने में आसानी हो, क्योंकि अरबन पापुलेशन बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अरबन सेन्टर्स भी बने। समाजवादियों की कोशिश थी कि अरबन सेन्टर बने। कई बार यह बात होती है कि सरकार अच्छी चीज नहीं बना सकती है। सरकार की चीज काम चलाऊ बनती है। इसलिए उस चैलेन्ज को मैंने स्वीकार किया और लखनऊ में आवास विकास के बजट से, सरकार के बजट से मैंने एक मॉल बनवाया था। जो आज प्लासिओ मॉल हो गया। मैं तो कहता हूं, माननीय सदस्यों में शायद ही कोई छूट गया हो जो उस मॉल में न गया हो। चाहे वह सत्ता पक्ष के हों चाहे हमारे विपक्ष के साथी हों। आज भी आस-पास के शहरों में बल्कि दिल्ली तक अगर कोई बेहतर मॉल दिखाई दे रहा है तो वही जो समाजवादियों ने बनाया था। आपने तो केवल एक काम किया। उसको बेच दिया। नेता सदन को पता है कि बिका कि नहीं बिका, मुझे नहीं पता। क्योंकि नेता सदन के जिस माननीय सदस्य से सम्बन्ध अच्छे हैं उसने एक पत्र लिखा था, उसकी जांच कभी नहीं हुई । नेता सदन को पता होगा।

अध्यक्ष महोदय, नेता, सदन के सबसे प्रिय माननीय सदस्य, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मॉल बिक गया है यह नहीं बिकना चाहिए था। यह बात सच है कि नहीं, नेता सदन ? अगर नेता सदन लूलू मॉल देखकर आयेंगे तो मैं नेता, सदन से कहूंगा कि जो मॉल बिक गया है। आपका, सरकार का नहीं बचा है। उस मॉल को भी कभी देखकर आयें। जब देखकर आयेंगे तो आपको लगेगा कि हां जिसने इस कान्सेप्ट को तैयार किया होगा। जिस आर्किटेक्ट ने इसको सेलेक्ट किया होगा, जिसने इसमें प्लानिंग की होगी उसमें जरूर थोड़ी बहुत बुद्धि रही होगी। अगर आपने उस मॉल को नहीं देखा तो नेता सदन आपने दुनिया में कुछ नहीं देखा। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में आप चले जाते तो हम लोग भी खुश होते और कम से कम रास्ता खोल देते कि हमारा एक मुख्य मंत्री वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में पहुंच गया तो हमें भी मौका मिल जाता। हम भी वहां तक पहुंच जाते। लेकिन आप ही नहीं जा पाये। यह मैंने अखबारों में पढ़ा था कि आपको जाना था। अध्यक्ष महोदय, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर नेता सदन भी दावोस पहुंच गये होते, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में, स्वीटजरलैण्ड में तो यह 34 लाख का आँकड़ा दिखाना पड़ रहा है। यह 34 लाख नहीं होता। यह आँकड़ा 50 लाख करोड़ तक पहुंच जाता। आप नहीं जा पाये । हमारे उत्तर प्रदेश को घाटा हो गया। कितना बड़ा घाटा हो गया। मुझे उम्मीद है कि अगली बार आप जरूर जायेंगे। जो हेल्थ का बजट था 44387 करोड़। क्या वजह है कि आप बजट तो ऐसा दिखाते हैं कि यह बजट है और खर्च कितना हुआ है ? मात्र 21 हजार करोड़, आप आधा बजट नहीं खर्च कर पाये। तभी हमारे माननीय उप मुख्य मंत्री परेशान होते हैं। क्यों छापे मारते हैं। छापा मारिए वित्त मंत्री के यहां पर। अध्यक्ष महोदय, छापा मार रहे हैं अस्पतालों में और पैसा वित्त मंत्री के यहां पर रखा है। क्या छापा मारते हैं आप ? आप सही जगह छापा नहीं मार पा रहे हैं। क्यों छापा मारते हैं आप ? मुझे अच्छा लगा हालांकि मैंने गवर्नर स्पीच में वह बात कही थी फिर मैं कहता हूं। एक तस्वीर मैंने रसूलाबाद

की लगा दी। हमारे डिप्टी सी0एम0 ने इतनी जल्दी साफ करा दिया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। स्टाफ, दवाई, सब कुछ पहुंच गया। मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन जो लिफ्ट समाजवादियों ने लगवाई थी वह आज भी चालू नहीं है। कम से कम लिफ्ट तो चालू करवा दें। एक जगह की है। आपकी बुराई इसलिए नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपको बजट ही नहीं दे रहे हैं। अगर 44 हजार का बजट है और आपको 21 हजार दे रहे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है। आप रॉंग नम्बर डायल कर रहे हैं। तभी आपका मेडिकल कालेज नहीं बन पा रहा है। फिर क्यों बनेगा मेडिकल कालेज जो आप सपना देख रहे हैं कि 45, 54, 50 मेडिकल कालेज हर डिस्ट्रिक्ट में हो जायें। पी0पी0पी0 मॉडल पर हो जायें। जब वित्त मंत्री जी अपने मेडिकल कालेज में बजट नहीं दे रहे हैं।

मान्यवर, मैंने पहले भी पढ़ा था और आज भी पढ़ देता हूं। प्रोफेसर के स्वीकृत 21 पद हैं और 9 कार्यरत हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के 31 पद हैं और कार्यरत 6 ही हैं एडिशनल प्रोफेसर के 53 पद हैं 30 कार्यरत हैं और सीनयर रेजीडेंट के 36 पद हैं 18 ही आपने किये हैं। इसी तरह से यह तो एक मेड़िकल कालेज का है और अगर 45 मेडिकल कॉलेज का निकलवायेंगे तो वहां जगह ही जगह खाली पड़ी है। आप क्यों रोक रहे हो आप क्यों बजट नहीं देते हो क्यों नहीं पदों को भरते हो आप और यही हालत आजमगढ़ की होगी यही हालत अम्बेडकर नगर की होगी और यही हालत के0जी0एम0यू0 की है। पी0जी0आई0 के प्रोफेसर छोड़ कर जा रहे हैं अगर आपको प्रोफेसर व डाक्टर को रोकना है तो आपको बजट बढ़ाना ही होगा। जो सुविधा पुरानी सरकार ने दी है उससे बेहतर सुविधा दीजिए। कैंसर मेडिकल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया जो बनकर तैयार हो गया और सरकार ने नाम बदल दिया, लेकिन हमें दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन आप बजट क्यों नहीं दे रहे हैं। वहां के हालात अभी तक 6 साल में कोई परमानेंट डायरेक्टर नहीं है अध्यक्ष महोदय। वहां 121 फैकल्टी सैंक्शन हैं और आप बताइये कि कितनी इस समय पर वहां मौजूद हैं। अभी मैंने एक सवाल पूछा था कि 93 पदों का विज्ञापन निकला, लेकिन कैंसिल हो गया आप ही बताइये कि क्या मानकानुसार है या नहीं है और नई मेडिकल काउंसिल बनी है इसमें कम से कम डिप्टी सीएम यह देख लेना कि आप छापा मारते रहें और अधिकारी एन0एम0सी0 के मानक को दूर कर दें इसलिए कम से कम मानक जो हो वह उसके अन्दर होने चाहिए। आप क्या सुविधा दे पा रहे हैं आप छठा कमीशन तक लागू नहीं कर पा रहे हैं। वहां डाक्टर रहेंगे कहां वर्क फोर्स है ही नहीं वहां पर मेंटिनेंस का कोई इन्तजाम ही नहीं है और कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां लगा हुआ ही नहीं है, इसलिए कम से कम बजट तो दिया जाए और अगर बजट खर्च नहीं होगा तो आखिरकार उत्तर प्रदेश को 36 परसेन्ट की ग्रोथ रेट जो होनी चाहिए वह नहीं हो पायेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास रेवेन्यू ही नहीं आ रहा हो और कलेक्शन ही नहीं हो पा रहा हो और आप केवल फीगर्स दिखा रहे हो जनता को और जो फीगर्स दिखा रहे हैं आप वह सिर्फ दिखावा ही है।

आपका जो संकल्प-पत्र है उसको आप पालिसी में क्यों नहीं ला रहे हो यह संकल्प-पत्र किसलिए था अगर ये संकल्प-पत्र था आपका तो विभाग वाइज इसमें बजट ही नहीं दिखाई देता है। आप आलू, टमाटर, प्याज के लिए एक हजार करोड़ रुपये दे रहे हैं तो इसमें लहसुन भी जोड़ दीजिए तभी बात पूरी होगी, क्योंकि कई हिस्सों में लहसुन भी बहुत खरीदा जाता है इसमें उम्मीद करता हूँ कि एक हजार करोड़ का बजट रखा जाएगा इन फसलों को खरीदने के लिए। आप 10 लाख रोजगार व स्वरोजगार की बात करते हैं। जब डेटा सेंटर आप बनाए और वह जब डेटा सेंटर बनेगा और कॉलेज जाने वाली प्रत्येक महिला को मुफ्ट स्कूटी मिलेगी क्या इस बजट में है चुनाव तो इसी वर्ष है या अगले वर्ष है। चुनाव लगता है अगले वर्ष है और काशी, मेरठ, बरेली, झांसी, गोरखपुर व प्रयागराज में मेट्रो बनेगी, लेकिन 6 साल में तो नहीं बनी यह आपका ही संकल्प-पत्र है, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं। अगर आप बजट दे रहे हैं तो काशी के लिए हर बार बजट देते और गोरखपुर के लिए हर बार बजट देते हैं और मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज इनमें मेट्रो कब बनेगी और लैपटॉप भूल जाइये केवल स्मार्ट फोन मिलेंगे टैबलेट भूल जाइये क्या टैबलेट के लिए बजट है तो बजट जब आपके पास है और बजट आप खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हो ?

बजट आपके पास है, लेकिन आप उसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपने जो संकल्प-पत्र में घोषणायें की हैं उनको बजट में शामिल कर लीजिये। आपकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ डाउन जा रही है, इण्डस्ट्री में आपकी ग्रोथ डाउन जा रही है, अगर आपकी ग्रोथ एग्रीकल्चर और इण्डस्ट्री में डाउन होगी तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आप वन ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। आपने शिक्षा मित्र की समस्या का समाधान नहीं किया। सुना था कि लाखों लोग बुलाये गये थे और कहा गया था कि जब नारे लगाये जायेंगे तब उनकी समस्या का समाधान होगा, वह लोग नारे लगाकर वापस चले गये, लेकिन उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश जी भर्ती को लेकर जो सवाल को उठा रहे थे वह बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेन्स की बात करती है। सरकार कहती है कि करप्सन के लिए जीरो टॉलरेन्स है। दागी अभ्यर्थियों की भर्ती हुई और जिन लोगों ने इसमें करप्सन किया है उन्होंने टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल किया है। उन्होंने सौ-सौ सवाल बड़ी आसानी से साल्व कर दिये जिसके बाद वह पकड़े गये और 70 से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं।

अगर आप भर्ती में ही जीरो टॉलरेन्स नहीं दिखा रहे हैं तो आपका करप्सन वाला जीरो टॉलरेन्स कहाँ गया और फिर जो अयोग्य लोग नौकरी पा जायेंगे वह लॉ एण्ड आर्डर को मेनटेन करने में कैसे जीरो टॉलरेन्स दिखायेंगे। एक अभ्यर्थी जेल में था वह जेल से पास हो गया। तो यही आपका जीरो टॉलरेन्स करप्सन के लिए है। न जाने कितने महीने से लोग धरने पर बैठे रहे, लेकिन यही जीरो टॉलरेन्स सरकार का है। एक भर्ती में घोटाला नहीं है, बल्कि ना जाने कितनी ही भर्तियों में घोटाला है। 69,000 वाले बच्चे न जाने कितने दिनों से धरना दे

देकर वापस चले गये। उन लोगों ने लगातार धरना दिया, लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। सुनवाई तभी होगी जब जातीय जनगणना होगी उससे पहले सुनवाई नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी माननीय सदस्य इधर बैठे हैं और जितने माननीय सदस्य उस तरफ बैठे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जातीय जनगणना चाहते हैं। बिना जातीय जनगणना कराए 'सबका साथ और सबका विकास' सम्भव नहीं है। इसके बिना उनका विकास कभी सम्भव नहीं हो सकता है। जो एक्विलिटी की बात है और नीति आयोग भी कह रहा है कि आप इस पैरामीटर में नीचे जा रहे हैं। जेण्डर एक्विलिटी और एक्विलिटीज समाज में तभी सम्भव है जब जाति की गिनती हो जाये और उनको भी बराबर का हक और सम्मान मिल जाये। मुझे याद है कि समाजवादी सरकार में 55 लाख से ज्यादा महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी जाती थी और उस समय यह फैसला लिया गया था कि जिसकी जितनी आबादी है उनको उस हिसाब से दिया जायेगा। आबादी के हिसाब से यह न मिल सके, इसलिये कुछ हाई कोर्ट गये थे और जब वह हाई कोर्ट में हार गये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुँच गये, लेकिन वहां भी वह हारे। समाजवादी पार्टी सरकार ने उस समय समाजवादी पेंशन में व्यवस्था की थी कि हर जाति की आबादी के हिसाब से उनको पेंशन दी जाये। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस समय टिप्पणी की थी कि गरीब महिलाओं के लिए इससे अच्छी स्कीम और कोई नहीं हो सकती है।

हमारी सरकार के समय में 36 जातियों को आबादी के हिसाब से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया था। बहुत सारे लोग जो किसी भी गिनती में नहीं आते हैं उनको जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। मैं आज भी फ्लोर ऑफ हाउस कहता हूँ कि हम लोग सरकार से जातिगत जनगणना के लिए लड़ेंगे और हम अपने विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो साथी कभी हमारे साथ रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि वह भी आयें और कम से कम जाति जनगणना में हमारा साथ दें।

अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने एक अखबार की बात कही मुझे नहीं पता की उसकी सच्चाई क्या है स्लिप आफ टंग भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि 46 एस0डी0एम0 में 56 यादव एस0डी0एम0 थे। नेता सदन से वह स्लिप आफ टंग हुआ था। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन एक अखबार की कोई कटिंग लाये मैं यही मान लेता हूँ कि विशेष जाति, लेकिन सदन में उस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं होती है जो बाहर होती है। जो बाहर कहा गया वह दूसरी बात थी। हमारे सदस्य इस तरफ के भी जानते हैं उस तरफ के भी जानते हैं। जो लॉबी में बैठे हैं वह लोग भी जानते हैं और पूरा प्रदेश भी इस बात को जानता है कि क्या उंगली उठायी गयी थी । अध्यक्ष महोदय, मैंने उम्मीद की थी कि नेता सदन की तरफ से वह सूची टेबल कर देते । लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी तक सूची टेबल नहीं की गयी है और अगर सूची टेबल हो जाये तो कम से कम यह सदन और पूरा प्रदेश जान ले कि आखिरकार उस समय क्या किया

गया था। एस0डी0एम0 की भर्ती में कौन कितनी बिरादरी के थे। अध्यक्ष महोदय, हालांकि जातियाँ आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं पढ़ सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आवश्यक नहीं हो तो न पढ़िये ।

श्री अखिलेश यादव-

वह जरूरी इसलिए है क्योंकि आरोप लगता है और उन्होंने अपनी बात को सच साबित करने के लिए हमारे विपक्ष के यह साथी हैं, आपको सत्ता में मानूं या विपक्ष में मानूं।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

अभी खड़ा होऊंगा तो बताऊंगा कि सत्ता में हूँ कि विपक्ष में हूँ।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, 2011 में यह हमारे मा0 सदस्य घूमते रहते हैं। एक जमाने में हमारा कभी बहुत पुराना साथ था। शुरुआती दौर में भी हमारे साथ थे और उसके पहले बहुजन समाज पार्टी में भी थे। 2011 में जिसका आरोप लगा था और सदन में जो प्रेस नोट पढ़ी गयी थी। नेता सदन अगर आप टेबल करना चाहें तो मैं क्यों पढ़ूं। जो आरोप लगा कि 2011 में 46 में 56, तो मैं यह मानता हूँ कि नेता सदन से यह स्लिप आफ टंग हुआ। 46 में 56 कुछ इस तरह का स्टेटमेंट था। अध्यक्ष महोदय, वह वीडियो ऑन लाइन है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। आज हम कुछ कहना चाहें वह नहीं हो सकता। नेता सदन जानते हैं। आपने दोबारा नेता सदन का भाषण नहीं पढ़ा, डांट पड़ेगी आपको घर जाकर। हो सकता है कि वह स्लिप ऑफ टंग हो गया हो। उस समय जो टोटल भर्ती एस0डी0एम0 की हुयी थी वह 30 थी जिसमें यादव एस0डी0एम0 मात्र 5 थे, जिसमें और बिरादरी के हैं मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। एक सात थे और एक तीन थे। पूरी सूची मेरे पास नहीं है, लेकिन सरकार सूची जारी करे। पी0सी0एस0 भर्ती में 2012 में जो आरोप लगा, उसमें यादव एस0डी0एम0 4 थे। 2013 में केवल 6 थे। 2015 में 3 थे। मैं चाहूंगा कि नेता सदन और सरकार इस सूची को जारी करे। विशेषाधिकार तो बनेगा।

मान्यवर, सरकार उस सूची को जारी करे और इसीलिए हम सब लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए जो आपके हित में भी है और समाज के हित में भी है और उन्हें जातीय एवं आबादी के हिसाब से हक एवं सम्मान मिलना चाहिए। यही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही संविधान का सपना है, यही डॉ0 राम मनोहर लोहिया जी का सपना था, यही नेता जी का सपना एवं संघर्ष था और यही सबका साथ एवं सबका विकास है, यही रामराज्य है और समाजवाद है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इस सरकार ने पिछड़ों को अपमानित करने के लिए जनगणना कराई थी कि क्लास-3 एवं क्लास-4 में कितने कर्मचारी हैं। मैं उस समय सदन में नहीं था। हमारे विपक्ष के लोग जानते

होंगे और सरकार के पास वह रिपोर्ट भी है। जिस तरह से अन्य प्रदेशों में हर स्तर पर जातीय जनगणना हो रही है तो यह सरकार उस आंकड़े से क्यों भागती है, सरकार उस आंकड़े को समाने रखे और अगर आप जातीय जनगणना के खिलाफ हैं तो फिर आप प्राइवेटाइजेशन एवं आउटसोर्सिंग के खिलाफ क्यों नहीं हैं। अगर सरकार जातीय जनगणना के खिलाफ है कि यह व्यवस्था जातिवाद फैला रही है तो आउटसोर्स व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए और हमारी सरकारी संस्थाओं का भी प्राइवेटाइजेशन खत्म होना चाहिए और यही समाजवादियों का पक्ष है। मैं मा0 सदस्य श्री ओम प्रकाश जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां पढ़ दीं और उन्होंने पंक्तियां ऐसी पढ़ीं कि मा0 नेता सदन भी कुछ पंक्तियां ले आए।

हालांकि हम लोग कवि नहीं हैं, लेकिन जब बजट में देखते हैं कि इतनी तुकबन्दी है, इतने बड़े बजट में कम-से-कम जिस तरह आपने डिलॉयट हॉयर किया है, थोड़ा खर्च कर देते तो आपको अच्छी लाइनें मिल जाती, क्या तुकबन्दी वाली लाइनें लाए हैं, आप। मा0 नेता सदन ने कुछ लाइनें पढ़ीं, जिस पन्ने को उन्होंने पढ़ा, आपने एक पन्ना पहले क्यों नहीं पढ़ा, हमें आप बाद की पढ़ाई क्यों करा रहे हैं। आपने भी इसी किताब (रश्मिरथी) से लिया होगा, मा0 नेता सदन हमें आगे की पढ़ाई करा रहे हैं। मैंने उस समय जो सवाल पूछा था वह हमी लोग महसूस कर सकते हैं कि जिस मुख्य मंत्री आवास में रहें और अगर कोई दूसरा वहां जाए तो वह गंगा जल से धुलवाए। मैं किसी संत के बुलाने पर पूजा-पाठ के लिए जा रहा था, मैं किसी संत के बुलाने पर गया था, मैं अपने आप पूजा-पाठ के लिए नहीं गया था। वहां पर जानबूझकर, साजिश करके एवं रणनीति बनाकर मेरा विरोध किया गया था। गोमती नदी के किनारे जब मुझे एक संत के द्वारा बुलाया गया और मैं वहां पर गया और संत अपने स्थान पर ले जाना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेण्ट इन्सपॉन्र्स लोग वहां पर पहुंच गये और काला झण्डा दिखाने लगे। मान्यवर, अगर राजनीति में आओ तो काले झण्डे के विरोध से मत घबराओ और मैंने मा0 नेता सदन को पिछली बार भी उदाहरण दिया था कि अगर मुझे कोई भी काला झण्डा दिखाता था या मुझे जानकारी मिलती थी, आप पता कर लेना, वह अधिकारी आपके साथ भी काम कर रहे हैं जो हमारे साथ अधिकारी काम कर रहे हैं, कोई नये अधिकारी भर्ती नहीं हो गये हैं। मैं उनको बुलाता था और पूछता था कि समस्या क्या है, आप जैसे मुकदमे नहीं लगाते हैं और आपने गवर्नमेण्ट इन्सपॉन्र्स लोगों को काले झण्डे लेकर भेजा और कहा कि आप पूजा-पाठ नहीं कर सकते हो, मैंने कहा कि आज चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आज पूजा-पाठ करके और संत से मिलकर ही जाऊँगा । उन्होंने कहा कि अगर आप हवन करोगे तो आपको धोती पहननी पड़ेगी, मैंने कहा कि मैं धोती नहीं लाया हूँ और मैं धोती नहीं पहनूंगा, केवल संत से मिलकर और परिक्रमा करके चला जाऊँगा ।

जब मैं गया, परिक्रमा कर ली, परिक्रमा भी नहीं करने दे रहे थे। मैंने कहा कि अगर परिक्रमा पर चल दिया है तो परिक्रमा होगी और मैंने किया। उसके बाद में एक झोपड़ी जो बनी

थी उस स्थान पर गया तो बहुत-से भारतीय जनता पार्टी के करीबी लोग और जहर उगलने वाले लोग वहां दिखाई दिये। तो आपने किताब का एक पन्ना आगे पढ़ दिया, हालांकि जहां से आपने पढ़ा उसके अगर और आगे पढ़ते तो शायद हमारी वाली बात नहीं की लेकिन वह बात आपने नहीं की क्योंकि आप उतना ही करेंगे जितना आपको सूट करेगा। आप वह नहीं कहेंगे तो हम लोगों को सूट करेगा इसलिए आपने अपने हिसाब से पढ़ा। मैं अपने हिसाब से नहीं पढ़ रहा हूँ और जो किताब वही पढ़ रहा हूँ और अपने हिसाब से नहीं सोच रहा हूं। अगर अपने हिसाब से सोचता तो कई और जगहें भी हैं वहां भी मैं पढ़ता। मुख्य मंत्री जी ने जो पढ़ा, उसके एक पन्ने पहले मैं पढ़ रहा हूं, उसी कविता और उसी राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की कविता को पढ़ रहा हूं-

द्वन्द्व-युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा,
अर्जुन को चुप ही रहने का गुरू ने किया इशारा।
कृपाचार्य ने कहा-'सुनो हे वीर युवक अनजान'
भरत-वंश-अवतंस पाण्डु की अर्जुन है संतान।
'क्षत्रिय है, यह राजपुत्र है, यों ही नहीं लड़ेगा,
जिस-तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा ?
अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो सभा में मौन,
नाम-धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन ?
'जाति! हाय री जाति!' कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला,
कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला
'जाति-जाति रटते, जिनकी पूंजी केवल पाखंड,
मैं क्या जानूं जाति ? जाति है ये मेरे भुजदंड,
'ऊपर सिर पर कनक-छत्र, भीतर काले के काले,
शरमाते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले,
सूत पुत्र हूँ मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन ?
साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन।

(सत्ता पक्ष के किसी सदस्य ने कहा कि पढ़ ही नहीं पा रहे हैं।)

अरे, पढ़ने नहीं आ रहा इसलिए क्यों ये किताब आज ही खरीदी है। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि पढ़ना नहीं आता है, चलिए, इन्होंने अभी तक 6 साल में 366 पॉलिटिकल थर्मल प्लांट नहीं कहा। (हंसी) लगता है मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा । (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप सभी लोग शांति बनाये रखिए।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, अब इसके आगे पढ़ता हूँ जो असली है,

'मस्तक ऊंचा किये, जाति का नाम लिये चलते हो,
पर, अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो।
अधम जातियों से थर-थर कांपते तुम्हारे प्राण,
छल से मांग करते हो अंगूठे का दान।

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

ऊपर वाली लाइनें तो इसलिए पढ़ दी क्योंकि नेता सदन ने तो पीछे पढ़ा था, आपने बाद में पढ़ा था, 16वें में क्या है और 15वें में ये क्या है ? ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई पांच हजार साल पुरानी है और अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया लेकिन मैं कहता हूँ कि सोने के पत्ते पर भी आप लिखकर दे देंगे तो भी मैं वह स्वीकार करने वाला नहीं हूं। मैंने रामचरित मानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा था कि नेता सदन यह बताएं कि शूद्र क्या है ?

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

और यही शूद्र आपकी ढाल न बनें तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते।

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

यह पढ़ने की बात कर रहे हो आप ? इतिहास के पन्ने उठाओ आप, क्या आप घर में गए होगे तो घर को गंगा जल से धोया होगा ? यह कहाँ का सिद्धान्त है, क्या यह आज के जमाने का सिद्धान्त है ? एक बार दुनिया के एक हिस्से में 400 साल पहले एक साइंटिस्ट, एस्ट्रोनामिस्ट, इस पर तो नहीं पढ़ना पढ़ रहा है मुझे ? साइंटिस्ट, एस्ट्रोनामिस्ट, गैलीलियो, उसने यह प्रूव किया कि सूर्य का चक्कर धरती लगाती है। चर्च को यह स्वीकार नहीं था क्योंकि चर्च ने यह कहा था कि धरती का चक्कर सूर्य लगाता है और उसे सजा मिली, सजा, उसकी जान चली गयी। लेकिन वही देश, समाज ने जब तरक्की की तो 400 साल बाद गलती स्वीकार किया कि चर्च ने गैलीलियो को गलत सजा दी।

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

अध्यक्ष महोदय, क्या नेता सदन यह बतायेंगे क्या शूद्र गलत है, कोई जाँघ से पैदा नहीं हो सकता। आप किसी को कभी गंगा जल से नहीं धुलवा सकते हो। बताओ, आप शूद्र हो कि नहीं हो ?

(सदस्य श्री ओम प्रकाश राजभर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे, आप कहाँ खड़े हो गए, आपकी बारी आयेगी, तब बोलिएगा।

श्री अखिलेश यादव-

(सदस्य श्री ओम प्रकाश राजभर की ओर देखते हुए) यह हँसी बता रही है कि आप साथ देने वाले हो। यह मुस्कराहट बता रही है। (हँसी) किसी प्रेसर को मत मानना।

(किसी सदस्य के कुछ बोलने पर)

इसीलिए जाति चाहते हैं और हम रामचरित मानस के खिलाफ नहीं है, किसने कह दिया कि हम खिलाफ हैं ? क्या हमारा स्टेटमेंट नहीं सुना आपने ? क्या प्रचार करते हो आप ? भगवान सबके हैं, किसी एक के भगवान नहीं हैं।

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

क्योंकि चन्दा आप लेते हो तो आपके भगवान हो गए ? और फिर जो गलत है, वह गलत है। आप किसी एक को खड़ा कर दें कि 'ताड़न' का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं कि 'ताड़न' की मीनिंग क्या है। क्या एक को खड़ा करके 'ताड़न' की मीनिंग बतायेंगे आप ? ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं, जो है सो है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है ? अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हम जातीय जनगणना चाहते हैं। मैंने इस स्टेट में लैपटॉप बाँटे। मैं इस स्टेट को आगे ले जाना चाहता था, आप कहते हो कि लैपटॉप में करप्शन हुआ है ? अगर कोई भी एक बता दे, नेता सदन बतायें करप्शन लम्बा हुआ या छोटा हुआ है ? क्या बात करते हैं? एक्सप्रेस-वे में घोटाला हुआ है और जब प्लेन उतारना पड़ा हरक्युलिस तो उसी एक्सप्रेस-वे पर जिसे समाजवादियों ने डिजाइन किया था। जानते हो हरक्युलिस कौन सा हवाई जहाज है ? घोटाला (हँसी) यह नहीं जानते हरक्युलिस। कौन है किसने डिजाइन किया वह हाई-वे ?

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के साथ बोलने पर)

अरे, पहले बोलना तो सीखो, भो-भो कर रहे हो। क्या कर रहे हो ?

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बोलें। इधर के भी माननीय सदस्य शान्त रहें।

(किसी सदस्य के यह कहने पर कि 'पानी पी लीजिए')

श्री अखिलेश यादव-

अभी पानी की जरूरत नहीं है, पानी पहले पी लो खुद ।

'जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी', क्या गलत है, इसमें तो नहीं गलत कहा, इसमें तो ठीक पढ़ा न ? आप तो राम चरितमानस को रिपीट कर रहे थे, इसको आप रिपीट कर दो और वह जो पंक्तियाँ हैं, मैंने कहा था कि नेता सदन पढ़कर सुना दें। नेता सदन कहें वह, किसी बात की बहस चल रही हो तो। इसलिए हमने पहले ही कहा कि हम लोग खिलाफ नहीं हैं, जो गलत है, वह गलत है। इस प्रदेश को कहाँ लिए जा रहे हैं आप ? आप दुनिया के दूसरे देश घूम करके आए। मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि जिन-जिन देशों को देख करके आप आए हैं, क्या उन देशों में कहीं भी एक जगह आपको सड़कों पर

छुट्टा जानवर घूमते हुए दिखे हैं ? और यह सूची लम्बी है अगर हम इस रिपोर्ट को सही माने और सरकार का बजट ठीक मानें तो बजट अभी कम है। अगर यह रिपोर्ट ठीक है तो अभी 11 लाख से ऊपर छुट्टा जानवर हैं प्रदेश में और 750 के लगभग बजट रखा है अगर अवारा पशुओं को जो सड़कों पर घूम रहे हैं अगर उनकी गिनती हो जाएगी तो यह न जाने कहां पहुंच जाएगी तो क्या जो मरने वाले लोग हैं जिनका जानवरों की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है या खेत को बचाने के लिए किसान की जान जा रही है उसके लिए मैंने 10 लाख रुपये की मांग की थी कि इस परिवार की मदद हो जाए और जो फसल का नुकसान हुआ हो तो उसकी भरपाई हो जाए। मैं इसकी पूरी सूची जो हमारे पास अभी है और मैं अपने मा0 सदस्य से कहूंगा कि मैं तो हासिल कर पाया हूँ दो दिन के अन्दर 13+8 = 21 हो गए और इसमें लम्बी सूची है इसको मैं टेबल करना चाहता हूँ कम से कम यह सरकार देखे और मैं लम्बी सूची दे करके आपको अपडेट कराऊंगा। यह आपकी सूची फैजाबाद की है और यह दोनों रिपोर्ट्स एक इंण्डिया टुडे की है और एक जो प्राइवेट संस्था है जिसके आंकड़े मैंने बोला था वह रिपोर्ट मैं टेबिल करूंगा। जब यह सरकार बजट ही नहीं खर्च कर पा रही है तो रोडवेज क्या ठीक करेगी जहां पर करोड़ों लोग चलते हैं।

शिक्षा व्यवस्था में अगर डी0बी0टी0 ठीक कर रहे हैं आप तो क्या बच्चों को ड्रेस मिल गई, मोजे मिल गए, स्वेटर, जूते क्या मिल पा रहे हैं और उनकी किताबें तो बहुत सी जगहें पहुंची ही नहीं हैं। यह पूरे प्रदेश का हाल किसी एक जगह का नहीं है, इसलिए अध्यक्ष महोदय अगर हम धार्मिक परंपराएं मानते हैं और रीति-रिवाज को मानते हैं तो यह समय नहीं है उन बातों के कहने का कि मैं उन रीति-रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्यों कि यह परम्परा में नहीं है अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें और उसको ले करके कहा जाए जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी और नेता सदन ने क्या कहा था वह मुझे क्लीयर नहीं पता है कि क्या कहा था इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परम्पराओं पर चलना चाहते हैं तो यह परम्परा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर यह परंपराओं पर बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत-से रीति-रिवाज नहीं माने वह ठीक नहीं लगेगा, मैं कहूँ तो ऐसी शिक्षा मुझे नेता जी ने नहीं दी है और मैं मिलेट्री स्कूल में पढ़ा हूं।

अध्यक्ष महोदय यह जो बजट है यह केवल मैंने जो तस्वीर दिखाई थी एम0ओ0यू0 हवा-हवा में है और जो आप ग्रोथ रेट पाना चाहते हैं वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की वह हवा-हवा में है। छः साल जिसने ऐसे ही काट दिए हो वह चार साल में कैसे हमारे उत्तर प्रदेश के वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को ले पाएगी और इस बजट ने पूरे उत्तर प्रदेश के किसान और खासकर नौजवानों को निराश किया है और जो बड़े-बड़े मेले लगे हैं इन मेलों में जो आए हुए उद्योगपति हैं आपके बजट से कोई प्रभावित होने वाला नहीं है और जो सबसे महत्वपूर्ण

सेक्टर है एम0एस0एम0ई0 जिसमें जान फूंकनी थी कि आप बड़े उद्योग ला रहे हैं, लेकिन एम0एस0एम0ई0 कितने बन्द हो रहे हैं उस दिशा में सरकार ने कोई काम नहीं किया है। यह बजट दिशाहीन है, यह बजट उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ नहीं ले जा सकता है। अध्यक्ष महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब नेता अपना दल श्री राम निवास वर्मा जी बोलेंगे। अब मैं सभी विधान मण्डल दल के सभी नेताओं को क्रम से बुलाऊँगा, फिर जो पुराना क्रम चल रहा था, इधर से दो मा0 सदस्य बोलेंगे और विपक्ष से एक मा0 सदस्य बोलेगा। अभी नेताओं के लिए 15 मिनट निर्धारित है। बाकी मा0 सदस्यों के लिए सात से आठ मिनट निर्धारित हैं। ये डिबेट अभी चलेगी, हम इसे अभी अगले 6 घण्टे रात साढ़े आठ बजे तक चलाएँगे, उसके बाद फिर निर्णय करेंगे कि इसको बढ़ाना है या नहीं। अब नेता अपना दल श्री राम निवास वर्मा जी।

***श्री राम निवास वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष महोदय, इस सम्मानित सदन में आदरणीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल निर्देशन में मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के एवं अपना दल (सोने लाल) की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन अनुप्रिया पटेल जी के अतुलनीय सहयोग से बनी सरकार द्वारा 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये का बजट जो प्रस्तुत किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। जिसमें सभी वर्गों के कल्याण और प्रदेश के समग्र विकास का खाका खींचा गया है। इस बजट में कुल 32721 करोड़ 96 लाख रुपये की नई योजनाएँ सम्मिलित की गई हैं। जिसमें प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। हमारी सरकार ने किसानों के हित में जो अब तक गन्ना किसानों के लिए सबसे अधिक भुगतान किया है और 46 लाख 42 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से लेकर अब तक 196 हजार करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया गया है। प्राथमिकताएँ यदि निश्चित हों और कार्य योजना स्पष्ट हों तो लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। लगातार दूसरी बार सत्ता में आई हमारी सरकार के पहले बजट में प्रदेश को आगे बढ़ाने और सोच की दिशा दोनों ही दिखाई पड़ती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढाँचा उसके केन्द्र में ही है। समाज के लिए लोक कल्याणकारी सरकार अन्नदाता की उपेक्षा नहीं कर सकती है। हमारी सरकार ने अपने बजट में उनकी आर्थिक उन्नति पर ध्यान केन्द्रित किया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रदेश विकास की पटरी पर तब ही आ सकता है, जब वहाँ औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए। प्रदेश के समग्र विकास हेतु यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 2023 में भागीदारी के लिए विभिन्न देशों से सम्पर्क किया गया। वैश्विक व्यापारिक समुदाय से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई उत्साहजनक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 33 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक कुल 19 हजार 58 निवेश आशय प्राप्त हुए हैं। जिसमें बेरोजगारी को दूर करने के लिए लगभग 94 लाख रोजगार के सृजन की सम्भावना है। हमारी सरकार ने इस बजट को पेश कर एक आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश की ओर कदम बढ़ाया है। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रूप से उनकी पुत्रियों की शादी योजना के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत उसके माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया, जो नारी शक्ति को नई ऊर्जा प्रदान करता है। समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए और श्रमिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अब तक 153 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों, निर्माण स्थलों का पंजीकरण कराया जा चुका है। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और सुदृढ़ करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करके इनको निरापद वातावरण उपलब्ध कराने के प्रति सरकार निरन्तर प्रयासरत है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कालेज 'वन डिस्ट्रिक वन मेडिकल कालेज' की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 21696 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों का निर्माण तथा 18407 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है। सरकार के अपने इस लोक कल्याण संकल्प-पत्र के वादे को पूरा करते हुए अब निजी नलकूप कनेक्शन पर किसानों के हित में बिजली छूट 100 फीसदी दी गई है, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। युवा रोजगार को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने युवाओं को शिक्षा, कौशल, विकास, स्टार्ट अप आदि के लिए भी भारी-भरकम धनराशि का प्राविधान किया है। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भी 40 हजार रोजगार का सृजन इस बजट में रखा गया है। युवाओं को टैबलेट, लैपटॉप की व्यवस्था, शोध को प्रोत्साहन और फिल्म सिटी का निर्माण, मेडिकल और स्टार्ट अप क्षेत्र को लगातार प्रोत्साहन हमारी सरकार के महत्वपूर्ण कदम हैं। पूरे बजट को देखें तो हमारी सरकार का बजट पोषणीय और तीव्र गति वाला बजट है, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिल सकेगा और दूरगामी लक्ष्य साधने में मदद मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को भी रख रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र नानपारा की समस्या रखना चाहता हूँ कि नानपारा नगर में कोई भी महिला डिग्री कालेज नहीं है । एक महिला डिग्री कालेज की स्थापना की मैं माँग करता हूँ एवं अपनी विधान सभा क्षेत्र नानपारा नगर में जो कि तहसील, मुख्यालय भी है, रोडवेज बस अड्डे की स्थापना किये जाने की माँग करता हूँ। मैं सभी प्रदेश वासियों को इस आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना सिद्धी को समर्पित लोक कल्याणकारी बजट के लिए बधाई देता हूँ। यह बजट प्रदेश वासियों के लिए खुशियों का द्वार सिद्ध होगा। धन्यवाद ।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। अपने श्रद्धेय मुख्य मंत्री जी को, यशस्वी वित्त मंत्री जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यह बजट गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों और बेसहारों की जिन्दगी में उम्मीद का चिराग रोशन करने वाला बजट है और मैं श्रद्धेय मुख्य मंत्री जी को विशेष तौर पर, बधाई देना चाहता हूँ कि अमृतकाल का यह पहला बजट, निश्चित तौर पर एक समावेशी बजट है। सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। साथ ही मा0 अध्यक्ष जी, बजट के माध्यम से योगी जी की सरकार ने आम आदमी तक पहुँचने का एक सफल प्रयास किया है। मैं अभिनन्दन करता हूँ, मैं बार-बार स्वागत करना चाहता हूँ मान्यवर, अध्यक्ष जी, जब से यह सदन चल रहा है हम सब लोगों ने देखा है अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तब भी हम लोगों ने देखा और बजट पर चर्चा हो रही है तब भी हम लोगों ने देखा है, विपक्ष की तरफ से बार-बार कुछ बातों को आगे किया जा रहा है। सरकार तो विकास पर चर्चा करना चाहती है, अभिभाषण से लेकर और यहाँ तक, अगर हम ठीक से देखें तो सरकार मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है लेकिन हमारा विपक्ष सांड़ पर अटका हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरह से विपक्ष की तरफ से बार- बार ऐसा होता है उससे उत्तर प्रदेश के अन्दर क्या मैसेज जा रहा होगा। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता यहाँ की बहस को जब देख रही होगी वह क्या सोच रही होगी।

मान्यवर, यह भी लोगों को समझ में नहीं आता है। आप सब लोगों की चिंता, विपक्ष की चिंता हम समझ सकते हैं। कुछ लोगों के आहार और व्यापार की चिंता बहुत विपक्ष को है। तो एक बात सरकार स्पष्ट करना चाहती है कि योगी जी की सरकार किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश की धरती पर अन्याय नहीं होने देगी। गाय हमारी माता है और निराश्रित पशुओं के साथ, हमारे गोवंश के साथ जो अत्याचार पिछली सरकारों में होता रहा है, वह हम नहीं होने देंगे। किसी भी सूरत में निराश्रित गोवंश को हम किसी का आहार नहीं बनने देंगे। जो व्यापार करने की कोशिश करेगा, उसका क्या हर्ष होगा, यह किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से गौवंश की व्यवस्था की है, उसके लिए मैं अभिनन्दन करना चाहता हूँ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर भी और बजट पर भी जो बोला गया, बजट कहाँ, इसकी चर्चा कहाँ, इससे कोई लेना-देना नहीं। जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बातें आयीं, वहीं बातें बजट पर भी आयी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह जातीय जनगणना एक बार इस देश में, गुलाम हिन्दुस्तान में हुई थी। यह विपक्ष चाहता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अंग्रेजों के बताये गये रास्ते पर चले तो हम बताना चाहते हैं कि योगी जी की सरकार अंग्रेजों के बताये गये रास्ते पर नहीं चल सकती है।

मान्यवर, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2004 से लेकर 2009 तक और 2009 से लेकर 2014 तक इनके समर्थन से दिल्ली में सरकार चल रही थी और वर्ष 2011 में देश के अन्दर उक्त जनगणना हुई, तब क्यों नहीं इन लोगों ने करा ली ? और अगर इनकी बात नहीं मानी गयी तो इन लोगों ने सरकार से समर्थन क्यों नहीं वापस ले लिया ? यह आरक्षण की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की यह बात करते हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि 4 बार की सरकार में, 4 बार दोनों पार्टियों को मौका मिला है, समाजवादी पार्टी को भी मिला है और बहुजन समाज पार्टी को भी मिला है। 4 बार के शासनकाल में जिस तरह का अन्याय, जिस तरह का अत्याचार अति पिछड़े समाज पर और अति दलित समाज पर इन लोगों की सरकारों ने किया है, वह किसी ने नहीं किया है, मैं दावे के साथ यह कहना चाहता हूँ। यह आँकड़े की बात करते हैं तो आप वह आँकड़े क्यों नहीं उठाते जिसमें 4 बार की आपकी सरकार में कितनी सरकारी नौकरी आपने दी है ? उसमें राजभर कहां है ? बिन्द कहां हैं उसमें ? बियार कहां है ? लोनिया चौहान कहाँ हैं उसमें ? केवट, मल्हार कहां है उसमें ? प्रजापति, कुम्हार कहां है ? पाल, गड़रिया कहां है उसमें ? कोल और खरवार कहाँ है उसमें ? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर उन 4 बार की सरकारों के आँकड़े आप उठा कर देख लें तो 80 प्रतिशत से ज्यादा सिर्फ एक जाति विशेष को अवसर देने का काम किया गया। मान्यवर, यह इनका सामाजिक न्याय है ? और दशमलव के भी आँकड़े को भी राजभर नहीं छूता । दशमलव के भी आँकड़े को हमारे निषाद, केवट, मल्हार, बिन्द, बियार नहीं छूता। हमारा पाल, गड़रिया, लोनिया, चौहान नहीं छूता। 75 वर्ष के आजाद हिन्दुस्तान में इनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जातीय बंधनों को वर्ष 2014 में भी उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने तोड़ दिया है।

वर्ष 2014 से लेकर 2017, 2019, 2022 में जातीय बंधनों से उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता बाहर निकल चुकी है और यह लोग जाति से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। हमें भरोसा है, उत्तर प्रदेश के पिछड़ों पर, दलितों, गरीबों, वंचितों पर। हमें यकीन है और उत्तर प्रदेश की जनता पूरा भरोसा करती हैं कि जब तक योगी जी के हाथ में उत्तर प्रदेश की बागडोर है और देश की बागडोर देश के यशस्वी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री पूज्य नरेन्द्र भाई मोदी जी के हाथ में है। हम नहीं मानते कि उनसे भी बड़ा कोई पिछड़े समाज में पैदा होने वाला कोई नेता होगा। जरूरत पड़ेगी तो हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान

लेंगे, लेकिन जो अधिकार उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं है, उसमें आप जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यह जनगणना कराने का अधिकार किसके पास है ? यह अधिकार भारत सरकार के पास है। आप क्यों उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे है ? आप विकास पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं ? आप मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं ? नहीं कर सकते मान्यवर, ये नहीं कर सकते। ये इसी तरह जातियों में फंसाकर कभी पिछड़ों का नारा देकर कहते हैं कि सोशलिस्टों में बांधी गांठ और पिछड़े पावें 100 में 60, और जब आपकी सरकार रहती है तो नारा भूल जाते हैं। ये जाति में उलझाकर रखना चाहते हैं, इनका ये सामाजिक न्याय नंगा हो गया है। देश के यशस्वी पूज्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के श्रद्धेय मुख्य मंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, एक-एक गरीब, दलित, मजदूर, हमारा नौजवान आज कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, इन लोगों को ये पच नहीं रहा है। इसलिए ये सब बात यह लोग कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे, नेता प्रतिपक्ष को बुरा लग गया, ठीक है पूरी दुनिया जानती है एक लम्बी विरासत नेता जी ने छोड़ी है लेकिन आप तो बैट-बॉल से ही बाहर नहीं निकलना चाहते, आपके बस का नहीं है कि आप संभाल पाओ और इसलिए कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास मत करिये, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जाग उठी है उसको जगाने की आवश्यकता नहीं है।

आज सुबह से हमारे परिषदीय विद्यालयों की चर्चा हो रही है। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने के लिए गरीब का बेटा जाता है, श्रमिक का बेटा जाता है, पिछड़ों के बेटे जाते हैं, दलितों के बेटे जाते हैं, बड़े लोगों के बेटे तो बड़े स्कूलों में जाते होंगे। क्या दुनिया नहीं जानती है कि वर्ष, 2017 से पहले गरीब का बेटा बोरा लेकर, टाट लेकर परिषदीय विद्यालयों में नंगे पांव जाता था, स्लेट तक उसके हाथ में नहीं हुआ करती थी। मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री योगी जी का उत्तर प्रदेश के गरीबों की तरफ से अभिनन्दन प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने गरीबों के बच्चों की चिंता, पिछड़े कमजोरों की चिंता, जिस दिल से, जिस मन से बड़प्पन के साथ की है उसके लिए आने वाला इतिहास सदा आपकी प्रशंसा करता रहेगा। इसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप जाकर देखिये कि परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के बैठने की जगह नहीं थी, वे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे, जमीन पर टाट बिछा कर पढ़ा करते थे लेकिन आज योगी सरकार की कायाकल्प योजना ने गरीबों की जिंदगी को बदल दिया है। आज हमें मना करना पड़ता है कि अब जगह नहीं बची है। अब लोगों का विश्वास, लोगों का यकीन, गरीब को भरोसा हो गया है और अब वह निश्चिंत होकर अपने बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं। यह एक उदाहरण है, इसका बजट में प्राविधान किया गया है। हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो श्रमिक हैं, उनके साथ काम करने का अवसर हमारे श्रद्धेय मुख्य मंत्री जी ने हमें दिया है। आज देश के अन्दर 28 करोड़ श्रमिक, श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और उत्तर प्रदेश

के अन्दर 8 करोड़ 39 लाख श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार को श्रद्धेय मुख्य मंत्री जी का हम अभिनन्दन करना चाहते हैं, हम वित्त मंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं कि उन्होंने दिल खोलकर हमारे संतों की याद में चिंता बजट में की है। ये 08 करोड़ 39 लाख जो गरीब हैं इनकी जिन्दगी को बना दिया, 75 साल से इनके पेट में जो आग लगी है उसे कोई बुझा नहीं पाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अंगीकार कर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ाने का जज्बा दिखाया, ये लोग मजाक बनाते हैं कि आप सब फ्री में बांट रहे हैं। जब गरीबों का पेट सरकार भर रही है तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, लानत है ऐसे विचारों पर।

मान्यवर, ये 8 करोड़ 39 लाख लोग कौन हैं, ये दलित हैं, ये कमजोर हैं, ये मुस्लिम समाज के, हमारे अंसारी समाज के, हमारे जुल्हा समाज के लोग हैं। हमनें क्या कोई भेद किया है इन लोगों में। जिस तरह से श्रद्धेय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम आवास के बजट को नहीं काटेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से जो गरीब बच जायेगा हम उसका घर बनायेंगे जो छूट जायेगा उसका उत्तर प्रदेश की सरकार घर बनायेगी। मान्यवर, क्या 75 साल में इन गरीबों को यह भी हक नहीं है कि रहने के लिए उनके पास घर हो और इस योजना का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। आपने हमें बोलने का मौका दिया, हम आपका फिर से आभार प्रकट करना चाहते हैं और एक बार फिर परम श्रद्धेय मुख्य मंत्री जी का और अपने विद्वान, यशस्वी वित्त मंत्री जी का मैं इस शानदार बजट को प्रस्तुत करने के लिए जो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने के लिए, एक मील का पत्थर साबित होगा इस बात की मैं बधाई देते हुए आपका पुनः धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री राजपाल सिंह बालियान-**

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, तीन-चार दिन पहले आपने वर्तमान सदस्यों के शिलापट्ट के लिए जो आदेश जिलों को किये हैं, मैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का और आपका धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, प्रदेश सरकार ने सदन में अपना दूसरा बजट 6 लाख 90 हजार 2 सौ 42 करोड़ 43 लाख का पेश किया है। यह बजट दिशाहीन है और जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। बजट में न आज की समस्याओं का समाधान है और न भविष्य की सम्भावना है। गाँव, गरीबों, किसानों, नौजवानों तथा बेरोजगारों के लिए बजट में कुछ नहीं है। यह बजट निराशाजनक है। यह बजट महिलाओं, किसानों, मजदूरों को निराश करने वाला बजट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी वैसा ही रवैया अख्तियार किया है जैसी केन्द्र की सरकार ने किया है। प्रदेश सरकार का यह 7वाँ बजट है। सरकार बताये, क्या किसानों की आय दुगनी हुई ? क्या किसानों के फसलों का सही मूल्य मिल रहा है ? डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक, खाद, बीज आदि सब महँगा हो चुका है।

यू0पी0 सरकार ने सदन में जो बजट पेश किया है, उसमें जनहित व जन-कल्याण के नाम पर आगामी लोक सभा चुनाव के लिए स्वार्थ हेतु पुनः वायदों का पिटारा खोला है। इस सरकार ने अपनी कथनी और करनी के अन्तर से जनता के साथ विश्वासघात किया है। कानून व्यवस्था में यह सरकार तानाशाह हो चुकी है। प्रदेश में बुलडोजर का आतंक है। यू0पी0 की कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। प्रदेश की महिलायें एवं बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिसका जीता जागता उदाहरण है, कानपुर देहात में माँ-बेटी की मौत व जनपद-प्रयागराज में सरेआम एक युवक तथा सुरक्षाकर्मी को मौत के घाट उतार दिया जाना। सरकार यह कहती है कि अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ प्रदेश में शांति एवं सद्भाव का वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है। जब कि ऐसा नहीं हो रहा है प्रदेश में चोरी, हत्या, डकैती, एवं बलात्कार की घटनायें चरम सीमा पर है। बुढ़ाना ब्लाक में ब्लाक प्रमुख पल्लो देवी के साथ वहाँ के पूर्व प्रमुख ने उनके ऑफिस का ताला तोड़ दिया, उनका शिलापट्ट तोड़ दिया, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं है। इस तरह की धींगा-मुस्ती, गुण्डई का काम कर रहे हैं। मान्यवर, मैं चिकित्सा स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है।

मान्यवर, सी0एस0सी0 व पी0एस0सी0 पर पर्याप्त मात्रा में डाक्टरों की भरपाई नहीं है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यक उपचार के संसाधन जैसे एक्स-रे, अल्ट्रासाउण्ड आदि मशीनें न होने के कारण मरीजों को इलाज न मिलने से काफी परेशानी होती है। कोई कर्मचारी वहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं है। हमारे विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के अन्तर्गत किसानों की राजधानी सिसौली विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आती है। सिसौली की जनसंख्या 35-38 हजार है और वह बाबा महेन्द्र सिंह टिकैत जी की राजधानी है, किसानों की राजधानी है। बाबा महेन्द्र सिंह टिकैत जी वहाँ रहते थे। अब उनका टिकैत परिवार वहाँ पर रहता है। वहाँ एक सामुदायिक केन्द्र है, जिसमें कोई डाक्टर नहीं हैं, केवल वार्डव्वाय वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था चल रही है। इसी तरह से गढ़ीनौआबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है वहाँ आज तक डाक्टर उपलब्ध नहीं है। एक सिसौली लिंक मार्ग जहाँ पर हिन्डन और आदमपुर बाईपास है वहाँ लगभग 35 हजार आबादी है। वहाँ पर एक पुल की आवश्यकता है। बुढ़ाना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भी डाक्टरों की लापरवाही है। वहाँ पर भी डाक्टर पूरी उपलब्धता से नहीं आते हैं और वहाँ पर काफी परेशानी रहती है। हरसोली नाले पर शाहपुर थाना के पश्चिम में नाले पर पुलिया की आवश्यकता है।

प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आग्रह किया जा रहा है, किन्तु आज तक प्रदेश में किसी उद्योग की स्थापना नहीं हो पायी है। प्रदेश की जनता के साथ छलावा है। प्रदेश की सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे हैं जिससे लोगों को आवागमन में बहुत परेशानी होती है। गन्ने के क्षेत्र में मौजूदा सरकार ने एक रुपये नहीं बढ़ाया है। बजट में गन्ना किसानों को कोई राहत नहीं दी गयी है। वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि कीटनाशक दवाइयाँ खाद आदि के कारण अबकी बार गन्ना महंगा तैयार हुआ है और इसके साथ ही साथ गन्ना के पिछले बकाया पेमेंट की माननीय मंत्री जी बात कर रहे थे, मंत्री जी यहाँ है नहीं। जो मौजूदा सीजन है उसका पेमेंट हमारी बुढ़ाना फैक्ट्री में नहीं हुआ है। पहले ऐच्छिक किसान अगर एक गाँव का गन्ना एक फैक्ट्री में जा रहा है तो उसका थोड़ा हिस्सा कुछ और फैक्ट्री में जाता था। तो वह किसान ऐच्छिक उसी फैक्ट्री में लगा लेता था। वह भी पाबन्द कर दिया है। गन्ने का बाउंड सरकार की इच्छा पर या सचिव की इच्छा पर निर्धारित होंगे। फसल बीमा योजना किसानों को कोई लाभ नहीं दिलाती है बल्कि यह योजना मात्र बड़ी-बड़ी बीमा कम्पनी दिखवा लें कि फसल बीमा के नाम पर कितना भारी भरकम प्रीमियम सरकार भरती है और कितना किसान को लाभ मिलता है। कृषक दुर्घटना के तहत 18 वर्ष से लागू की जाती है।

(इस समय अपराह्न 02 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुए।)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री राजपाल सिंह बालियान-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मुझे 15 मिनट बोलने के लिए मिला है। अभी मेरा समय अवशेष है। अधिष्ठाता महोदय, 'किसान सम्मान निधि' योजना सरकार की काफी तारीफ करती है, जबकि सच्चाई यह है कि पात्र किसान इससे वंचित रहते है। सही किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता और अपात्र लोगों को लाभ मिल जाता है। मान्यवर, पता नहीं निःशुल्क बीज वितरण कब हो जाता है और कब दिया जाता है। किसानों की सब्सिडी आप लोगों ने कम कर दिया है। सब्सिडी अधिक होनी चाहिए और इसका सही रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। बजट में जो रखा गया है कि किसान की बिजली फ्री कर दी गयी है, तो उनके यहाँ मीटर किस बात के लिए लगाए जा रहे हैं। सरकार से हमारा अनुरोध है कि किसानों के पिछले बिजली बिल बकाये को भी माफ कर दें। युवाओं के फिजिकल तैयारी के लिए कोई सुविधा नहीं दी गयी है, हमारे युवा जान जोखिम में डालकर सड़कों के किनारे दौड़ लगाते हैं। रोजगार के नाम पर बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, मगर होता कुछ नहीं है, युवा रोजगार के नाम पर हर बार ठगा जा रहा है।

दूध किसानों के आमदनी का एक जरिया है। जो किसान थोड़ा-बहुत दूध बेचता है, तो उसके दूध खरीद की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार को दूध खरीद की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। प्राइमरी स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है, शिक्षा का स्तर शून्य के बराबर है। बच्चों को सही शिक्षा उपलब्ध नहीं है। शिक्षामित्रों के सहारे विद्यालय चल रहे हैं। कायाकल्प के नाम पर धन का दुरुपयोग हो रहा है। विद्यालयों की हालत बहुत खराब है। आज मैंने प्रश्न लगाया था, तो उसमें मा0 शिक्षा मंत्री जी का शिक्षामित्रों के प्रति जवाब आया कि वर्ष 2017 में मा0 हाईकोर्ट का निर्णय आया था, उसके बाद उनका वेतन रु0 10 हजार कर दिया गया। महँगाई को देखते हुए सरकार को चाहिए कि शिक्षामित्रों का वेतन बढ़ाया जाए।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहाँ सिसोली 35 हजार की आबादी का गाँव है। यह बाबा महेन्द्र सिंह टिकैत जी का गाँव है। वहाँ पर केवल 2.5 किमी0 सड़क बनना है। मैं एक बार लोक निर्माण मंत्री जी से भी कह चुका हूँ, उन्होंने उस सड़क को बनाने का वादा किया था, लेकिन सिसोली से क्या दुश्मनी है कि आज तक वह सड़क नहीं बन पायी है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत ।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2023-24 के ऐतिहासिक बजट के लिए अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। सर्व प्रथम में अपनी तरफ से तथा अपने निर्बल, इण्डियन शोषित हमारा दल आम दल की तरफ से मा0 मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को और वित्त मंत्री श्री खन्ना जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक ऐतिहासिक बजट सदन में पेश किया और इस बजट में मैंने देखा कि प्रदेश के विकास के लिए जितने भी सेक्टर हैं, हर सेक्टर के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है और इस वर्ष हमारे विधायकगण की मांग को देखते हुए जो उनकी निधि बढ़ाने का कार्य किया गया है उसके लिए मैं आपको बधायी देता हूं, धन्यवाद देता हूं।

हमारे प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ से ज्यादा है और यहां पर 10 करोड़ से ज्यादा लोग आम आदमी के रूप में जाने जाते हैं, जिनको हमारी सरकार ने चाहे वह किसान सम्मान निधि सम्मान के माध्यम से हो, चाहे वृद्धा अवस्था पेंशन से या अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं, उनको सीधे लाभ पहुंचाने के लिए पिछले 6 वर्षों में लगातार काम किया है और आप सभी जानते हैं कि जब पूरे देश व पूरी दुनिया में कोरोना का प्रहार हुआ था और पूरी दुनिया में लाखों लोग मारे गये थे। वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2021 तक लगातार 2 वर्षों तक कोरोना काल रहा, उस दौरान हमारे भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री मा0 मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में देशवासियों की रक्षा के लिए कार्यक्रम आयोजित किये और हर व्यक्ति के लिए मुफ्त में टीका उपलब्ध कराया और हमारे उत्तर प्रदेश में मा0 योगी जी ने निरन्तर काम करते हुए प्रदेशवासियों को हर प्रकार से इस बीमारी से मुक्त रखने का प्रयास किया और आज उत्तर

प्रदेश का हर व्यक्ति कोरोना के द्वारा जो संकट पैदा हुआ उस संकट से मुक्त हो चुका है। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आप सभी जानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश आज से 6 वर्ष पहले अन्य दलों के शासन में था और इस प्रदेश में गुण्डाराज, माफियाराज था, प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी । आम आदमी बुरी तरीके से पीड़ित था, फर्जी मुकदमें होते थे। कभी भी, किसी का भूमि कोई भी कब्जा कर लेता था और जब देश में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उसके तीन वर्षों के कार्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा कायम हुआ इस देश में, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी ऐतिहासिक जीत हासिल की और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। विकास में जो अवरोध इस प्रदेश में था, उस अवरोध को समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की चाहे सड़कें हो, चाहे नदियाँ हों या फिर उद्योग धन्धे हों, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ।

आज जिन प्राथमिक विद्यालयों में अपने बच्चों का लोग एडमिशन नहीं कराते थे, अगर 100-50 बच्चों का एडमिशन होता था, तो वो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में जा करके पढ़ना नहीं चाहते थे। हमारी सरकार ने काया-कल्प योजना के माध्यम से उन प्राथमिक विद्यालयों को जिस प्रकार से एक नये बदलाव की दिशा में पहुँचाया है। आज लगभग 1 करोड़ 90 लाख विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसके लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। आज प्रदेश के गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा रहे हैं और उन्हें बेहतर तरीके से पुस्तकों से लेकर के, उनकी ड्रेस मटेरियल हर चीज हमारी सरकार उपलब्ध करवा रही है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों को भूख से बचाने के लिए, हमारी सरकार ने हर गरीब परिवार को मुफ्त में अनाज दिया। आज पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना हुआ है कि यह सरकार गरीबों की सरकार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यह नारा आज जन-जन को अपना व्यक्तिगत नारा लगता है। आदरणीय महोदय, आप सब जानते हैं कि महिलाओं को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे उपाय किये हैं। अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो उसके पैदा होने के साथ ही उसको आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य, उसकी शिक्षा के लिए हर प्रकार का सहयोग और उसके सम्मान के लिए सरकार ने अनेक कानून बनाये। उन कानूनों के द्वारा आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही न्यायप्रिय वातावरण बना हुआ है।

आदरणीय महोदय, हमारी सरकार ने अपने इस बजट में जो व्यवस्था बनायी है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1525 करोड़, धर्मार्थ मार्गों के लिए 1000 करोड़, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 5,332 करोड़, विद्युत वितरण क्षेत्र में, उसकी बेहतर व्यवस्था के लिए 6500 करोड़ और

किसान पाठशाला आयोजन के लिए 2023-2024 के लिए 17 हजार पाठशालाओं का आयोजन होगा। पशुपालन के लिए, आप सब जानते हैं कि अभी चर्चा भी हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में निराश्रित पशुओं की बड़ी समस्या है। हमारी सरकार ने हर विधान सभा क्षेत्र में अनेक गौशालाओं को निर्मित किया है, व्यक्तिगत स्तर पर या फिर सरकारी स्तर पर गौशालायें चलायी जा रही हैं और इस गौवंश की रक्षा के माध्यम से सरकार ने जिस प्रकार का संदेश दिया है, वह सामाजिक रूप से हमारे प्रदेश को और मजबूत बनाता है। आदरणीय महोदय, मैं आपको इस विषय पर भी बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा, पिछले 06 वर्ष में जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में हाईवेज बने हैं, जिला मार्ग बने हैं। मान्यवर, पहले इस प्रदेश में अगर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता था तो अगर 500 किमी0 जाना होता था तो दस बारह घंटे लगते थे, लेकिन आज अगर 500 किमी0 जाना है तो चार घंटे से ज्यादा वक्त नही लगता है। इस प्रकार का विकास कार्य हमारी सरकार ने किया है।

विद्युत व्यवस्था के मामलें में अक्सर लोग चर्चा करते थे कि उत्तर प्रदेश में विद्युत की बड़ी समस्या है, लेकिन मैं ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले एक वर्ष में उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बहुत ही बेहतरीन किया। आज जितने भी गांव, जितने भी कस्बे हैं जहां पर जर्जर तार हुआ करते थे वहां पर सारे तारों को बदल दिया गया है। जितने भी पोल जर्जर थे उन सारे पोलों को दोबारा हटाया गया। अब कहीं भी तारों को लेकर के कोई समस्या नही है और विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हमारी सरकार ट्रान्सफार्मर को भी उच्चीकृत कर रही है। ट्रान्सफार्मर जहां पर 63 के0वी0ए0 थे 100 के0वी0ए0 और जहां पर 100 के0वी0ए0 थे वहां पर 250 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगा कर हमारी सरकार ने उन क्षेत्रों को बेहतर बनाने का काम किया है। इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष के आग्रह की जरूरत नही है हमारी सरकार सभी के सभी ऐसे कार्यक्रम पूरे प्रदेश के लोगों के लिए एक तरीके का कार्यक्रम कोई भेद-भाव नहीं, बिना किसी भेद-भाव के सारे कार्यक्रम कर रही है। अभी आपने पिछले तीन दिनों तक दस से लेकर बारह फरवरी में जो उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ इस समिट का हमारे विपक्ष के लोगों को शायद अनुमान नही है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने जनपद स्तर पर मैंने देखा है जनपद सन्तकबीरनगर में जहाँ पर मात्र 300 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था जो एक वातावरण बना, जो हमारें मंत्रि-मण्डल के सहयोगी, हमारें मंत्रि-मण्डल के लोग, विदेशों में गए और निरन्तर विदेशों में जाकर के अपने देश के प्रवासी भारतीयों से भी मिले और उनको भी आमंत्रित किया और एक ऐसा वातावरण बना कि आज हमारे छोटे से जनपद सन्तकबीरनगर में भी 300 करोड़ के लक्ष्य का बीस गुना छह हजार करोड़ के वहां पर प्रस्ताव मिले हैं और इस कारण से ही जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखा था वह लक्ष्य भी कई गुना बढ़ कर के पैंतीस लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो वातावरण, औद्योगिक विकास का बनने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश का अभी जो अनुमानित है कि पंचानबे

लाख लोगों को रोजगार मिलेगा मुझे लगता है कि यह रोजगार एक करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है। उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं देखता हूँ कि हमारे नौजवानों में जो बच्चे स्कूल, कॉलेज में पढ़ रहें हैं उन नौजवानों में आज एक आशा और विश्वास पैदा हुआ है कि मा0 योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में सरकार काम कर रही है आने वाले दिनों में हर सेक्टर में बेहतर रोजगार मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था का परिणाम है कि इस प्रदेश में अपराध घटे हैं चाहे वो डकैती हो, हत्या हो, लूट हो, बलात्कार हो, या अन्य प्रकार के जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश में घटे इसके पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में अपराधियों का और अपराधों का बोलबाला था। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में फर्जी मुकदमें किस प्रकार से लिखाये जाते थे जो व्यक्ति सरकार से जुड़ा हुआ था वही आपकी जमीनें कब्जा करता था और जब आप थानों में जाते थे तो उलटे आपके ऊपर ही मुकदमें लिखाये जाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज कोई भी व्यक्ति फर्जी मुकदमे नहीं लिखा सकता है आपने देखा होगा अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने इलाहाबाद की घटना पर यहां पर सदन में जोरदार शोर शराबा हो रहा था, मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी सरकार को कि अड़तालीस घंटो के अन्दर यह परिणाम हमारे सामने दिखाई दिया है और आज यह उत्तर प्रदेश में वातावरण बना है कि इस प्रदेश में न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, अत्यन्त ही शक्तिशाली और परिणामदायी है।

आज इस अवसर पर मैं अपनी विधान सभा के सम्बन्ध में भी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ विधान सभा क्षेत्र माना जाता रहा है। इस विधान सभा क्षेत्र में विकास के कार्यों में आजकल जो तेजी है अगर यही तेजी बरकरार रखी गयी तो शायद विकास के मामले में हमारी विधान सभा भी आगे आयेगी, लेकिन उसके लिये बहुत सी बुनियादी चीजों की जरूरत है। हमारी विधान सभा क्षेत्र में अभी भी सड़कें काफी बुरी तरह से खराब हैं, इसका कारण यह है कि हमारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, सड़कें बनती हैं और टूट जाती हैं। इसलिये मैं मा0 सदन के माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारी विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिये विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। सिंचाई के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि हमारी विधान सभा क्षेत्र के बहुत से गाँवों में सिंचाई के लिये नहरों का जाल बिछा हुआ है और जहाँ पर नहरें नहीं पहुँच पा रही हैं वहाँ पर ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई की जा रही है। नहरों के दुरुस्तीकरण के लिये मैं मा0 मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जहाँ पर नहरें टूटी-फूटी हैं, जहाँ पर कच्चे पाथ-वे हैं, उन नहरों को भी पक्का बनाया जाये। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो 'वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज' की बात की गयी है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज की बात की गयी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनपद सन्तकबीरनगर के खलीलाबाद नगर से सटी हुयी हमारी

विधान सभा शुरू हो जाती है और यह 50 किलोमीटर की लम्बाई में है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी तथा मा0 वित्त मंत्री जी से जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी विधान सभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज तथा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिये प्रस्ताव किया जाये तथा उसके लिये फंड दिया जाये जिससे कि वहाँ भी विकास का कार्य हो सके। इसके साथ ही मैं अपने जनपद की उन बातों को भी बताना चाहता हूँ जो बातें मेरे जनपद सन्तकबीरनगर के विकास के लिये जरूरी हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी-

मान्यवर, बस एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर लूँगा । आप सभी जानते हैं कि आजकल पर्यटन एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। पर्यटन के क्षेत्र में हमारे जनपद सन्तकबीरनगर में दो ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं। एक तो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है और दूसरा रामसर साईट बखीरा झील है, अगर इन दोनों स्थानों का विकास कर दिया जाये तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश में पर्यटन का बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण केन्द्र बन सकता है और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने का अवसर बन सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर से मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को और अपने वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये एक बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री अधिष्ठाता-

श्री ओम प्रकाश राजभर जी।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद। काफी दिनों से बजट के ऊपर जो चर्चा हो रही है मैं बैठकर उसको सुन रहा हूँ और महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर हमारे प्रतिपक्ष के तमाम नेता या तो झूठ बोलते हैं या तो जानते नहीं हैं। इधर से चर्चा हुयी कि यह झूठ का पुलिन्दा है और दिशाविहीन बजट है, लेकिन पाँच करोड़ चाही। ई कहाँ से आयी ? अगर बजट में कुछ नहीं है तो ई पाँच करोड़ कहाँ से आयी ? बजट में अगर कुछ नहीं है, यह झूठ का पुलिन्दा है और दिशाविहीन बजट है तो फिर पाँच करोड़ चाही और तीन करोड़ बोनस और चाही यानी कुल आठ करोड़ चाही, ई आई कहाँ से ? अब यह आप जानो, आप लोग चर्चा कर रहे हो, हमारे भी लोग पाँच करोड़, तीन करोड़ मांग रहे हैं। आप लोग भी मांग रहे हो, लेकिन जब बजट में है ही नहीं तो यह सरकार देगी कहाँ से ? इस नाते हमने देखा कि जब यह बॉल उधर रहती है तो भारी भरकम बजट और जब वह बॉल इधर रहती है तो वही बजट झूठ का पुलिन्दा बन

जाता है। फिर इधर से उधर जाकर वही काम शुरू हो जाता है। खैर, हम शिक्षा के सवाल पर आते हैं। शिक्षा पर सरकार ने जो प्रयास किया है उस प्रयास में कुछ कमी है। उस पर हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि भारत देश में एक प्रदेश तेलंगाना है जिसकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 3 करोड़ 51 लाख 93 हजार 878 है। वहां पर 500 कॉलेज के0जी0 से लेकर पी0जी0 तक हैं जहां पर पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक के लिए निःशुल्क शिक्षा, भोजन और आवास आदि की सुविधायें दी जा रही हैं। वहां पर ऐसे 500 कॉलेज खोले गये हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत विकास किए हैं, अच्छी बात है आपने विकास किया है हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन शिक्षा के सवाल पर जिस जाति की बात आई है, जाति है कि, जाति जाती नहीं, और चुनाव आता है तो जाति याद आ जाती है।

हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर इन्होंने शिक्षा पर कुछ नहीं किया है तो आप भी इनके नक्शे-कदम पर न चलें, आप कम से कम तेलंगाना में एक प्रतिनिधि भेजकर वहां से पता कर लीजिए कि आखिर वह स्टेट इस तरह की सुविधा कैसे दे रहा है ? उस व्यवस्था को यहां लाकर शुरू किया जाय क्योंकि जब तक शिक्षा समाज में नहीं होगी तब तक न तो प्रदेश तरक्की कर पायेगा और न ही देश तरक्की कर पायेगा। इस नाते शिक्षा के सवाल पर जो बजट आया है उस पूरे बजट में यह व्यवस्था नहीं है।

हमारी कोशिश होनी चाहिए है कि जिस तरह तेलंगाना में 500 कॉलेज के0जी0 से पी0जी0 तक खोलकर निःशुल्क चलाये जा रहे हैं उसी तरह यहां भी वह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। दूसरा विषय हमारा है कि सरकार ने बहुत काम किया है, भू-माफिया के नाम पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने भी इसको पढ़ा है। भू-माफिया के नाम पर बजट में कहा गया है कि प्रदेश में एंटी भू-माफिया पोर्टल पर 3 लाख 41 हजार 236 शिकायतें आई हैं और 3 लाख 39 हजार 552 शिकायतें निस्तारित कर दी गयी हैं। मान्यवर, भू-माफिया के नाम पर हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि भूमिहीनों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। इसको भी आप दिखवा लीजिए, क्योंकि यह पूरे प्रदेश का मामला है, यह हमारा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। जो भूमिहीन हैं, जो दशकों से गांव सभा की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर 50 साल, 60 साल 100 साल से बसे हैं उनको गांव में ग्राम प्रधान की गोलबन्दी की वजह से दर्खास्त दी जाती है जिससे आदेश हो जाता है और भूमिहीनों के घरों को गिरा दिया जाता है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन उन भूमिहीनों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको भू-माफिया बनाकर उनके मकानों को गिराया जा रहा है। इस पर आप अपना ध्यान जरूर डालिए। इस तरह की घटनायें आए दिन हमारे सामने आती हैं और तमाम सदस्यों के सामने भी इस तरह की घटनायें आती होंगी। इस नाते भूमिहीनों को भू-माफिया बनाने का काम नहीं होना चाहिए।

आगे हम महिलाओं की बात करते है। सरकार ने महिलाओं को बजट तो दिया है लेकिन अब हम क्या कहें, यह लोग आधी आबादी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि महिलाओं की आधी आबादी है। बजट तो बहुत लम्बा है, लेकिन इस पूरे लम्बे बजट में महिलाओं के विकास के लिए, जहां आधी आबादी है वहां 5 हजार 895 करोड़ रुपये सभी मदों में महिलाओं के लिए आपने दिया है। इस नाते महिलाओं के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि जब आधी आबादी है, जब देश की सर्वोच्च कुर्सी पर महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर महिला प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्री की कुर्सी पर महिला मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी की कुर्सी पर महिला जिलाधिकारी सुशोभित कर सकती हैं और फाइटर प्लेन चला सकती हैं तो महिलाओं के लिए नौकरियों में 50 प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया जाये। इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगी। हम जिस सुरक्षा की बात पर चर्चा करते हैं। आज अगर आप शिक्षण संस्थानों में देखेंगे आधी आबादी महिलाओं की है। चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो वहां महिलाओं के लिए सीटे सुरक्षित कर दी जायें। इनको निःशुल्क पढ़ाकर अच्छी व्यवस्था देकर आगे बढ़ाने का काम किया जाये । हम इनकी सुरक्षा की बात करते हैं। 75 साल बीत गये और पुरुष 75 साल से महिलाओं के विकास की ही बात करते हैं, इनकी सुरक्षा की बात करते हैं। यह मामला वहां का नहीं है लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से चाहूंगा कि लोक सभा/विधान सभा में भी यहां से पत्र जाये कि महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी जायें ताकि वे अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें किसी के भरोसे न रहें।

मान्यवर, सरकार ने एक्सप्रेस-वे बनाया। इस एक्सप्रेस-वे में एक पूर्वान्चल का आता है। उसका भी हम आनन्द लेते हैं। बलिया के हमारे विधायक जी भी आनन्द लेते है। मऊ के और अम्बेडकरनगर के विधायक जी भी आनन्द लेते हैं। सटे हुए कई जिलों के लोग लेते हैं। इधर जब हम कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं तो अखिलेश जी ने बनाया है आगरा एक्सप्रेस-वे, उसका भी आनन्द लेते हैं। बुन्देलखण्ड का जब से बना है तब से हम गये नहीं है। नोएडा का भी है, उधर जाते हैं तो उसका आनन्द लेते हैं। हम लोग तो आनन्द लेते हैं, लेकिन एक्सप्रेस-वे बनने से ग्रामीण इलाकों की सड़कें टूट गयी हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सबका ध्यान सिर्फ एक्सप्रेस-वे पर चर्चा करने में है। हमने यह बना दिया, हमने यह बना दिया। अच्छा किया आपने। जनता ने आपको चुनकर भेजा है तो किसलिए भेजा है ? बिगाड़ने के लिए कि बनाने के लिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इधर की बॉल जब उधर जाती है या उधर की बॉल इधर आती है तो हमने कभी यह नही सुना 75 साल की आजादी में कि प्रदेश को बिगाड़ने के लिए प्रदेश को विनाश के रास्ते पर ले जाने के लिए जनता ने चुना हो । जनता तो विकास के लिए ही चुनती है। चाहे सपा को चुने, कांग्रेस को चुने, बसपा को चुने, भाजपा को चुने। किसी को चुने । जनता विकास के लिए ही चुनती है। जो ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। पूरा बजट हमने देखा, सरकार का एक्सप्रेस-वे पर पूरा ध्यान है। ग्रामीण इलाके पर जो बजट है हमने उसको भी देखा। लेकिन यह बजट बहुत कम है। हम लोग गांव से चुनकर आते

हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं। ग्रामीण इलाके हमारी विधान सभा क्षेत्र से ही पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे जाती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी एक्सप्रेस-वे की चर्चा कर रहे थे। मुझे याद है जब मैं उनके साथ था तो महमूदाबाद से लखनऊ तक हम लोग 2 बजे रात को रथ यात्रा लेकर आये थे। उसी पर आये भले ही हिचकोले खाते हुए आये हों लेकिन रास्ता वहीं मिला। जो पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे बना। हो सकता है आपके पास अच्छी टैक्नॉलाजी रही हो। आप प्रतिपक्ष के नेता है। आप सलाह अच्छी न दे पाये हों कि इस तरह का हमने बनवाया है आप इस तरह का बनवा दीजिए तो बेहतर बना होता। लेकिन इतना जरूर है कि जो पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे बना है उससे हमारे लिए, पूर्वान्चल के इलाकों के लिए लखनऊ आने के लिए बेहतर आवागमन सुविधा हो गयी है। इसको नकारा नहीं जा सकता है।

मान्यवर, हमने देखा कि आवास के लिए सरकार ने बजट दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 2011 की जनगणना के आधार पर आवास बनाने की सूची बनी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आज 2023 है। जिस बाप के पास 4 बेटे थे। 5 साल 6 साल के बाद वह चार जगह मड़ई डाल लिये। पता लगा कि 3 लोग आवास के पात्र हो गये। आज भी गांव में 5-6-10-12 ऐसे बेचारे हैं, जो नेताओं के फलैक्स डालकर अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। इस नाते हम आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि 2011 की जो जनगणना है उसके बाद आज परिस्थिति बदली है। इसमे बदलाव की जरूरत है। आज गांव में सर्वे करा लीजिए जो वास्तव में पात्र है उसको आवास देने का काम करिये। आपने बहुत आवास दिये। यह सरकार थी तो इन्होंने भी आवास दिया, आप आये तो आप भी आवास देने का काम कर रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। यह तो एक प्रक्रिया है और मान्यवर पिछड़ी जाति की बेटी की शादी की बड़ी विसंगति है मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराऊंगा कि आपने पिछड़े वर्ग की बेटियों के लिए शादी अनुदान की राशि 150 करोड़ रुपये दिये है बेशक आपने पिछले बजट से बढ़ाया है और हम इसका स्वागत करते है। आपने सामूहिक विवाह के लिए भी 600 करोड़ रुपये दिया है इसके लिए बहुत-बहुत आभार लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी विसंगति है और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि पिछड़ा वर्ग विभाग बना है इसकी आबादी 52 प्रतिशत है और पिछड़ों की बेटी की शादी के लिए मात्र 20 हजार रुपये मा0 मंत्री जी आप भी पिछड़ी जाति से ही आते हैं ध्यान रखिएगा यह जो मैं कह रहा हूँ यही विसंगति है कि 20 हजार रुपया पिछड़ी बेटी की शादी में महंगाई के समय में ऊट के मुंह में जीरा है। इसी नाते वहीं जब सामूहिक विवाह होता है तो आप 35 हजार रुपये नगद देते है और दस हजार का सामान देते है और आयोजन में खर्च करते है और श्रम विभाग से पचास हजार रुपया आप शादी अनुदान देते हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है कि बीस हजार से बढ़ाकर के उसको सामूहिक विवाह व श्रम विभाग द्वारा जो पचास हजार दिया जाता है वहीं पिछड़ी जाति की बेटी की शादी में भी पचास हजार रुपये करने का समय आ गया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि आपके कई विभाग अनेक योजनाएं चलाते है जैसे कि विधवा पेंशन पारिवारिक लाभ, वृद्धा पेंशन और पिछड़े वर्ग के लोग कभी नहीं जान पाते कि कितने लोग लाभान्वित हुए इसलिए मेरा अनुरोध है कि जब पिछड़ा विभाग बना हुआ है तो यह सिर्फ पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बना हुआ है। यह सभी योजनाएं एक जगह से चलाने पर पिछड़े समुदाय को आसानी होगी और उसका सभी काम एक जगह से होगा और समुदाय में एक अच्छा मैसेज भी जायेगा कि सरकार हम पर इतनी धनराशि खर्च कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक देश एक राशन कार्ड बनाने के लिए सरकार पहल कर रही है और एक देश एक टैक्स लेने की बाद कर रही है मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि बजट में व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन एक देश एक शिक्षा लागू करने के लिए बजट में जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत जो तेलंगाना को जो मामला है उससे सीख लेकर के एक नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम करने के लिए पूरे बजट में हमने देखा कि कही भी हमें ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं दी और पूरे बजट में महंगाई पर कहीं कुछ नहीं दिखा लेकिन हो सकता है कहीं हमारी नजर या हमारे चश्मे में कमी हो। हमारे कुछ साथी कहा करते है मंहगाई कहां है लेकिन मैंने दस दिन पहले टायर अपनी गाड़ी में डलवाये तो जो पांच हजार में टायर लगवाये थे वह अब दस हजार के हो गये हैं और जो मोटरसाइकिल 50 हजार रुपये की खरीदी जाती थी आज वह एक लाख की हो गयी है और पैट्रोल, डीजल हम सभी लोग भरवाते हैं देखिए कितना महंगा हो गया है। महंगाई पर पक्ष और विपक्ष को सामूहिक चिंतन करना चाहिए। इस सदन में बैठे लोगों का ही नहीं 25 करोड़ आबादी का सम्बन्ध है महंगाई का और इस पूरे बजट में हमने पढ़ा है लेकिन कहीं महंगाई कम करने का प्रावधान नहीं है जो मजदूर मजदूरी करता है और गरीब रिक्शा चलाता है कैसे उसको लाभ मिले आज वह गेहूँ और आटा जब खरीदने जाता है।

माननीय अधिष्ठाता जी, जो आपका आदेश है हम उसे कानून मानते हैं। हम अनुशासन में रहकर ही काम करते हैं। अगर आपकी इजाजत होगी तो ही मैं आगे बोलूँगा नहीं तो मैं समाप्त कर दूँगा। मैंने माननीय अध्यक्ष जी से 20 मिनट का समय मांगा था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बात दो मिनट में पूरी कर लूँ।

हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने हमसे पूछा था तो मैं उसी समय खड़ा हुआ था और सोचा था कि उत्तर दे दूँ लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि नहीं समय आयेगा तब उत्तर दीजियेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने हमसे पूछा था कि क्या आप शूद्र हो। तो मान्यवर, जब इस देश में मनु स्मृति बनी और चार वर्ण ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने तो शूद्र में अहीर, गड़ेरी, कुण्डी, कोरी, भार, चमार, मुसहर, धोबी, खटिक, पासी, केवट, बिन्द, मल्हार, जुलाहा, अंसारी, शेख, सैय्यद, पठान, धरितार पासी, कुजड़ा यह 6743 जातियाँ जब बनाई गईं तो उस समय मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जाति कभी जाती नहीं है, चुनाव आता है तो यह जाति याद आ जाती है। यह हमने देखा है और जाति को नकारा नहीं जा सकता है। हम शूद्र हैं और हम जातिवार

जनगणना के लिए 20 साल से लड़ते आ रहे हैं। हमारे जो विपक्ष के साथी हैं चाहे वह बसपा के साथी हों, चाहे कांग्रेस के साथी हों, चाहे सपा के साथी हों जब अकेले हम बाहर चिल्लाते रहे तो किसी को सुनाई नहीं देता था। उस समय बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा सुनाई दिया और थोड़ी चर्चा हुई, लेकिन सपा को सुनाई नहीं दिया। कांग्रेस से सपा का उस समय गठजोड़ था। उन्होंने प्रस्ताव दिया तो इन्होंने सुना होगा लेकिन मैं उस समय साथ नहीं था और चूंकि उस समय हम सदन से बाहर रहते थे। हम जातिवार जनगणना के पक्षधर हैं। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी, तब तक मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बंजारा, बहेलिया, राजभर, चौहान, बारी, बियार आदि जातियाँ जिनका कोई पेशा नहीं है उनका उत्थान नहीं हो पायेगा । हमने बजट पुस्तिका में पढ़ा है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का उल्लेख है, लेकिन जिसको कोई श्रम दिया ही नहीं गया है उसको कौन सा काम देंगे, उनके लिए भी काम की व्यवस्था कराई जानी चाहिये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भर को कोई काम नहीं मिला है, चौहान को कोई काम नहीं मिला है, बारी-बियार को कोई काम नहीं मिला है, बंजारा को कोई काम नहीं मिला है, अर्धवंशी को कोई काम नहीं मिला, तो इनको भी कोई पेशा दिलाने की व्यवस्था बनाई जाये ताकि यह भी अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इसी नाते नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल किया था उसका यही उत्तर है कि मनु स्मृति में जो व्यवस्था बनी हम उसके हिसाब से हम शूद्र हैं। जब तक तहसीलों में ठप्पा मारकर जाति प्रमाण-पत्र दिया जायेगा और कहा जायेगा कि तुम भर हो, चौहान हो, बिन्द हो, केवट हो, मल्लाह हो, ब्राम्हण हो, राजपूत हो, तब तक ओम प्रकाश राजभर जाति को मानता रहेगा और जाति की लड़ाई लड़ता रहेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार उत्तर प्रदेश की 18वीं विधान सभा का दूसरा बजट प्रस्तुत कर रही है। सत्तापक्ष अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत करने का दावा करता है। अगर संख्या को देखा जाये तो 6,90,000 करोड़ का बजट लाकर सरकार अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा तो जरूर पीट रही है, पर मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि पिछले वर्ष भी हम सब इसी सदन के सदस्य थे। सरकार 6,15,000 करोड़ का भारी-भरकम बजट लेकर आई थी और सरकार ने कहा था कि यह सबसे बड़ा ऐतिहासिक बजट है। उसके बाद 33,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी सरकार लेकर आई। कुल 6.49 लाख करोड़ का बजट पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार लेकर आई थी पर अफसोस की बात यह है कि पिछले बजट का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केवल 50 प्रतिशत बजट सरकार खर्च कर पायी है और कई ऐसे विभाग थे जिसमें 30 प्रतिशत से ज्यादा बजट सरकार खर्च नहीं कर पायी है। आज नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही जो मैंने अपने भाषण में भी कही थी कि सरकार एक ट्रिलियन इकानॉमी का सपना देख रही है। सपना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वह तथ्य उसमें है ही नहीं । धरातल पर नहीं उतर सकता है। अगर आज की परिस्थिति हम देखें तो 16.5 प्रतिशत की हमारी जी0डी0पी0 है। अगर वन ट्रिलियन का टारगेट हमें अचीव करना है तो जो मानक हैं उसके हिसाब से 33-34 प्रतिशत हमारा ग्रोथ रेट होना चाहिए तब हम पहुंचेंगे। जबकि सरकार इसी बजट में खुद स्वीकार कर रही है कि उसका लक्ष्य 19 प्रतिशत का है। तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि सरकार केवल आँकड़ों के दम पर जनता को गुमराह करने का प्रयास क्यों कर रही है। मूल बातों से जनता का ध्यान भटकाने का क्या यह कोई नया तरीका है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अगर हम बजट को ध्यान से देखें और अगर हम पिछले बजट से उसको कम्पेयर करते हैं तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। कुछ प्रमुख विभाग जिनके बजट का पैसा सरकार नहीं खर्च कर पायी है और जिनकी वजह से बहुत सी महत्वपूर्ण योजनायें आज भी अधर में लटकी हैं। ग्राम्य विकास विभाग जिसमें 28 हजार 146 करोड़ रुपये मिले थे और इतने महत्वपूर्ण विभाग में भी केवल 14 हजार 99 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर पायी थी। चिकित्सा विभाग जिसमें 44 हजार 387 करोड़ रुपये मिले थे उसमें आधे से भी कम 21 हजार 676 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर पायी। ऊर्जा विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। क्योंकि अगर प्रदेश का इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है तो हमें अपने इस सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। मैं तो यह कहूंगी कि सरकार जैसे भी नीति लाना चाहती है लेकर आये पर कम से कम सरकार नये ऊर्जा के हमारे जो स्रोत हैं, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। पर अफसोस की बात यह है कि सरकार इसमें 54 हजार करोड़ के बजट में केवल 32 हजार करोड़ रुपये खर्च कर पायी है। अगर सरकार चाहती तो कोई नया संयत्र लगा सकती थी। पिछले 6 वर्षों में सरकार एक भी नया प्रोडक्शन सेंटर नहीं खोल पायी है। लोक निर्माण विभाग जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब तक हम उसको सुदृढ़ नहीं करेंगे तब तक हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं करेगी। इतने महत्वपूर्ण विभाग में भी 27 हजार करोड़ के बजट के बाद उसके सापेक्ष केवल 7500 करोड़ रुपये ही खर्च कर पायी है जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा उनकी बात से अपने को संबद्ध करती हूँ कि एक्सप्रेस-वे बनने चाहिए। जिले से जिले को जोड़ना आवश्यक है, पर इस प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी गाँव में रहती है अगर हम गाँव की सड़कों को नहीं जोड़ेंगे तो हम शहर की सड़कों को जोड़कर उत्तर प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। मान्यवर, एक अनुरोध है कि जब दलीय नेता बोलते हैं तो कम से कम बजट पर जब भाषण होता है तो वित्त मंत्री जी का होना एक परम्परा है।

[03:49] आय-व्यय की साधारण चर्चा के मध्य संसदीय कार्य मंत्री के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री रघुराज प्रताप सिंह-**

मान्यवर, एक अनुरोध है कि मा0 नेता कांग्रेस बोल रही हैं, हम लोगों का मनोबल बढ़ता अगर मा0 नेता सदन होते, मा0 नेता प्रतिपक्ष होते, मा0 संसदीय कार्य मंत्री होते तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता और मा0 सदस्यों की संख्या देख ही रहे हैं, अब ऐसे में हम बोलें भी तो क्या बोलें। अगर आपका निर्देश हो तो हम लोग बोलें। जहां सुनी जाए वहां बोले, यह तो हम लोगों का अपमान हुआ।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मा0 वित्त मंत्री जी ने बजट रखा है तो कम से कम मा0 वित्त मंत्री जी को सदन में उपस्थित रहना ही चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

सरकार की तरफ बड़े गम्भीर मा0 मंत्री जी विराजमान हैं।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, हम लोगों का निवेदन है कि आधे घण्टे के लिए सदन स्थगित कर दिया जाए और जब मा0 नेता सदन आ जाए तब हम लोग बोलें।

श्री अधिष्ठाता-

आपने आधे में ही अपनी बात को छोड़ दिया है, मा0 मोना जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, आपकी बात को काटना उचित नहीं है, क्योंकि पीठ से निर्देश हुआ है, लेकिन यह परम्पराएं सदन की गरिमा के विपरीत हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी भी विराजमान हैं।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, अभी-अभी विराजमान हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने आपके आग्रह को स्वीकार कर लिया है। मा0 मोना जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[03:50] वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, एक और गम्भीर प्रोजेक्ट **है** और इत्तेफाक से आज मा0 वित्त मंत्री जी की जगह मा0 सिंचाई एवं जल शक्ति मंत्री जी बैठे हैं। जल जीवन मिशन योजना का वर्ष 2024 तक का लक्ष्य है कि 2.26 करोड़ हाउसहोल्ड तक पहुंचाना है। जिसमें 9.77 लाख मतलब अभी केवल 30 प्रतिशत अपने लक्ष्य को हम अचीव कर पाये हैं और लक्ष्य बहुत बड़ा है उस तक कैसे पहुंचा जाए और समय बहुत कम है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचना है। जबकि सबसे बड़ी विषमता यह है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में और खासकर जो नदी के किनारे क्षेत्र हैं वहां आर्सेनिक एवं खारे पानी की जो समस्याएं हैं वह बड़ी विशाल समस्या है। पानी की वॉटर लेबल दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में यह सबसे बड़ी चुनौती है कि शुद्ध पेयजल हर व्यक्ति तक पहुंचाना। मुझे विश्वास है कि यदि यह योजना क्रियान्वित हो जाती तो शायद ज्यादा-से-ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सकता था। पर अफसोस की बात है कि इस विभाग में भी हम अभी केवल 13 लाख 734 करोड़ रुपये के सापेक्ष 03 हजार करोड़ रुपये ही खर्च कर पाये हैं। इसी तरह से मैं मानती हूँ कि यह हम सबसे सम्बन्धित मामला है, समाज कल्याण एक ऐसा विभाग है जो इस प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोगों के हाथ को थामने एवं उनको मजबूत करने का काम करता है। उसका पेंशन के अलावा छात्रवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मैं पिछले वर्ष का आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि लगभग 1.25 करोड़ छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए अपलाई किया जिसके सापेक्ष मात्र 26 लाख छात्रों को ही छात्रवृत्ति मिल पाई। जबकि समाज कल्याण विभाग का बजट 11 हजार 769 करोड़ रुपये था और उसके सापेक्ष मात्र 5600 करोड़ रुपये ही सरकार खर्च कर पाई। क्या यह पैसा उन बच्चों को नहीं दिया जा सकता था, जिन वर्गों के बच्चों ने अपलाई किया था।

अगर मिल जाता तो शायद वह पढ़ाई कर लेते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए। कृषि, आज ही मैं अखबार में पढ़ रही थी कि सरकार ने दो हजार करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि के लिए अवमुक्त किये। मान्यवर, पिछले बजट में लगभग 7100 करोड़ रुपये कृषि विभाग को मिले थे, उसके सापेक्ष केवल तीन हजार करोड़ रुपये सरकार खर्च कर पायी है। यह किसान सम्मान निधि तो आपके घोषणा-पत्र में भी थी, क्यों नहीं दे दी गयी थी ? इस पैसे को बचाया क्यों गया, जो सबसे बड़ी वजह बजट में हम लोगों ने देखी, थोड़ा-बहुत अध्ययन किया, सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में और जो पिछला बजट बनाया था उसमें ऐसी घोषणाएं कर दी थीं जिसकी सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। बहुत सारी योजनाएं तो केवल फाइलों में बन्द पड़ी हुई थीं और आज भी बन्द पड़ी हुई हैं। हमारे आज मत्स्य मंत्री जी हैं नहीं, उनकी पीड़ा मैं समझ सकती हूं। पिछली बार उन्हें पांच करोड़ रुपये मिले थे उसमें दो करोड़ रुपये उन्हें निषादराज बोट सब्सिडी योजना के नाम पर मिला।

हास्यास्पद है कि अभी तक उसकी गाइडलाइन उन्हें नहीं मिल पाई है। इसी तरह से गन्ना किसानों का मामला था, कई चीनी मिलों के विस्तारीकरण की बात की गयी थी। बारांबकी, मोहिउद्दीनपुर, छाता आदि चीनी मिलों के विस्तारीकरण की बात की गयी थी। दो वर्ष बीत गये हैं, पिछले बजट में प्रावधान भी था और पैसा सरकार के पास पड़ा भी हुआ है, पर अभी तक विस्तारीकरण की कोई गाइडलाइन पिछले दो सालों में सरकार जारी नहीं कर पाई । खाद्यान्न, बड़े दुःख की बात है कि जिस 25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व यहां बैठे हम सब लोग कर रहे हैं उस पर हाई कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले गम्भीर टिप्पणी की और हाई कोर्ट ने कहा कि कुपोषण के इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी दयनीय है। यह एक गम्भीर विषय है। अगर खाद्यान्न की घोषणा हम केवल चुनावी वर्ष में करेंगे तो यह स्थिति और भी गम्भीर होती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब तो सरकार जो बजट लाई है वह और भी बड़ा बजट है, इनके पास फिजिकल डैफिजिट कम हुआ, रेवन्यू बढ़ा है तो जनता को खाद्यान्न मिलना चाहिए, गरीब आदमी को खाद्यान्न मिलना चाहिए। कुपोषण को हटाने के लिए सरकार के पास क्या रोडमैप है, यह सरकार को बताना चाहिए।

अगर मैं बात करूं, सरकार के मैनीफैस्टो की, जो घोषणा-पत्र उन्होंने दिया था, जिसके दम पर जीतकर ये आए थे। मैं तो एक गृहिणी हूं, महिलाओं के लिए इन्होंने दो-तीन बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी, कहा था कि होली-दीवाली पर फ्री सिलेण्डर मिलेगा। एक दिवाली बीत गयी और एक होली भी हफ्ते भर बाद आने वाली है, उस सिलेण्डर का अभी कहीं कोई अता-पता नहीं है, न मुझे बजट में कोई प्रावधान दिख रहा है। दूसरा, बेटियों को स्कूटी देने का वायदा किया था, अरे बेटी तो जब घर आती है तो उसे नेग देकर वैसे भी विदा कर दिया जाता है तो कम-से-कम उससे किये हुए वायदे को तो सरकार को पूरा करना चाहिए था। स्कूटी की घोषणा के सम्बन्ध में आपने बजट में क्या प्रावधान किया है ? दूसरा, बुजुर्ग महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन की भी घोषणा की गयी थी, मैं कल एक सदस्य को सुन रही थी कि अबकी बार ट्रांसपोर्ट का जो रेवन्यू जेनरेशन हुआ है वह रिकॉर्ड है। अगर आपके पास इतना प्रॉफिट है तो बुजुर्ग महिलाओं से जो आपने वायदा किया था उसको पूरा करने में आपको क्या दिक्कत है ? क्या देरी है ? उनका आशीर्वाद ही मिलेगा, उसको भी सरकार को पूरा करना चाहिए। इसी तरह से अगर हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बहुत सारे काम हुए हैं, पर बहुत सारे काम होना बाकी भी हैं। जिस तरह से ट्रामा सेंटर, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 में डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टॉफ की, उपकरणों की जो कमी है उसे भी देखना चाहिए। आप मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, पर जो सबसे बड़ी जरूरत है कि उन मेडिकल कालेजों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, मरीजों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए और जो इक्यूपमेंट्स हैं, जो हमारी डायग्नोस्टिक्स हैं, उनके लिए आपके पास क्या तैयारी है ? दो साल से आप लगातार, पिछला एक वर्ष पूरा हो गया है, यह दूसरा वर्ष शुरू होने जा रहा है, पाँच साल आप सत्ता में थे, आप यह बता दें कि कितने

डाक्टर्स का आपने रिक्रूटमेंट किया है जो कि इन मेडिकल कालेजेज में या जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कालेज हैं या पैरामेडिकल स्टाफ की हमारी जो जरूरत है, उनको पूरा करने के लिए सरकार के पास क्या रोडमैप है ? केवल मेडिकल कालेज बनाने से या मशीनें खरीदने से इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर नहीं सकती है। उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जिस प्रकार का मुझे बजट दिखायी दे रहा है, उसको पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखायी नहीं देती है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेनीफेस्टो में इन्होंने अन्नपूर्णा योजना की घोषणा की थी, मैं वह भी याद दिलाना चाहती हूँ। बड़ी वाहवाही लूटी गयी थी कि अन्नपूर्णा योजना आयेगी, गरीब लोगों को खाना मिलेगा। उसका भी इसमें कोई प्रावधान नहीं है। मैं तो यह जानना चाहती हूँ कि ऐसी योजना की घोषणा करने की आवश्यकता क्या है, जिसको आप पूरा करने में सक्षम नहीं हैं या जिसको पूरा करने की आपके अन्दर इच्छा शक्ति न हो। उसकी घोषणा करने की आवश्यकता क्या है ? इसीलिए सारे लोगों का और उत्तर प्रदेश की जनता का भी यही सवाल है कि केवल कागज पर फीगर लिख देने से, बजट का बड़ा आकार दे देने से जनता की समस्या पूरी नहीं होगी। जनता की समस्या तब पूरी होगी, जब आप उस पर लिखे गए आँकड़ों के हिसाब से उसको जनता तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। गाँव में बिजली के मीटर लग गए। हम सभी क्षेत्र में जाते हैं, आज की तारीख में सबसे ज्यादा समस्या है, बिजली के मीटर पर जो बिल आ रहा है, उसके नाम पर वसूली शुरू हो गयी है और सबसे ज्यादा अगर इससे कोई परेशान है तो किसान परेशान है। उसकी तो लागत आपने इतनी बढ़ा दी, बिजली का बिल बढ़ा दिया, डी0ए0पी0 का दाम बढ़ा दिया, यूरिया का दाम बढ़ा दिया, बीज का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम ऐसे ही बढ़ चुका है और एमएसपी आप उनको दे नहीं रहे हैं। उसकी आय दोगुनी हो नहीं रही है, लागत तो उसकी चार गुना बढ़ गयी। जब वह अपनी फसल को बेचने जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलता और बेचने भी क्या जाए, जब वह इतनी महंगाई के बावजूद फसल उगाता है तो वह रात भर लाठी लेकर उसका पूरा परिवार फसल ही ताकता है। यदि थोड़ी-बहुत चरने से बच जाती है और वह जब लेकर जाता है तो औने-पौने दाम पर वह अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। इसके अलावा इस बजट में कर्मचारियों के लिए भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। पुरानी पेंशन पर सरकार मौन है । यहाँ पर माननीय वित्त मंत्र जी नहीं हैं। मैं जब बोलती हूँ तो अक्सर वह राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जरूर जिक्र करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दिया है, उसे बहाल किया है और जो डिफरेंट का कम्पोनेंट है, वह प्रदेश सरकार दे रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सबसे बड़ी विडम्बना है कि आज जो अस्थाई कर्मचारी हैं, उनके विनियमितीकरण करने का सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं है। लाखों की संख्या में आपके इम्प्लाई मानदेय पर चल रहे हैं, कान्ट्रैक्टर उनका एक्सप्लायटेशन कर रहे हैं, सरकार उनसे काम तो ले रही है, पर उनको सुविधा देने और उनके नियमितीकरण करने के नाम पर सरकार शान्त है। छोटे

कारोबारियों के लिए भी कोई योजना इस पूरे बजट में दिखायी नहीं दे रही है। उनको आपने कुछ नहीं दिया, लेकिन उनको आपने सबसे बड़ी समस्या जीएसटी की दे दी। आज वह सबसे ज्यादा परेशान है, जीएसटी के कागज बनाने में और जो जीएसटी के नाम पर उनसे वसूली की जा रही है, चार पैसा जो वह कमा भी पा रहा था, वह भी कमाने में सक्षम नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, मैं अन्त मैं यह जरूर कहूँगी कि महंगाई और बेरोजगारी जो आज सबसे बड़ी विभीषिका बनकर प्रदेश की जनता के सामने है, उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने न तो कोई रोडमैप बनाया है और न ही सरकार ने कोई योजना इसमें दी है।

महोदय, अन्त में इतना जरूर कहूंगी। हमारे यहां तदर्थ शिक्षक हैं लगभग 2000 आज भॅखमरी की कगार पर वह खड़े हैं। हैं आज वह मजबूर है, क्योंकि उन्होंने लोन ले रखे हैं बेटी की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और समस्या यह है कि पिछले आठ माह से उनको वेतन नहीं मिल रहा है तो मेरा अनुरोध है कि सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए कम से कम जो मा0 उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से उनको नियमित करने के साथ-साथ उनका जो पिछले आठ माह का वेतन है वह भी देना चाहिए। अगर मैं अपनी बात नहीं कहूंगी तो मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। मेरी बात मेरे अकेले की नहीं है मेरे सदन में सभी साथियों की है, मैं पुनः इसको दोहराऊंगी ।

मा0 अधिष्ठाता महोदय महंगाई केवल जनता के लिए नहीं बनी हम लोग भी इसी प्रदेश में रहते हैं इसी महंगाई से हम सब भी जूझ रहे हैं। विधान सभा का जो सदस्य होता है उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है एक अपने परिवार की और दूसरी अपने क्षेत्र की जनता की और दोनों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। विधायक निधि पांच करोड़ मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की हम लोग इन्तजार कर रहे हैं 31 मार्च आने वाली है तीन करोड़ तो हमें मिल चुकी है और दो करोड़ का इन्तजार हम लोग कर रहे हैं और उसमें भी जी0एस0टी0 कट गई। पहले 8 परसेण्ट जी0एस0टी0 कटती थी अब 12 परसेण्ट हो गई है। अगर यह पांच करोड़ मिलेगा भी पिछला वाला तो उसमें लगभग हमारे पास 90 लाख रुपये उसमें भी कट जाएगा। मेरा अनुरोध है संसदीय कार्य मंत्री जी से और जो मंत्री जी बैठे हैं इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। प्रदेश में जो भी काम होगा वह विधायक निधि से प्रदेश के विकास के लिए होगा। तत्काल हमें पांच करोड़ का प्रावधान तो आगे के लिए दे दिया है और पिछला भी पांच करोड़ मिलना चाहिए उसका जो अवशेष दो करोड़ है वह मिले और जी0एस0टी0 की परिधि से इसको बाहर होना चाहिए। हम जब घर पहुंचेंगे और आप भी जब घर पहुंचेंगे और बाकी के सदस्य जब घर पहुंचेंगे तो हमारे क्षेत्र का जो मतदाता है तो वह यही पूछेगा का-का मिला, कुछु लाए हम सबके लिये। क्या जवाब देंगे। गर्मी आने वाली है मा0 मंत्री जी सामने बैठे है इनके पास पैसा बहुत है कम से कम दो-दो सौ हैडपम्प क्षेत्र के लिए हम सबको दे दीजिए। आज यह इत्तेफाक की बात है कि जब यह हम मांग कर रहे हैं तो यही सामने बैठे हैं और इनके पास पैसा भी पर्याप्त है। आज इनसे अनुरोध करेंगे कि दो-दो सौ

हैण्डपम्प सभी विधान सभा के सदस्यों के लिए दे दीजिए। मैं महिला हूँ गृहणी हूँ आप मा0 मंत्री जी हो, सबसे सशक्त मंत्री हो या मुख्य मंत्री जी को इस श्रेणी में नहीं ला सकते हैं, पर बाकी सब जब घर पहुंचते हैं तो उनसे यह पूछा जाता है कि हम लोगों के लिए आपने क्या किया है ? यह सवाल जो हमारी मेरी तो भाभी हुईं, चाची हुईं और परिवार के सभी लोग हैं मैं यह कहना चाहती हूँ कि उनकी भी समस्या को समझें इन्हें भी घर चलाना है, परिवार को चलाना है तो पहले एक कमेटी बनी थी जिसमें वेतन और पेंशन इन दोनों को रिव्यू करने के लिए और मैं तो कहूंगी कि उसको इंडेक्स से जोड़ना चाहिए जैसे हर कर्मचारी और हर किसी की जुड़ती है और उस कमेटी का रिव्यू किया जाए वह कमेटी फिर से पुनर्जीवित हो और वह इसको रिव्यू करे। रिव्यू करके विधायकों का वेतन बढ़ाया जाए। आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष और सभी दलीय नेताओं की बातों से अपने को सम्बद्ध करती हूँ। धन्यवाद।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के रखे गए बजट पर हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय श्री लालजी वर्मा जी ने जो एक तरह से संशोधन रखा या उसे कट मोशन कह लें। मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने आपको पूरी तरह से सरकार के द्वारा चुनाव में जारी किए गए संकल्प-पत्र और पिछले वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ने जो प्रावधान रखे थे, मैं अपने आपको उस पर ही आधारित रखते हुए चर्चा करूँगा । मा0 मंत्री जी एक बात का दुर्भाग्य है कि इस बार हम लोगों के ऐसे दलीय नेता आए हैं, जो हम लोगों के अगुआ हैं, गार्जियन हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष उनको हम लोगों की चिन्ता ही नहीं रहती है कि यहाँ और भी कोई दल है। जब वे बोलते हैं तो सदन में समर्थन जुटाने के लिए कभी ओम प्रकाश जी का, कभी बसपा का, कभी और किसी का नाम जरूर ले लेते हैं। लेकिन जब हम लोगों की बारी आती है तो वे गायब हो जाते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि हम लोग बिना गार्जियन के हो जाते हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ मा0 सदस्य श्री अवधेश प्रसाद जी बैठे हैं, आदरणीय माता प्रसाद पाण्डेय जी भी बैठे हैं, आप सभी जानते हैं, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले यह परम्परा रही है कि हम लोग हमेशा आपस में चर्चा करके एजेण्डा बना करके चर्चा में भाग लेते थे। खैर कोई बाद नहीं लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्य यह है कि जब दलीय नेता बोल रहे हैं तो मा0 वित्त मंत्री जी भी उसको बहुत गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। खैर हम तो केवल कह ही सकते हैं। मैं वित्त मंत्री जी को केवल एक चीज के लिए बधाई दूँगा कि जब उन्होंने अपना बजट तैयार किया है तो हर नियम का उन्होंने ध्यान रखा है। आदरणीय लालजी वर्मा जी भी वित्त मंत्री रहे हैं। ये जानते होंगे कि इस बात पर उन्होंने कम से कम अपने आपको कण्ट्रोल के अन्दर रखा है। इसमें जो 4.8 की सीमा है, उन्होंने उससे अपने आपको अन्दर रखा है।

लेकिन इसका परिणाम क्या है, मैं आगे कोई बात कहूँ, उससे पहले मैं वित्त मंत्री जी को एक चीज जरूर बताना चाहूँगा ।

*संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मंयकेश्वर शरण सिंह)-

मा0 अधिष्ठाता जी, मंत्रि-परिषद् का सामूहिक दायित्व होता है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री मा0 जल शक्ति मंत्री जी बैठे है, नन्दी जी बैठे हैं, राजभर जी बैठे हुए हैं, तीन-तीन कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है किसी का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना और राज्य मंत्री के रूप में मैं भी बैठा हूँ। हम लोग जितने भी मंत्री यहाँ बैठे हैं, सब गम्भीर हैं।

श्री अधिष्ठाता-

सरकार विपक्ष को लेकर गम्भीर है, आप अपनी बात कहें।

श्री उमाशंकर सिंह-

आप हम लोगों के बड़े भाई हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसकी आवश्यकता तब आती है, जब हमारा सदन चलता है, तो सदन में चर्चा के समय यह देखा जाता है कि मंत्रि-मण्डल समूह का कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद है कि नहीं है। यह उस समय की बात है, लेकिन आज चूँकि वित्त मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट भाषण पर हमारे दलीय नेता चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आदरणीय वित्त मंत्री जी का होना आवश्यक था।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मैं आपको उसके लिए भी बता दूँ कि मा0 वित्त मंत्री जी ने विधान परिषद् में वित्त से सम्बन्धित सारे कार्य हमको सौंप रखे हैं, तो आप यह मान कर चलिए कि आधा वोट है।

श्री उमाशंकर सिंह-

अभी हम आपका आश्वासन लेंगे। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह जो बजट की विसंगतियाँ आई हैं, बजट खर्च करने में जो कमी रही है।

श्री उमाशंकर सिंह-

जो पिछला बजट हमारा था, उस बजट को हम खर्च नहीं कर पाये और यह बजट में विसंगतियाँ कहाँ से हो रही हैं, हालाँकि इस बात को केवल मा0 वित्त मंत्री जी को आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहूँगा कि जब बजट बनाया जाता है तो वित्त मंत्रालय के द्वारा एक सर्कुलर जारी होता है और उस सर्कुलर के माध्यम से बजट बनाने के लिए सम्बन्धित सभी विभागों को कहा जाता है। उस सर्कुलर का भी मैं उल्लेख करूँगा आपका यह 30 सितम्बर, 2022 का सर्कुलर है जिसको मा0 वित्त मंत्री जी ने जारी किया कि आप कैसे बजट बनाएंगे। इसका बजट बनाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा इसके बाद और इसी के साथ जब हमारा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट बना दिया जाता है, तो बजट खर्च करने का भी एक सर्कुलर जारी होता है और वह भी वित्त मंत्रालय ही जारी करता है, वह सर्कुलर 07 जून, 2022 का है उसमें जिम्मेदारी ठहरायी गई है। मैं चाहूँगा कि वित्त मंत्री जी भी इसका जरूर संज्ञान लेंगे, यह उनके अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया है, उसमें जिम्मेदारी फिक्स करने तक की बात लिखी गई है। सम्बन्धित विभाग को जो बजट दिया जा रहा है, यदि वह अपने दिये गये बजट के अनुरूप खर्चा नहीं कर पाते हैं।

समय-समय पर इसमें विभागाध्यक्ष की और ए0सी0एस0 की रिस्पॉन्सबिलिटी फिक्स की गई है कि आप इसकी मॉनीटरिंग करेंगे और इसकी मॉनीटरिंग करके बजट खर्च का पूरा हिसाब-किताब रखेंगे लेकिन बिल्कुल नहीं किया गया। उसके कारण क्या हुआ जैसे नेता प्रतिपक्ष जी अभी गिना रहे थे, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने इसे कोड किया कि पी0डब्ल्यू0डी0 जैसे महत्वपूर्ण विभाग में भी सरकार इतनी उदासीन है। अधिष्ठाता महोदय, यही वजह है कि हम पी0डब्ल्यू0डी0 में 29.14 परसेन्ट खर्च कर पाये, सब मिलाकर उसकी बहुत सारी मदें हैं, सब मदों में मैं वक्त नहीं जाया करना चाहता हूँ लेकिन आप इस बात का अन्दाजा लगाइये कि जिस विभाग का 29.14 प्रतिशत बजट ही 20 फरवरी तक खर्च हुआ हो। यह मैं जो बता रहा हूँ यह अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। यह पब्लिक डोमेन में मौजूद है। कोषवानी को हमारे सभी सदस्य जानते हैं, कोषवानी ट्रेजरी की एक साइट है। ऐसा न हो कि कल सरकार खड़ी होकर कहे कि आपने गुमराह किया है। यह मैं जो भी बता रहा हूँ ऑन रिकार्ड बता रहा हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, नगर विकास मंत्री जी एक तो पता नहीं क्या सोच करके उन्हें दो महत्वपूर्ण विभाग एक मा0 मंत्री जी को वह भी जो नये हैं और पहली बार सदस्य निर्वाचित हुये हैं, दिये गये हैं। आप कहेंगे कि आप यह आरोप क्यों लगा रहे हैं, उनके पास 10 विभाग भी हो सकते हैं। मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि हम इधर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी है। आज नगर विकास विभाग में केवल 6.84 प्रतिशत बजट खर्चा हुआ है। इसलिए चूँकि यह अपने आपमें एक बहुत बड़ा विभाग है, बहुत से इसके काम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं लेकिन उसके लिए हमें रोज मॉनीटरिंग करनी पड़ेगी, घण्टों-घण्टों बैठक लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी बहुत सारी इकाइयाँ हैं, लेकिन उसमें भी यही हाल है। हमारे बड़े भाई हैं जो संसदीय कार्य मंत्री जी, हालांकि अभी इन्होंने जिन 301 योजनाओं का जिक्र किया, मुझे लगता है कि यदि वह जारी कर देंगे तो काफी खर्चा बढ़ जाएगा, जो अभी समिति ने अप्रूव्ड किया है। मैंने पता किया है कि अभी वह जारी नहीं किया गया है। हालांकि आज के दिन या 20 तारीख में 21.13 परसेन्ट बजट ही जारी हुआ है, जो प्रमुख विभाग हैं, जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री जी भी काफी प्रयास करते हैं। हम तो चाहते हैं कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि मैक्सिमम बजट काटकर स्वास्थ्य में खर्चा किया जाए तो भी कम होगा लेकिन जो

बजट हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करने के लिए दे रहे हैं, वह पूरा बजट भी यदि खर्च नहीं कर पायें तो उदासीनता कहीं-न-कहीं साफ झलकती है। बड़े भाई हमारे पीछे बैठे हैं, उसमें उनकी भी सहभागिता है, वह भी इसके राज्य मंत्री हैं। सरकार ने उसमें 24.5 प्रतिशत खर्च किया है। पंचायती राज में भी 24.84 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग में चूँकि हमें बिजली खरीदनी पड़ रही है तो बजट के सापेक्ष हमने 42.65 प्रतिशत खर्च किये हैं। चिकित्सा शिक्षा में 29.76 प्रतिशत और परिवहन में 31.98 प्रतिशत खर्च हुआ, यह छोटा उदाहरण दिया जो प्रमुख विभाग हैं, इसलिए नहीं दिया है कि मैं आलोचना कर रहा है। मैं यह कह रहा हूँ यदि हमारे मंत्रि-मण्डल समूह की जिम्मेदारी है तो सम्बन्धित मंत्री जी के अधीनस्थ जो उनके विभागाध्यक्ष हैं जो अपर मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, जो उनकी पूरी सचिवालय की टीम है उन सब लोगों की भी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और वित्त विभाग के द्वारा पहले ही सर्कुलर जारी किया गया है कि बजट खर्च करने के लिए आपको समय-समय पर मॉनीटरिंग करनी पड़ेगी, यदि नहीं करते हैं, तो यह रिसपॉन्सबिलिटी आपकी होगी।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मान लीजिए प्रेस में कहने के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि हम कहें कि हमारा पहला बजट इतना था, हमारा दूसरा बजट इतना आया । अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट का आकार बनाया है, मैं ज्यादा समय न लेते हुए उसमें केवल दो-तीन चीजों पर ही आपका फोकस कर रहा हूँ। जी0एस0टी0 में जो राज्य के स्वयं कर हैं, उनमें जो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्त मंत्री जी ने एचीव करने की उम्मीद की थी, उसमें हमने माइनस 16 परसेण्ट कम एचीव किया है। आज जो हम बजट का आकार बना रहे हैं, उसमें दो बातें आएंगी कि या तो उस विभाग में जो परसेण्टेज आ रहा है, उसकी जब मॉनीटरिंग होगी, तो हो सकता है वह विभाग यह कहें कि हमको वित्त विभाग से पैसा नहीं मिल रहा है। मुझे इस रिपोर्ट को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार हम जी0एस0टी0 में जो राज्य के स्वयं कर हैं, उसको एचीव करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हम 42 परसेण्ट एचीव कर लेंगे, जबकि पिछला जो टारगेट था, उसमें हम माइनस 16 थे। इसी तरह से राज्य के स्वयं कर अधिष्ठाता महोदय, आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि इसमें एचीव करने का जो हमारा टारगेट था, उसमें हमने माइनस 47 परसेण्ट कम एचीव किया है। आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 94 परसेण्ट इसमें भी चूंकि अभी 47 परसेण्ट तो कम किया है, लेकिन इसके बाद भी हम 94 परसेण्ट और अधिक एचीव कर लेंगे। अधिष्ठाता महोदय, बजट का आकार तो बढ़ता जायेगा, लेकिन केवल यह कह देने से कि हम इससे ज्यादा 94 परसेण्ट एचीव कर लेंगे तो हमारी प्राप्तियाँ यह हो जाएंगी तो अधिष्ठाता महोदय यह गलत होगा। इसी तरह से वेतन पेन्शन में भी जो हमें प्राप्तियाँ थीं, उसमें 15 परसेण्ट कम हमारी प्राप्तियाँ हुईं और 27 परसेण्ट का हमने अगला टारगेट रखा है। अधिष्ठाता महोदय, दो-तीन बातें और बताना चाहूंगा जैसे जी0एस0टी0 है, उसमें हमारा जो पिछला टारगेट था, हम उसको एचीव नहीं कर पाए हैं, जो हमें भारत सरकार से मिल रही थी,

माइनस 13 परसेण्ट और इस साल उम्मीद की गयी है कि 41 परसेण्ट हमको प्राप्तियाँ होंगी। इसी तरह से एक्साइज में हम 16 परसेण्ट कम एचीव कर पाए हैं और इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि 40 परसेण्ट अधिक हम एचीव करेंगे। इसी तरह से बिजली टैक्स पर जो ड्यूटी है, इसमें हमने 57 परसेण्ट कम एचीव किया है और इस बार उम्मीद की है कि 173 परसेण्ट अधिक हम एचीव करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। क्या करेंगे छापा मरवायेंगे, गरीबों को जेल भिजवायेंगे, विजिलेन्स वालों के दौरे की दुकान चलेगी। विजिलेन्स वाले तो यह सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो कोई रोजगार ही नहीं है। हम सीधा आरोप लगा रहे हैं, वह इसलिए कि गांव में रहने पर यह सब देखने को मिलता है।

अधिष्ठाता महोदय, स्टैम्प ड्यूटी में हमने 18 परसेण्ट कम एचीव किया है, लेकिन इस बार 42 परसेण्ट की उम्मीद कर रहे हैं। सेल्स टैक्स से हमने 13 परसेण्ट कम एचीव किया है और इस साल हम 42 परसेण्ट का टारगेट लेकर चल रहे हैं। इसी तरह से चूंकि एक और जो विशेष बात है कि सरकार की जो हम अन्य प्रदेशों से तुलना करते हैं कि अन्य प्रदेशों का क्या मानक है, क्योंकि देश स्तर पर एक सर्वे किया जाता है। उस सर्वे के आधार पर यह देखा जाता है कि कौन-सी स्टेट का किस मद में उसका फोकस है। अधिष्ठाता महोदय, यदि देखा जाये तो पुलिस में चूंकि यह सबसे आवश्यक है, उसमें हमने 2.9 परसेण्ट अपना प्रोविजन किया है, लेकिन अगर एवरेज देखा जाये तो अन्य स्टेट चूंकि हम रोज-रोज कहते हैं कि हमें पुलिस को अत्याधुनिक बनाना है। हम कहते हैं कि हमको पुलिस को ऐसा सुसज्जित करना है कि इससे कोई माफिया या क्रिमिनल टकरा न पाये, लेकिन हम इस पर खर्च कितना कर रहे हैं ? जहां दूसरे स्टेट 5.8 परसेण्ट अपने बजट का खर्च करते हैं, वहीं हम खर्च कर रहे हैं 2.9 परसेण्ट। इसी तरह से केवल एक ऊर्जा का क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अन्य स्टेट्स से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, चूंकि यह भी बताना जरूरी है, नहीं तो हमारे वित्त मंत्री जी कहेंगे कि आपने इसको नहीं बताया। ऊर्जा पर हम 6.7 परसेण्ट खर्च कर रहे हैं, जबकि अन्य स्टेट हमारे 4.8 परसेण्ट खर्च कर रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, इसी तरह से बहुत सारे विषय हैं जिसमें समय लगेगा। ग्रामीण विकास में हम 5 परसेंट खर्च कर रहे हैं और अन्य राज्यों में हमारा 5.7 परसेंट है। हमारे साथी कह रहे हैं कि घड़ी बढ़ रही है तो मैं केवल संकल्प-पत्र का ही जिक्र करूंगा और उसी के आधार पर अपनी बात रखूंगा। आई0टी0 और इलेक्ट्रानिक विभाग है, सरकार के संकल्प-पत्र में था कि हम 02 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्ट फोन देंगे जिसके लिए वर्ष 2022-23 में उन्होंने बजट में 1500 करोड़ रुपये का प्राविधान भी किया था। पूरा साल बीत गया, लेकिन 1500 करोड़ रुपये के लैपटॉप और टैबलेट खरीदने का टेण्डर और निविदा अभी भी फाइनल नहीं हो पायी है। आज की डेट तक हम 20 लाख 50 हजार युवाओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन दे पाये हैं। इस बार बजट में रु0 3600 करोड़ का प्रोविजन है। 1500 करोड़ तो हम पिछली बार रखे थे, लेकिन उस 1500 करोड़ रुपये का हम युटिलाईजेशन नहीं कर पाये

अगर आप युटिलाईजेशन करते तो आज विपक्ष को कहने का मौका नहीं मिलता है यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कल हमारे उत्तर प्रदेश की जनता यह भी कहेगी कि इनका संकल्प-पत्र आपको भी पढ़ना चाहिए। इनके संकल्प-पत्र के आधार पर हम लोग इन्हें वोट दिये थे। आप लोगों को भी समय-समय पर इनको याद दिलाना चाहिए। जो हमारी जिम्मेदारी है उसके तहत हम आपको याद दिला रहे हैं।

इसी तरह से खाद्य एवं रसद विभाग के बारे में अभी आदरणीय मोना जी ने उल्लेख किया। जब वह यहां पर रहती हैं तो घर से खाना बनकर टिफिन में आता है, हम लोगों को भी खिलाती हैं, लेकिन एक गृहणी के नाते हो सकता है कि शाम वाला खाना वह बनाती होंगी। गृहणी का अच्छा अनुभव है इसलिए इन्होंने जो कहा उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। वर्ष 2022-23 के संकल्प-पत्र में घोषणा थी कि हम दीवाली और होली पर एक-एक सिलेण्डर मुफ्त देंगे। उस समय मैं कह सकता हूँ कि काउण्टिंग के तुरन्त बाद होली पड़ी उस समय सरकार का बजट नहीं आया था। सरकार अपना बजट मई में लेकर आयी थी, लेकिन उसके बाद दिवाली पड़ी थी, लेकिन दिवाली पर नहीं दिया गया और इसके लिए बजट की भी व्यवस्था थी। अधिष्ठाता महोदय, 6571 करोड़ 13 लाख रुपये का इसके लिए बजट में प्रोविजन भी किया गया था। हमारे बजट का जो आकार था कि हम इतना भारी बजट लेकर आये हैं उसमें साढ़े 6 हजार करोड़ यह भी जुड़ा था, लेकिन हम दे नहीं पाये। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि अभी होली आने वाली है। कम-से-कम उस बजट से होली वाला सिलेण्डर तो दे दीजिये। इस बार आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 में वह बजट घटा दिया, इस बार आप 3047 करोड़ रुपये रखे हैं। अधिष्ठाता महोदय, चीनी मिल के लिए भी चर्चा हुई, हमारे विद्वान मंत्री जी के लिए मैं बताऊँ, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में वर्ष 2007-2012 वाले कार्यकाल में कृषि मंत्री रहते हुए खाद्यान्न उत्पादन में हमारे कृषि विभाग को भारत सरकार की तरफ से पूरे भारतवर्ष में 02 बार लगातार प्रथम पुरुस्कार मिला था। हमारे कृषि मंत्री जी को दो बार लगातार खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम पुरुस्कार मिला था। एक बार नहीं, दो बार हमारे कृषि मंत्री जी को खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम पुरुस्कार मिला था या तो अब वह उस स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

उमाशंकर जी, कृपया समाप्त करें, क्योंकि और सदस्यों को भी बोलना है। नेता बसपा, आप ही ने व्यवस्था तय की थी।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, कभी हम भी आयेंगे तो आपको मौका मिल जायेगा।

(सदन में हँसी)

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, चीनी मिलों के विस्तारीकरण के लिए पैसा रखा था। मान्यवर, बात इसलिए आनी चाहिए कि जब सरकार कार्यवाही निकाल कर पढ़ेगी तो हो सकता है कि उस विभाग की मॉनीटरिंग करने में उसे मदद मिले और हो सकता है कि उस विभाग के

अधिकारी गलत रिपोर्ट देते होंगे। मोदी नगर की स्थापना के लिए 20 करोड़ रखा गया था, छाता के लिए 50 करोड़ रखा गया था। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, इसमें एक रुपया खर्च नहीं हुआ है। मान्यवर, विशेष तौर पर एक और चीज पर आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा कि हमारे आदरणीय निषाद जी अभी नहीं हैं, पिछली बार इनका 5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। अब इनको भी चाहिए कि कम से कम एक विभाग की जिम्मेदारी मिली है, तो समय से उस बोर्ड का गठन करा दें और इस पैसे का यूटिलाइज कर दें। न उसकी गाइडलाइन बनी और न बोर्ड का गठन हुआ । उसमें जीरो खर्चा है और आज उस बजट को घटा करके 2 करोड़ कर दिया गया है, 3 करोड़ कम दिया गया है। यह सीधा जनता से जुड़ा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

जनता की बात जल्दी कह लीजिए।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, भामाशाह भाव स्थिरता कोष का गठन हुआ था और यह संकल्प-पत्र के प्रथम हेडलाइन में था कि हम आलू, टमाटर, प्याज जैसी फसलों का जो मूल्य निर्धारण करने के लिए अपने बजट में व्यवस्था रखेंगे कि अगर इसका बाजार भाव अधिक होगा तो हम अपने फण्ड से दे करके इसको कन्ट्रोल करेंगे। अधिष्ठाता महोदय, दुर्भाग्य है कि पिछले बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी थी। लेकिन आज तक इसका गठन भी नहीं हो पाया है। इसलिए इस गम्भीरता मुझे लगता है कि देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की एक और सबसे बड़ी घोषणा थी हमारे धर्मार्थ विभाग के लोग होंगे, पुरोहित कल्याण बोर्ड, इसमें हुआ था कि बुजुर्गों, संतों, पुजारियों और पुरोहितों को सम्मान और पुरुस्कार देने के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जायेगा, लेकिन आज तक उसका गठन नहीं हुआ है। कुछ बातें और कहकर मैं समाप्त करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आपके हाथ में कितने कागज रह गये हैं ?

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मैं कानून की बात कर लेता हूँ। रोज हमारे वित्त मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी एन0सी0आर0बी0 की चर्चा करते हैं, इसलिए यह जानना जरूरी है, जैसे ही इधर से सवाल आयेगा, एन0सी0आर0बी0 वाली बुक उठ जायेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा, आज उनको मैं वित्त मंत्री नहीं कह रहा हूँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहा हूँ कि जब 2007 से 2012 तक हमारी सरकार थी, वह 2009 से 2011 तक की एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट निकाल लेंगे। अधिष्ठाता महोदय, उस समय क्राइम में उत्तर प्रदेश 34वें नम्बर पर था। मैं यह बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, रिकार्ड के साथ कह रहा हूँ। हमसे कम क्राइम केवल एक स्टेट नागालैण्ड में था । हम क्राइम में 34वें नम्बर में थे,

तो अन्दाजा लगाइये कि एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट थी और क्या लॉ एण्ड आर्डर होता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियुक्तियों की बात रह गई ।

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपया समाप्त करिये।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर नियुक्तियों की बात इधर और उधर दोनों ओर से हो रही हैं।

श्री अधिष्ठाता-

वह अन्य लोगों ने कह लिया है।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारा समय आपमें जोड़ दिया जाये, पूरा 15 मिनट जोड़ दिया जाये ।

श्री उमाशंकर सिंह-

नहीं-नहीं, बड़े भाई हैं । मान्यवर, बस 1 मिनट नियुक्तियों की बात कहकर अपनी बात समाप्त करेंगे। आज सभी लोग पिछड़े के, एस0सी0 के हिमायती बन रहे हैं। मान्यवर, बहुत दूर नहीं, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो मुहिम चला करके जितने विभागों में बैकलॉग था, उन सारे बैकलॉग को भरा गया है, यह बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में हुआ, बाकी किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ। जो नये साथी होंगे, उनको अनुभव नहीं होगा, जो जानते नहीं होंगे, जो अध्ययन नहीं करते होंगे। मैं जो भी बात बोलता हूँ, जो भी बात करता हूँ, मैं चौराहों और नुक्कड़ सभाओं की बात नहीं करता हूँ। मैं टू द प्वाइंट बात करता हूँ, उसका रिकार्ड दूँगा। मैं नये साथियों से भी कहता हूँ कि हमें यह नहीं सीखना चाहिए कि जो हम चट्टी-चौराहों, नुक्कड़ सभाओं में बोलते हैं, वह नहीं बोलना चाहिए।

मान्यवर, यहाँ पर सीखना है तो संसदीय भाषा में जो प्वाइंट होगा आदरणीय माता प्रसाद पाण्डेय जी हैं वह बहुत सीखे हैं । मान्यवर, जनपद बलिया में माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। वर्ष 2022 से मेडिकल कॉलेज देने की बात आ रही है लेकिन बलिया को अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है। लिख कर आता है कि जमीन खोजी जा रही है। फिर आया सरकार से कि हम इसको पी0पी0पी0 मॉडल पर करेंगे। मैंने सरकार को ऑफर भी दिया था कि रसड़ा के शहर में हमारी खुद की जमीन 30 बीघे है सरकार फ्री में ले ले और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोल दे। हम जमीन फ्री में दे रहे हैं जिला के लिए कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोलें। आपको सारे पॉवर हैं, कैबिनेट से पॉवर है, उसके मानको को शिथिल करने का राइट है अगर 10 किलोमीटर के दायरे में जमीन नहीं मिल रही है तो 12 किलोमीटर जा करके कैबिनेट में उसको शिथिल कर सकते हैं और

मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे मंत्री जी प्रसन्न हैं अभी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा तुरन्त करेंगे।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, एक तो मुझे बड़ा हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है। इस बीच मैंने देखा आज हमारे जो माननीय विपक्षी दल के नेतागण हैं यह सब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प-पत्र पढ़ने लगे हैं और इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के संकल्प-पत्र की चिंता होने लगी है। इससे मुझे बड़ी खुशी और बड़ा गर्व हो रहा है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मुझे पूछना है कि आखिर आपको जनता ने चुना कैसे आपने जनता को कहां गुमराह किया वह जनता को बताना पड़ेगा। अगर गुमराह कर ही दिया है तो जनता के साथ धोखा मत करिये।

मान्यवर, संकल्प-पत्र पढ़ करके यह लोग भी इधर आ जायें। हम लोग समाहित कर लेंगे।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, आइना दिखाना तो हमारा काम है हम तो दिखायेंगे आइना कि आपने कितनी घोषणायें की थीं।

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री (डा0 सोमेन्द्र सिंह तोमर)-

मान्यवर, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक बजट पर बोलने का अवसर दिया है। मैं सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यशस्वी वित्त मंत्री अभिभावक आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी का धन्यवाद इन शब्दों के साथ करना चाहूंगा। जो होता है वह होने दो यह पौरुष हीन कथन है, जो हम चाहेंगे वह होगा इन शब्दों में ही जीवन है।

श्री अधिष्ठाता-

सोमेन्द जी, आप अपनी बात को 10 मिनट के अन्दर रखेंगे।

डा0 सोमेन्द्र सिंह तोमर-

मान्यवर, ठीक है। पण्डित दीनदयाल उपाध्याय, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की सोच को साकार करने वाला यह ऐतिहासिक बजट है। जो डबल इंजन की सरकार लेकर आई है। मैं सर्वस्पर्शी, सर्वहितैशी, सर्वउपयोगी विकासोन्मुख जो यह बजट पेश हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को देश का नम्बर एक प्रदेश बनाने में सहायक होगा। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को पूर्ववर्ती सरकारों ने एक बीमारू राज्य बना दिया था। एक सोच थी कि इस उत्तर प्रदेश का भला नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिनके निर्देशन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी

मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था और देश के 44 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। उत्तर प्रदेश की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ही अयोध्या और मथुरा में जन्म लिया ।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज अयोध्या, मथुरा, काशी, गढ़मुक्तेश्वर, मेरठ के ऐतिहासिक नौचण्डी मेले को सरकार प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। मेरठ के अन्दर भगवान विश्वामित्र की तपोस्थली है जहाँ भगवान विश्वामित्र ने तपस्या की थी और राक्षसों के संहार के लिए भगवान श्रीराम और लक्ष्मण को लेकर आए थे। मा0 मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से लगभग तीन करोड़ रुपये से आज हम उसका जीर्णोद्धार और सौन्दर्यीकरण करा रहे हैं। माँ मंशा देवी शक्तिपीठ का जीर्णोद्धार मा0 मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने कराया है। मैं पूर्ववर्ती सरकारों में, जहाँ पश्चिम की उपेक्षा की जाती थी और हम देखते थे कि दिल्ली के नजदीक होने के बावजूद भी दिल्ली चाहे हरियाणा की तरफ बढ़ी, चाहे राजस्थान की तरफ बढ़ी, लेकिन मेरठ दिल्ली से नजदीक होने के बावजूद भी उधर किसी का ध्यान नहीं गया।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमें याद है कि वर्ष 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने के लिए तत्कालीन सरकार से एन0ओ0सी0 माँगी गयी, लेकिन उस समय की सरकार ने एन0ओ0सी0 नहीं दी। हम लोगों को मेरठ से दिल्ली तक का सफर लगभग 4-5 घण्टे में तय करना पड़ता था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की देव तुल्य जनता ने जो सरकार बनायी, सरकार बनने के बाद सबसे पहले एन0ओ0सी0 मिली और उसी का परिणाम है कि एन0 एच0-24, जो गुर्जर सम्राट राजा मिहिरभोज को कनेक्ट करता है। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्या जी उस समय हमारे लोक निर्माण मंत्री थे। मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 गडकरी जी के आशीर्वाद से मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे बना और 45 मिनट में आज हम लोग मेरठ से दिल्ली तक का सफर तय कर रहे हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों में जब हम लोग मेरठ से दिल्ली जाते थे, तो जाम की समस्या बहुत थी। इसके अलावा हम लोग देखते थे कि वर्ग विशेष को खुश करने के लिए एक लाइन शुक्रवार के दिन बन्द करा दी जाती थी, लेकिन आज मुझे बताते हुए यह खुशी है कि आज चारों तरफ नेशनल हाइ वेज का जाल बन रहा है। चाहे मेरठ से सोनीपत मार्ग हो, आज हम लोग मेरठ से नजीबाबाद तक क्रॉसिंग फ्री हाई-वे बना रहे हैं। इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी संकल्प-पत्र की बात हो रही थी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संकल्प-पत्र में बोलती है, उसे पूरा करती है। हम उस सरकार के प्रतिनिधि हैं। हम जो शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी हमारी

सरकार करती है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उप मुख्यमंत्री मा0 बृजेश पाठक जी का, जिन्होंने एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के तहत लगभग 45 जनपदों को मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित किया और 14 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था की और 16 जनपदों में पी0पी0पी0 पर स्थापना की जा रही है। हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने वाले लोग हैं। 'आयुष्मान कार्ड' की हम लोग बात करें, तो हम देखते थे कि जब कोई गरीब बीमार हो जाता था, कोई एक्सीडेंट हो जाता था और जब वह प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता था, तो वह सोचता था कि मेरी सारी जमीन बिक जायेगी, मेरी सारी सम्पत्ति चली जायेगी। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मा0 मोदी जी का। उन्होंने 'आयुष्मान कार्ड' के माध्यम से पाँच लाख तक का इलाज निःशुल्क कराने का काम किया और जो शेष रह गये, उन्हें मा0 मुख्य मंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने 'मुख्य मंत्री आरोग्य योजना' के माध्यम से लाभान्वित करने का काम किया। अगर हम किसानों के ऋण की बात करें तो लगभग 36 हजार करोड़ का ऋण माफ करने का काम मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यदि मैं चीनी मिलों की बात करूँ, तो पूर्ववर्ती सरकारों में हम देखते थे कि उन चीनी मिलों को बेचने और नीलाम करने का काम किया जाता था । यदि मैं मोइउद्दीनपुर चीनी मिल की बात करूँ, तो 25 सौ से 35 सौ टी0डी0सी0 और 35 सौ से 5 हजार बढ़ाने की घोषणा हमारी सरकार ने की है।

मैं उस समय पंचायतराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह जी, जिनके आशीर्वाद से हम देखते हैं कि गांव के अन्दर चाहे हम अन्त्येष्टि स्थल की बात करें, खेल के मैदान की बात करें और पंचायत घर बनाने का काम जो हमारी सरकार ने किया, यानी सचिवालय के रूप में आज वह व्यवस्था कि हमारे किसी भी गांव के नागरिक को शहर में न जाना पड़े सारे प्रमाण-पत्र हम वहां बनवा सकते है। आज सरकार बनने के बाद 2017 में क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकलते हैं, मैंने उस समय मा0 मुख्य मंत्री जी से खेल विश्वविद्यालय की मांग की और धन्यवाद करना चाहता हूँ मा0 मुख्य मंत्री जी का कि उन्होंने मेरठ के अन्दर खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और इस बार के बजट में 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

हम लोग जानते हैं कि मेरठ क्रांति की भूमि है 1857 की क्रांति करने वाले उस समय के कोतवाल धनसिंह गुर्जर ने उस क्रांति का नेतृत्व किया और बाबा श्यामल भमौरी गांव की शहादत को पहचान देने का काम भी किया, तो वह भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया तथा मा0 मुख्य मंत्री जी ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का नाम अपने गुर्जर धनसिंह कोतवाल जी के नाम पर रखा और मैं सुन रहा था हमारे कुछ साथी बोल रहे थे कोतवाल धनसिंह जी के बारे में, लेकिन जब वह सत्ता में होते हैं तब उन्हें कोतवाल धनसिंह गुर्जर याद नहीं आते हैं। वर्ष 2012 से 2017 के बीच उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कोतवाल धनसिंह गुर्जर का नाम बढ़ना चाहिए।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मा0 योगी जी का उन्होंने जिस थाने के वह कोतवाल थे वहां पर उनकी मूर्ति लगाकर उनकी उस शहादत को बल देने का काम किया है। इसके अलावा शहीद स्मारक पर कोतवाल धनसिंह गुर्जर की मूर्ति लगे उसके लिए निर्देश भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने दिये हैं। मेरठ में या तो स्लॉटर हाउस हुआ करते थे या वाहनों का मेला होता था, वाहन कहीं भी चोरी हो, पूछा यहीं जाता था कि कटान मेरठ के अन्दर ही होगा। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूज्य योगी जी की कानून व्यवस्था के कारण न तो वहां अब वाहनों का मेला है और न ही पशुओं का मेला है और कानून व्यवस्था के रूप में घटना कहीं भी होती थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया मेरठ से शुरू होती थी, लेकिन आज देश के अन्दर योगी मोदी मॉडल ही जो प्रशंसा हो रही है, योगी मॉडल के माध्यम से आज यदि कोई सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचायेगा तो वह उसकी सम्पत्ति से वसूला जायेगा । हमारे कुछ वरिष्ठ साथी ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे, संकल्प-पत्र में हमने घोषणा की कि हम किसानों को निजी नलकूपों के लिए फ्री बिजली देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मा0 मुख्य मंत्री जी का कि उनके आशीर्वाद से वर्ष 2022 से पहले हमने बिजली बिल 50 प्रतिशत किया और इस बार वर्ष 2023-24 के बजट में हमने बिल 100 प्रतिशत फ्री करने का काम किया है। जहां पर हमारे विपक्ष के साथियों ने एक भ्रान्ति फैलायी कि मीटर के कारण बिल बढ़कर आता है, मैं आग्रह करना चाहता हूँ मा0 अधिष्ठाता महोदय, कहीं भी मीटर से बिजली का बिल किसी ट्यूबवेल का नहीं आया होगा। लेकिन वह भ्रान्तियां फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी सरकार का कि उन्होंने किसानों को इस तरह से बिजली देकर एक बहुत बड़ा काम किसानों के लिए किया है। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करूं, मैं जी 20 की बात करूं, आज सरकार के प्रति क्रेडिविलिटी यही है कि निवेश जिस तरह से हो रहा है यह इस बात का प्रमाण है कि आज पूरे देश के अन्दर और मैं बात करूं अगर विश्व में भी तो सबसे ज्यादा निवेश के प्रति रुचि कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश के लिए है।

''हवा में रहेगी मेरे खयाल की बिजली, ये मुस्ते खाक है फानि रहे ना रहे''।

आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नितिन अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत की गयी 2023-2024 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 05 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य देश के सामने रखा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 01 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य प्रदेश के सामने रखा, निश्चित तौर पर यह जो 2023-2024 का बजट आया है, यह उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का भी लक्ष्य तभी पूरा होगा जब उत्तर प्रदेश अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। 06 लाख 90 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रदेश की जनता के सामने रखा। मैं

कह सकता हूँ कि यह बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव डालने वाला है। इस महीने हम सब जानते हैं कि 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' भी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई। यह हम सबको पता है कि जिस तरीके से हमारे ही देश के नहीं बल्कि विदेशों से आये हुए उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में अपने उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर की और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिसकी छवि 2017 से पहले अपराधिक छवि एक बदनाम प्रदेश की छवि हुआ करती थी, आज उस छवि में पूरी तरीके से बदलाव हुआ और 35 लाख करोड़ ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को मिले। मैं तो कहना चाहता हूँ विपक्ष से कि आप विकास की बात करते हैं, आप सरकार पर आरोप लगाते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं।

आप अपना समय याद करिये, जब आपकी सरकार प्रदेश में थी और आपकी सरकार के मुखिया उत्तर प्रदेश के एक जनपद में जाने से डरते थे, उन्हें लगता था कि अगर मैं उस जनपद में चला जाऊँगा तो शायद मैं उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री नहीं रहूँगा। आज हमारी सरकार है, जिस सरकार में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे बुन्देलखंड हो, चाहे पूर्वान्चल हो, चाहे मध्यान्चल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, पूरे प्रदेश में उद्यमियों ने उद्योग लगाने में अपनी इच्छा जाहिर की। आज यह बदलाव जो उत्तर प्रदेश में आया है इसका पूरा का पूरा श्रेय अगर मैं दूँगा तो आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दूँगा। (मेजों की थपथपाहट)

मैं अगर तुलना करूँ तो 2016-17 में 03 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का बजट उत्तर प्रदेश का हुआ करता था, वह आज 06 लाख 90 हजार करोड़ का बजट हो गया, तकरीबन दो गुना बढ़ गया। पिछले 07 वर्षों में प्रदेश का बजट दोगुने से भी ज्यादा हुआ है। अगर मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2016-17 में रु0 50,942/-हुआ करती थी, आज वही प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 01 लाख रुपये से ज्यादा हो चुकी है, करीब-करीब दोगुनी प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। 2016-17 में जो जी0एस0टी0/सेल्स टैक्स उत्तर प्रदेश में 51 हजार करोड़ रुपये का होता था वह आज 01 लाख 25 हजार करोड़ हो गया है, दोगुने से ज्यादा वृद्धि हो चुकी है।

मान्यवर, रोजगार की बात होती है। मैं लगातार देखता हूँ, विपक्ष कहता है कि प्रदेश सरकार की रोजगार देने में क्या उपलब्धि है ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2017 में जबसे हमारी सरकार बनी। 2017 से 2022 (पाँच वर्ष) के कार्यकाल में हमारी सरकार ने जो सीधी भर्ती होती है उसमें करीब 05 लाख से ज्यादा नौजवानों को सीधी सरकारी भर्ती देने का काम किया और लगातार यह प्रक्रिया अभी तक चल रही है। 2022 में हमारी सरकार दोबारा लौट करके आयी । लगातार हमारी सरकार यह प्रयास कर रही है कि कैसे हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, रोजगार देकर उनको उनके पैरों पर खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जो निवेश के प्रस्ताव हमें मिलें हैं, वे निवेश होने के

उपरान्त, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के करीब 01 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देने में सफल होंगे, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

(मेजों की थपथपाहट)

प्रदेश की अर्थव्यवस्था का दायरा बहुत तेजी से बढ़ा है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं कोई चीज कहना चाहता हूँ कि जो हमारा राजस्व उत्तर प्रदेश में बढ़ा। मान्यवर, आज चाहे कोई भी विभाग हो जो राजस्व देने वाले विभाग होते हैं चाहे वह जी0एस0टी0 के माध्यम से आ रहा हो, चाहे वह आबकारी के माध्यम से आ रहा हो, चाहे वह स्टाम्प शुल्क के माध्यम से आ रहा हो, चाहे वह ट्रान्सपोर्ट के माध्यम से आ रहा हो, चाहे वह खनन के माध्यम से आ रहा हो, आज हर क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है अगर मैं कुछ आँकड़े आपके सामने रखूं तो अगर मैं जी0एस0टी0 की वैट और स्टेट जी0एस0टी0 की बात करूं तो 2022-23 में रु0 67,488 करोड़ (सड़सठ हजार चार सौ अट्ठासी करोड़ रु0) की जी0एस0टी0 हम लोगों को मिली थी और अभी जो हमारा बजट आया है उस बजट में हमने उसका अनुमानित 95,203 करोड़ (पंचानबे हजार दो सौ तीन करोड़ रु0) का हमने एस्टीमेट किया है कि इस साल हमें इतना रेवेन्यू जी0एस0टी0 के माध्यम से आएगा जो करीब 41 प्रतिशत ज्यादा है अगर मैं आबकारी की बात करूं तो रु0 41,349 करोड़ (इक्तालिस हजार तीन सौ उन्चास करोड़ रु0) के सापेक्ष हमने इस बार 58,000 करोड़ (अट्ठावन हजार करोड़ रु0) का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष से करीब 40 प्रतिशत ज्यादा है, इसी के साथ-साथ सेल्स टैक्स की बात करूं तो रु0 31,542 करोड़ (इकतीस हजार पांच सौ बयालिस करोड़ रु0) के सापेक्ष रु0 31,788 करोड़ (इकतीस हजार सात सौ अट्ठासी करोड़ रु0) यह भी 32 प्रतिशत अधिक है। स्टैम्प ड्यूटी जो रु0 24,267 करोड़ (चौबीस हजार दो सौ सड़सठ करोड़ रु0) थी वह बढ़कर रु0 34,560 करोड़ (चौतीस हजार पांच सौ साठ करोड़ रु0) का लक्ष्य हमने बनाया यह भी करीब 42 प्रतिशत अधिक है। ऐसे ही लगातार यह बढ़ता चला जा रहा है और राजस्व का जो हमारा कलेक्शन है और जो जी0डी0पी0 है अब मैं जी0डी0पी0 की भी बात आज सदन के सामने रखना चाहूंगा कि 2016-17 में हमारे प्रदेश की जो जी0डी0पी0 थी वह बारह लाख अट्ठासी हजार करोड़ थी, आज मैं बताना चाहता हूँ कि 2023-24 में हमारे प्रदेश की जो जी0डी0पी0 है वह चौबीस लाख सैंतीस करोड़ रु0 हो चुकी है। जो दुगने से ज्यादा आज हमारी जी0डी0पी0 बढ़ गई है।

अगर मैं विभिन्न विभागों की तरफ जाऊँ मैं नेता प्रतिपक्ष की बातों को सुनता हूँ वह हर भाषण में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे की बात जरूर करते हैं। वह कहते हैं कि हमने इतना बड़ा एक्सप्रेस-वे बना दिया इससे बड़ा एक्सप्रेस-वे कभी बना ही नहीं, तो तमाम तरीके की बातें सामने आती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी में जितने एक्सप्रेस-वे बने उतने एक्सप्रेस-वे आज तक कभी किसी भी सरकार में नहीं बनें। चाहे वह बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे हो, चाहे वह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हो अभी इसी बजट में दो लिंक एक्सप्रेस-वे की घोषणा हुई जिसमें झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे की बात हुई जो बुन्देलखण्ड का

एक बड़ा शहर माना जाता है और साथ ही साथ चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की बात हुई इस बजट में दोनो लिंक एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए दो सौ पैंतीस करोड़ रु0 का आवंटन आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री जी ने करने का काम किया है। वहीं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे में डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना के लिए पांच सौ पचास करोड़ रु0 की व्यवस्था करी है।

मैं अगर किसानों की बात करूँ अगर मैं केवल गन्ना किसानों की बात करूं तो पिछले पांच वर्षों में हमारी सरकार ने एक लाख छियानबे हजार करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान करने का काम किया। अगर मैं पिछली सरकार की तुलना करूं तो उस सरकार में करीब छियालिस लाख बाइस हजार गन्ना किसानों का भुगतान हुआ, जो एक रिकॉर्ड है 2012 और 2017 में जब इनकी सरकार थी पांच वर्ष की अवधि में जितना गन्ना मूल्य का उन्होंने भुगतान किया था हमने उससे छियासी हजार करोड़ से ज्यादा का गन्ना का भुगतान करने का काम किया है। किसानों को निजी नलकूपों के माध्यम से आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं मैं बधाई दूंगा उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस बजट में जो 50 प्रतिशत पहले जो सब्सिडी मिला करती थी उस सब्सिडी को पॉवर सब्सिडी को बढ़ाने का काम 100 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसमें करीब 15 सौ करोड़ रु0 का आवंटन

सरकार ने करने का काम किया है। ऐसे फ्लड कन्ट्रोल और इरीगेशन की अगर मैं बात करूं तो रु0 10,952 करोड़ (दस हजार नौ सौ बावन करोड़ रु0) एलोकेशन हमारी सरकार ने करने का काम किया है। विधवा पेंशन एक बड़ी स्कीम है सोशल वेलफेयर स्कीम है इस स्कीम में हमारी सरकार ने रु0 4,032 करोड़ (चार हजार बत्तीस करोड़ रु0) एलोकेशन किया है करीब बत्तीस लाख साठ हजार ऐसी हमारी माताओं को इस परियोजना से जोड़ने और उनको लाभ देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं बजट के चाहे वो महिलाओं के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, चाहे स्टार्टअप के माध्यम से कर रहें हों, चाहे हम रोजगार देने के माध्यम से कर रहे हों, सभी तरीके से स्वास्थ्य सेवा की अगर हम बात करें तो आज हमारी सरकार ने रु0 12,631 करोड़ (बारह हजार छह सौ इकतीस करोड़ रु0) से ज्यादा का प्राविधान स्वास्थ्य सेवाओं में देने का काम किया है।

मान्यवर, मेडिकल एजुकेशन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि मा0 प्रधानमंत्री जी ने जो एक विजन दिया था कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिये तो आज प्रदेश में 'एक जिला एक मेडिकल कॉलेज' की योजना को रफ्तार देते हुये 14 नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गयी है जिसके संचालन के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में करीब 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था करने का काम किया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसी के साथ-साथ मैं बजट की कुछ हाईलाइट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में हमारी सरकार ने 12,39,877 आवासों का लक्ष्य रखा है और इस योजना के लिये सरकार ने 09 हजार करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था करने का काम

किया है। इसी के साथ-साथ 05 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसमें लखनऊ एयरपोर्ट तथा वाराणसी एयरपोर्ट संचालित हो रहा है तथा 03 एयरपोर्ट्स बन रहे हैं इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ-साथ करीब 16 घरेलू एयरपोर्ट्स को मिलाकर उत्तर प्रदेश में करीब 21 एयरपोर्ट क्रियाशील होंगे। 'महाकुम्भ मेला 2025' का आयोजन होने वाला है, उसके लिये ढाई हजार करोड़ मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1200 करोड़, खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी के लिये 30 करोड़, ऐसे ही लगातार सभी विभागों में उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट देने का काम किया है। मैं आज यह कहना चाहता हूँ कि गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं तथा प्रदेश के हर वर्ग के लिये इस बजट को लाया गया है। यह बजट केवल गाँव, किसान का बजट नहीं, बल्कि हर क्षेत्र के और हर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिये हम इस बजट को लेकर आये हैं और निश्चित तौर पर यह बजट उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा । मैं इसके लिये आदरणीय मुख्य मंत्री जी तथा आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी, धन्यवाद। श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, बजट के आँकड़ों पर बहुत चर्चा हो चुकी है इसलिये मैं उस पर नहीं जाऊंगा। कुछ छोटी-छोटी समस्याएं हैं जिन पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि सरकार उन पर आगे कुछ कार्य करे । जहाँ तक इनके बजट का सवाल है तो आपने जो अपनी प्राप्तियाँ दिखायी है वह 06 लाख 83 हजार 292 करोड़ 74 लाख रुपये दिखायी है और कुल प्राप्तियों में जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं उसको हम कहेंगे नहीं और पूँजीगत प्राप्तियाँ अलग हैं। मान्यवर, इनका जो अनुमानित व्यय है वह 06 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये है और कुल व्यय में 05 लाख 02 हजार 354 करोड़ 01 लाख रुपये राजस्व लेखे का व्यय है और 01 लाख 87 हजार 888 करोड़ 42 लाख रुपये पूँजी लेखे का व्यय है।

मान्यवर, वह बजट अच्छा होता है जिसमें पूँजी लेखे में ज्यादा खर्च करके ऐसेट तैयार किया जाता है और उस ऐसेट से आने वाले समय में हमारी परिसम्पत्तियाँ होती हैं। राजस्व लेखे का व्यय तो व्यय होकर चला जाता है। हम देख रहे हैं कि आजकल जो बजट बनता है उसमें राजस्व लेखे पर व्यय ज्यादा है और पूँजी लेखे पर कम व्यय है जबकि पूँजी लेखे पर ज्यादा खर्च करना चाहिये, क्योंकि इससे हमारा ऐसेट तैयार होता है, आने वाले दिनों में हमारी पूँजी बढ़ती है और उससे हमारी राजस्व प्राप्तियाँ बढ़ती हैं। इसमें यह व्यवस्था नहीं हो पायी है। दूसरी बात मैं यह कहूँगा कि अभी आपने इतना बड़ा बजट बना दिया, ठीक है, लेकिन पिछली बार आपने जो बजट बनाया था उसका तो पूरा नहीं हो पाया। आप जितनी राजस्व

प्राप्तियों का अनुमान लगाते हैं लास्ट में उतनी राजस्व प्राप्तियाँ नहीं आती हैं और उसी बजट के अनुपात में आप अपनी परियोजनाओं का, अपनी योजनाओं का बजट बनाते हैं। जब वह धनराशि आती ही नहीं है तो यह परियोजनाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जिसके लिए आप बजट में सबको दिखाते है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये तरक्की करेंगे, हम वो विकास करेंगे। जब धन ही नहीं रहेगा तो फिर कहां से वह सब बनेगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो आपका पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग है जिससे आपने जो भी काम किया या कराया है इसमें बड़ी विसंगतियाँ है। बजट के बारे में बहुत चर्चा हो गयी है मैं उसको नहीं दोहराऊँगा लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बड़ी सड़कें तो आप बना देते है लेकिन गांव के अन्दर की सड़कों पर आपका ध्यान नहीं जाता है। उसके लिए भी आपको ध्यान देना चाहिए। गांव की सड़कें टूट गयी हैं उनकी रिपेयरिंग तक नहीं पा रही है। एक गांव से दूसरे गांव 4 किलो मीटर, 5 किलो मीटर, 10 किलो मीटर जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। इसलिए आपको मेरा सुझाव है कि ग्रामीण अंचल की जो छोटी-छोटी सड़कें हैं उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जो सड़कें टूट गयी हैं उसके लिए इस बजट में प्राविधान करना चाहिए। आपने बजट तो दिया है लेकिन यह बजट दूसरे कामों में चला जाता है।

अगर कहीं बजट बचता है तो पुनर्विनियोग करके यह काम आप करा दीजिए क्योंकि सड़कों के मामले में गांव की हालत बहुत खराब हो गयी है, और यह सब आप अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले इतने विभाग नहीं थे एक पी0डब्ल्यू0डी0 था जहां पर एक मान्यवर थे उन्होंने एक विभाग अलग से खोल दिया था तो वह विभाग काम करने लगा, उसके बाद एक दूसरा विभाग आ गया, फिर तीसरा विभाग आ गया और सब विभागों पर मण्डी समिति से लेकर तमाम विभागों से आपने काम के लिए पैसे आवंटित किए और लोगों ने सड़कें बनाई लेकिन उन सड़कों की रख-रखाव की जिम्मेदारी उनकी नहीं रही। वह सड़कें बनाकर छोड़कर चले गये और जब वह छोड़कर चले गये तो सड़कें टूट गयी, उनकी रिपेयरिंग ही नहीं हुई, उनके लिए पैसा ही नहीं है। हमारा कहना यह है कि आप जो भी करें, लेकिन इसकी एक परमानेंट व्यवस्था जरूरी होनी चाहिए। आपके यहां तमाम एजेंसियाँ बन गयी हैं। अभी बहुत सारी एजेंसियों में बहुत सारे लोगों को दुख भी झेलना पड़ा है। इन एजेंसियों के माध्यम से जो आप सड़क बनाते हैं उन सड़कों का मानक भी अलग-अलग है। जैसे पी0डब्ल्यू0डी0 ने 1 किलोमीटर सड़क बनायी तो उसका अलग मानक होगा, आर0ई0एस0 बनायेंगी तो उसका अलग मानक होगा, सिडको बनायेगा तो उसका अलग मानक है। जब यह अलग-अलग मानक की सड़कें बनेंगी तो जिसका मानक कमजोर होगा वह सड़क टूट जायेगी। मेरा निवेदन है कि जो भी विभाग सड़क बनायें उसका मानक एक होना चाहिए। चाहे सड़क थोड़ी कम ही बने लेकिन ठीक बननी चाहिए। इसलिए मेरा मा0 मंत्री जी से सुझाव है कि सड़क की लागत का जो मानक बने वह एक सा होना चाहिए फिर चाहे वह पी0डब्ल्यू0डी0 हो, चाहे वह आर0ई0एस0 हो, चाहे सिडको हो या चाहे जो भी हो, सबकी

लागत जब एक हो जाएगी तो सड़क की गुणवत्ता में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा क्योंकि मा0 सिंचाई मंत्री बैठे है मैं इनसे भी कहना चाहूँगा कि हम लोग पूरब से आते है और हम लोग हमेशा दैवीय आपदा के शिकार बनते हैं। हमारी बोई हुई फसल, हमारी सारी मेहनत एक बाढ़ आती है और बर्बाद करके चली जाती है। उन किसानों के घरों में जो 20-20 एकड़ धान की रोपाई किए थें आज बाजारों से चावल खरीद रहे हैं। क्योंकि बाढ़ आई और सारी फसल डूब गयी, सड़ गयी, पैदा नहीं हुई । नेपाल से निकली हुई छोटी-छोटी नदियाँ इस बाढ़ का कारण हैं क्योंकि इनका हमारी तरफ जो राप्ती नदी है और जो छोटी-छोटी नदियाँ हैं इनका स्रोत नेपाल है और नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता है तो हम लोग डूब जाते है जिसके कारण घरों में पानी भर जाता है। लोग छतों पर रहते हैं। हमारी विधान सभा में बहुत से गांवों में लोग छतों पर तीन-तीन दिन बैठे रह गये। बाढ़ का पानी मैं मानता हूँ कि हमारी-आपकी व्यवस्था से नहीं होगा । बहुत पहले योजनायें बनीं थीं। जलकुम्भी योजना, जल कुण्ड योजना लेकिन नेपाल से हमारे सम्बन्ध पता नहीं किन परिस्थितियों में ठीक नहीं रहे। यह योजनायें नहीं बन पाईं और उन योजनाओं के नाते पानी बड़े पैमाने पर हम लोगों के यहां आ जाता है। फिर हम लोगों ने प्रयास किया था। हम खुद गये थे। हमारे सिंचाई मंत्री जी भी गये थे। मैं नेपाल के प्रधानमंत्री जी से मिला था, राष्ट्रपति जी से मिला था कि कुछ तो आप लोग करें। आप हमारे पड़ोसी हैं।

मान्यवर, हमारे बार्डर पर बंधा भी नहीं बनाने देते। इसके लिए वे आपत्ति पैदा कर देते हैं कि अगर आप बंधा बना देंगे तो हम डूब जायेंगे । मान्यवर, इस पर बहुत सोच-विचार कर काम करने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितना आप राहत का पैसा देते हैं। यह छोटी नदिया हैं। ह्वांग-हो नहीं है। अगर ह्वांग-हो को चीन कन्ट्रोल कर सकता है तो छोटी-छोटी नदियां जैसे राप्ती को आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते। या तो इनकी जलधारा घुमाकर घाघरा में करा दीजिए। घाघरा में पानी निकल जायेगा। हम लोगों के यहां नहीं जायेगा । हम हर साल परेशान होते हैं। दूसरा यह कि इस पैसे को बचाकर अगर इनके किनारे आप तटबन्ध बना दें। बहुत कमीशन की रिपोर्टें हमने पढ़ी हैं। सबसे पहले जयसुख लाल हाथी जी के टाइम पर कमीशन बना, वे उसके चेयरमैन थे। उन्होंने बहुत सारे सुझाव तटबन्धों के लिए दिये थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा उसको देख लीजिए, उसमें आप कितना सुझाव कर सकते हैं। अगर आप तटबन्ध बना देंगे तो हम बाढ़ से बच जायेंगे। हमारा एक बन्धा भोजपुर से लेकर साहपुर बासे तक है इस पर 75 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ और 5 साल से लगातार वे लोग डूब रहे है। जगह-जगह गैप है। वह गैप भरा नहीं जा रहा है। जब हमने पूछा क्यों नहीं भरा गया तो कहते है कि पैसे नहीं मिलते हैं और उस पर आज ज्यादा लागत आ गयी होगी लेकिन आपसे निवेदन है आपने कुल 5 करोड़ रुपये दिये हैं और 5 करोड़ में गैप नहीं भरा जाता। आपने मुझे लिखकर दिया है कि उसमें बहुत गैप है, हम उसे ठीक करायेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इन गैपों को आप ठीक करा दें जिससे कि हम लोग बाढ़ से तो बच सकें । मान्यवर, एक

और बात मैं कहूंगा कि इसको आप गम्भीरता से लें। हम लोग बहुत परेशान हैं। लाख कोशिश करते हैं, खाद डालते हैं, बीज डालते हैं। हमने कुछ एरिया पर बन्धे के माध्यम से बाढ़ रोक दी है। बूढ़ी राप्ती का दायां तट पर हमने पूरी बाढ़ रोक दी। बहुत बड़ा बन्धा बनवाया था। सिंचाई मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह से कहकर । उधर हम लोग सुरक्षित हो गये। इधर बूढ़ी राप्ती की तरफ से अगर बायां तट बन जाये तो पूरी तहसील इटवा और डुमरियागंज दोनों बाढ़ से बच जायेगी। यही मेरा आपसे निवेदन है।

***श्रीमती अनुपमा जायसवाल-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराईयों से आभार व्यक्त करती हूं। मैं बधाई देना चाहती हूं, माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को एवं परम् विद्वान वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी को जिन्होंने एक बार फिर एक लोक कल्याणकारी बजट हमारी सम्मानित जनता के लिए इस अति सम्मानित सदन में पेश किया है। विपक्ष की बौखलाहट बता रही है कि यह बजट कितना जनप्रिय है और कितना लोकप्रिय है।

[इस समय सायं 05 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती कृष्णा पासवान पीठासीन हुई]

जिस शिद्दत और जिम्मेदारी से इस बजट को बनाया गया है तो इस पर मुझे ये लाइने याद आती हैं कि उठाने हैं अभी दरिया से मुझको प्यास के पहरे अभी तो खुश्क पहरों पर रिमझिम मुझे लिखनी है। मा0 वित्त मंत्री जी को मैं केवल इसलिए बधाई नहीं दे रही हूँ कि उन्होंने बड़ी सुझबूझ के साथ उत्तर प्रदेश की विधान सभा के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा बजट 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये का प्रस्तुत किया है बल्कि इसलिए भी आभार व्यक्त कर रही हूँ कि इस बजट में समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चला गया है चाहे वह महिला हो या किसान, श्रमिक हो या नौजवान समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। वास्तव में हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते है और हमारी पार्टी का तो मूलमंत्र ही यही है कि 'सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास' वित्त मंत्री जी का भी यकीन इसी में है इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने हम जो कहते हैं कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो के आधार पर बजट प्रस्तुत किया है।

मा0 मुख्य मंत्री जी ने विकास की गंगा को बहाने का कार्य किया है। प्रदेश के विकास के चार-पांच मानक होते हैं जैसे कि प्रदेश का औद्योगिक विकास हो और प्रदेश का शैक्षणिक विकास हो और प्रदेश का आर्थिक विकास हो और प्रदेश का सामाजिक विकास हो पर अफसोस है कि भाजपा से पूर्व की सरकारों ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। जब यह शासन में थे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो केवल स्वः निहित स्वार्थ में व्यस्त थे और मजबूर थे और प्रदेश का विकास कर न सके और जब आज आदरणीय योगी जी की सरकार आर्थिक मोर्चे पर, शैक्षणिक मोर्चे पर स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर और कानून व्यवस्था के प्रश्न पर अंत्योदय के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है तो इन से देखा नहीं जाता है। गूंगे बता रहे हैं कि मेरा किरदार है गलत, बहरों को ये गुमा है कि गलत बोलते हैं। हम आज यह मुख्य मंत्री जी के प्रयासों की आलोचना कर रहे हैं लेकिन अफसोस है मुझे कि आपके यह इरादे और प्रयास निर्रथक सिद्ध होंगे क्योकि लोगों ने कई बार कोशिश की है मुझे मिट्टी में दबाने की लेकिन उन्हें मालूम नहीं मैं बीज हूँ और मुझे आदत है बार-बार उग आने की। यही कारण है चाहे कितनी भी साजिशें रची गयी हों सारे जाति धर्म सम्प्रदाय के सियासी समीकरणों को धवस्त करते हुए योगी जी ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह करिश्मा भी पहली बार कर दिखाया जब 37 वर्षों बाद किसी सरकार को दोबारा से प्रदेश की जनता ने काम करने का मौका दिया है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में कानून का राज कायम किया माफियाओं, गुंडो और दंगाईयों के आतंक से जन सामान्य को राहत दिलायी है और नए रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ और प्रदेश में उद्योग धंधो को बढ़ावा दिया गया महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करके उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का काम किया गया और प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के रूप में 1 करोड़ 85 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है और मा0 मुख्य मंत्री जी ने 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की है। वर्ष 2022 में वर्ष 2016 के सापेक्ष डकैती में 80.13 प्रतिशत और लूट में 61.51 प्रतिशत, हत्या में 32.45 प्रतिशत और रोड होल्डअप में 100 प्रतिशत की कमी आयी है। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। 9 सृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय व आवासीय भवनों के लिए 850 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संचालन हेतु 12631 करोड़ रुपये व प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 1655 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

महोदया, आज निर्बाध बिजली की आपूर्ति से हमारा उत्तर प्रदेश रात में चांद सितारों जैसा झिलमिलाता रहता है। माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयास से किसान सम्मान निधि के सम्यक बजट प्रस्ताव से उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान उसका गांव, उसका खलिहान, उसका चौबारा बड़े शिद्दत के साथ मुस्कराता है। नई यूनीफार्म में कापी-किताबों से सुसज्जित बैग और नये आत्मविश्वास से नन्हें-नन्हें पैरों में जब जूते-मोजे पहनकर प्रदेश का बचपन बैग टांग कर स्कूल के लिए चलता है तो हमारे देश और प्रदेश का भविष्य खिलखिलाता है। प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरोत्थान के अभियान के साथ जब उत्तर प्रदेश शंखनाद करता है तो दुनिया पर हमारी सांस्कृतिक चेतना का जादू छा जाता है, लेकिन विपक्ष का काम तो केवल विरोध करना है और वह आपको करते भी रहना चाहिये। निकालते रहो मेरे किरदार में नुक्स, तुम नहीं होगे तो हमें तराशेगा कौन। वास्तव में भाजपा के पूर्व की सरकार बड़े दावों

और वादों के साथ आई थी। 'पूरे हुये वायदे और अब हैं नये इरादे' का नारा देने वाले घोषणा-पत्र के अनगिनत दावों और वादों से मुकर गये थे। तभी तो दुष्यन्त कुमार की पंक्तियाँ मुझे याद आती है कि 'कहां तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहां एक दिया भी मयस्सर नहीं था पूरे शहर के लिए।' गुड गवर्नेन्स के हर पहलू पर हमारे तेजस्वी मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में समयबद्ध रूप से की गई प्रभावी कार्यवाही के कारण आज उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी) अन्तर्गत आवास निर्माण, स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत इण्डिया स्मार्ट सिटी एवार्ड कान्टेस्ट और पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में धनराशि हस्तांतरण कराने में इन सारी चीजों में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना, चीनी उत्पादन और एथनाल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। हमारा उत्तर प्रदेश चिकित्सा संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। भारत सरकार द्वारा स्टार्ट अप रैंकिंग के तहत् उत्तर प्रदेश को इन्स्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास निधि लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराने वाले राज्य के रूप में भी यह प्रथम स्थान पर है।

मान्यवर, आज हमारा प्रदेश ना केवल देश के अन्दर बल्कि वैश्विक समुदाय के मध्य भी अपनी सशक्त उपस्थिति को दर्ज करा रहा है। सबसे बड़ी बात, अपराधियों के हौसले पस्त कर जंगल राज समाप्त कर योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम किया है। प्रदेश में प्रयागराज की घटना पर योगी जी का सीधा आर्डर शुरू हो गया है अपराधियों का इन्काउण्टर। मिट्टी में मिलाने की जो शपथ उन्होंने इस पवित्र सदन के अन्दर ली थी वह आज दिखाई दे रही है। अभी तो एक काम तमाम और बाकी का है इंतजाम।

जहां तक क्षेत्र के लिए कुछ मांगने की बात है महोदया, लोग तो मांगते हैं और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सबको मिल रहा है। मांगने की कोई सीमा नहीं है। मुझे पता है कि हम जब भी मांगेंगे हमारे उदार मुख्य मंत्री जी और उससे कहीं भी अधिक उदार जिनके पास पूरा कोष है मा0 वित्त मंत्री जी देने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं कोई एक-दो चीज नहीं मांगुंगी मैं जब-जब मांगूगी, आप सब जब-जब मांगेगे यह जरूर देंगे। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अंत में अमृत काल में सर्वत्र अमृत बरसाने वाले बजट का अपनी विधान सभा और प्रदेशवासियों की ओर से बहुत-बहुत स्वागत और अभिनन्दन करती हूँ और मा0 वित्त मंत्री जी को एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत बधायी देती हूँ। आप इसी प्रकार से वित्त मंत्री के रूप में और ऊपर भी जायें लेकिन जब तक आप वित्त मंत्री हैं तब तक आप हम

लोगों की जो मांगे हैं उसे पूरा करने का काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द, जय श्री राम।

*श्रीमती अलका सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, जैसाकि वित्त मंत्री जी बजट लेकर आये हैं और मा0 मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश को नई ऊंचाईयों तक लेकर जाना चाहते हैं। जब से यह बजट प्रस्तुत हुआ है तब से विपक्ष के तमाम मा0 सदस्यों की चर्चा को सुना जिन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने यह-यह नहीं किया। तमाम आरोप-प्रत्यारोप लगाये। मैं अब यथार्थ की बात करती हूँ और यथार्थ की बात यह है कि जैसाकि अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मेरी सरकार में यह हुआ, मेरी सरकार में यह हुआ । मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की दो छोटी-छोटी रोडों का जिक्र करना चाहती हूँ। एक है पवाया से कटिहार फार्म और दूसरी रोड है सिकरोरी से महिमाखेड़ा। यह सड़क 2-2 किमी0 की हैं अगर यह बन जातीं अगर पवाया से कटिहार फार्म की रोड बनती तो कम से कम 60 गाँव सीधा लखनऊ से जुड़ते, इन लोगों का जीवन-यापन में सुधार होता, गरीबों को दवाईयाँ समय पर मिल पातीं। दूसरी रोड सिकरोरी से महिमाखेड़ा बनती तो यहाँ पर भी 70 गाँव ऐसे हैं जो सीधे लखनऊ से जुड़ जाते। यानी कुल 130 गाँव लखनऊ से जुड़ जाते। यदि पूर्व की सरकार और उनके जनप्रतिनिधियों ने काम किया होता तो यह दोनों रोडें बन गयी होतीं। मैं इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से लोक निर्माण विभाग के मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इन रोडों पर विशेष ध्यान दिया जाये। करीब 130 गांव सीधे लखनऊ से इन दोनों सड़कों से जुड़ते हैं। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूँ वह विधान सभा क्षेत्र लखनऊ से 70 किमी0 दूर है और जो मेरा जिला हरदोई है वह मेरी विधान सभा क्षेत्र से लगभग 60-70 किमी0 आगे पड़ता है। यानी मेरी विधान सभा क्षेत्र लखनऊ और हरदोई के बीच में आती है। मरीजों का मुद्दा बहुत गम्भीर है।

मैं अपने उप मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ से जब किसी गम्भीर दुर्घटना में कोई मरीज सी0एच0सी0 में आता है तो उसे हरदोई रिफर किया जाता है और जो मेरी विधान सभा क्षेत्र के आखिरी गाँव भटपुर है या ब्लाक भरावन के जो गाँव है वहाँ से हरदोई जिला अस्पताल 90 किमी0 पड़ता है। गम्भीर हालत में किसी मरीज का 90 किमी0 जाना और हरदोई से लखनऊ लगभग 110 किमी0 पड़ता है। किसी गम्भीर मरीज को एक दिन में लगभग 200 किमी0 ट्रेवल करने के बाद ट्रीटमेंट मिल पाता है। मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार की पालिसी में चेंज करके गम्भीर मरीज को सण्डीला से हरदोई रेफर न करके सीधे लखनऊ के अस्पताल में रिफर किया जाये। तीसरा मेरा मुद्दा यह है कि विधान सभा क्षेत्र सण्डीला को जिला

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनाया जाना चाहिए। एक ऐसी विधान सभा क्षेत्र जहाँ पर मुंसिफ कोर्ट नहीं है। सण्डीला को जिला बनाने के लिए पूर्व की सरकारों में क्या किया गया। मैं इस सदन के माध्यम से अपने मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि मेरी विधान सभा क्षेत्र सण्डीला को जिला बनाने की घोषणा की जाए उसकी प्रक्रिया शुरू कराई जाए क्योंकि मेरी विधान सभा क्षेत्र लखनऊ के मध्य है जहां पर बड़ी समस्याएं है। छोटे-छोटे निपटारों के लिए मुन्सिफ कोर्ट तक नहीं है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के लोगों को 90 किलोमीटर जाना पड़ता है। किसान जो एक दिन में 300-400 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं अगर वह किसी काम के लिए जनपद हरदोई जाते हैं तो उनका पूरा दिन खराब होता है और आने-जाने में उनका कम से कम 300-400 रुपये लग जाता है। इसलिए वहां पर मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना और विधान सभा क्षेत्र सण्डीला को जिला बनाये जाने की मांग भी करती हूँ। अभी सदन में पिछड़ों की बात हो रही थी । मै अलका सिंह 'अर्कवंशी' पुनः कहना चाहती हूँ जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे समाज से आई हूँ जिसको 70 सालों तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अर्कवंशी समाज की पूरे प्रदेश में लगभग 70 लाख आबादी है, मैं उदाहरण हूँ और मा0 नेता प्रतिपक्ष से सवाल करना चाहती हूँ कि मेरे लोगों ने आपको वोट दिया है, क्या आपने मेरे लोगों को ब्लॉक प्रमुख तक का टिकट दिया है, नहीं दिया है। मेरा समाज 70 साल से संघर्ष कर रहा था और मेरे समाज को भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिष्ठा एवं सम्मान दिया है। आप पिछड़ों की बात करते हैं, आईए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं कि मा0 मोदी जी ने क्या किया है तो मैं बताती हूँ। आप सिंधी समाज को जानते हैं, आप नहीं जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि सिंधी समाज अफ्रीका से आए हुए वह लोग हैं जिन्हें दासता के लिए हिन्दुस्तान लाया गया और यह हमारे देश में लगभग 100-150 साल पहले से रह रहे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता था । केवल मा0 मोदी जी थे जिन्होंने उस समाज को प्रतिनिधित्व दिया है और एम0एल0ए0 बनाया है। आप पढ़कर देखिए, यह मेरी सरकार कर रही है। जब आपने एक तथाकथित क्रिकेटर के फिल्म स्टार पुत्र को भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से नवाजा था वहां आज हमारी सरकार देश के वरिष्ठ सम्मान को आदिवासियों एवं जन-जन तक पहुंचा रही है। यह मा0 मोदी जी की पिछड़ों एवं दलितों के प्रति सोच है। जब एक दलित की बेटी पहली बार आई थी तब पूरे प्रदेश का मीडिया, भारतीय जनता पार्टी एवं शासन सत्ता में बैठे लोग गवाह थे कि उसके साथ कितनी जघन्यता करने की कोशिश की गयी थी। मैं मा0 सुश्री मायावती जी की बात कर रही हूँ। पक्ष-विपक्ष हो सकता है। क्यों, कैसे एक दलित महिला सिंहासन पर बैठ गयी, कैसे वह शासन सत्ता चला सकती है। आज वह लोग सामाजिक समरसता एवं न्याय की बात कर रहे है। मा0 नेता कांग्रेस कह रही थीं कि मा0 मोदी जी ने महिलाओं के लिए क्या किया है। मा0 मोना जी सदन में उपस्थित नहीं हैं वरना मैं उनसे पूछती कि आपको शालिनी खन्ना का नाम याद है, आपको याद नहीं होगा।

मैं इस सदन के माध्यम से मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं समस्त मा0 सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में हजारों सैनिक बलिदान हुए हैं, विशेष रूप से आर्मी के लोग जिनकी बदौलत हम लोग यहां पर बैठे है। श्री रवि खन्ना, वायु सैनिक जिनको आतंकवादियों ने गोली

मार दी थी उनकी विधवा पत्नी का नाम शालिनी खन्ना है, उस महिला के 3-4 साल तक के दो बच्चे थे, आज वह महिला बूढ़ी हो गयी है। उस समय आपकी सरकार कहां थी, आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला थीं। आप न्याय की बात करती हैं, आप महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं और मेरी सरकार 32 साल बाद, उस महिला को तो भूल गई थी कि उसके पति को कश्मीर में गोलियों से मार दिया गया था। वह महिला भूल गयी थी कि उसको कभी न्याय भी मिल पायेगा। शायद वह उस समय 30-32 साल की थी और आज मुझे लगता है कि वह 60 साल के ऊपर हैं। आतंकवादियों ने शालिनी खन्ना के पति को गोलियों से मार दिया था और दो मासूम बच्चों के सिर से बाप का साया छीन लिया था। जिन आतंकवादियों ने उनको मारा था उनको प्रधानमंत्री कार्यालय पर बिठाकर चाय पिलाई जाती थी, जश्न होते थे। आप पूछ रही हैं जिसकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला थीं। मेरी सरकार ने 32 साल बाद मा0 मोदी जी की सरकार आने के बाद शहीद श्रीमान् रवि खन्ना जी वायु सेना कर्मचारी और उनकी पत्नी श्रीमती शालिनी खन्ना एवं उनके बच्चों को न्याय मिलने की उम्मीद जागी और मेरी सरकार ने एक महिला के सम्मान में उस केस को आगे बढ़ाया है। यह मेरी सरकार ने महिलाओं के सम्मान के प्रति किया है। अब पिछड़ों की बात करती हूँ।

महोदया, भारत का स्वर्णिम काल लिखने वाला हमारा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, आप उन्हें भूल गये । आप कहते हैं कि हम जब सरकार में थे, हमने ये किया, हमने वह किया, बहुत अच्छा किया। आपने किसी मौर्य को उप मुख्य मंत्री या मुख्य मंत्री क्यों नहीं बनाया, आपने उस चक्रवर्ती सम्राट के वंशज को क्यों नहीं कुछ बनाया ? लेकिन जब लोगों ने कहा भारत का शौर्य चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने उसका ध्यान रखा और केशव प्रसाद मौर्य जी, एक चक्रवर्ती सम्राट के वंशज को यहां बैठाया ताकि वह उस समाज का उत्थान कर सकें जिसने भारत के गौरव का स्वर्णिम काल लिखा है। मैं अपनी राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त करती हूं, मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस तरह का बजट बनाया और मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने प्रधानमंत्री एवं मुख्य मंत्री जी को, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। एक सवाल और करना चाहती हूं, हमारी कुछ विपक्ष की महिलाएं कह रही थीं

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त करिए। सभी लोग कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करिए । मो0 नासिर जी आप बोलिए।

***हाजी नासिर कुरैशी-**

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे वर्ष 2023-24 के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और नेता प्रतिपक्ष और तमाम विपक्ष के सदस्य, जो बजट पर बोले, मैं उनसे अपने आप को संबद्ध करते हुए अपनी विधान सभा क्षेत्र की समस्याएं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखना चाहता हूं। महोदया, मैं मुरादाबाद जिले से देहात विधान सभा क्षेत्र 27 से आता हूँ जो कि दो भागों में बटी है। जिसका 40 प्रतिशत हिस्सा देहात से लगा हुआ है और 60 प्रतिशत हिस्सा शहर से लगा हुआ है। महोदया, देहात में ग्राम पीपलसाना गांव पड़ता है जहां पर काफी समय से एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है लेकिन काफी टाइम से वह चालू नहीं हुआ है। मैं मांग करता हूँ कि उस स्वास्थ्य केन्द्र को जो काफी टाइम से बना हुआ है उसको चालू करने का काम किया जाये क्योंकि तमाम ग्रामीण जनता परेशान है और उनको काफी दूर जाना पड़ता है। साथ ही उसके बराबर से ही नगर पंचायत भोजपुर पड़ता है जहां पर मैंने पूर्व में भी मांग की थी कि वहां पर एक कन्या डिग्री कॉलेज की बहुत ही आवश्यकता है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि वहां पर एक कन्या डिग्री कॉलेज बनना चाहिए।

महोदया, मेरा देहात विधान सभा क्षेत्र 27 जो शहर का हिस्सा आता है वहां पर मुरादाबाद एक पीतल नगरी का शहर है और पीतल का वहां पर बहुत बड़ा कारोबार है। वहां पर बड़े नजदीक-नजदीक मोहल्ले हैं जैसे लालबाग, जामा मस्जिद, बारादरी, कच्चा बाग, मुफ्तीटोला सभी इस तरह के मोहल्ले हैं जहां पर हाथ के दस्तकार काम करते हैं, पीतल के बर्तन की रगड़ाई, छिलाई, पॉलिश और ढलाई का काम होता है। आज कल वहां पर बिजली की बहुत भारी समस्या चल रही है, वहां पर तमाम छापे पड़ रहे हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, अगर उनका लाइट का बिल दो महीने भी लेट हो जाता है तो उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। और वह परेशान रहते हैं और चेकिंग की तो कोई हद ही नहीं है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो या सुबह का कोई टाइम हो, वहाँ लाइट की इतनी चेकिंग की समस्या है कि बिजली घरों में उन्होंने तमाम प्राइवेट लोग रख लिए हैं, जो मुखबिरी करने का काम कर रहे हैं। विजलेंस से फोन आता है और उनको बुलाकर दफ्तर के बाहर ही वसूली की जाती है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि लाइट और चेकिंग के नाम पर उनका जो उत्पीड़न हो रहा है, उनका उत्पीड़न खत्म होने का काम होना चाहिए, मैं आपसे ऐसा अनुरोध करता हूँ। महोदया, हमारी विधान सभा क्षेत्र में एक गवर्नमेण्ट इण्टर कालेज पड़ता है, जिसमें बहुत विशाल एक खेलकूद का मैदान है और गवर्नमेंट की भी पहली प्राथमिकता है कि खेलकूद के मैदान को बड़ा किया जाए, लेकिन उस मैदान को छोटा करने का काम किया जा रहा है, जबकि वहाँ पर एक बहुत पुराना जर्जर भवन है, उसे तोड़ करके भवन बनाया जा सकता है। उसे न तोड़ करके बच्चों का खेलकूद का जो मैदान है, उसमें भवन बनाया जा रहा है और उस मैदान को छोटा किया जा रहा है।

मा0 अधिष्ठाता-

माननीय विधायक जी, 05 मिनट का समय पूरा हो गया है। अब आप समाप्त करें।

हाजी नासिर कुरैशी-

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारी विधान सभा क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण रोड बहुत बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। यह दोनों रोड नैनीताल को जा रहे हैं। एक टांडा रोड पड़ता है और

दूसरा रोड रामपुर चौराहे से भोजपुर तक पड़ता है, उसमें इतने गहरे-गहरे गड्ढे हो गए हैं कि वहाँ पर कई गाड़ियाँ पलट चुकी हैं, तमाम महिलाओं को वहाँ पर चोट लग चुकी है, उस रोड पर बहुत से हादसे हो चुके हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह माँग करता हूँ कि जल्द से जल्द उन रोडों को बनाने का कार्य किया जाए।

मा0 अधिष्ठाता-

अब माननीय सदस्य, नन्द किशोर गूजर जी बोलें।

हाजी नासिर कुरैशी-

(कुछ समय तक बोलते रहे, किन्तु माइक बन्द कर दिए जाने के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया)

श्री नन्द किशोर-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूँ कि प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट माननीय वित्त मंत्री, माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा पेश किया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत अभिनन्दन और स्वागत करता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र लोनी एक विचित्र स्थिति की विधान सभा क्षेत्र है जो दिल्ली से सटी हुई है और दिल्ली से सटी होने के कारण दिल्ली के मुख्य मंत्री केजरीवाल ने एक षड़यन्त्र के तहत् रोहिंगियों और बंग्लादेशियों को ट्रेन से भर-भर करके बंग्लादेश और पश्चिम बंगाल के रास्ते पूरी दिल्ली और दिल्ली के आसपास बसाया जा रहा है। बंगाल के पूरे हिस्से से लेकर बिहार, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। यह स्टोरी कई चैनल ने कवर की है। इस सम्बन्ध में जब मैने सम्बन्धित अधिकारियों को कहा तो कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद अभी भी कुछ लोग वहाँ बसे हुए हैं। जिनके वोटर कार्ड और आधार कार्ड दिल्ली के हैं। जब चुनाव होता है तो दिल्ली वोट डालने के लिए जाते हैं। यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत गम्भीर विषय है और बहुत बड़ा खतरा है। जब भी कोई दंगे होते हैं यह लोग उसमें शामिल पाए जाते हैं और जो सरकारी भूमि है पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार में इन लोगों को बसाया गया उनके आधार कार्ड बने और वह बकायदा पकड़े गए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है और उन्हें बसाकर के वहां का मूल निवासी बनाने जैसा राष्ट्र विरोधी कार्य समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया। मेरी आपसे मांग है कि एक एस0आई0टी0 का गठन हो और वहां बोर्ड ऑफ रेवन्यू की टीम भी जाए और उनको चिन्हित करके जो सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है, वह बेशकीमती भूमि है वहां से इसको खाली कराया जाए यह बहुत गम्भीर विषय है। मेरी विधान सभा क्षेत्र का विषय है जिसको वन विभाग की भूमि या सरकारी पार्क है उनमें बसाया गया है। लोनी क्राइम सिटी के रूप में जाना जाता था जहां बॉलीवुड में अपराध के ऊपर मूवी तक बनी है। मेरे यहां समाजवादी पार्टी द्वारा चुने गए अब गठबंधन में हैं ये उनके अपराध का रिकॉर्ड है जो कि आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड में 60 के लगभग मुकदमें दर्ज हैं यह केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान

और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दर्ज हैं और यह कोई आंदोलन के मुकदमें नहीं है यह हत्या, मर्डर, डकैती, अपहरण के मुकदमें दर्ज हैं और यह गठबंधन के द्वारा अभी इसी विधान सभा में मेम्बर हैं। समाजवादी पार्टी अपराध को रोकने की बात करती है। आज भी इनके ऊपर मुकदमें दर्ज हैं और पूरी लोनी के अन्दर हत्याएं, मर्डर, डकैती का अड्डा बना दिया गया था। आज भी इनके ऊपर मुकदमें चल रहे हैं और यह अपराध की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी अपराध की बात करती है।

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

यह विधान सभा के अन्दर धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। चुने हुए प्रमुख को जिला पंचायत सदस्य को इन्होंने गोलियों से भून दिया था और समाजवादी पार्टी के लोग अपराध रोकने की बात करेंगे। इनके द्वारा पूरी जमीनों पर कब्जा कराया गया । यह केवल उत्तर प्रदेश के मुकदमें नहीं है सन् 1976 से लेकर के आज तक की लिस्ट है और यह लगातार फोन करके धमकी देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने घरों में सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती रखने का काम किया। पिछले सन् 1992 से लेकर आज तक जितने भी कर्मचारी इनके यहां रहे हैं मेरी अध्यक्ष जी से मांग है कि सारे कर्मचारियों की तनख्वाह इनसे वसूल की जाए।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से सदन में शोर एवं व्यवधान की स्थिति)

(शोर एवं व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, सारे कर्मचारियों की तनख्वाह इनसे वसूल की जाए। इन्होंने सारी हदें पार करते हुए अपने घर में सरकारी कर्मचारियों को धमका कर रखा और जब हमने उसका संज्ञान लिया तो उनको वापस बुला लिया गया। ये मा0 योगी जी की सरकार है। इसलिए मेरी मांग है मा0 अध्यक्ष जी से इनके सारे मुकदमे चलाए जाएँ। जिन्होंने गवाही दी उनको मार दिया गया। उन लोगों की हत्या कर दी गई। अध्यक्ष जी, इनके सारे मुकदमों में पुनर्विवेचना हो । ईमानदारी के साथ जाँच हो ताकि गरीबों को इंसाफ मिल सके। जिनके लोग मारे गए हैं उनको इंसाफ मिल सके। मान्यवर, ये लोग क्या अपराध की बात करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाएँ। समय हो गया।

श्री नन्द किशोर-

मान्यवर, दिल्ली-सहारनपुर रोड पर 452 करोड़ रुपये का घोटाला सपा सरकार में हुआ था, उसको एन0ओ0सी0 नही दी गई थी इनके द्वारा। मैं मा0 योगी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी सरकार आने के बाद बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में लोनी के अन्दर एक विकास की नदी बही है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने कल कहा था, इलाहाबाद के प्रकरण पर महाराज जी ने कहा था कि मैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दूँगा तो आज

अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देता हूँ। आज हमारे लोनी क्षेत्र में कुछ समस्याएँ हैं। मैंने वहाँ एक टीम बनाने की मांग की है। उनको पूरा करने का काम किया जाए। वैसे तो हमारे यहाँ ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं कहता हूँ कि ये लोग साँड़ की बात कर रहे थे लेकिन इनकी सरकार में सारी गौ-माताओं को कटवाया जाता था। आज मा0 मुख्य मंत्री जी को गौमाता का, भगवान श्री राम का आशीर्वाद है इसलिए इन लोगों की इतनी ताकत नहीं है उनको कोई हिला सके।

वर्ष 2024 में हमारी अस्सी की अस्सी सीटें आएँगी। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो 07 नवम्बर, 1966 को स्वामी करपात्री जी महाराज आन्दोलन कर रहे थे तो उस समय गौ-भक्तों पर गोलियाँ चलाकर ढाई हजार से ज्यादा सन्तों को मरवाने का काम इन्दिरा गांधी की सरकार ने किया था और वही पाप सन्तों को मरवाने का काम, कारसेवकों को मरवाने का काम उनको सरयू में डालने का काम सपा की सरकार ने किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के उस पाप के लिए अखिलेश यादव जी इस देश से, प्रदेश से माफी मांगें, अन्यथा ऐसी पार्टी को समाप्त करना चाहिए । जो पार्टी आतंकवादियों का समर्थन करती हो, बहन बेटियों के बलात्कार का समर्थन करती हो, ऐसी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अभी यहाँ पर गूगल की बात की जा रही थी। मैं एक बात कह कर अपनी बात पूरी करूँगा । मा0 अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा था कि गूगल कर लें कि राम चरित मानस और भगवान राम जिसको सद्दाम हुसैन ने भी माना और उन्होंने वकालत की थी कि राम मन्दिर बनना चाहिए। इनके लोगों को इनकी पार्टी को उससे सीख लेनी चाहिए थी जिन्होंने साधु-सन्तों पर गोली चलवाई। आज राम चरित मानस के साथ जो किया गया, उसे पूरे देश की जनता देख रही है और एक दिन इनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मानस पर जो कहा गया। आप चाहो तो गूगल पर देख लो। मा0 अखिलेश जी टेक्निकल व्यक्ति हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन गूगल करके देख लो।

***श्री राजेश चौधरी-**

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट एक कान्तिकारी बजट है। यह विकास का बजट है।

जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा,
जो जल रहा है तिल-तिल, उसी दिये में उजाला होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इनके पेट में बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। जब उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे जा रहा होता है। ये तो उत्तर प्रदेश का विनाश करना चाहते हैं, बरबाद करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐतिहासिक काम हो, कोई भी अच्छा काम हो तो इनको परेशानी जरूर होती है। किसानों के हित का बजट, नौजवानों के हित का बजट, महिलाओं के हित का बजट ऐसा बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ला सकती है। बिजली की बात विपक्ष के नेता कर रहे थे। वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक भी बिजली का क्या हाल था, यह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, आज कोई किसान जब घर से 10 बजे निकलता है तो 10 बजे उसके ट्यूबवेल पर बिजली आ जाती है। उसका समय निश्चित रहता है। किसानों के लिए अलग फीडर निर्माण करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, केन्द्र की सरकार ने किया और इनके जमाने में क्या होता था, बिजली कभी आ जाये तो बहुत बड़ी बात समझो। ट्यूबवेल की तरफ किसान देखता रहता था, बल्ब की तरफ किसान देखता रहता था कि बल्ब जल जाये और जाकर कैसे भी स्टार्टर दबाऊँ। वह जैसे ही ट्यूबवेल पर जाता था, बिजली आती थी, बटन दबाता था तो बिजली चली जाती थी। फिर वह ट्यूबवेल की तरफ निहारता रहता था, बल्ब की तरफ कि किसी तरह से बिजली आ जाये। बेचारा थक-हार कर रात में लौट करके घर को आता था। सोचता था कि दिन भर का भूखा-प्यासा जाकर घरवाली के पास बैठकर भोजन करूँगा, चैन से उसका चेहरा देखूँगा लेकिन जैसे ही गांव के नजदीक आता था तो फिर दोबारा से वहां बिजली का बल्ब ट्यूबवेल पर जलता देखकर बेचारा फिर दौड़कर वापस आता था और जैसे ही ट्यूबवेल पर फिर पहुँचता था तो दोबारा से वही हाल कि फिर बिजली चली जाती थी। यह हाल उत्तर प्रदेश का इनके जमाने में बिजली का था। आज शान से किसान 10 बजे जाता है, बटन दबाता है और 5 बजे तक बिजली आती है जिससे पूरा सिंचाई का काम करके वह वापस आता है। हमने अलग फीडर इसीलिए बनाये थे। विकास की बात यह करते हैं।

हमारे सौमेन्द्र भाई कॉमन फैसिलिटी सेण्टर बनाने की बात कह रहे थे। क्या कभी किसी ने इसकी कल्पना की थी। गांव में जाकर देखिए तो इतने सुन्दर-सुन्दर कॉमन फैसिलिटी सेण्टर बने हैं जो होटल नजर आते हैं। पंचायत घर ऐसा लगता है जैसे जिलाधिकारी का ऑफिस होगा। पंचायत घर ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़े अधिकारी का बहुत बड़े नेता, मंत्री का ऑफिस होगा। वहां ग्राम पंचायत का प्रधान बैठता है, वहां ग्राम पंचायत सेक्रेटरी बैठता है, वहां बीट कॉन्सटेबल आता है, वहां लेखपाल आता है, वहां सरकारी विभागों से सम्बन्धित सारे लोग आकर बैठते हैं और गांव का आदमी जाकर वहां अपनी समस्या बताता है। वहां जो पंचायत मित्र उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया है, वह क्लिक करके एक बार में सारी समस्याओं को ऑनलाइन कर देता है। लगभग 40-45 साल से इस सरकार के पहली सरकार के आने से पूर्व ऐसी अनेक नहरें थी, अनेक राजवाहें थे जहां पानी आता ही नहीं था। कभी

देखा ही नहीं था, उनका अस्तित्व खत्म हो गया था। योगी सरकार आने के बाद किसान के लिए टेल पर पानी पहुँचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। यदि हम शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे और फ्री में जूते, फ्री में मोजे, फ्री में स्वेटर, फ्री में किताब, फ्री में बैग, फ्री में फीस और जब विद्यालय की हालत देखेंगे तो चमचमाती हुई टाइल, वहां बना हुआ शौचालय एक नये विकास की गाथा उत्तर प्रदेश के अन्दर लिख रहा है। कोरोना काल आया तो समस्या यह खड़ी हो गयी कि कैसे बच्चे पढ़े। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने चिन्ता की और हर नौजवान के लिए टेबलेट और स्मार्ट फोन बाँटने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। पर्यटन के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि मैं तो ब्रज भूमि से आता हूँ, वह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, पवित्र भूमि है। वहां के लिए जो क्रान्तिकारी काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, मोदी जी की सरकार कर रही है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रज तीर्थ विकास परिषद् के नाम से पूरे ब्रज क्षेत्र का विकास हो रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से यह अपील करना चाहूंगा कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का जो विकास हो रहा है, उसकी जिन शब्दों में प्रशंसा की जाये वह कम है। सारी परिक्रमा के विकास की योजना बनाकर, डी0पी0आर0 बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी जाये, मेरी आपसे यह अपेक्षा रहेगी। वहां पर जो पैदल परिक्रमा मार्ग बनने वाला है, उसका जल्दी से जल्दी डी0पी0आर0 बनाकर माननीय नितिन गडकरी जी के विभाग को भेजा जाये। यमुना एक्सप्रेस-वे मेरे क्षेत्र से होकर जाता है। 12-14 साल पहले उसका संचालन शुरू हुआ था और सामने हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं, इन्होंने ही शुरू किया था और बनाया था। उस पहली सरकार ने फीता काटा था इन्होंने आज जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वह हाई-वे हमारे सीने से गुजर के साँप जैसे जा रहा हो उसमें हम चढ़ नहीं सकते हैं तो मेरी यह माँग होगी कि सुरीर और टैटी गाँव के बीच में हाई-वे पर कट बनाकर वहाँ के लोगों को हाई-वे पर चढ़ने की सुविधा प्रदान की जाए, जेवर एयरपोर्ट मेरे क्षेत्र के बराबर में आता है। मेरी इस सदन के माध्यम से माँग होगी कि वहाँ पर उसके विकास के लिए नये-नये कोई उद्योग विकसित किये जाएं। मेरे क्षेत्र में वह जगह भण्डी खन भी आती है कि जहाँ भगवान कृष्ण ने राधाजी ने विवाह किया है वहाँ पर लक्ष्मी जी के मंदिर का विकास किया जाए शेरगढ़-छाता-नीहझील मार्ग का निर्माण किया जाए और मांट विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 15-15 हजार की ऐसी पाँच पंचायतें है शेरगढ़, नवझील, सुरीर, मांट, सोनई उनको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए और यमुना एक्सप्रेस-वे से वृन्दावन को जोड़ने वाला जो मार्ग बन रहा है, उसके कार्य पूर्ण करा दिये जाए। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अवधेश प्रसाद-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे 2023-2024 के सामान्य बजट जो मा0 खन्ना जी ने मा0 योगी जी की सरकार का बजट रखने का काम किया है, उस पर मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

मान्यवर, बजट में और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि किसानों की आय वर्ष 2022 में दुगुनी होगी। मान्यवर, हमारा देश किसानों का देश है और हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हमारे नेता श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि यदि हिन्दुस्तान को तरक्की करना है तो हमारे किसानों को तरक्की करनी होगी। तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से गया है लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जिस रास्ते से चलने के लिए मा0 चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा थे, उन्होंने जो रास्ता बताया था, खेत और खलिहान का, उस खेत और खलिहान पर आज सांड़ों का राज है। सांड़ हमारी खेती को भी चरते हैं और हमारी जान भी लेते हैं और किसानों की आमदनी दुगुनी नहीं हुई बल्कि किसान बर्बाद और तबाह हुआ है

मा0 नेता सदन द्वारा किसानों के उत्पादन के सम्बन्ध में, किसानों का इतना गेहूँ पैदा हुआ, इतना धान पैदा हुआ और इतना पैसा मिला बताया गया लेकिन मान्यवर, उन्होंने यह नहीं बताने का काम किया कि किसानों को गेहूँ पैदा करने में, धान पैदा करने में और गन्ना पैदा करने में कितनी लागत लगी है यदि लागत का हिसाब किया जाए तो किसानों की आमदनी दुनी नहीं हुई है बल्कि लागत बढ़ी है और किसान बर्बाद और तबाह है। मान्यवर, यह बजट 6 लाख 90 हजार करोड़ से ज्यादा का है लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा वैसे हमारे नेता मा0 अखिलेश जी ने आज ही बजट के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा की है। हम आँकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहते। हमारे वरिष्ठ साथी श्री लालजी वर्मा जी ने बहुत आँकड़े पेश किये हैं। हम आँकड़ों में नहीं जाना चाहते लेकिन आज कुछ विभागों के बारे में हम आपके सामने सदन में रखना चाहते है। इस वर्तमान सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है 'जल जीवन मिशन योजना' जिसके तहत् लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए टंकियों की व्यवस्था की गयी है। टंकियाँ तो 10 साल में बनेंगी लेकिन पानी की जरूरत आज है। और जब आज जरूरत है और जहां-जहां टंकियां बन रही हैं मान्यवर, तो वहां पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं और पाईप जो पड़ रही है वह बड़ी सड़ी-गली है। हम सदन में आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि टंकियां न बनें। मान्यवर, टंकियां बनेंगी तो आपको भी इस बात का अनुभव है कि हमारे क्षेत्र मिल्कीपुर में कई ऐसे गांव हैं जहां पर 25-25, 30-30, 40-40 मजरे हैं। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जो टंकियां बन रही हैं निश्चित तौर से मैं दावे से कह सकता हूँ कि वहां पानी नहीं जायेगा। गर्मी का दिन आ गया है आज लोगों को इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प की जरूरत है, उन्हें लगाया जाय जिससे पानी की समस्या को दूर किया जा सके। इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने की जो योजना है उसे सरकार ने बन्द किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी कल बोलेंगे मैं उनसे मांग करता हूँ कि प्रत्येक क्षेत्र में, कम-से-कम दो-दो सौ इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प दें जिससे गर्मी में पेयजल की जो समस्या आने जा रही है उससे हम निजात पा सकें।

मान्यवर, पी0डब्लू0डी0 का तो बहुत उल्टा हाल है। इस वित्तीय वर्ष के बजट में मार्च का महीना बचा है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने 28.67 परसेन्ट बजट खर्च किया है। इन्होंने गड्ढा मुक्त का नारा दिया था लेकिन इनकी सड़कें आज गड्ढा युक्त हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में अमानीगंज से रूदौली देख लें, रूदौली में सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वहां सड़कों में गड्ढा-गड्ढा ही हैं और अमानीगंज से खण्डासा जाते हुए हमारा जो ब्लाक है, कोटिया, से लेकर खण्डासा ब्लाक और उसके आगे धोड़वल और ईमानगंज, सड़कों पर भी गड्ढा-गड्ढा है। अभी पी0डब्लू0डी0 के राज्य मंत्री जी गये थे, हमने उनको बताने का काम किया था और उन्होंने कहा कि सड़कें सही हो जायेंगी। मान्यवर, इनकी योजना सड़क मरम्मत की है। आज सड़कों के मरम्मत की जरूरत नहीं है आज पी0डब्लू0डी0 विभाग को मरम्मत की जरूरत है तभी हमारी सड़कें अच्छी बनेंगी। गड्ढा मुक्त केवल लीपा-पोती है, भ्रष्टाचार है इससे पैसा खींचा जा रहा है, जब तक हाट-मिक्स प्लाण्ट्स के द्वारा हमारी सड़कें नहीं बनेंगी तब तक सड़कों का रखरखाव, व सड़कों में मजबूती नहीं आयेगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि हाट-मिक्स प्लाण्ट के द्वारा सड़कों का निर्माण करें। मान्यवर, इस बजट में अनुसूचित जाति के लिए 25 फीसदी से कम पैसा खर्च किया गया है। यह सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है, दलित विरोधी इसलिए है कि एस0सी0 उत्पीड़न पर जो पैसा मिलता था इस सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, बागवानी पर एक पैसा नहीं दिया, हमारे अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिली और अनुसूचित जाति जनजाति एवं वित्त विकास निगम में 02 साल हो गया एक पैसा नहीं दिया गया।

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में आश्रम पद्धति विद्यालय है। जब हम समाज कल्याण विभाग के मंत्री थे तो उसे बनवाने का काम किया था, मुगीसपुर में बड़ी शानदार बिल्डिंग बनी है। पिछले दिनों में जब कोरोना काल था तब वहां मरीज भर्ती होते थे। आश्रम पद्धति विद्यालय 08 साल से नहीं चलाया गया। यह सरकार किस तरह का संदेश देना चाहती है। यही नहीं मान्यवर, हमारे क्षेत्र में देवगांव है जहां पर अस्पताल बनकर तैयार है लेकिन 08 साल हो गया वहां पर न तो डॉक्टर भेजा गया न कोई दवा है, पूरी तरह से वहां पर सांड़ों का राज है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में हैरिंग्टनगंज ब्लाक है। सिधौरा में आई0टी0आई0 कालेज की स्थापना हुई है। आई0टी0आई0 कॉलेज हैरिंगटनगंज में चलना चाहिए था लेकिन आज अयोध्या में चल रहा है, अयोध्या में भर्तियाँ हो रही हैं। इस तरह की व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

श्री अधिष्ठाता-

जिला तो आपका ही है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में अमानीगंज ब्लाक बहुत दूर है, वह 50 किमी0 दूर है। तो हम चाहते हैं कि एक ब्लाक डीलीसरैया के पास कर दिया जाये, जिससे लोगों को सुविधा हो।

हमारे क्षेत्र हैरिंगटनगंज में ब्लाक की बिल्डिंग बड़ी जर्जर है। यहाँ पर माननीय मित्रसेन यादव जी, एक संघर्षशील नेता, उनके नाती अंकुर सेन आज ब्लाक प्रमुख हैं। उसके पहले अंकुर सेन की माँ थीं, बिल्डिंग बहुत जर्जर है, कभी भी गिर सकती है। हम माँग करते हैं कि वहाँ का जो हमारा ब्लाक है। उस ब्लाक की बिल्डिंग इसी वित्तीय वर्ष में बनाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय विधायक जी, समय हो गया है, आप बहुत सीनियर है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त कर रहे हैं। मान्यवर, जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, हमारे क्षेत्र में बकचुला है। बकचुला में एक महीने पहले 12 साल के बच्चे को मार दिया गया। उसकी हत्या की गई। यह कानून की बात करते हैं। हमारा क्षेत्र सोहवल, जहाँ से हम सात बार विधायक रहे हैं, वहाँ पर अजनईतारा है, वहाँ पर 10-12 परिवार हैं, पासी बिरादरी के हैं, दलित बिरादरी के, उनके घरों को ढहा दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय विधायक जी 10 मिनट हो गये हैं। अब माननीय विधायक, अपना दल, श्री जय कुमार सिंह जैकी बोलें।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, बस एक मिनट दे दीजिए। हम माँग करते हैं कि जो हमने सुझाव दिये हैं, जो हमने माँगे रखी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन माँगों पर यह सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और माननीय योगी साहब, जो हमारे नेता सदन हैं, इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, हम उनका आदर करते हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जो-जो बातें हमने रखी हैं। उन बातों पर अमल होगा और उसकी घोषणा करेंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

***श्री जय कुमार सिंह जैकी-**

मा0 अधिष्ठाता महोदया, इस सम्मानित सदन में आदरणीय वित्त मंत्री, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के समर्थन में मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । अधिष्ठाता जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री योगी जी एवं अपना दल (सोनेलाल) की राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहन अनुप्रिया पटेल जी के अतुलनीय योगदान बनी सरकार द्वारा 6 लाख 90 हजार के लगभग बजट प्रस्तुत किया गया है। जो पिछले वर्ष की तुलना में 75 हजार करोड़ से ज्यादा है। सभी वर्गों के कल्याण और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के समग्र विकास का खाका खींचा गया है। यह बजट हमारी सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रदेश के गाँव, गरीब, किसान, नौजवान, युवा, खिलाड़ी, महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हित की पूर्ति करने वाला है। इस बजट में कुल 32 हजार 7 सौ 21 करोड़ 96 लाख की नई योजनायें सम्मिलित की गई हैं। जिसमें प्रदेश के युवा, महिला और किसानों का विशेष ध्यान दिया गया है। अधिष्ठाता महोदया, बजट भाषण पर हम लोग दो दिन से विपक्ष की बातें सुन रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस बजट में प्रदेश के लिए कुछ नहीं हैं। अब यह बात समझ में नहीं आ रही कि विपक्ष के साथियों को यह बात कब समझ में आयेगी क्योंकि 6 वर्ष हो गये हैं और 6 साल के कार्यकाल में लगातार दूसरी बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहन अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में, संजय निषाद जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी तो जब जनता के बीच में हमें जनादेश मिला है तो इसका मतलब यह है कि पाँच साल इस सरकार ने जो काम किया है, वह जनता के प्रति समर्पित है और गरीबों के प्रति समर्पित है। वहीं आपका 2012 से लेकर 2017 तक, अभी नेता विरोधी दल द्वारा जिन बातों को कहा जा रहा था।

मान्यवर, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि जिन बातों के लिए लगातार यह बात हो रही थी। इसके बाद जब वर्ष 2017 में चुनाव हुआ तो आपके द्वारा किये हुये कामों का रिजल्ट यह निकला कि सवा 300 विधायक इधर बने और 47 विधायक उधर बने। यह जनता ने आपको तय किया था। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुये अपने जनपद फतेहपुर की कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अध्यक्ष की पीठ पर जनपद फतेहपुर से ही चुनी हुई विधायक आज उस सीट पर है। मैं फतेहपुर की कुछ बातें आपके बीच में कहना चाहता हूँ। जनपद फतेहपुर को बुन्देलखण्ड जनपद से जोड़ा जाये क्योंकि बुन्देलखण्ड की जैसी स्थिति फतेहपुर जनपद की है। जो सूर्य की कर्क रेखा जाती है उसके आधार पर जो गर्मी के समय में मई, जून के आधार पर बुन्देलखण्ड में हाई कोर्ट ने यह माना है कि जब कोर्ट की छुट्टियाँ होती है उसका जो समय निर्धारण होता है। तो उसमें बुन्देलखण्ड की तर्ज में ही फतेहपुर का भी निर्धारण होता है। जो यमुना की पट्टी है उसकी लगातार जैसे बांदा की तरफ है, हमीरपुर की तरफ है उसी तरह से जनपद फतेहपुर का प्रवेश है। इसलिए मै चाहता हूँ कि फतेहपुर को पूर्वांचल से हटा करके बुन्देलखण्ड से जोड़ा जाये। अगर ऐसा होगा तो फतेहपुर जनपद का विकास होगा। हमारे यहाँ चौडगरा से जो बांदा जाने वाला मार्ग है जिससे चित्रकूट जाया जाता है। वह मार्ग बहुत खराब है क्योंकि वह एम0डी0आर0 मार्ग है, जिला मार्ग है उसके कारण वह हमेशा खराब रहता है। हम चाहते हैं कि उसे फोर लेन से बनाया जाये। ताकि आने जाने वाले लोगों को जो लोग चित्रकूट जाते हैं, बांदा जाते है या उस मार्ग से और जगहों पर जाते हैं उनके लिए सुविधा हो। बिन्दकी बाईपास जो 14 बरस से था उसके लिए मैं पी0डब्लू0डी0 के मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि 14 वर्ष से जो समस्या थी थी उसका समाधान जो भूमि का अधिग्रहण था वह अधिग्रहण करा करके भूमि का पैसा देने का काम

किया है। सिंचाई विभाग में जो परधान की कोठी और जोनिहा कोठी है उसका जीर्णोद्धार किया जाये। इसके बाद परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बस अड्डा के लिए 2 करोड़ 88 लाख रुपये दिया है इसके लिए परिवहन मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मेडिकल कॉलेज के लिए आज माननीय अध्यक्ष जी पीठ पर नहीं है उन्होंने मेडिकल कॉलेज को जगह दिलाने के लिए मेरी विधान सभा क्षेत्र में जो काम किया है उसके लिए मैं अध्यक्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी ने जगह दी तो हमारे फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज बना है। नारैचा से टांडा, अमौली विन्द नदी पर पुल बनाने के लिए बहुत आवश्यकता है। जिससे गाँव के लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा रहेगी। खूटा से गड़ी विन्द नदी पर पड़ते है इनके आवागमन में जो हमारे ब्लाक में आने जाने का रास्ता है वह दो भागों में बंटा है अगर यह पुल बना दिया जाये तो उसकी समस्या का समाधान हो जायेगा। हमारे हाई-वे गोपालगंज पर अस्पताल है इसको भी अगर उच्चीकृत कर दिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद एक बात और कहना चाहता हूँ। तमाम बार विपक्ष के द्वारा कानून व्यवस्था की बात आती है। कानून व्यवस्था के लिए जनपद फतेहपुर में आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि फतेहपुर जनपद में यह स्थिति है कि इस समय धर्मान्तरण का प्रकरण बहुत तेजी से फतेहपुर जनपद में चल रहा है। आप सबको जानकारी होगी आज जिन लोगों के ऊपर 72-72 मुकदमें हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे वह कुछ फोटों हैं जिन्हें आज मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज यह स्थिति है कि जिनके साथ (यह फोटो है) 72 मुकदमें हैं और 72 मुकदमें वाले लोग ये हैं, सदन में। फतेह दुर्बधन में लगभग एक लाख गरीबों को धर्मातरण करके ईसाई धर्म कराया गया है। इसको लेकर लगातार अभी जाँचें चल रही हैं। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सरकार इसका संज्ञान ले। जितने मुकदमें लिखाये गये हैं, उनकी जाँचे शुरू हैं, लेकिन चाहता हूँ कि इसकी कोई समिति गठित करके जाँच की जाए, जिसकी बहुत आवश्यकता है। जो स्थिति है, उसके आधार पर कोई न कोई व्यक्ति जाँच को प्रभावित करता है। ये जाँच लम्बे समय से चल रही है। इससे स्थिति धीरे-धीरे खराब होगी, इसलिए इसको संज्ञान में ले करके इसकी शीघ्र कार्रवाई की जाए। मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं एक बात कह कर अपनी वाणी को विराम दूँगा कि ''दुनिया के रैन बसेरे में, पता नहीं कितने दिन रहना है, जीतेंगे सबके दिल को, बस यही हमारी नेता अनुप्रिया पटेल का कहना है।'' धन्यवाद।

मा0 अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण ।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी)-

मान्यवर, मा0 आदरणीय नेता विपक्ष ने आज कहा था कि संकल्प-पत्र किसलिए जारी होता है, जब उस पर अमल नहीं होता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के संकल्प-पत्र में लिखा था कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। ये बात अलग है कि वर्ष

2012 में कोई प्रस्ताव हुआ हो, कि जो आतंकवादी है, उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन वर्ष 2017 में सबसे पहला प्रस्ताव था कि उत्तर प्रदेश के किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये कर्जा माफ किया जायेगा। यह इस बात का सबूत है कि हम संकल्प-पत्र पर अमल करते हैं।

मान्यवर, किसानों के बारे में मैं थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डालूँगा। उन्होंने किसानों के बारे में, एग्रीकल्चर ग्रोथ के बारें में कही थी। मान्यवर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिसिंग, ये तीनों की ग्रोथ रेट वर्ष 2013-14 में 11.7, 2014-15 में 3.0, 2015-16 में 11.1 और 2021-22 में 16.4 है। मान्यवर, मैंने एक बात देखी कि हमारे विपक्ष के जितने भी साथी हैं, उन्हें सांड़ों का डर बहुत सता रहा है। वे इतने परेशान हैं कि भगवान जानें, उन्हें रात को नींद आती है या नहीं आती। आदरणीय पाण्डेय जी से अनुरोध करूँगा और मुझे मालूम है कि आप शास्त्र भी देखते हैं। सतयुग से लेकर, त्रेता से लेकर द्वापर तक कभी किसी राजा ने, कभी किसी शासक ने राजकोष से गौ-पालन के लिए पैसा खर्च नहीं किया। पूरी दुनिया में या यूँ कहें कि ये उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपये गौ-पालन के लिए खर्च किया है। मान्यवर, आज हमारी गौ-शालाओं में चार प्रकार की व्यवस्था है। स्थायी गौ-शाला, वृहद् गौ-आश्रय स्थल, कान्हा गौ-शाला और कांजी हाऊस है। इनमें 10 लाख 88 हजार 5 सौ 10 गऊ और सांड़ रह रहे हैं।

मान्यवर, जो अपनी माँ की जय न बोल सके क्या वो सपूत होगा । ये भारत माता, गऊ, गंगा और गीता की देन है, जहाँ इनकी पूजा होती है। जो इनकी पूजा न कर सके क्या वह भारत माता का सपूत हो सकता है। मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि संस्कृति को मत भूलो। इस भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा यदि किसी नीति को प्राथमिकता दी गयी है तो वह चाणक्य नीति को दी गयी है। चाणक्य ने भी कहा था कि किसी भी राष्ट्र की सफलतम राजनीति वह है जिसमें धर्म का प्रवेश होगा। बिना धर्म के राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। मैं यह नहीं कह रहा हूं। हमारे धर्म की तो व्याख्या की गयी है।

''परहित सरिस धरम नहिं भाई।
पर पीड़ा सम नहिं अधमाई''।।

अनेक हमारी परिभाषाएं हुयी हैं, लेकिन आलोचना के तौर कोई भी बात कहना, अब दिक्कत क्या हो रही है कि जो भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। भारतीय संस्कृति में कभी भी हवन पूजा बिना धोती पहने हो ही नहीं सकता है, मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं। मैं उस समय मंत्री था और जब मैं ऐसे ही इन कपड़ों में काशी गया, तो मै बाबा विश्वनाथ की पूजा नहीं कर पाया और इसके बाद जब मैं धोती बांध कर आया तब पूजा की। अब इस पर कोई नाराज हो जाये कि मुझे हवन पर नहीं बैठने दिया, मुझे पूजा नहीं करने दी और यह कह दिया कि धोती नहीं पहन रखी। धोती पहनी जाती है उसका पालन करना चाहिए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आदरणीय नेता विपक्ष ने बड़ी अजीब सी बात कही, उन्होंने कहा कि नेता सदन का वृक्षों से कोई लगाव ही नहीं है, पेड़-पौधों से कोई मतलब ही नहीं है। पूरी दुनिया में गिनीज बुक में लिखा जा रहा कि भारतवर्ष में मात्र 5 साल में 56 करोड़ 44 लाख 33124 पौधे लगे हैं। वह कह रहे हैं कि पेड़ों से लगाव ही नहीं है। क्योंकि नेता जी धरती पुत्र कहे जाते थे, हमने भी उनके नेतृत्व में काम किया है अब यह उनके पुत्र हैं इनके बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, ये कभी इंजीनियरिंग की बात कर देते हैं और कभी अंग्रेजी की बात कर देते हैं। यदि वह जनेऊ वाले नेता होते तो मैं उनसे यह कह देता कि उनको गाय, भैंस का अन्तर पता नहीं है, लेकिन अब मैं उनसे यह भी नहीं कह सकता हूँ । मान्यवर, एक बड़ी टिप्पणी भी की और बहस भी हुयी शूद्र के ऊपर, बात शूद्र के ऊपर चली इसमें किसी को कोई मतभेद है नहीं कि भारत की पहचान भगवान श्री कृष्ण की वजह से है, इसमें भी कहीं कोई मतभेद नहीं है कि गीता का सम्मान पूरे विश्व में हर धर्म का व्यक्ति करता है और जिस जाति गणना की वह बात करते हैं, उस जाति वाले ने जो कहा उसका तो पालन करो, जिसकी वजह से तुम जाने जाते हो। ''ताहि अहीर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे'' उसका तो पालन कर लो उसने क्या कहा है। श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में कहा है-

''ब्राम्हणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वाभावप्रभवैर्गुणै।''

हे परन्तप ! ब्राम्हण, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है, जन्म के द्वारा नहीं किया जाता। आदरणीय योगी जी ने यही तो कहा था, देखिये जन्म के द्वारा कोई शूद्र नहीं होता है, कर्म के द्वारा होता है। अब इसके बावजूद कोई 'भगवद् गीता' को न माने। हजारों किमी0 दूर अमेरिका और इंग्लैंड से आकर, धोती बाँधकर जिस गीता का लोग वृन्दावन और हरिद्वार में अध्ययन कर रहे हैं, अब उस 'गीता' को भी यदि कोई न माने तो इसके बाद मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आदरणीय योगी जी ने यह बात कही थी कि जिन-जिन का जो कर्म है, वह कर्म के अनुसार तय होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने गीता के अट्ठारहवें अध्याय के चौवालिसवें श्लोक में कहा है कि-

कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्।
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्।।

कृषि करना, गो-रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। मैं यदि सेवा करूँगा, श्रम करूँगा तो मैं भी शूद्र होऊँगा । कर्म के अनुसार ही तय होना है, जो आज से 5000 वर्ष पहले गीता में कह दिया गया है, जिसको पूरी दुनिया मान रही है। यही हमारे भारत की संस्कृति है ।

आदरणीय वर्मा जी इस कागज को आपके पास भेजूँगा । मान्यवर, अन्त में मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा-

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।।

अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म का यदि पालन करोगो तो नर्क के गामी बनोगे...

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

'गीता' में साफ-साफ कहा गया है कि अपने धर्म में यदि कोई कमी भी है तो उस कमी को सुधार करो। लेकिन अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म की बात मत करो। अरे! अब तो समझ जाओ। इस धर्म के नाम पर तुमने अयोध्या में सरयू का पानी लाल कर दिया, इस धर्म के नाम पर मुजफ्फरनगर में आपने क्या कर दिया ? इस धर्म के नाम पर आपने और दूसरी जगहों पर क्या कर दिया ?

(शेम-शेम की आवाजें आयीं।)

जब आप इनमें सफल नहीं हो पाये तो अब जाति पर आ गये। अरे ! हमारी जाति किसान है। किसी भी किसान का गेहूँ 5 हजार रुपये क्विंटल समाजवादी सरकार में नहीं बिका, किसी मजदूर को 5 हजार रुपये रोजाना मजदूरी समाजवादी सरकार में नहीं मिली। हम किसान सब एक हैं, मजदूर सब एक हैं। किसान और मजदूर की बात करिये। मैं इसलिए अनुरोध करना चाहता हूँ। आदरणीय वर्मा जी से कि मेरी बात जरूर पहुँचा दें और इन कागजों को जरूर पहुँचा दें कि अपने धर्म का त्याग करना उचित नहीं होता, पाप होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सुरेश कुमार-

माननीया अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2023-2024 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी विपक्ष की तरफ से किसानों के लिए बहुत बातें की गयीं, आरोप भी लगाया गया भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन जबसे देश और प्रदेश में भा0ज0पा0 की सरकार बनी, किसानों को सम्मान निधि के रूप में 6000 रु0 वर्ष में दिये जा रहे हैं। गन्ना भुगतान 2017 से अब तक 01 लाख 96 हजार करोड़ का किया गया तथा धान का समर्थन मूल्य 2040 रु0 तथा गेहूँ का समर्थन मूल्य 2060 रुपये दिया गया। किसानों को सिंचाई के लिए अब बिजली की मुफ्त व्यवस्था की गयी है। कृषक दुर्घटना बीमा के लिए 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है। किसी भी किसान को अगर कोई जन्तू काट ले या किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाये तो उसको 05 लाख रुपये दिये जाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह किसानों के हित की सरकार है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, माननीय योगी जी ने तय किया है कि-

जो श्रम से माटी की रज को, सोना, चाँदी कर देता,
इन खेत-खलिहानों को, बहुमूल्य अन्न से भर देता।
सौगन्ध है अब चोटी से गिरते हुए पसीने की,
अब असमय धड़कन बन्द नहीं होगी किसान के सीने की।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहे हैं। अटल इरादा पूर्ण विश्वास वंचित को मिल रहा है पक्का आवास। इज्जत घर भी गरीबों को मिल रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 33.50 लाख करोड़ रु0 का एम0ओ0यू0 हुआ इससे प्रदेश की जी0डी0पी0 भी बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। नौकरी की बात यह लोग कर रहे थे जब पिछली सरकार में नौकरी की बात होती थी चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे शिक्षक की भर्ती हो, चाहे लेखपाल की भर्ती हो या अन्य कोई भर्ती हो, जैसे भर्ती निकलती थी इनके लोग जिले-जिले में झोला लेकर वसूली करने के लिए टहलने लगते थे, इन्होंने समय को नहीं समझा, समय की मांग थी, वक्त की मांग थी, भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती हो वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा क्यों न कितनी ही बड़ी हो क्यों न कितनी ही कठिन हो हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा, इसलिए जनता ने इन्हें हटा दिया। जी-20 की मेजबानी भारत को मिली है यह बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में इसकी 11 बैठकें होगी जिसमें लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोयडा चयनित किया गया है यह हम सबके लिए बड़े ही गौरव की बात है। कन्या विवाह के लिए छह सौ करोड़ रु0 का बजट प्रस्तावित है। जब गरीब के जेब में पैसा नहीं होता तो मन में हौसला नही होता वह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से नहीं कर पाता था। आज जबसे यू0पी0 में भाजपा की सरकार बनी है मा0 योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में गरीब भी अपनी बेटी की शादी धूमधाम के साथ और खुशियों के साथ कर रहा है। 3 महिला बटालियन का भी गठन हो रहा है। ओ0डी0ओ0पी0 की जब बात चल रही थी तो पैंतीस हजार लोगों को अब तक रोजगार मिला और हर जिले की अलग पहचान हुई।

यह लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं मा0 योगी जी की कानून व्यवस्था जगजाहिर है। गुंडे आज जो गले में तख्ती टांग कर घूम रहें है त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो अब गुंडागर्दी नहीं करेंगे। इसका परिणाम अभी कल इलाहाबाद में आ गया है। सपा के राज में झील पर पानी बरसता था। उत्तर प्रदेश में कौन कहता है खेत में पानी बरसता था उत्तर प्रदेश में सपा के गुंडे, माफियाओं के अलावा कोई हँसता नहीं था उत्तर प्रदेश में। इन्हीं के लोग कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। मा0 योगी जी के नेतृत्व में जमीन भी खाली हुई और उनपर कार्रवाई भी हुई। आयुष्मान भारत की बात जब होती है तो पांच लाख रु0 तक का गरीब को इलाज कराने के लिए परिवार को मुफ्त में मिलता है। यह बहुत बड़ी बात है जब हम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो जो डाक्टरों की कमी थी हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और डाक्टर की कमियों की भी पूर्ति होगी। विद्युत व्यवस्था की बात जिला मुख्यालय को 24 घण्टे, तहसील को 22 घण्टे, और गांव को भी 18 घण्टे बिजली मिल रही है नहीं तो कब बिजली आती थी कब बिजली जाती थी इसका पता नहीं चलता था। यह अनुसूचित जाति की हितैषी की बात करते हैं, यह कतई अनुसूचित जाति के हितैषी नहीं हैं और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नौ सौ बासठ करोड़ रु0

की व्यवस्था छात्रवृत्ति के लिए इस बजट में की गई है। प्रतिभावान छात्रों के लिए देश में पढ़ने के लिए दस लाख रु0 और विदेश में पढ़ने के लिए 20 लाख रु0 की बगैर गारण्टी के लोन की व्यवस्था की गई है। आई0टी0आई0 में मुफ्त शिक्षा अनुसूचित जाति के बच्चों को पचास प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। बाबा साहब ने कहा था जब समाज का अंतिम व्यक्ति उच्च कुर्सी पर बैठ जाय तो समझ लेना कि असली लोकतंत्र आ गया है। राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाने का काम अगर किसी ने अनुसूचित जाति को किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब का मिशन अधूरा भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरा, बाबा साहब के पंच तीर्थ स्थल भी बना कर अनुसूचित जाति का गौरव बढ़ाने का काम भी किया है। शिक्षा भूमि लंदन में जहां पर बाबा साहब ने शिक्षा ली थी वहां पर भी हॉस्टल बनाने का काम किया है। संकल्प भूमि बड़ौदा, दीक्षा भूमि नागपुर, समाधि स्थल महाराष्ट्र, नागपुर चिचोली, सपा ने दलितों के साथ बहुत दगा किया है मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि दगा किसी का सगा नहीं न मानो तो करके देखो और जिसने-जिसने दगा किया है उसके घर जाकर देखो।

मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के लिए कुछ मांग आपके माध्यम से करता हूँ कि हमारी विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर में तहसील नहीं है वहां पर तहसील बनाने की व्यवस्था हो, जगदीशपुर को नगर पंचायत बनाने की व्यवस्था हो, जगदीशपुर में भाले सुल्तान चौकी है उसको थाना बनाने की व्यवस्था हो । इन्हौना से बाजार शुक्ल होते हुए रीछ धात्र तक सड़क उच्चीकरण एवं चौडीकरण हो।

मान्यवर, हलियापुर को ब्लाक बनाये जाने की मैं मांग करता हूँ। हमारी विधान सभा क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे इंटरनेशनल मण्डी तथा इण्डस्ट्रियल एरिया बनाये जाने की व्यवस्था की जाये। इसके अतिरिक्त जामो ब्लाक में बालिका डिग्री कॉलेज तथा इण्टर कॉलेज बनाया जाये। बाजार शुकुल को नगर पंचायत बनाये जाने के साथ ही वहाँ पर बालिका डिग्री कॉलेज तथा इण्टर कॉलेज बनाये जाने की व्यवस्था की जाये। हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम करती है तो पहले भारत माता की जय बोलती है। श्रद्धेय अटल जी की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अटल जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। यह जीता-जागता राष्ट्रपुरुष है, हिमालय इसका मस्तक है, गौरीशंकर इसकी शिखा है। पावस के काले-काले मेघ इसके कुंतल केश हैं। पंजाब और बंगाल इसकी दो विशाल भुजायें हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो इसकी जंघाए हैं सूरज और चांद इसकी आरती उतारते हैं। यह वन्दन की भूमि है। यह अभिनन्दन की भूमि है। इसका बिन्दु-बिन्दु गंगाजल है। इसका कंण-कंण शंकर है। हम जियेंगे तो इसके लिये और हम मरेंगे तो इसके लिये और मरने के बाद जब मेरी अस्थियाँ गंगा जी में प्रवाहित की जायेंगी, उनमें कोई कान लगाकर सुनेगा तब भी एक ही आवाज आयेगी 'भारत माता की जय, भारत माता की जय'। धन्यवाद।

मा0 अधिष्ठाता-

मा0 विधायक श्री शहजिल इस्लाम अंसारी जी ।

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। अभी इससे पहले इस सदन में मा0 गन्ना मंत्री जी गन्ना किसानों को ले करके चर्चा कर रहे थे। जो बजट आया है उसमें गन्ना किसानों के लिये कुछ भी नहीं है, जबकि तकरीबन 07 लाख करोड़ का यह बजट है और मेरे ख्याल से पिछला बजट तकरीबन सवा छः लाख करोड़ का बजट था, लेकिन उसके बावजूद भी गन्ना किसानों को निराशा ही हाथ लगी है। आप लोग खुद कहते हैं कि यह डबल इंजन की सरकार है। पिछले दिनों मैंने एक प्रश्न भी उठाया था कि क्या आपको केन्द्र सरकार से कुछ अनुदान मिला है तो जवाब आया था कि अनुदान नहीं मिला है। आपकी तो डबल इंजन की सरकार है तो अगर आप चाहें तो किसानों के हितों के लिये, किसानों के भुगतान के लिये आप केन्द्र सरकार से अनुदान ले सकते थे, लेकिन आपने कोई अनुदान नहीं लिया। यह दर्शाता है कि आप लोग किसानों को ले करके कितने हितैषी हैं। मान्यवर, मा0 मंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गन्ना विकास और चीनी उद्योग के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश में 119 चीनी मिलों पर 09 हजार 144 करोड़ रुपया बकाया है जिसमें पिछले वर्ष की 699.47 करोड़ रुपये की धनराशि भी शामिल है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है। गन्ने तथा चीनी उत्पादन का स्तर भी लगातार गिरता चला जा रहा है। अगर आप देखें तो वर्ष 2019-2020 में 1118.20 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करके 126.37 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया था। इसी प्रकार से वर्ष 2020-21 में गन्ने की मात्रा घटकर 1027.50 लाख क्विंटल रह गयी और चीनी का उत्पादन घटकर 110.59 लाख क्विंटल रह गया। इसी प्रकार से वर्ष 2021-2022 में गन्ने की कुल पेराई 1016.26 लाख क्विंटल हुयी, जबकि चीनी का उत्पादन 101.98 लाख क्विंटल रह गया।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब गन्ना किसानों का भुगतान ही नहीं हो पा रहा है तो इसकी वजह से लोगों ने गन्ना लगाना ही कम कर दिया है। कहीं दूर मत जाइये, मा0 विधायक जी भदोही से ही आते हैं। मा0 मंत्री जी भदोही गये थे, वहाँ पर औराई चीनी मिल जो बन्द हो गयी थी, वहाँ पर घोषणा करके आये थे कि हम लोग यह चीनी मिल शुरू करायेंगे, लेकिन वह चीनी मिल शुरू नहीं हो पायी और वहाँ के लोगों ने गन्ना उगाना भी बन्द कर दिया। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह सरकार किसानों के प्रति कितनी सचेत है। वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक आपकी सरकार में गन्ने का मूल्य सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये क्विंटल बढ़ा था।

मा0 गन्ना मंत्री जी बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि आप भी किसान परिवार से आते हैं और आपके यहां भी लोग गन्ने की खेती करते हैं। अभी आपने कहा कि विपक्ष के लोगों को सांड़ों की बहुत चिन्ता है, सांड़ इन्हीं को परेशान कर रहे हैं। मैं मा0 मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष का कोई सदस्य हो या विपक्ष का कोई सदस्य हो सांड़ सबको परेशान कर रहे हैं फर्क बस इतना है कि सत्ता पक्ष के जो हमारे मा0 सदस्य हैं वह अपनी पीड़ा जगजाहिर नहीं कर सकते हैं। जब यह लोग क्षेत्र में जाते हैं तो गन्ना किसान सांड़ की बात करते हैं, लेकिन यह लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर आप लोगों की सरकार है। मेरे क्षेत्र में एक सेमीखेड़ा सहकारी चीनी मिल है वहां पर गन्ना किसानों का 40 प्रतिशत भुगतान रह गया है। इसी तरह से किसान सहकारी चीनी मिल शाहजहांपुर के अन्दर तिलहर है, वहां के गन्ना किसानों का भी 40 प्रतिशत भुगतान रह गया है। हमारी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मीरगंज की एक चीनी मिल है वहां पर भी गन्ना किसानों का 50 प्रतिशत भुगतान रह गया है। इस सम्बन्ध में सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है कि 14 दिन के अन्दर आप गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे मैं जानना चाहता हूँ कि अगर 14 दिन के अन्दर भुगतान नहीं होता है तो क्या 18 प्रतिशत ब्याज सहित पैसा वापस किया जायेगा या नहीं किया जायेगा ? आज आप देख रहे होंगे कि महंगाई चरम सीमा पर है और गन्ने का रेट 350 रुपये प्रति कुन्टल है एवं डीजल एवं कीटनाशक दवाइयों में उछाल आ गया है, बीज की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपको पी0डब्ल्यू0डी0 के बारे में भी बताना चाहता हूँ।

मा0 अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आपके पाँच मिनट समाप्त हो गये हैं।

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात तो कर लूँ जहां से मैं चुनकर आता हूँ। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे चुनकर इस सदन में भेजा है। नैनीताल स्टेट हाई-वे पर हमारा एक दोहरा टांडा कस्बा है जहां पर सबसे बड़ी राईस मिलें हैं। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि इण्डस्ट्रीज लेकर आएंगे 35 लाख करोड़ रुपये के एम0ओ0यू0 साइन हुए हैं जो इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं उनको आप बचा लीजिए, क्योंकि प्रदेश का विकास तभी सम्भव है जब उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब उसकी रोड अच्छी होगी, जब उसकी बिजली अच्छी होगी, लेकिन वहां के इण्डस्ट्रीज आपको रेवेन्यू देते हैं वहां से आपके राजस्व विभाग को बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त होती है, 100 प्रतिशत बिजली के बिलों का भुगतान रहता है। धौरा टांडा में जो राइस मिलें हैं वहां का चावल देश विदेश में जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि धौरा टांडा की तरफ भी ध्यान रखें।

मा0 अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य 7 मिनट हो गये हैं अब आप समाप्त करें। सभी को बोलना है, अभी हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है।

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, सरकार ने बरेली के अन्दर एम्स की स्थापना करने का वादा किया था। बरेली के अन्दर एम्स की स्थापना करने के लिए सैकड़ों एकड़ भूमि पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक वहां पर एम्स की कोई भी शुरूआत नहीं हो पायी है। इसी प्रकार से हमारी भोजीपुरा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, बिलवा में कृषि विभाग की सैकड़ों एकड़ भूमि पड़ी हुई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर कृषि विश्वविद्यालय बनवाया जाय।

मा0 अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारी बात सुन ली जाय। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो प्रदेश का विकास कैसे होगा ? हम लोग यहां पर किसलिए चुनकर आते हैं ? हम विपक्ष में बैठे हैं अगर हम अपनी पीड़ा यहां नहीं सुनायेंगे तो किसको सुनायेंगे ? हम लोगों को स्मार्ट सिटी के नाम पर ठगा जा रहा है।

मा0 अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अब आप बैठ जायें अभी दोनों पक्षों के बहुत से मा0 सदस्य बोलने के लिए बैठे हैं। आपकी बात आ गयी है।

(श्री शहजिल इस्लाम अंसारी माइक बन्द होने के बाद भी लगातार बोलते रहे)

श्री सुशील सिंह-

माननीय अधिष्ठता महोदय, आपने इस बजट सत्र पर आदरणीय योगी महराज जी व वित्त मंत्री जी को बधाई, मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आज जो विपक्ष में लोग बैठे हैं और हम भी सत्र में कई दिनों से यह देख रहे थे कि बजट सत्र में ऐसी-ऐसी बातें आईं जिन्हें सुनने में भी अचम्भा जैसा लगता है। बात करते हैं पहले की सरकारों की जो किसानों की रहनुमा बनती हैं, उसका जिक्र भी आज माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने किया था। जहां मैं रहता हूँ कपसेटी से बाबतपुर सड़क जो वाराणसी में पड़ती है। यह जरूर है कि उन्होंने उस सड़क का शिलान्यास किया था। लेकिन दुःख की बात है कि किसानों का मुआवजा एक रुपये भी उस सरकार द्वारा नहीं दिया गया। ये किसानों के हितैषी बनते हैं। किसान ने आन्दोलन किये। खैर किसानों नें उनको 2017 में जवाब भी दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आदरणीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हुए। मैं सेवापुरी विधान सभा क्षेत्र में रहता हूँ जो कपसेटी में पड़ता है। बगल में

तीन किलोमीटर की दूरी के बाद पिण्डरा पड़ता है जो बाबतपुर विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। ढाई सौ करोड़ रुपये, माननीय विधायक जी, हमारे अवधेश सिंह जी हैं हम लोगों ने निवेदन किया और महाराज जी ने ढाई सौ करोड़ रुपये मुआवजा किसानों को देने का काम किया और यह किसानों के हितैषी बनते हैं। वहीं पर जिस सड़क की बात उन्होंने की, शिलान्यास किया, उस सड़क पर आर0ओ0बी0 हमारी सरकार ने दिया। हम लोग कपसेठी से बाबतपुर जाते हैं 15 से 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ अपनी विधान सभा व चन्दौली जनपद की। वहां पर पण्डित कमलापति त्रिपाठी जी जिनके बारे में हमें लगता है कि यहां पर तमाम सीनियर सदस्यगण होंगे, सभी लोग जानते होंगे। जो मुख्य मंत्री भी रहे। चन्दौली के लिए उन्होंने बहुत विकास किया और भी सरकारें आई, लेकिन जब-जब भाजपा की सरकारें आईं। चाहे हमारे मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह जी हुए या कल्याण सिंह जी हुए। उन्होंने जनपद चन्दौली में लिफ्ट कैनाल सिंचाई के लिए किसानों को जो पूर्व की सरकारों ने दिये होंगे, उसको रिमॉडलिंग और अच्छा कराने का काम किया। लेकिन बीच में जब और सरकारें आईं जब बसपा, सपा की सरकारें रहीं। उन लोगों ने किसानों के हित के बारे में सोचने का काम नहीं किया। अभी हमारी सरकार ने 100 करोड़ रुपये देकर नारायणपुर पम्प कैनाल को अच्छा करने का काम किया जिस पर काम तेजी से चल रहा है। हमारे क्षेत्र में कई लिफ्ट कैनालें मिली हैं जिन्हें हमारे आदरणीय योगी जी महाराज ने दिया है।

सबसे बड़ा विषय श्री अवधेश प्रसाद जी, सीनियर विधायक जी कुछ कह रहे थे। मैं सुन रहा था और बहुत अजीब लग रहा था कि किसानों की फसल का दुगुना दाम है। वह किसान है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं किसान हूँ और मैं खुद खेती करवाता हूं। मैं विपक्ष के लोगों को चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूँ कि चन्दौली चलें। किसानों का बहुत बड़ा क्षेत्र है चन्दौली जिसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। ब्लैक राइस जो देश के बाहर भेजा जाता है, चन्दौली से विदेशों में भेजा जाता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे चन्दौली आयें और देखें कि किसान दुगुना नहीं पांच गुना कमाने का काम करता है। यह मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं। आप तो सिर्फ बनाई हुई बातें कहते हैं। हमारी सरकार ने किसान सम्मान की योजना दी। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के आशीर्वाद से 6000 रुपये आज किसानों को मिल रहा है। हो सकता है कि जो बड़े किसान हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है लेकिन छोटे किसानों के लिए 6000 रुपये बहुत होता है। आपने कभी उनके दुख-दर्द को नहीं समझा। किसानों का 36 हजार करोड़ ऋण हमारी आदरणीय योगी जी की सरकार ने माफ किया। आप किसानों के हितैषी बनते हैं, रहनुमा बनते हैं। हमेशा धरना-प्रदर्शन करने लगते हैं। आपकी सरकार थी, आपने क्या किया ? आदरणीय मुलायम सिंह जी की भी सरकार थी, उन्होंने किसानों के बारे में कितना काम किया ? और पूर्व मुख्यमन्त्री जी किसानों के रहनुमा बनते बड़ा दुख होता है। मैं चन्दौली की बात करना चाहता हूँ और विकास की गति को बताना चाहता हूँ। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 से अब तक 6 साल में कितना विकास हुआ ?

मान्यवर, आदरणीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से मेरी विधान सभा क्षेत्र में बाबा किनाराम मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है और मेड़िकल कॉलेज बनने को बाद आप सभी जानते होंगे कि अगल-बगल जनपद के लोगों का भी लाभ होता है और पास में ही बिहार सटा हुआ है उसको भी लाभ होगा। किसानों के हित के बारे में बताना चाहता हूँ इंडो इजराइल तकनीक से सब्जी अनुसंधान केन्द्र बन रहा है, हमें लगता है उत्तर प्रदेश में दो या तीन ही जनपदों में ही होगा। इजराइल के माध्यम से इंडो इजराइल तकनीकि के साथ हमारी सरकार हमारी विधान सभा क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र खोल रही है, जिसमें दस करोड़ की लागत से वह वहां पर बन रहा है और हमारे उस जगह के किसान सब्जी बोयेंगे इंडो इजराइल के माध्यम से और क्या आप जानते हैं इंडो इजराइल के बारे में आप सभी ने सुना होगा। पूर्व मुख्य मंत्री जी बार-बार यही कहते हैं कि महाराज जी विदेश नहीं गये हैं, लेकिन आप तो गये होंगे तो इजराइल के बारे में पता करिए कि वहां जमीन कम है तो वह सब्जी कैसे पैदा करते होंगे और हमारे मुख्य मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में दिया और यह विकास लोगों को दिखाई नहीं देता है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे कि हम सड़क की बात कर लें तो हमारे जनपद में 400 करोड़ रुपये की सड़क बन रही है। दूसरी सड़क भी 500 करोड़ की लागत से बन रही है। पंडित दीनदयाल से मुगलसराय तक और सैदपुर से चन्दौली तक लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से सड़क बन रही है और इन्हें विकास नहीं दिखायी देता है। आइये हमारी विधान सभा क्षेत्र में देख लीजिए सड़कों का जाल बिछा पड़ा है। हो सकता है कहीं सड़कें खराब हो तो मैं नहीं कह सकता लेकिन आकर देखिए अगर आपको देखना है तो, आप तो बुराई करते है जैसे कि आप धर्म की बात करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपनी आदरणीय योगी जी की सरकार से कुछ और भी काम है जिसको हम चाहते हैं और हमने वर्ष 2022 के चुनाव में अपनी जनता से वादा किया था कि हमारे क्षेत्र में जो हमारा धानापुर पड़ता है सकलडीहा तहसील पड़ती है वहां लगभग 132 राजस्व गांव है और तहसीलों में 50 से 60 गांव ही आते हैं लेकिन सकलडीहा में 132 राजस्व गांव में है हमने शासन में दे रखा है अगर वह भी बजट में शामिल कर ले, और एक पैन्टून पुल जो गाजीपुर व चंदौली से जोड़ने का काम करता है, जो गाजीपुर व चन्दौली के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, तो उस पुल को आदरणीय योगी जी ने दिया था, पक्का बनाने का निवेदन अपनी सरकार से है। किसानों से सम्बन्धित मामला है हमारा क्षेत्र गाजीपुर से सटा हुआ है और हमारे क्षेत्र में बिजली गाजीपुर से आती है और जो काफी दूर पड़ जाता है और बार-बार ट्रिपिंग हो जाती है उसके लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि 132 के0वी0 का सबस्टेशन हमारी विधान सभा क्षेत्र में स्थापित किया जाये। वर्ष 2012 से पहले हमने धानापुर में 132 के0वी0 लगवाया था यह दूसरा 132 के0वी0 और मिल जायेगा तो क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।

आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु')-

अधिष्ठाता महोदय, आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ उनके परम सहयोगी जिनकी विद्वता और अनुभव को लेकर शायद ही इस विधान सभा में किसी को कोई शक हो आज पूरा सदन इस बजट से बहुत ही खुश है। आपका ध्यान एक विशेष बात पर आकर्षित करना चाहता हूँ मैं आयुष का मंत्री हूँ और 9 नवम्बर, 2014 को जब केंद्र में काशी के यशस्वी सांसद मा0 नरेन्द्र मोदी जी ने जब केन्द्र में सरकार बनी तो पहली बार देश में आयुष मंत्रालय बना, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था कि प्रदेश में उस समय माननीय अखिलेश जी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में आयुष का मंत्रालय नहीं बनाया गया। वर्ष 2017 में जब माननीय योगी जी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में पहली बार आयुष मंत्रालय बना। आयुष का मतलब आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी होता है । इन विधाओं को लेकर इस मंत्रालय का गठन हुआ। भगवान धनवन्तरी जिनको आयुर्वेद का भगवान माना जाता है, उनके मानवीय अवतार काशी नरेश के रूप में 'दिवोदास' जी को माना जाता है, महर्षि सुश्रुत जिनको दुनिया फादर ऑफ सर्जरी कहती है वह दिवोदास जी के शिष्य हुआ करते थे और महर्षि पतंजलि जिनका जन्म गोण्डा में जरूर हुआ और दुनिया जिनको योग का अधिष्ठाता मानती है उन सबकी नगरी काशी है। काशी ने उन दिनों को भी देखा है कि जब मोहन सराय से लेकर रामनगर को जोड़ने वाला 18 किलोमीटर का यह बाईपास 18 वर्षों में बन पाया था। रामनगर को काशी से जोड़ने वाला एक पुल 15 साल तक अपने उद्घाटन की बाट जोहता रहा। हम अपने यशस्वी मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि पिछली बार जब हमारी सरकार बनी तो आठ महीने में रामनगर का वह पुल बन गया, जिस रामनगर में काशी नरेश रहते हैं, उसको जोड़ने का काम हुआ। एक अजीब बात है कि सपा के लोगों को कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता उनको सिर्फ अपने किये गये काम दिखाई देते हैं। जैसे अगर किसी की आँख की रोशनी सावन में चली जाये तो हमेशा उसको हरा दिखाई देता है। मैं सपा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अरे कुछ तो अच्छा देखना स्वीकार करिये। इनके बारे में कहना चाहता हूँ कि-

'गम से हो दूर, बहुत दूर तुम्हे क्या मालूम,
कैसे जीते है मजबूर तुम्हे क्या मालूम,
जुगनू बन-बनकर अंधेरे में चमकने वालों,
किसकी दुनियां हुई बेनूर तुम्हें क्या मालूम।

आपकी सत्ता को हम सबने बड़े करीब से देखा है। आप लोग ओ0डी0ओ0पी0 का भी मजाक उड़ाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी जब दुनिया के किसी देश में जाते हैं और काशी की मीनाकारी का सामान वहां के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट करते हैं, तो काशी के लोगों का सीना गर्व

से चौड़ा हो जाता है। लकड़ी के खिलौने, सुहाग का प्रतीक बनारसी साड़ी, बनारसी पान, हमारे बनारस के नौ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको ओ0डी0ओ0पी0 में मान्यता मिली है। उत्तर प्रदेश से 90 जी0आई0 टैग हो चुके हैं जिनमें अकेले 09 वाराणसी से हैं।

मैं आपको इसलिये बता रहा हूँ कि काशी में आज दो-दो कैंसर के हास्पिटल हैं। वाराणसी के बारे में बहुत सारे लोग आपको बतायेंगे कि वहां रिंग रोड है, टी0एफ0सी0 है, जहां दुनिया के लोग अपने सामानों की प्रदर्शनी लगाते हैं। काशी को बहुत सारी चीजें मिली हैं। जिस तरीके से माननीय योगी जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को सारे संसार में मान्यता दिलाई गई है वह अद्भुत है। जब न्यूयार्क के टाइम्स स्क्वायर, लंदन की बिग बेन घड़ी के नीचे और फ्रांस के एफिल टावर के नीचे जब हम विदेशियों को योग करते हुए देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। विश्व योग दिवस पर योग करने का हिन्दुस्तान का लक्ष्य 25 करोड़ का था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 05 करोड़ लोगों ने योग किया, जिसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स को सारे संसार में मान्यता दिलाने का काम किया है। मिलट्स मतलब ज्वार, बाजरा, सावां, कोदो, रागी से है। भगवान श्री कृष्ण के सामने जब उनके मित्र सुदामा मिलने जा रहे थे तो उनके सामने संकट था कि राजा के सामने उनके मित्र क्या लेकर जायें। आपको याद होगा कि वह एक छोटी सी सांवा की पोटली लेकर गये थे। लेकिन अब किसी सुदामा को कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि यही मिलेट्स दुनिया के लिए खाद्य आहार बनने जा रहा है और 2023 को भी सारे विश्व ने विश्व मिलेट्स इयर घोषित किया है। हम उसके लिए भी बधाई देना चाहते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं मा0 श्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने इको टूरिज्म बोर्ड बनाया है। जिसमें आयुष भी हैं, जिसमें टूरिज्म के लोग हैं। महोदया, पहली जनवरी की सुबह जब काशी के लोगों ने देखा कि मात्र तीन दिनों में साढ़े तीन लाख लोगों ने जनवरी के पहले सप्ताह में बाबा विश्वनाथ के उस भव्य कॉरीडोर का दर्शन किया। महाशिवरात्रि पर काशी में सात लाख लोगों ने एक दिन में बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है। अब उत्तर प्रदेश के लोग उस दिन का इन्तजार कर रहे हैं जिस दिन अयोध्या में भगवान श्रीराम का मंदिर बनेगा उसके बाद मुझको लगता है कि दुनिया में टूरिज्म के लिए वह दिन ऐतिहासिक होगा जब सारे संसार के लोग अयोध्या, काशी और मथुरा के दर्शन करेंगे। मथुरा में भी कॉरीडोर बनने का काम शुरू हो गया है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि दुनिया में एक छोटा सा देश है स्विटजरलैण्ड जिसकी आबादी हमारे दो जिलों के बराबर है। संसार में प्रति व्यक्ति आय वहाँ की सर्वाधिक है उसका कारण वहाँ का टूरिज्म है। हम उस दिन का इन्तजार कर रहे हैं जिस दिन उत्तर प्रदेश की आय का सर्वाधिक बड़ा साधन टूरिज्म होगा। इको टूरिज्म बोर्ड ने सलखन को जो दुनिया का सबसे पुराना जीवाष्म का पार्क है सोनभद्र में राजदरी, देवदरी जो चन्दौली राजदरी, देवदरी के झरने हैं उसको उसमें शामिल किया है। उत्तर प्रदेश के 75 स्थानों का चयन पर्यटन के लिहाज से किया गया है। हम इसके लिए भी

बधाई देना चाहते हैं। सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि आपने कोरोना के काल में आयुष के महत्व को देखा है। आयुष के काढ़े को, दुनिया जिस गिलोय को नहीं जानती थी इस कोरोना के काल में सारे संसार ने गिलोय का काढ़ा, दालचीनी का काढ़ा पीकर अपनी प्राण रक्षा की। आयुष कवच एप से 26 लाख लोगों ने जुड़कर उत्तर प्रदेश में योग करके अपनी प्राण रक्षा की । हम बधाई देना चाहते हैं अपने यशस्वी मुख्य मंत्री जी को जिनके कोरोना काल में किये गये कार्य के मॉडल को सारे देश ही नहीं सारे विश्व ने सराहा और उसको महत्व दिया। मैं मा0 यशस्वी मुख्य मंत्री जी के लिए कहना चाहता हूँ कि हम समुन्दर के साथ गाते हैं, हम लहरों पर घर बनाते हैं ठण्ड लगती है जब पहाड़ों को बीनंकर बिजलियाँ जलाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री मदन भैया-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया है। इससे पहले बजट पर काफी चर्चा हुयी। मैं विपक्ष के लीडर आदरणीय अखिलेश यादव जी के विचारों से एवं प्रतिपक्ष के अन्य नेता के विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि यह किसान की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट नहीं है। मान्यवर, जैसाकि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। लेकिन कृषि करने वाले किसान, मजदूर लोग सबसे ज्यादा चिंता अपने बच्चों को पढ़ाने की और अच्छे स्वास्थ्य की करते हैं। लोनी संयुक्त चिकित्सालय में अभी तक मशीन नहीं लगी है इसे लगाया जाय।

मान्यवर, लेकिन अफसोस है कि वर्ष 2023-24 के बजट में अन्य राज्यों के सापेक्ष शिक्षा का बजट कम हो गया है यानी पहले औसतन आवंटन 14.8 प्रतिशत था जो कि अब 13 प्रतिशत है, जबकि 1.8 प्रतिशत कम है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट जरूर बढ़ा है और सबसे बड़ी चीज उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते, कृषि का बजट 5.8 प्रतिशत कम है, जो कि एक सोचने वाला विषय है। आम आदमी सबसे ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाने एवं हेल्थ की चिंता करता है, क्योंकि यह बजट किसान की अपेक्षाओं आम आदमी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, लेकिन कुछ चीजें जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया है, बशर्ते वह लागू हो जाए और बजट पूरा खर्च हो जाए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी विधान सभा क्षेत्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मुजफ्फरनगर की खतौली विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ कि दो महिला राजकीय कालेजों की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ ठेकरा विधान सभा क्षेत्र के लोनी कस्बे में उस वक्त के मा0 मुख्य मंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दो महिला राजकीय कालेज एवं एक आई0टी0आई0 कालेज दिया था, लेकिन अफसोस है कि आज उन राजकीय कालेजों में अध्यापक नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि कम-से-कम उन इण्टर कालेजों को भेद-भाव भुलाकर कि अखिलेश यादव जी ने उन कालेजों को बनवाया है, उनमें

आप अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो एक्सीडेंटल एम0एल0ए0 हवा में हो जाते हैं उन्हें कृपया आप नियमावली पढ़वाने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य सिर्फ पांच मिनट ही बोलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लम्बी लिस्ट है, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मदन भैया-

मान्यवर, सामने आ जाइए, जवाब दे दिया जायेगा लेकिन विधान सभा का उपयोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नही करना चाहिए और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से यह बात सरकार तक जायेगी और हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तक जायेगी क्योंकि वह भी एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। वह भी ऐसे गैर अनुशासित व्यक्तियों को जो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ सकते हैं। वह अपने हितों को साधने के लिए अपने गुनाहों को छिपाने के लिए विधान सभा का दुरुपयोग न करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके कारण से आपने मुझे यह अवसर दिया, ऐसे अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं का जिन्होंने 82 हजार से भी ज्यादा मतों के अन्तर से मुझको जीताकर सदन में भेजा है।

माननीय अधिष्ठाता महोदया, यहां पर अभी चर्चा हो रही थी, हम लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी को सुन रहे थे। क्रिकेट के खेल की बात, बॉल की बात, तमाम ऐसी बातें, तो मुझे याद आया कि इसी सदन में उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि मैं एक बार प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण के लिए गया था, जहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब वे वहां गये, वहां पर बच्चे उनको देखकर खिल-खिलाकर हंसने लगे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या मुझे पहचानते हो, तो बच्चों ने कहा हां, तो उन्होंने कहा बताओ मेरा नाम क्या है ? तो बच्चों ने कहा, राहुल गांधी। दूसरी तरफ, हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आजाद भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला कि जब कोरोना का पहला कालखण्ड हुआ, माननीय महाराज जी के पिताजी का देहान्त हो जाता है और वे उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानकर अपनी तत्कालीन टीम 11 के साथ, उनकी जानों को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और अपने पिता के अन्तिम दर्शन नहीं कर पाते हैं ।

माननीय मोदी जी जैसा उदाहरण पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलेगा कि जिनकी माताजी का निधन होता है और वे पुत्र धर्म का पालन करने के लिए माँ के अन्तिम संस्कार के लिए जाते हैं और फिर राजधर्म के पालन के लिए लौटकर देश की सेवा में लग जाते हैं ऐसा दूसरा उदाहरण इस आजाद भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिला। मैं आदरणीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को धन्यवाद करता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी को, आदरणीय हमारे मोदी जी को, जिनके कुशल मार्गदर्शन और माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये का इतना भारी-भरकम बजट जनहित के लिए पेश किया गया। जिसमें 32 हजार 721 करोड़ 96 लाख रुपये की नयी योजनाएं भी शामिल है। राजकोषीय घाटा भी 84 हजार 883 करोड़ 16 लाख रुपये अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48 प्रतिशत है। यह प्रदर्शित करता है कि यह बजट पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए पेश किया गया है, उनके उत्थान के लिए पेश किया गया है। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए आग्रह करना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक कॉलोनी है। जब कानपुर कभी मैनचेस्टर कहा जाता था, मैंने अपने जीवन के 42 वर्ष लेबर कॉलोनी के एक कमरे में गुजाकर इस सदन में पहुंचा हूँ, इसलिए उसका दर्द पीठ के समक्ष बयां करना चाहता हूं। मैं इस पीठ से आग्रह करना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के 14 जिलों से भी ज्यादा जगह 29 हजार 587 से भी ज्यादा कॉलोनियां हैं वहां के मूल निवासी उनमें निवास कर रहे हैं, कई-कई पीढ़ी के लोग वहां रह रहे हैं। सन् 1985-86 के आस-पास एक योजना बनी थी जिसमें उड़ीसा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के लिए वहां के स्वामित्व का मामला था। जो स्वामित्व वहीं के रहने वाले लोगों को उसी दशा में दे दिया जाए, एक ऐसा प्रस्ताव आया था जिसमें उड़ीसा एवं दिल्ली को तो दे दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया गया। मैं आपकी पीठ से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पर कृपा हो जाए क्योंकि जब हमारे मुख्य मंत्री जी प्रत्येक धर्मक्षेत्र में, प्रत्येक भाषा-भाषी के लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, तो श्रमिक लेबर कॉलोनी के वासियों का स्वामित्व भी मात्र टोकनमनी लेकर दे दिया जाए। मैं आग्रह करना चाहता हूँ मेरे यहां छठी मैया का पूजन बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, पांच मिनट में अपने क्षेत्र की भी समस्या रख दीजिए, बहुत लम्बी लिस्ट है।

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

मान्यवर, साढ़े छः लाख से ज्यादा लोग इसमें पूजन करते हैं, तो उन घाटों के निर्माण को पूरा करा दिया जाए। हमारे दादानगर का समानान्तर पुल, जो पास भी हो गया, जिसे टेण्डर प्रक्रिया में जाना है, उसको भी तेजी से बढ़ाकर टेण्डर प्रक्रिया में भेज दिया जाए। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि झकरकटी बस स्टेशन, जहां से 1500 बसें आस-पास के राज्यों में जाती

है, सारे जिलों में जाती हैं उसका निर्माण पी0पी0पी0 मॉडल पर होना है उसको भी टेण्डर प्रक्रिया में डालकर काम जल्दी कराया जाए। पनकी पड़ाव हमारे यहां रेलवे क्रासिंग है, मानव रहित रेलवे क्रासिंग का उद्देश्य हमारी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का है और दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन पर हर पांच मिनट पर गाड़ियां निकलती हैं, लाखों लोग प्रभावित होते हैं तो उस पर एक ओवरब्रिज बना दिया जाए जिससे लोगों को राहत हो जाए। हमारे यहाँ एक नहर है, किसी समय कानपुर की जब सवा दो लाख आबादी होती थी, आज 55 लाख उसकी आबादी है और नहर कानपुर से बाहरी क्षेत्र में थी। वह कच्ची नहर आए दिन कट जाती है। एक 71 वर्षीय बूढ़ी माँ का नहर में फिसल जाने से निधन हो गया। आस-पास 50 हजार की जनता रहती है। उस नहर को पक्की कर दिया जाए। नमामि गंगे के अन्तर्गत 19 घाट माननीय मोदी जी ने कानपुर में बनाये हैं, वहाँ पर महिलाओं के लिए स्नान हेतु स्नान गृह बना दिया जाए। हमारे अरमापुर से विषधन तक 60 किमी0 की सड़क है, उसका निर्माण करा दिया जाए।

अन्त में आपको और सरकार एवं मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, अपनी समय सीमा में, अपना निवेदन पूर्ण करता हूँ।

भारत माता की जय।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, आप समाप्त करें। अब श्रीमती गुड़िया कठेरिया जी बोलें।

(सदस्य श्रीमती गुड़िया कठेरिया ने बोलना प्रारम्भ कर दिया, इसलिए मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र मैथानी के आखिर के कुछ वाक्य सुनाई नहीं दिए।)

श्रीमती गुड़िया कठेरिया-

माननीय, अधिष्ठाता जी, आपने मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय महोदया, मैं औरैया विधान सभा क्षेत्र से आती हूँ। आप लोग जो किसानों की बात करते हैं, हमारे यहाँ के किसानों के साथ उस सरकार में क्या होता था, मैं वह आज सबके सामने बताना चाहती हूँ। हमारे वहाँ किसानों के धान से लदे ट्रैक्टर सीधे-सीधे गायब हो जाते थे और हमारा किसान रो-रोकर तड़प-तड़प कर मर जाता था, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। वहीं अछल्दा नहर पर दिन में 12:00 बजे या रात में निकलने में आदमी भयभीत रहता था। आज हमारे मुख्य मंत्री जी की वजह से चाहे दिन हो, चाहे रात हो, आज वही किसान मण्डी में अनाज लेकर पहुँचता है और बेच कर चाहे वह 10 लाख का अनाज बेच कर आए, सीधा-सीधा अब वह घर में पहुँचता है। यह हमारी योगी सरकार है। अधिष्ठाता जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी बहनों को जो सुरक्षा मिली है, यह योगी सरकार में मिली है। आज पूरे उत्तर प्रदेश की बहनों का उनके ऊपर आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा। अभी

2027 का चुनाव आयेगा तो फिर से आयेंगे, योगी जी । हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाएँ गहना पहनने को तरसती थीं। हमारी औरैया विधान सभा क्षेत्र एक ऐसी विधान सभा थी, जहाँ दिन में हमारी बहन-बेटी निकलने में डरती थी। आज हमारी औरैया विधान सभा क्षेत्र में चाहे दिन के 12:00 बजे जाओ, चाहे रात के 12:00 बजे जाओ, हमारी बहन-बेटी के साथ में कोई घटना नहीं घटती। हमारी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो एनटीपीसी, गेल है, वहाँ के अधिकारियों के साथ जब हम बैठे, मैं सहर्ष आपसे कहना चाहती हूँ, मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ? वह बोले हमें यहाँ पर किसी बात की दिक्कत नहीं है, लोग बताते हैं कि सपा सरकार में दिक्कत थी, यहाँ पर वसूली की जाती थी। आज वहाँ पर हमारे अधिकारी बड़े स्वतंत्रता से रह रहे हैं। वहाँ से हमारे लेबर ड्यूटी करके जाते थे, सब जानते थे कि आज इनकी पगार मिलने वाली है, तब उनको रास्ते में लूट लिया जाता था । परिवर्तन हुआ है, सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास हुआ है। यह हमारी योगी सरकार है। आज चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, योगी सरकार में सभी जातियों का समावेश हुआ है। महोदया, मैं अपने औरैया विधान सभा क्षेत्र की जो समस्या है, उसे आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमारी औरैया में जो गल्ला मण्डी है, जिसमें किसान उल्टी तरफ से निकलते हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिज का निर्माण करवाने का कष्ट करें। महोदया, मेरी औरैया में एक संस्कृत विद्यालय है। जो दो-ढाई सौ साल पुराना है। वहां दो सौ, ढ़ाई सौ छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं और जो बिल्डिंग जर्जर पड़ी है उसको बनवाने की आप कृपा करें इससे छात्र-छात्राओं के लिए लाभ होगा और हमारी संस्कृति भी बनी रहेगी।

मान्यवर, मैं अपनी औरैया के लिए एक और मांग करती हूँ कि हमारी औरैया में अक्सर बारिश होने पर जलभराव की समस्या रहती है, इसलिए वहां पर गहरा नाला का निर्माण किया जाए, आपकी महान कृपा होगी। मान्यवर, मैं आपके सामने एक विषय और रखना चाहती हूँ कि अजीतमल में हमारा एक बस स्टैण्ड बना हुआ है, उसका पुनः निर्माण करवा दिया जाए और सौन्दर्यीकरण करा दिया जाए, आपकी महान कृपा होगी। मान्यवर, यह विकास की बात करते हैं अभी हमारी औरैया में भीखेपुर से जुही खां और डीजलपुर तक हमारी एक रोड 26 करोड़ की बन रही है। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जो हमने विषय बताए हैं इसको अवश्य लिया जाए। इसी के साथ-साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री बेदी-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, आपने बजट पर मुझे बोलने के लिए मौका दिया है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से प्रदेश में बहुत बड़ा बजट प्रस्तुत हुआ है। अगर यह बजट सही ढंग से लागू किया गया तो निश्चित ही प्रदेश का विकास होगा। प्रदेश में गरीबों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है जिसमें एस0सी0एस0टी0 और ओ0बी0सी0 आते हैं और मैं निवेदन करता हूँ कि उनकी छात्रवृत्ति को बढ़ाया जाए। उसमें कितने बच्चे जो गरीब हैं

एस0सी0, एस0टी0 के हैं और ओ0बी0सी0 के हैं वह एडमिशन नहीं करा पाते हैं तो मेरा निवेदन है कि पहले एडमिशन कराया जाए उसके बाद उनकी छात्रवृत्ति से काट लिया जाए। किसानों की सिंचाई का जो बिल है वह माफ किया गया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन हमारे नेता मा0 ओम प्रकाश जी की सदैव मांग रही है कि जो गरीबों के घरेलू बिजली का 300 यूनिट का बिल है उसको भी माफ कर दिया जाए और गांव में जो सामूहिक शादियां होती हैं वह अच्छी बात है, लेकिन कुछ गरीब जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं उनके प्रार्थना-पत्र पर बाद में उनको भी स्वीकार कर लिया जाए, उनको भी दिया जाए, क्योंकि पहले शादी के लिए यह अनुदान मिलता था अभी हाल ही में इसे बन्द कर दिया गया है। जो गरीब है, जो बंजर जमीनें है, ऊसर जमीनें हैं उस पर पचासों साल मेरा अनुरोध है कि वह लोग अगर खाली कर देंगे तो फिर कहां जाएंगे और हमारे विधान सभा क्षेत्र जखनिया जनपद गाजीपुर में बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं है। लेकिन जो भी छोटे-बड़े हॉस्पिटल हैं, उसमें डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है तो उसकी भी व्यवस्था की जाए। हमारे विधान सभा क्षेत्र में क्या, पूरे गाजीपुर में 40 सालों से बिजली के तार नहीं बदले गए हैं। उनके टूटकर गिर जाने से कहीं आग लग जाती है, कहीं घर जल जाते हैं, कहीं फसल जल जाती है, इसलिए तारों को तत्काल बदलवाया जाए। हमारी मांग है कि गाजीपुर से बहुत बच्चे मिलिट्री में जाते हैं, सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं और खेल प्रतियोगिताओं में भी सबसे ज्यादा जाते है। इसलिए वहाँ एक मिनी स्टेडियम दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विधायक जी समाप्त करिए।

श्री बेदी-

हमारे यहाँ एक नगर पंचायत सादात है। वहाँ नाली और सड़क की समस्या है, उसको भी ठीक किया जाए। विधान सभा क्षेत्र जखनियाँ में बहरियाबाद बाजार है, जखनियाँ बाजार है, सादियाबाद बाजार है, दुल्लहपुर बाजार है, मौधिया बाजार है, हंसराजपुर, भुड़कुड़ा बाजार इनमें नाली बनवाई जाए। मैडम, अभी पाँच मिनट नहीं हुआ है, आप देख लीजिए। आखिर मैं रिजर्वेशन का हूँ तो मुझे एक-आध दो मिनट ज्यादा मिलना चाहिए। अभी मेरा एक मिनट बाकी तब भी आप मेरा बोलना बन्द करा रही हैं। हमारे जफराबाद विधान सभा क्षेत्र में जलालपुर स्टेशन है, जलालपुर में हर दम जाम लगा रहता है तो वहाँ एक ओवरब्रिज बनाया जाए। ऐसे ही जखनियाँ स्टेशन है, वहाँ पर भी ओवरब्रिज बनाया जाए।

अमारी गेट रेलवे क्रॉसिंग नायक डीट हाल्ट रेलवे क्रॉसिंग पर फलाईओवर ब्रिज निर्माण कराया जाय। धन्यवाद।

शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क का सुन्दरीकरण, सौदर्न्यीकरण कर करें। पर्यटन स्थल घोषित किया जाय।

बहरियाबाद पानी की टंकी से भरतपुर होते हुए आजमगढ़ सीमा तक मार्ग जर्जर अवस्था में है । इसको जल्द से जल्द बनवाया जाये।

श्री अंकित भारती-

मा0 अधिष्ठाता महोदय और सभी सम्मानित सदस्यों को जय भीम। सर्वप्रथम मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया है। साथ ही साथ मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 श्री अखिलेश यादव जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे प्रदेश में मुझे अपना सबसे नौजवान प्रत्याशी बनाया और विधान सभा क्षेत्र-374, सैदपुर, गाजीपुर की प्यारी जनता ने मुझे भारी मतों से जिताकर सदन में भेजने का काम किया। मैं सैदपुर की जनता को भी पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। यह सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़ों की विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षित पदों के सापेक्ष रिक्तियों को भरने के लिए क्या विशेष अभियान चलाकर उसे पूरा करने जा रही है ? यह सरकार किस प्रकार की समानता की बात करती है ? क्या जातिगत जनगणना करा कर सबको उनकी संख्या के अनुसार भागेदारी देने में क्यों पीछे हट रही है ? इनकी सामाजिक समानता की परिभाषा क्या है ? मैं जानना चाहूँगा। सरकार गन्ना किसानों के विकास की बात करती है, क्या जनपद गाजीपुर में गन्ना किसान नहीं है ? जनपद गाजीपुर में नन्दगंज में कई वर्षों से एक मिल बन्द पड़ी है। सरकार ने उसके जीर्णोद्धार की बात अपने बजट में क्यों नहीं की ? इसी प्रकार सरकार की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है।

मा0 अधिष्ठाता महोदया, सरकार महिला शिक्षा व उनके उत्थान की बात करती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई वर्षों से ग्राम सभा खानपुर में एक राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज बनकर तैयार है, परन्तु उसमें पठन-पाठन शुरू कराने का सरकार को ध्यान भी नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा सेहमलपुर में अग्निशमन उपकेन्द्र लाखों रुपये खर्च करके अर्द्धनिर्मित अवस्था में पड़ा है। उसके पूर्ण निर्मित न होने के कारण आए दिन अग्निकाण्ड होने पर किसानों व छोटे व्यापारियों की लाखों-लाख रुपये की क्षति होती है और जान-माल का खतरा भी बना रहता है। मा0 अधिष्ठाता महोदया, सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश की सड़कें बहुत अच्छी हैं, मैं मा0 पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कें जैसे उचौरी से पोखरा मोड़ तक, सीयावा से शिशुचक होते बौरवा मार्केट तक, रामपुर पानी की टंकी से ईशोपुर हाई-वे तक, देवकली सिरगिठा मार्ग से सैचना तक एवं पचरासी माइनर से कुर्बान सराय होते हुए पहाड़पुर मार्ग तक देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

ग्राम सभा मेवादा से बाबतपुर गोमती नदी पर पुलिया बन जाने से गाजीपुर, बनारस और जौनपुर के लोग जुड़ जाएंगे जिनके मध्य आवागमन आसान हो जाएगा और व्यापारिक गतिविधियाँ भी बढ़ जाएंगी। मा0 अधिष्ठाता महोदया, यह सरकार चिकित्सा क्षेत्र में विकास की

बात कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थापित सैदपुर का मुआयना उदाहरण के तौर पर कर लें वह स्वयं अपनी आँखों से देख लेंगे कि संसाधनों का कितना अभाव है, उनकी आँखें और पूरे बजट की पोल खुल जाएगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के देवकली ब्लॉक में कोई समुचित खेल का मैदान नहीं है यह सरकार क्या वहाँ पर एक खेल का मैदान उपलब्ध कराने का कार्य करेगी या सिर्फ नकली आँकड़े पेश कर अपनी पीठ थपथपाती रहेगी। मा0 अधिष्ठाता महोदया, यह बजट किसान, गरीब, महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग विरोधी है। सरकारी रोजगार की सम्भावना समाप्ति के कगार पर है। महंगाई व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं है। सरकार के जनपदीय अधिकारी चुने हुए विधायकों की जनहित में कहीं बात नहीं सुनते हैं तथा निरंकुश और बेलगाम होकर कार्य कर रहे हैं। अंत में मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बातें मैंने कही हैं, सरकार उसका संज्ञान ले। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भीम।

श्री जय प्रकाश निषाद-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-24 के मा0 योगी जी, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर बोलने के लिए आपने हमे अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा राज्य लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश का यह बजट सर्व विकासोन्मुखी है इससे गाँव, गरीब, किसान, बेरोजगार, नौजवान, महिलाओं और बेटियों का सम्मान किसानों का उत्थान और 'सबका साथ सबका विकास' बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अन्त्योदय जैसे सपनों को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश में आम जनता के लिए खुशहाली और अमन चैन लाने वाला यह बजट साबित होगा। वैसे भी कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश को पूरा देश जानता है। उत्तर प्रदेश में मा0 योगी जी की सरकार ने चाहे कानून व्यवस्था के लिए काम किया है और चाहे सुशासन के लिए काम किया है। उसकी अन्य प्रदेश के लोगों के द्वारा प्रशंसा की जाती है। वैसे तो विरोधी का काम विरोध करना है बंधुओं आज मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलूँगा जो भी सरकार का बजट आया है बहुत सारे बंधुओं ने उसके समर्थन में कहा मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए अपने विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर देवरिया जिसका अधिकांश भाग कछारांचल पड़ता है जहाँ राप्ती, गुर्रा, बथुआ, मदना, कुरना, नकटा नदी नालों से घिरा हुआ है, जिसमें राप्ती और गुर्रा नदी के किनारे बंधों के बीच लगभग 52 राजस्व गाँव घिरे हुए हैं तथा गुर्रा एवं बखिया नदी के बीच 46 गाँव इन दो बन्धों के बीच घिरे हुए हैं जिसको हम कछार दोआब के नाम से जानते हैं उस क्षेत्र में जब बरसात का समय आता है या बाढ़ का समय आता है तो पानी इतना भर जाता है कि खरीफ और रवी की कोई भी फसल नहीं हो पाती है। जल निकासी के लिए समुचित व्यवस्था न होने के नाते वहाँ किसानों की फसल के बचाव के

लिए वहाँ से जलमग्न क्षेत्र के पानी की निकासी के लिए पम्प स्टेशन का निर्माण कराया जाए ऐसी दशा में आज तहसील रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र से जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 50 किलोमीटर और देवरिया 35 किलोमीटर है। उक्त क्षेत्र में एक भी मण्डी न होने के कारण किसानों को कच्चे माल अथवा अपने पैदा हुए पैदावार के माल को मण्डी में ले जाने में काफी कठिनाई होती है, उनको दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, इसलिए एक मण्डी का निर्माण कराया जाय। रूद्रपुर नगर पंचायत जिले का निर्माण हुआ तभी से वह पंचायत और तहसील बनी हुई है। वहां पर बस स्टेशन बने काफी समय हो गया है, बस स्टेशन का भवन जर्जर हो गया है। बस स्टेशन का निर्माण कराया जाय तथा देवरिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र-रूद्रपुर, तहसील-रूद्रपुर के अन्तर्गत दर्जनों इण्टर कालेज और डिग्री कालेज हैं, जहां युवाओं को खेलने का बड़ा अच्छा अवसर रहता है, वह पढ़ाई के साथ-साथ खेला भी करते हैं। मेरा माननीय खेल मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी एक मिनी स्टेडियम बनाया जाय, जिसके लिए लगभग साढ़े 3 एकड़ जमीन ग्राम भिरबिसरी, विकास खण्ड-गौरी बाजार, तहसील-रूद्रपुर में है। जिसे हमने लिखकर भी दिया है। सिंचाई मंत्री जी यहां बैठे हैं, संज्ञान ले रहे हैं, हम सब लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम भी कर रहे हैं।

मान्यवर, दूसरी काशी के रूप में मिनी काशी के रूप में जाने वाला देवरिया जिले का रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र का वह भूतभान महाकालेश्वर स्वयं भू महाशिवलिंग, दुग्धेश्वर नाथ बाबा जो अनादिकाल से रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत में विराजमान हैं। जहां पर वर्षवार शिवरात्रि, नवरात्रि इत्यादि प्रकार के आयोजनों पर विशाल मेले के रूप में हजारों लाखों की संख्या में दर्शनार्थी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करने के लिए आया करते हैं। वहां पर मन्दिर के पीछे 132 एकड़ का भीटा टीला और सहनकोट का स्थान है, जहां पर पुरातात्विक महत्व का स्थान है और वहां पर बरसात के दिनों में मिट्टी ढुलती है। कभी-कभी तमाम प्रकार के शंकर की, देवी-देवताओं की मूर्तियां निकलती हैं। इसलिए वहां पुरातात्विक महत्व को देखते हुए पर्यटन के विकास के दायरे में लिया जाय और उसका विकास किया जाय। एक विषय है, नगर पंचायत-रूद्रपुर में, नकईल मार्ग पर एक पक्का पुल बनवाया जाय, हमारे क्षेत्र में करौता के पास एक पीपा का पुल लगवाया जाय, राप्ती नदी में नकई घाट के पास एक पीपा का पुल लगवाया जाय तथा रूद्रपुर कपरवाट घाट का पुनर्निर्माण कराया जाय। यह सारी समस्याएं हैं, इनको जोड़ लिया जाय। पुनः मैं माननीय योगी जी के इस विकासोन्मुखी बजट का समर्थन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं।

श्री राजेश्वर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐतिहासिक बजट रखा है इसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदया,

किसी भी बजट का आंकलन 05 बिन्दुओं पर किया जाता है। फिजिकल रिस्पॉन्सबिलिटी मैनेजमेंट ऐक्ट श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी 2003 में लाये थे, जिसमें किसी बजट का आंकलन करने के लिए बिन्दु है। जो बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए, रेवेन्यू सरप्लस कितना होना चाहिए, ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडीचर क्या होना चाहिए, नई नीतियां क्या होनी चाहिए और हमारे खर्चे क्या होने चाहिए। इन सारे पांचों एकाउण्ट्स में उत्तर प्रदेश का बजट 100 में 100 नम्बर पाता है, ऐसा बजट हमारे योगी आदित्यनाथ जी ले करके आये हैं। 1,87,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडीचर है, जो ऐतिहासिक है। कैपिटल एक्सपेंडीचर वह पैसा होता है जिससे नये प्रोजेक्ट्स लाये जाते है। नये प्रोजेक्ट्स से रोड बनती है, अस्पताल बनते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विकास होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडीचर में आज हमारा रेवेन्यू सरप्लस रेट पर है और 68,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू सरप्लस है। हम बढ़ी हुई पेंशन भी दे रहे हैं, हम बढ़ी हुई तनख्वाह भी दे रहे हैं, हम सब्सिडी भी ज्यादा दे रहे हैं। अगर हम इसके आंकड़ें लें तो बसपा सरकार में कुल बजट 1 लाख 80 हजार करोड़ का था, जितना आज हम कैपिटल एक्सपेंडीचर पर खर्च कर रहे हैं। ऐसा बजट हमारे योगी आदित्यनाथ जी और हमारे वित्त मंत्री खन्ना जी लेकर आये हैं।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, मैं सबेरे चर्चा में सुन रहा था, हमारे विपक्ष से बहुत ही गम्भीर बातें कही जा रही थीं, डिलॉइट कम्पनी का नाम आया कि डिलॉइट को क्यों काम दिया गया ? डिलॉइट कम्पनी के बारे में जरूर बताना चाहूँगा कि यह विश्व की 4 सबसे बड़ी कंसल्टिंग कम्पनीज में है। चाहे के0पी0एम0जी0 हो, चाहे पी0डब्ल्यू0सी0 हो, चाहे अर्नस्ट एण्ड यंग हो, चाहे डिलॉइट हो। इन कम्पनियों का टर्नओवर, यदि खाली हम कन्सल्टेंसी की बात करें तो डिलॉइट का टर्नओवर 7 लाख 20 हजार करोड़ है। ऐसी कम्पनी है जो 150 देशों में है। जिसके पास 600 से ज्यादा आफिस हैं और 180 साल पुरानी है। ऐसी कम्पनी जिसमें सवा लाख लोग काम करते हैं, वह यदि हमको ज्ञान दे रही है तो इसमें क्या बुराई है ? हमें हर जगह से ज्ञान लेना चाहिए। हमारी जो सोच है, वह 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हमें जहाँ से ज्ञान मिलेगा, जहाँ से नॉलेज मिलेगी, उसको हम हासिल करेंगे। दूसरी बात है, सबेरे पूछा जा रहा था और हरक्यूलिस की चर्चा हो रही थी कि हरक्यूलिस कहाँ है, हरक्यूलिस लैण्ड किया। अधिष्ठाता महोदया, मैं बताना चाहूँगा कि ग्रीक के डेमिगोड है, ढाई हजार साल पहले, जो आकाश के पुत्र माने जाते हैं, जिन्होंने राक्षसों का वध किया। आज के हरक्यूलिस हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो आतंकवाद का, भ्रष्टाचार का वध कर रहे हैं और उसको उत्तर प्रदेश से जड़ से उखाड़ कर फेंक दे रहे हैं। तीसरी बात आई थी कि बजट लैप्स हो गया। बजट कैसे लैप्स होता है। अधिष्ठाता महोदय, पी0ए0सी0 की मीटिंग में मैंने देखा है। इनके रिज्यूम में खाली एक विभाग का, गृह विभाग का बजट 3300 करोड़ था, जिसमें 906 करोड़ लैप्स हो गया, इसको लैप्स कहते हैं कि पुलिस विभाग के न अस्पताल, न पुलिस

विभाग के आवास बन रहे थे, न हथियार, गोला-बारूद आ रहा था और उसका बजट लैप्स हो गया था, इसको बजट लैप्स कहते हैं।

अधिष्ठाता महोदया, बात हो रही थी कि हम एक ऐसा टार्गेट लेकर चल रहे हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे आयेगा । महोदया, यह कैसे आयेगा, मैं आपको कुछ आँकड़े बताता हूँ और यही हमको क्लेरिफाई करेंगे कि हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है। 1947 से आज तक हमारे पास 1 ट्रिलियन डॉलर एफ0डी0आई0 आया है, जिसमें कि आधा ट्रिलियन, उसका आधा हिस्सा हमारे पिछले 8 वर्षों में आया, लगभग 80 महीनों में आया है। इस तरह से हमारा एफ0डी0आई0 बढ़ रहा है और पिछले 8 साल से लगातार एफ0डी0आई0 बढ़ रहा है और जब कोविड था, कोविड के दौरान हिन्दुस्तान पर इतना ट्रस्ट है कि साढ़े सात लाख करोड़ का एफ0डी0आई0 आया और यह एफ0डी0आई0 162 देशों से आया तथा यह एफ0डी0आई0 61 सेक्टर्स में आया। यह हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश के ऊपर ट्रस्ट है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी पर देश-विदेश की कम्पनियों को इतना विश्वास है कि साढ़े तैंतीस लाख करोड़ के 19 हजार एम0ओ0यू0 साइन हुए हैं। इसका परिणाम आने वाले समय में हम सब देखेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदया, हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था को भी देखते हैं, डबल इंजन सरकार की लगातार चर्चा हो रही थी। पहला ट्रिलियन इकोनॉमी हम कब हुए ? पहला ट्रिलियन इकोनॉमी होने में हमको 67 साल लगे। दूसरा ट्रिलियन इकोनॉमी होने में हमको 8 साल लगे। तीसरा ट्रिलियन इकोनॉमी होने में हमको मात्र 5 वर्ष लगे। यह हमारी ग्रोथ रेट है। हम एक ग्रोथ मल्टीप्लायर की ओर जा रहे हैं, हम कोई साधारण इकोनॉमी की तरह नहीं चल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये। अब माननीय मंत्री, श्री ब्रिजेश सिंह बोलें

श्री राजेश्वर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, दो चीजें और कहना चाहूँगा कि पूरे सदन में छापों की बात हो रही है। हमारी सरकार भ्रष्टाचारियों पर छापे मार रही है। आज खनन माफिया जेल में हैं और पुराने खनन मंत्री जेल में हैं। हमारा युवा आज यह चाहता है कि उसको रोजगार के अवसर मिलें, हम स्टार्ट-अप फण्ड और इक्यूबेशन फण्ड 4 हजार करोड़ के लाये है। युवा एक उज्ज्वल भविष्य देख रहा है। हिन्दुस्तान एक युवा देश है, हमारी 100 करोड़ की युवा आबादी है, जो कि 35 साल से नीचे है। हम अगले 20 साल में कहाँ पहुँचेंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमने पिछले 5 वर्षों में फ्रांस को, यू0के0 को, इटली को, रूस को इकोनॉमी में पीछे छोड़ दिया । इसलिए अपने युवा को कम मत आंकिये। हम सेंटर फॉर एक्सीलेंस बना रहे हैं। आप देखिये, मेरे क्षेत्र सरोजनीनगर में एन0सी0डी0सी0 बन रहा है, कम्युनिकेबल डिजीजेज का वर्ल्ड का बेस्ट सेंटर बन रहा है, जो कोविड से लड़ेगा । हमारे वहाँ ब्रम्होस बन रहा है, जो 330 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, वह हमारे वहाँ बन रहा

है और इनके वहाँ सेंटर फॉर एक्सीलेंस में माफियाओं की ट्रेनिंग होती थी। चाहे गाजीपुर हो, चाहे रामपुर हो और चाहे आजमगढ़ हो, ये वहाँ पर क्या ट्रेनिंग देते थे ? जिसका परिणाम अभी हम इलाहाबाद में देख रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मेरा कहना है कि युवाओं का समय बहुत कीमती है, विपक्ष को युवाओं का समय जातीय बातें करके खराब नहीं करना चाहिए। उसको पढ़ने के अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि वह देश के लिए और कंट्रीब्यूट कर सके। हर युवा का सपना है कि वह आई0टी0 जाये, विदेश में पढ़ाई करे। इसलिए उसको अच्छे संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। इसी बात के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद ।

श्री नफीस अहमद-

मान्यवर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वर्ष 2023-24 के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं नेता प्रतिपक्ष की बातों से अपने आपको जोड़ते हुये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो बजट का आकार पिछले वर्षों के बजट में 8 से 10 फीसदी बढ़ाया जाता रहा है। अब तक के सबसे बड़े बजट पर पीठ थपथपा रही सरकार को देखना चाहिए कि पिछली बार का जो बजट था वह 6.15 लाख करोड़ रुपये का था और बाद में करीब 33 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट मिला दें तो यह राशि 6.48 लाख करोड़ पहुंच जाती है। इस बार का तथा कथित बजट 6.90 लाख करोड़ का रहा जो 6.5 फीसदी बढ़ा है। जब यह बजट आया तो इस बजट के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के ऊपर ऋणग्रस्तता बढ़ कर 7 लाख 84 हजार करोड़ तक पहुंच जा रही है। इस बजट से यहाँ के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इस बार जो बजट आ रहा है उसमें किसान, नौजवान और अल्पसंख्यक लोगों को शोषित, वंचित लोगों को उम्मीदें थीं कि इस बजट में उनके लिए हिस्सेदारी होगी, लेकिन इस बजट के आने से लोगों को बहुत मायूसी का सामना करना पड़ा है। इस बजट में शुरुआत में वित्त मंत्री जी ने जो समिट हुई उसके बारे में बताया पूरे लखनऊ को सजाने का काम किया गया, लेकिन जो बाहर से लोग आये उन्हें हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा बनाई हुई चीजों को ही दिखाना पड़ा और उसी बिना पर उन्होंने लखनऊ में लोगों को आकर्षित करने का काम किया। आज तक यह नहीं बताया गया कि पिछली बार जो समिट में इन्वेस्टमेंट आया था वह पूरा कम्पलीट हुआ है कि नहीं हुआ और उससे लोगों को कितना रोजगार मिला, उसके बारे में नही बताया गया। मैं कहना चाहूंगा कि जिस शहर में कानून व्यवस्था नहीं है उस शहर में उद्योग की कुछ आस नहीं है, यू0पी0 को सजाया था सड़कों को कला से सजाया । महफूज रखा हमने हवादीरों से की बला से कतरा भी पानी का तेरे पास नहीं है, यह फलसफा मइया का भी पर्याप्त नहीं है।

सरकार ने बजट में छोटे लघु उद्योग को नजरअंदाज किया है। जहाँ तक मैं जिस शहर से, जिस जिले से ताल्लुक रखता हूँ वहाँ पर साड़ी उद्योग का कारोबार है। बनारसी साड़ी उद्योग के बुनकर बड़ी तादात में रहते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर काले बर्तन भी बनाये जाते हैं,

लेकिन उन सारी चीजों को उन्होंने नजरअंदाज करने का काम किया है। मैं जिस क्षेत्र से गोपालपुर से आता हूँ वहाँ पर बड़ी तादात में गन्ना किसान है। इस बजट में गन्ना किसानों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। पिछले सत्र का जो भुगतान था वह इस सत्र में हो रहा है। जो कि कहा जाता है कि गन्ना किसानों के लिए इस सरकार ने हाल ही में चीनी मिल को ग्रीन ईंधन का हब बताया। एथेनॉल उत्पादन में नम्बर 1 होने का दावा किया। बिजली, खाद, एथेनॉल, चीनी सब बन रहा है। मगर किसानों के गन्ने का दाम बढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा है। तमाम सारी चीजें वित्त मंत्री जी ने कही कि सरकार ने ऐसे काम कर दिये कि पूरी फिजाओ में, हवाओं में, आसमान में, परिंदे सब चहक रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आसमाँ की बुलन्दी से जल्द लौट आना, हमें जमी के मसायल पर बात करनी है, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपा कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। चिकित्सा के क्षेत्र में जहाँ तक कहा जा रहा है कि नये मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। नए मेडिकल कॉलेज पी0पी0पी0 मॉडल पर चलाने की योजना बना रहे हैं।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, ये बताएं कि पी0पी0पी0 मॉडल पर कैसे गरीबों का इलाज होगा ?

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विधायक जी आप 5 मिनट के अन्दर ही अपनी बात समाप्त करिये।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। इससे पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि आजमगढ़ के चक्रपानपुर मेडिकल कॉलेज में जल्द ही किडनी और हार्ट का इलाज शुरू करा देंगे, लेकिन अभी तक इलाज शुरू नहीं कराया गया। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का बजट ही समाप्त कर दिया गया। इस बजट में योजना की बात कही गई है, लेकिन जिस तरीके से सभी विभागों के पैसों के बारे में बताया गया, वो चीजों का बजट में उल्लेख नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विधायक जी अब आप अपनी बात को समाप्त करिये। मा0 मंत्री ब्रिजेश सिंह जी।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं वर्ष 2017 से लगातार माँग कर रहा हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में तहसील बना दी जाए। हमारी विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ ग्रस्त इलाका है, पिछड़ा इलाका है, जहाँ से शहर दूर है, वहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया जाए। साथ ही साथ हमारा बिलरियागंज, रौनापार का जो क्षेत्र है, वहाँ की सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो गयी है, उसको बना दिया जाए। अन्त में ये शेर

कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूँगा कि ''अड़े थे, जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीना छूट गया, एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी नहीं है, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में।'' बहत-बहुत धन्यवाद ।

लोक निर्माण सूक्ष्म राज्य मंत्री (श्री ब्रिजेश)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद प्रकट करता हूँ। महान लोकतांत्रिक परम्पराओं से परिपूर्ण आदरणीय सदन एवं सम्मानित जनप्रतिनिधियों के समक्ष बजट पर चर्चा करते हुए मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूँ। मैं इस सदन के साथ-साथ अपनी विधान सभा क्षेत्र देवबन्द के उन सभी मतदाताओं का भी आभार और धन्यवाद करता हूँ, जिनके सहयोग, सम्बल और शुभाशीष के कारण मैं पुनः इस सदन में पहुँचा। मैं धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्र की अस्मिता के प्रति भगवान श्री राम का स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में रामराज्य स्थापित करने में हमारी सरकार के प्रयासों को शक्ति, सामर्थ्य और मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने के लिए अपने प्रदेश के यशस्वी वित्त मंत्री मा0 सुरेश खन्ना जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारी सरकार 24 घण्टे, 365 दिन बिना किसी भेदभाव के विकास का उद्देश्य और सेवाभाव लेकर 25 करोड़ जनता के कल को एक बेहतर कल बनाने के लिए काम कर रही है। हमारी भावना नेक है। हम केवल नजारे ही नहीं बदल रहे हैं, हम वो नजर भी बदल रहे हैं, जिस पर कोई बाहर से आने वाला हमारे यू0पी0 वालों को देखता था ।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, नजारे बदलने के इसी विकास क्रम को आगे बढ़ाने वाला ये वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं और भावनाओं के अनुरूप गाँव-गरीब, किसान, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का काम करने वाला बजट है। अन्त्योदय के मूल मंत्र को चरितार्थ करने वाले ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं प्रदेश के जन-जन के सर्वांगीण विकास कल्याण के प्रति समर्पित बजट के लिए एक बार पुनः मैं मा0 मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस बात का प्रमाण है, आज देश ही नहीं, बल्कि विदेश से भी निवेशक बढ़-चढ़कर निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। यह भय, भ्रष्टाचार, गुण्डाराज, माफियाराज मुक्त उत्तर प्रदेश सुशासन के कर्तव्यपथ पर चल रही हमारी सरकार की मेहनत का नतीजा है, जोकि पिछली सरकारों में कल्पना भी करना मुश्किल था । आज प्रदेश सरकार ने तटस्थ नीति, साफ नियत पारदर्शी रणनीति साकार करके दिखाया है। निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अभूतपूर्व निवेश उत्तर प्रदेश की समृद्धि में तेजी से अग्रसर भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है यशस्वी

मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सफलता के नये आयाम स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता योगी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा दिन-रात किये गये अथक परिश्रम का ही परिणाम है। उत्तर प्रदेश में निवेश के द्वार भयमुक्त वातावरण में खोल रहे हैं।

आदरणीय योगी जी के लिए सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ "राह संर्घष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता हैं।" आज जब नेता प्रतिपक्ष बजट पर बोल रहे थे तो बहुत सी उन्होंने अपनी बातों को सदन में रखा। समाचार पत्र की कई कटिंग्स दिखा रहे थे, कुछ चीजों को उन्होंने टेबल किया। लेकिन यह बदलते भारत का बदलता उत्तर प्रदेश है और इस बदलते भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी पहचान, जिस समाज को जिस बनटंगिया जाति को पिछले 75 वर्षो में किसी ने सम्मान नहीं दिया, प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी चिन्ता की उनको सारे अधिकार दिलाये और आज की एक कटिंग सदन में रखना चाहता हूं, जिस बनटंगिया समाज को 75 वर्षों में किसी ने सम्मान नहीं दिया उसी बनटंगिया समाज के बालक रंगमंच पर कैटवॉक करते नजर आ रहे थे, यह योगी आदित्यनाथ जी के विजन का परिणाम है, यह बदलते भारत का उत्तर प्रदेश है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस पूरे प्रदेश के अन्दर जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, इन्होंने 5 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 1 एक्सप्रेस-वे प्रदेश को दिया और आज जब अपना भाषण कर रहे थे, तो ऐसे गिना रहे थे जैसे प्रदेश को उन्होंने जाने क्या दिया है। योगी जी की सरकार का ही परिणाम है कि आज हम 6-6 और 9-9 एक्सप्रेस-वे पर काम कर रहे हैं। मा0 सदस्य माता प्रसाद जी ने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए एक प्रश्न उठाया था, तो मैं उनको बता दूं इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों हेतु 1525 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं अपने मुख्य मंत्री जी का, मा0 वित्त मंत्री खन्ना जी का पूरे उत्तर प्रदेश की शक्तिपीठ माता शाकुम्भरी देवी के पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए इस बजट में हमें 50 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया, मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं, मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक विकास की गति में प्रगति लाने में निरन्तर प्रयासरत् है। प्रदेश सरकार के सदस्य के रूप में ही नहीं बल्कि सम्मानित सदन के सदस्य के रूप में हम जनता के विश्वास के न्यासी हैं और विकास तथा जन-कल्याण के लक्ष्यों को पूरा करना हमारा सबका सम्मिलत दायित्व है, हमारी भावना 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया' की है मैं अन्त में केवल इतना ही कहूंगा कि 'दीप बन जलते रहें, पुष्प बन खिलते रहें, लोक मंगल के लिए चलते रहें, चलते रहें' अन्त में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास एक बार पुनः इस बजट का समर्थन करते हुए, मा0 मुख्य मंत्री जी व मा0 वित्त मंत्री जी को बधायी देते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिन्द, जय भारत, भारत माता की जय ।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय-

"वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा।" मा0 अधिष्ठता महोदया, आज बजट पर हो रही इस चर्चा में आपने मुझे भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किये गये बजट 2023-24 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा समर्थन इस बजट को मूल्यों, मौलिकता, मदद, भावना, मेहनत, लगनशीलता, जन लगाव, जन सरोकार, तथ्यों, उत्साह, नियत, नीति, नेतृत्व और सोच और सटीक अनुमान व विशलेषण के आधार पर है। पूज्य महाराज जी के मार्गदर्शन में मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट अक्षरशः प्रेरक व जीती-जागती विकास पुस्तिका है। कोरोना जैसी बीमारी से जहां तमाम देश के राज्य अभी भी अपनी गाड़ी को पटरी पर नहीं ला पाये हैं, जिनकी स्थिति चिन्तनीय है, ऐसे हाल में मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों की उपलब्धियां प्रस्तुत बजट में उल्लेखनीय हैं। "पुरानी कश्ती को पार लेकर थकत हमार हुनर गया है, नये खेवैय्या कहीं ना समझे नदी का पानी उतर गया है"।

मा0 अधिष्ठाता महोदया जी, मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया, यह बजट, इसमें सूर्य देव का किरदार देख पा रहा हूं।

(इस समय रात्रि 08 बजकर 05 मिनट पर की अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

यह ज्ञात है कि मैं जनपद गोण्डा के एक अत्यन्त ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूँ। यह वही ग्रामीण इलाका है, जहाँ महर्षि पतंजलि, जमदग्नि, ऋषि पाराशर, अष्टावक्र जैसे महान ऋषि-मुनियों की तपोस्थली व जन्म भूमि रही है। बाबा तुलसीदास के अनुसार, एक राजा कैसा होना चाहिए, इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा था 'तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु सो होय।' इस बजट में भी मैं समझता हूँ कि किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं गया है, कोई भी क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र को पुष्पित, पल्लवित करने के लिए ऊर्जा व मुद्रा रूपी नीयत व नीति रूपी खाद-पानी की समुचित व्यवस्था की गयी है। यह वही ऊर्जा, यह वही कीमत है जिससे सूरज ने समान रूप से जगत का हर कोना रोशन कर रखा है और तमाम तम (अंधकार) हर लिया है। हमारे नेता पूज्य महाराज आदरणीय योगी जी ने परिश्रम की जो इतनी लम्बी रेखा खींची है, उसको पार कर पाना सामान्य इंसान के लिए सहज नहीं है। हम उस रेखा को पार कर पायें या न कर पायें, मगर उससे प्रेरित जरूर होते हैं और आने वाली राजनीतिक पीढ़ियाँ होती रहेंगी, अहर्निश, अटूट, अविराम, अबाध रूप से निरन्तर सतत्, साल दर साल, दिन-प्रतिदिन की परिश्रम की इतनी बड़ी साधना, इतना बड़ा सतत् अनुष्ठान यह किसी योगी मात्र से ही सम्भव है। मैं पूज्य महाराज जी के लिए मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि 'जिसको तूफान से उलझने की हो आदत, ऐसी कश्ती को समन्दर भी दुआ देता है'।

विपक्ष के हमारे साथी वो आदमी हैं जो आफताब में कीड़े निकालते हैं। उनकी अपनी मजबूरी है। उनके पास जो शब्दकोष है उसका शीर्षक ही जब नकारात्मकता हो तो उसी में से शब्द चुन-चुन कर मृत फूलों का हार बनाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

पाण्डेय जी, अब समाप्त कर दीजिए ।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय-

मगर विपक्ष के साथी यह भूल जाते हैं कि-

सफर में मुश्किलें आयें तो जुर्रत और बढ़ती है,
कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है । ।

श्री अध्यक्ष-

पाण्डेय जी, अब बैठ जाइये। आप लिखकर दे दीजिए, उसको जुड़वा दिया जायेगा।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय-

मान्यवर, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें दिनांक 01 मार्च, 2023 से आरम्भ करने हेतु कार्य सूची में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक की अनुदानवार माँगों पर विचार एवं उनका पारण कल दिनाँक 01 मार्च, 2023 से प्रारम्भ कर दिया जाय और तद्नुसार कल दिनाँक 01 मार्च, 2023 को अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग तथा अनुदान सं0-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) विभागों की अनुदान माँगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी मदों को कल दिनाँक 01 मार्च, 2023 की कार्य-सूची में सम्मिलित कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक की अनुदानवार माँगों पर विचार एवं उनका पारण कल दिनाँक 01 मार्च, 2023 से प्रारम्भ कर दिया जाय और तद्नुसार कल दिनाँक 01 मार्च, 2023 को अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग तथा अनुदान सं0-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) विभागों की अनुदान माँगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी मदों को कल दिनाँक 01 मार्च, 2023 की कार्य सूची में सम्मिलित कर लिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, हमने तो परसों वाला भी लिखकर भेजा था।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

यह चीज तो बैठकर तय हो जानी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय पाण्डेय जी, चूँकि कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक नहीं हो पायी थी, इसी कारण यह प्रस्ताव आया है। कल कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक कर लेंगे जिससे जितनी मदें आनी हैं वो सारी मदें आ जाएं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, कल किसी समय बीच में कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक कर लें जिससे परसों 02-03-2023 और 03-03-2023 को जिन विभागों का बजट आना है वो आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा तथा हाजी इरफान सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना को विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रकरणों को नियम-66 के अन्तर्गत जांच अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु मैंने विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित कर दिया है :-

1-श्री अमिताभ बाजपेई, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री अजय कुमार सिंह, इंस्पेक्टर, कोतवाली, कानपुर नगर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 23 मई, 2022 के सम्बन्ध में शासन द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण।

2-श्री हाजी इरफान सोलंकी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री कमलेश फाइटर, यू-ट्यूबर, जन-एक्सप्रेस फाइटर जी कहिन के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के सम्बन्ध में शासन द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण।

उपर्युक्त मामले में दी गयी सूचना आज दिनांक 28 फरवरी, 2023 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग मानी जायेगी।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

जो मा0 सदस्य उपस्थित होंगे उनकी याचिका उपस्थित मानी जाएगी और जो मा0 सदस्य उपस्थित नही होंगे उनकी याचिका उपस्थित नही मानी जाएगी।

ई0 बृजेश कठेरिया (उपस्थित), श्री सचिन यादव (उपस्थित), डा0 अमित सिंह चौहान (उपस्थित), डा0 डी0 सी0 वर्मा (उपस्थित), डा0 शिव प्रताप सिंह (उपस्थित), डा0 सुनील पटेल (उपस्थित), डा0 विनोद कुमार बिन्द (अनुपस्थित), श्री वीर विक्रम सिंह (अनुपस्थित), श्री मौ0 फहीम इरफान (उपस्थित), श्री अजय सिंह (उपस्थित), श्री अतुल प्रधान (उपस्थित), श्री अनिल प्रधान (अनुपस्थित), श्रीमती अनुपमा जायसवाल (उपस्थित), श्री अरमान खान (उपस्थित), श्री अशरफ अली खान (उपस्थित), श्री अशोक कुमार (उपस्थित), श्री आशू मलिक (उपस्थित), श्री कविन्द्र चौधरी (उपस्थित), श्री कैलाश नाथ (उपस्थित), श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) (उपस्थित), श्री चंदन चौहान (उपस्थित), श्री चन्द्रपाल सिंह (उपस्थित), श्री बाबू लाल (उपस्थित), श्री जयमंगल (अनुपस्थित), श्री ज्ञानेन्द्र सिंह (उपस्थित), श्री देवेन्द्र कुमार निम (उपस्थित), श्री प्रसन्न कुमार (उपस्थित), श्री पंकज कुमार मलिक (उपस्थित), श्री प्रेम नरायन पाण्डेय (उपस्थित), श्री बम्बा लाल (उपस्थित), श्री भूपेश चौब (उपस्थित), श्री बेदी (उपस्थित), श्री महेन्द्र नाथ यादव (अनुपस्थित), श्री मूलचंद सिंह (उपस्थित), श्री रमेश चन्द्र मिश्र (अनुपस्थित), श्री रवि शर्मा (अनुपस्थित), श्री राजपाल सिंह बालियान (उपस्थित), श्री राजीव कुमार (उपस्थित), श्री विनोद चतुर्वेदी (उपस्थित), श्रीमती पूजा (उपस्थित), श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्र कुमार (उपस्थित), श्री राजेन्द्र कुमार (उपस्थित), श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (उपस्थित), श्री राम अचल राजभर (उपस्थित), श्री राम फेरन पाण्डेय (उपस्थित), श्री राम अवतार सिंह (उपस्थित), श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी (अनुपस्थित), श्री लकी यादव (अनुपस्थित), श्री लक्ष्मी राज सिंह (उपस्थित), श्री विनोद शंकर अवस्थी (अनुपस्थित), श्री श्रीकान्त कटियार (उपस्थित), श्रीमती सरोज सोनकर (अनुपस्थित), श्री हंसु राम (उपस्थित), श्री हरिओम (उपस्थित), श्री हरेन्द्र सिंह (उपस्थित), डा0 रागिनी (उपस्थित), श्रीमती गीता शास्त्री पासी (अनुपस्थित), श्रीमती सलोना कुशवाहा (उपस्थित), श्रीमती सैय्यदा खातून (उपस्थित), श्री राजेश चौधरी (उपस्थित), श्री जवाहर लाल राजपूत (उपस्थित), अमरेश कुमार (उपस्थित)।

ई0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

ई0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयी :-

1-जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत किशनी करहल मार्ग सेरम्पुरा (सामान) तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज शाक्य व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका,

---

† छापी नहीं गयी

2-जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत ग्राम रैपुरा (समान) में गंगासी रजवा की पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव नरायन शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका,

3-जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत मनिगांव मार्ग से बल्लमपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका,

4-जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत मैनपुरी-किशनी मार्ग पर नगला सड़क से सुगांव तक डामर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती प्रेमलता यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका तथा

5-जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत बासक राजावाहा पर कुर्रा में ग्राम नगला में कैटल घाट बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 5 याचिकाएं†

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थिति की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम शादीपुर में श्री जयवीर सिंह जी के घर से श्री राकेश कटेरिया जी के घर (लम्बाई लगभग 100 मी0) तक तथा नरेन्द्र सिंह जी के घर से शेरबाबू के घर (लम्बाई लगभग 50 मी0) तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेरबाबू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम किशनी में पंचायत घर से श्री अमृतलाल जी के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीता राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड हाथवंत के अन्तर्गत ग्राम फरीदा बरौली में श्री महेश प्रधान जी के घर से श्रीवास्तव जी के घर (लम्बाई लगभग 100 मी0) तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीवास्तव जी व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

4-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम मिलिक प्रथम में श्री सुरेन्द्र सिंह जी के घर से श्री रामजीलाल जी के घर (लम्बाई लगभग 100 मी0) तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

5-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अकबरपुर मस्तपुर में गढिया बम्बा से लेकर श्री नेपाल सिंह के मकान (लम्बाई लगभग 100 मी0) तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

श्री अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री अमित चौहान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाऐं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद अयोध्या, तहसील सोहावल के ग्राम मधुपुर के हनुमत नगर भरतकुण्ड मार्ग से पाना का पुरवा सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

2-जनपद अयोध्या, तहसील सोहावल के अन्तर्गत 15 वर्ष पूर्व निर्मित गन्ना विकास विभाग की सड़क महांवा छतिरवा अन्तपुर मार्ग (वि0ख0 मसौधा) के पुनर्निर्माण/मरम्मत के सन्दर्भ में श्री हीरा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

3-जनपद अयोध्या, तहसील सोहावल के अन्तर्गत जिला पंचायत अयोध्या की राष्ट्रीय राजमार्ग से कटरौली सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण/मरम्मत के सन्दर्भ में श्री साहब सरन यादव व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका तथा

4-जनपद अयोध्या, तहसील सोहावल के ग्राम पलिया रिसाली में हनुमत नगर भरतकुण्ड मार्ग से चकजंगली सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण/मरम्मत के सन्दर्भ में श्री शशि सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका।

डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम असदनगर में गंगाराम मौर्य के घर से मुन्नालाल के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पस्तौर में देवस्थान से धौंरा रोड तक खड़न्जा व गोरा नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती ममता गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सिजातपुर से ग्राम गुगई मनकरा रोड तक खड़न्जों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विशाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के जौने ठिरिया मार्ग से मिनी स्टेडियम (खेल मैदान) तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू कुर्मी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

5-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम हल्दी कलां से ग्राम औरंगाबाद के बीच भांखडा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

डा0 शिव प्रताप यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

डा0 शिव प्रताप यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के विकास खण्ड के अन्तर्गत एन0एच0-730 से ग्राम पतुली-सदाडीह तक क्षतिग्रस्त मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

2-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के विकास खण्ड के अन्तर्गत एन0एच0-730 से ग्राम सोनपुर-पुरैना क्षतिग्रस्त मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नितीश यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

3-जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गैसड़ी अन्तर्गत ग्राम छपिया-प्रतापपुर सम्पर्क मार्ग का जीरो से लेपन स्तर तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामतेज यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

4-जनपद बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी, जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गैसड़ी अन्तर्गत ग्राम भदुई-कन्धई डिहवा सम्पर्क मार्ग का जीरो से लेपन स्तर तक का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामदीन यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

5-जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड पचपेड़वा अन्तर्गत एन0एच0-730 से ग्राम मोतिहवाडीह से भैसवा सम्पर्क मार्ग का जीरो से लेपन स्तर तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका।

---

† छापी नहीं गईं।

डा0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ †

डॉ0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रोहनियां के अन्तर्गत सुजाबाद में लालचन्द्र साहनी के मकान से काली माता मन्दिर (लम्बाई लगभग 800 मी0) तक सड़क निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

2-जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रोहनियां के अन्तर्गत टिकरी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय टिकरी से उत्तर की नाली (लम्बाई लगभग 500 मी0) के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राजकुमार गौतम व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

3-जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र-387, रोहनियां के अन्तर्गत सुसुवाही विश्वकर्मा नगर कालोनी में मुख्य मार्ग से सरकारी नाले तक भूमिगत नाली का निर्माण कार्य (लगभग 500 मी0) के निर्माण के सम्बन्ध में श्री गुड्डू पटेल एवं अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

4-जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र-387, रोहनियां के अन्तर्गत छितौनी कोट में नहर से लेकर शोभनाथ पाल के घर तक सड़क (लगभग 600 मी0) के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अनील पाल एवं अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका तथा

5-जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र-387, रोहनियां के अन्तर्गत ग्राम सभा लहिया में नाली (लगभग 800 मी0) के निर्माण के सम्बन्ध में श्री बबलू पटेल एवं अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका।

डा0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

डा0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी के अन्तिम छोर पर बसा गांव वन विभाग के बिच मगरधा कला में पनकी रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण कुमार पाल एवं अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकायें व्यपगत हुयीं :-

1-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड मदनापुर में बिरियाकला के पश्चिम से रसीदपुर होते हुए खमरिया पेट्रोल पम्प तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री जयवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड मदनापुर में नगरिया से रामनगर होते हुए ग्राम बोझी तक जर्जर सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में श्री जयवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड मदनापुर में नगरिया से रामनगर होते हुए ग्राम रसीदपुर के दक्षिण डबरी नाला व कुढ़ेना नाला पर पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री जयवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

4-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड मदनापुर में ग्राम नगरिया में श्री गिरीशपाल सिंह पूर्व सैनिक के मकान से रसीदपुर डामर रोड तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री जयवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका तथा

5-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड मदनापुर में बिरिया मकन्दपुर में श्री विजय सिंह के मकान से हजरतपुर इटौआ होते हुए परौर घाट तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री जयवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका।

श्री मौ0 फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ तथा जनपद सम्भल संबंधित याचिकाएँ †

श्री मौ0 फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की गयी मानी गईं :-

1-जिला मुरादाबाद के तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम धर्मपुर कलां में रामगोपाल के मकान से कुन्दन सिंह के मकान तक लगभग 120 मीटर सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में श्री वाजिद खां, निवासी मुरादाबाद की याचिका,

2-साक्षर भारत मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश भर के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा प्रेरकों की 30 से 40 माह की बकाया मानदेय धनराशि 662.41 करोड़ रुपये के भुगतान के सम्बन्ध में मौ0 अरकान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद सम्भल के तहसील चंदौसी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम बहोरनपुर स्योंडारा से ग्राम गुरसरी तक 2 किलोमीटर सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री जोगेश्वर मौर्य निवासी जनपद सम्भल की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम रामनगर गंगपुर में प्रा0 विद्यालय से वीरेश के मकान तक 150 मीटर रास्ते की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजेन्द्र सिंह, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गईं।

5-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी व बिलारी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम पालनपुर में आशिक अली के मकान से कुशनपाल के मकान तक लगभग 150 मीटर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शहनशाह अली, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत सी0बी0एन0 मार्ग चरहुआ, गांधीग्राम वाराही माता उमरी तक मार्ग को (ओ0डी0आर0) में सम्मिलित करके चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत सुसुन्डा त्यौरासी कुड़ियावं अकोहरी पी0डी0 बंधा मार्ग को (ओ0डी0आर0) में सम्मिलित करके चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

3-जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत करनैलगंज किमी0 218 से फतेहपुर, महाराजगंज, शीशामऊ बबुरास मार्ग को (ओ0डी0आर0) में सम्मिलित करके निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मेरठ के विकास खण्ड किला परीक्षितगढ़ के अन्तर्गत ग्राम बली से ग्राम बड़ला तक काली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कालू व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका तथा

2-जनपद मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज, मेरठ व सी0एच0सी0 फलावदा तथा सी0एच0सी0 सरधना में स्टाफ की उपलब्धता कराए जाने के सम्बन्ध में श्री शाही अब्बास व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका।

---

† छापी नहीं गईं।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद चित्रकूट के वि0ख0 कर्वी के ग्राम पंचायत हिनौतामाफी में इण्टर कालेज निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केदारनाथ गुप्ता एवं अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

2-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर के वि0ख0 कर्वी के ग्राम भंभई में चकला गुरुबाबाल रोड से छेदीलाल यादव के पुरवा तक रोड व नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

3-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर के वि0ख0 कर्वी के ग्राम पंचायत छपरामाफी के गनेश का पुरवा में मेन रोड से गनेश के पुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालचन्द्र भारतीय एवं अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

4-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर के वि0ख0 कर्वी के ग्राम पंचायत भरथौल में बरूआ में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका तथा

5-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर के वि0ख0 कर्वी के ग्राम खुटहा में कुबेर सिंह पटेल के दरवाजे से राधेश्याम के दरवाजे तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय सिंह पटेल एवं अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में नगर क्षेत्र के अन्तर्गत मो0 गुलाम अलीपुरा दरगाह थाने के बगल से प्रा0वि0 होते हुए बदलूराम पहलवान के मकान होते हुए स्व0 भगौती प्रसाद गुप्ता, पूर्व सभासद के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली लगभग 500 मी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में नगर क्षेत्र के अन्तर्गत मो0 बक्शीपुरा वार्ड चांदमारी शमशान घाट से हनुमान मंदिर होते हुए नेता के मकान तक सी0सी0 व नाली लगभग 500 मी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तोताराम यादव व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

3-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में नगर क्षेत्र के अन्तर्गत मो0 बक्शीपुरा वार्ड चांदमारी हनुमान मंदिर से आगे वाली गली की आन्तरिक में होते हुए दिनेश पाण्डेय व तोताराम यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली लगभग 500 मी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

4-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चिक्तौरा ग्राम पंचायत अहिरौरा में अहिरौरा से कुम्हारनपुरवा तक डामर रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम गोपाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका तथा

5-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा ग्राम पंचायत अहिरौरा में सम्पर्क मार्ग से लालगढ़ा तक डामर रोड के निर्माण के सम्बन्ध में डा0 श्याम कुमार चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री अरमान खान, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र-171, लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत अकबरी गेट, नक्खास बाजार में भूमिगत पार्किंग स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में मो0 हाशिम एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र-171, लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत स्थित तिब्बिया यूनानी कालेज के नये भवन का निर्माण कार्य पूरा करवाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित कर संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती शबीह फातिमा एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र-171, लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत मौज्जम नगर चौराहे के पास स्थित पंजाब बेकरी से हुबलाल मंदिर के आगे तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में मो0 इरशाद उर्फ मुन्ना एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र-171, लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत अशोक नगर निकट काला पहाड़ से 5वीं गली में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती हमीदा बेगम एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गईं।

5-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र-171, लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत आवासीय मोहल्ले/कालोनी में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष कुमार मिश्रा एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री अशरफ आली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बंधित 2 याचिकाएँ†

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के वि0ख0 थानाभवन से ऊन रोड पर बुंटा लिंक तक क्षतिग्रस्त मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सलीम व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका तथा

2-जनपद शामली के ग्राम मालेन्डी राजबाहे से मालेन्डी बाईपास से होते हुए भैंसवाल नाले तक क्षतिग्रस्त मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका।

श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुयी मानी गयीं :-

1-जनपद रायबरेली के ब्लाक छतोह के अन्तर्गत ग्राम सभा बेवल में भगवान सिंह के घर से श्याम लाल पाल के दरवाजे तक लम्बाई लगभग 250 मी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान बक्श सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के ब्लाक सलोन के अन्तर्गत ग्राम सभा कालू जलालपुर में पक्की रोड से विवेक तिवारी के घर तक लम्बाई लगभग 225 मी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सियाराम मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के ब्लाक डीह के अन्तर्गत ग्राम सभा पदमनपुर में पूरे ललक में पक्की सड़क से शिव भूखन पासी के दरवाजे तक लम्बाई लगभग 220 मी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कन्धई व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के ब्लाक सलोन के अन्तर्गत ग्राम सभा केमुपुर में बबलू पाण्डेय के घर से राहुल पाण्डेय के घर तक लम्बाई लगभग 225 मी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बबलू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गईं।

5-जनपद रायबरेली के ब्लाक सलोन के अन्तर्गत ग्राम सभा बिजवलिया में राम प्रताप के घर से श्रीराम के दरवाजे तक लम्बाई लगभग 240 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रताप व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री आशु मलिक सदस्य, विधान सभा की जनपद सहानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड पुवांरका अन्तर्गत ग्राम मथना में बलाहरो वाला तालाब ट्रांसफार्मर से पूरब की ओर ग्राम सम्भल की रजापुर वाले मार्ग तक सड़क (लम्बाई लगभग 1.00 किमी0) का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रहमान व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बस्ती की विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड दुबौलिया में भिउरा मार्ग से झंगिया गांव तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती की विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत नरथरी चौराहे से पिपरहिया होते हुए बुद्धि बाजार से ठउहिवना गौनहा हलुआ मार्ग (लम्बाई लगभग 5 कि0मी0) तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती की विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत पवनीजप्ती अमरपुर गौर गांव हलुआ मार्ग (लम्बाई लगभग 1.5 कि0मी0) तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

4-जनपद बस्ती की विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत राम जानकी मार्ग से अवधूत नगर गांव तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभूषण यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

5-जनपद बस्ती की विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत भिउरा मार्ग से पकड़ी चौहान चौधरी पुरवा तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषि कुमार गौतम व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

---

† छापी नहीं गईं।

श्री कैलाश नाथ, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री कैलाश नाथ, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बलरामपुर की तहसील-तुलसीपुर के विकास खण्ड महाराजगंज तराई क्षेत्र स्थित खरझार नाले पर बने तटबन्ध को दोनों तरफ 01 किमी0 और अधिक दूरी तक बनाने के सम्बन्ध में श्री नंद कुमार वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

2-जनपद बलरामपुर की तहसील-तुलसीपुर के अन्तर्गत ग्राम महादेव, हरिहरनगर, हड़पुर, जनकपुर, ओजाहवा आदि आधा दर्जन ग्रामों को जल भराव से बचाने के लिये बूढ़ी राप्ती की खुदाई एवं सिल्ट सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष पाठक एवं अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

3-जनपद बलरामपुर की तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत मथुरा बाजार के लिए पूर्व में स्वीकृत 33/11 का विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजी अवस्थी एवं अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री गौरी शंकर वर्मा, (कोरी) सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की मानी गयीं :-

1-जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर में युवाओं को खेलने के लिये एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के उरई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत एट से कोटरा बेतवां के पुल तक सड़क के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकित गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के उरई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जालौन नगर में हुलकी माता मंदिर से ग्राम सौमई परवई के जोड़ने वाले रास्ते में नदी पर पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मलखान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के 221-उरई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उरई नगर के शहरी क्षेत्र में एक कोतवाली की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गईं।

5-जनपद जालौन के 221-उरई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रेनिया रेलवे फाटक पर उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जय नरायन साहू व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ†

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के वि0ख0 मोरना के ग्राम टन्ढेडा में प्रधान के कार्यालय से बाईपास मार्ग होते हुए बेहड़ा सादात तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खुर्रम प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

2-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के वि0ख0 जनसठ के ग्राम नया गांव भुम्मा में नन्द किशोर के मकान से शमशान घाट तक क्षतिग्रस्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अश्वनी कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

3-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के वि0ख0 मोरना के ग्राम भोपा में नहर के समीप स्थित जनता इण्टर कालेज से कावड़ तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

4-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के वि0ख0 जनसठ के ग्राम रहड़वा ब्रम्हानन्द उर्फ पप्पू के खेत से फरीदपुर तक मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

5-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के वि0ख0 मोरना के ग्राम योगेन्द्र नगर से खुशीपुर मार्ग तक मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लोकपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मार्ग गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई-दानपुर के अन्तर्गत ग्राम उमरारी से ग्राम ना तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत धर्मपुर मार्ग से ग्राम ऐदलपुर तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयवीर व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत ग्राम जरेना में खूबी मास्टर के घर से बिन्नामी के खेत तक 1200 मी0 मार्ग पर खड़ण्जा लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुंवरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई के अन्तर्गत बेलौन पैंठ से ग्राम विजय नगलिया तक 02 किमी0 मार्ग की विशेष मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनवीर व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र डिबाई की नगर पालिका डिबाई के अन्तर्गत मौहल्ला सराय किशनचन्द में ओमप्रकाश के मकान से गनेषी के मकान तक 400 मी0 मार्ग का आर0सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीनेश लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री बाबू लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री बाबू लाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत दूरा मार्ग पर रेलवे उपरिगामी मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मुख्तार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

2-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत मण्डी मिर्जा खां सामरा रोड से हनुमान मन्दिर (हवेली वाले) सहनपुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री टिकेन्दर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

3-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम सामरा की चारागाह की जमीन पर गौशाला का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

4-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत आलू प्रोसेसिंग प्लान्ट के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गईं।

5-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री होशियार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका।

श्री जयमंगल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-महराजगंज से सम्बन्धित

04 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री जयमंगल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद महाराजगज के विधान सभा क्षेत्र सदर महाराजगंज में कप्तानगंज सिसवा मार्ग से नगर पंचायत धुधली में सामुदायिक स्वास्य केन्द्र तक पक्की सड़क का निर्माण काय कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधे श्याम गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका,

2-जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर महाराजगंज के अन्तर्गत हनुमानगढ़ी से करमहा तक क्षतिग्रस्त मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश अग्रहरी व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज को याचिका,

3-जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर महाराजगंज के अन्तर्गत पड़री वार्ड में बलिया नाले पर अर्द्धनिर्मित पुल को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप गौंड व अन्य निवासीगण जनपढ़ महाराजगंज की याचिका तथा

4-जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर महाराजगंज के अन्तर्गत सेन्दुरिया से सबया तक जर्जर मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र पनियरा के अन्तर्गत नगर पंचायत पनियरा व परतावल को आदर्श नगर पंचायत घोषित कराने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका,

2-जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र पनियरा में गण्डक नदी मेदनीपुर नरायन टोला के सामने नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भोलामल व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

3-जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र पनियरा में रोहिन नदी के बंधे पर जल निकासी हेतु लाल बडहरा सुचितपुर बधौना बंधा पर पम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम निषाद व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका,

4-जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र पनियरा में नगर पंचायत पनियरा व परतावल को मानक के अनुरूप बिजली न उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुष्ण मुरारी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका तथा

5-जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र पनियरा में सिरसिया गोडधोवा मंगलपुर पटखौली मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम दूबे व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की सहारनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सहारनपुर के ब्लॉक नांगल में ग्राम बसेड़ा से ताजपुर तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

2-जनपद सहारनपुर के ब्लॉक नांगल में ग्राम साधारणसिंर से ताजपुर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र राणा व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

3-जनपद सहारनपुर के ब्लॉक रामपुर मनिहारन में ग्राम धारकी के पुल से खटकाहेड़ी तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

4-जनपद सहारनपुर के ब्लॉक रामपुर मनिहारन में चहेड़ी से पहासू तक का रास्ते का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका तथा

5-जनपद सहारनपुर के ब्लॉक बलिया खेड़ी में ताहरपुर से शमशान घाट तक सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विपुल पंवार व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका।

---

† छापी नहीं गईं।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद-शामली के वि0ख0-कांधला के एलम से भनेडा होते हुए कनियान वाया भभीसा तक लगभग 8 किमी0 मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव पंवार एवं अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

2-जनपद शामली में स्थित दोआब शुगर मिल के दक्षिण की ओर से ग्राम लिलौन तक जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण/नवीनीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कालखण्डे एवं अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

3-जनपद-शामली के वि0ख0-शामली के ग्राम लांक से भिक्का माजरा चौराहे तक लगभग 1 किमी0 मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरसैन एवं अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

4-जनपद-शामली के वि0ख0 शामली के ग्राम भाज्जू से श्मशान के पूर्व की ओर से सी0 कांटे होते हुए मुण्डभर की सीमा तक लगभग 1.500 किमी0 मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमपाल एवं अन्य निवासीगण की याचिका तथा

5-जनपद-शामली के वि0ख0-शामली के ग्राम-लिलौन में राजवाहे पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू एवं अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की मानी गईं :-

1-जनपद मुजफ्फरनगर ग्राम-दूधली एवं ग्राम कसौली, ब्लाक चरथावल में लगभग 3.00 किमी0 सड़क का निर्माण एवं इन्हीं दोनों ग्रामों के बीच हिण्डन नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल मास्टर एवं अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

2-जनपद मुजफ्फरनगर, ग्राम-लडवा, ब्लाक-बघरा, विधान सभा क्षेत्र चरथावल में पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक की नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री भोपाल एवं अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

3-जनपद मुजफ्फरनगर, ग्राम-लच्छेड़ा, ब्लाक-सदर, विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम लच्छेड़ा से साझक नाले तक सड़क मार्ग लम्बाई लगभग 2 किमी0 मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

4-जनपद मुजफ्फरनगर, ग्राम-साल्हखेड़ी, ब्लाक-बघरा, विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम साल्हखेड़ी से बुढीना कला तक सड़क मार्ग लम्बाई 2.3 किमी0 मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र एवं अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

5-जनपद मुजफ्फरनगर, ग्राम-तावली, ब्लाक-बघरा, विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ब्लाक बघरा के तावली में 01 राजकीय इण्टर कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शौकीन एवं अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयी :-

1-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड बेलसर के बिरसिंहपुर में टेढ़ी नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिवंश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज या बेलसर में गन्ना समिति की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित तिवारी एवं अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज या बेलसर में मिनी स्टेडियम की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी एवं अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज के अन्तर्गत अत्यधिक आवागमन वाला मार्ग तरबगंज, करनीपुर, रानीपुर, चौबेपुर सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अश्वनी मिश्रा एवं अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

---

† छापी नहीं गईं।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद उन्नाव, विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा दौतियाल पुर में सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू पाल एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव, विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा महमूदपुर के मजरा रोशननगर में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू पाल एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

3-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा अम्बहरा के मजरा रामपुर में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन कुमार प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सोनभद्र के ब्लाक कोन अन्तर्गत ग्राम गिधिया में अजनिया से किशुनपुरवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,

2-जनपद सोनभद्र के ब्लाक नगवा अन्तर्गत ग्राम गोटीबांध में उच्च प्रा0 विद्यालय से भलुहनिया चन्दौली जिले के बार्डर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री संदीप जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,

3-जनपद सोनभद्र के ब्लाक नगवा अन्तर्गत ग्राम सुअरसोत चरगढ़ा में रोड पर नवडीहा मोड़ के पास से कोदई गांव तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बुल्लू खरवार व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,

4-जनपद सोनभद्र के ब्लाक नगवा अन्तर्गत ग्राम गोटीबांध में नारायण केसरी के घर से सरई गाड़ बार्डर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बसन्त केसरी व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका तथा

5-जनपद सोनभद्र के ब्लाक चातरा के अन्तर्गत ग्राम नौडीहा गांव से बघैलापुखरा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चौबे व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका।

---

† छापी नहीं गईं।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित यचिका†

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां में बुढ़ानपुर पिच रोड से गजाधरपुर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री विजय एवं अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्मलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बस्ती के पोस्ट पुरानी बस्ती में अस्पताल चौराहे पर दुकानों के सामने जाने वाले रास्ते के बगल नाली बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अहमद इकबाल व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती के मोहल्ला मिल्लत नगर बेलवाडांडी वार्ड नं0-18 में पीसीओ चौराहे से उमर फारूक स्कूल तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वजैर अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती के मोहल्ला माली टोला, रहमतगंज वार्ड नं0-10 स्थित मंगल बाबा रोड से होते हुए आशिक अली के मकान होते हुए नूरजहां के मकान तक विद्युत पोल लगवाए जाने के सम्बन्ध में श्री आशिक अली व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

4-जनपद बस्ती के मोहल्ला माली टोला, रहमतगंज वार्ड नं0-10 स्थित मंगल बाबा रोड से होते हुए आशिक अली के मकान होते हुए नूरजहां के मकान तक मरम्मत सड़क कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशिक अली व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

श्री मूलचन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री मूलचन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जालौन की तहसील कोंच के अन्तर्गत सिकरी रजवाहा के पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविंद्र याज्ञिक व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के अन्तर्गत एट बंगरा भीकेपुर राज्य मार्ग पर एट के पास रेलवे क्रासिंग का उपरिगामी सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लखन गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

3-जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत रामपुरा में 132 के0वी0 का विद्युत उपकेंद्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मिट्टू चिरवारिया व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

4-जनपद जालौन की तहसील कोंच के अन्तर्गत नदीगांव में 132 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री दशरथ सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के विकास खण्ड महाराजगंज के अन्तर्गत मनीकापुर में निषाद बस्ती में बगावहा के नार पर बाक्स कलवर्ट निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकरन व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के विकास खण्ड महाराजगंज के अन्तर्गत अमीरी (कोबी)-गद्दीपुर में बाक्स कलवर्ट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन गौतम व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के विकास खण्ड महाराजगंज के अन्तर्गत राजकीय पशु अस्पताल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चंदन निषाद व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के विकास खण्ड बदलापुर के अन्तर्गत ग्राम बरौली में राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

5-जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के विकास खण्ड बदलापुर के अन्तर्गत ग्राम गढ़ा गोपालपुर में राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) †

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद झांसी महानगर के वार्ड नं0-31 सिद्धेश्वर नगर, आई0टी0आई0 के पीछे, मदन पेट्रोल पम्प के सामने नहर के पास, सीपरी बाजार में सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाकांत शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गईं।

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मुजफ्फरनगर के वि0ख0 शाहपुर के ग्राम उमरपुर से बुढाना शाहपुर रोड पुलिस चौकी तक जर्जर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सद्दाम व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

2-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के कस्बा शाहपुर स्थित हास्पिटल के बराबर से ग्राम शोरों तक (लम्बाई 1.5 कि0मी0) तक मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

3-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के वि0ख0 शाहपुर के ग्राम काकड़ा से रसूलपुर लिंक रोड तक जर्जर मार्ग (लम्बाई 1.5 किमी0) मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

4-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के वि0ख0 शाहपुर-बुढ़ाना रोड से दक्षिणी रोड ग्राम शोरो तक (लम्बाई 1.5 किमी0) मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिजेन्द्र चेयरमैन व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

5-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के बुढ़ाना खतोली रोड से टाण्डा-मजरा (लम्बाई 3 किमी0) मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चेयरमैन व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका।

श्री राजीव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजीव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विकास खण्ड किला परीक्षितगढ़ के अन्तर्गत ग्राम बली से ग्राम सठला तक काली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत ग्राम जालौन बावई मार्ग से ग्राम हरदाई राजा के आम रास्ता तक सड़क की मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 राजेन्द्र सौनकिया निवासी जनपद जालौन की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद जालौन के विकास खण्ड कदौरो में बरहई से पथरेटा मोड़ तक सड़क की मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामू महाराज, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के विकास खण्ड कदौरा में हमीरपुर मार्ग भेड़ी तक सड़क की मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवनीत मिश्रा, निवासी जनपद जालौन की याचिकार तथा

4-जनपद जालौन के नगर पालिका कालपी नगर में दुर्गा मन्दिर से कोतवाली होते हुए मुख्य बाजार खोया मण्डी एन0 एच0 के छूटे हुए भाग तक सड़क की मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज चतुर्वेदी, निवासी जनपद जालौन की याचिका।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत सड़क/पुल का कतिपय मार्गों पर निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री आशीर्वाद यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद खीरी के 90 विकास खण्ड मोहम्मदी में ग्राम मियांपुर में विस्थापित बंगाली समाज के लोगों को आवंटित भूमि को संक्रमणीय कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परमानंद घोष व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

2-जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के राजापुर बेनी 25 नं0 राजकीय नलकूप से मियांपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नत्थूलाल शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

3-जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के नगर पंचायत बरबरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

4-जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी में पोस्टमार्टम हाउस बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका तथा

5-जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी में मियांपुर से रधौला तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरदार जगजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका।

---

† छापी नहीं गईं।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थिति की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के अन्तर्गत ग्राम बरासराय में 25 के0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर, 7 पोल, तार शीघ्र लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार पाठक व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

2-जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सण्डवा चण्डिका के अन्तर्गत एफ0 सी0 आई0 गोदाम आशापुर भाटन से इण्टर कालेज पाराहमीदपुर तक दूरी लगभग 5.00 किमी0 मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव विलाश व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

3-जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सण्डवा चण्डिका के अन्तर्गत अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव विलाश व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

4-जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सण्डवा चण्डिका के अन्तर्गत बाबू का पुरवा गांव के बीच से कलेन्जर नाथ मन्दिर से होते हुए जलालपुर गांव तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव विलास व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका तथा

5-जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत गड़वारा वार्ड कुआं में गाटा संख्या-46 में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्वीकति प्रदान करवाते हुए निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजाराम व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ ग्राम तकरोही में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 05 याचिका†

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थिति की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बस्ती की तहसील भानपुर के अन्तर्गत दुबौली-काटेखैरा मार्ग पर स्थित सकतपुर से शेखापुर उर्फ इब्राहीम चक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भाल चन्द्र चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद बस्ती की तहसील भानपुर के अन्तर्गत भानपुर तेनुआ असनहरा मार्ग से दरियापुर बुजुर्ग अड़वाघाट मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती की तहसील भानपुर के अन्तर्गत मानिकचन्द्र-सल्टौआ मार्ग से पुरैना सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा/इन्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

4-जनपद बस्ती की तहसील भानपुर के अन्तर्गत जन प्रबोधन विद्यालय लक्ष्मनपुर से जी0बी0एम0 कान्वेंट स्कूल लक्ष्मनपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी जनपद बस्ती की याचिका तथा

5-जनपद बस्ती की तहसील रुधौली के अन्तर्गत हनुमानगंज-सुरवार मार्ग पर स्थित कुडी बनकटिया मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश मौर्या, निवासी जनपद बस्ती की याचिका।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं व जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 01 याचिका†

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थिति की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा बुढ़नपुर बनरबली राजभर के घर से बेलहरी पिच रोड तक सीसी रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसुन्दर राजभर एवं अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर अन्तर्गत स्थित अकबरपुर-अयोध्या सम्पर्क मार्ग (दिलीप ढाबा) से ग्राम सभा पियारेपुर प्राथमिक विद्यालय तक सीसी रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुतुबउद्दीन एवं अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3-जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड-नवाबगंज अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत सेरसा में 25 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर के स्थान पर 63 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगवाने के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा मजीसा प्रा0वि0 से अजीत यादव के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गईं।

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा रामपुर रामपट्टी (प्रा0वि0 अमरौला) से राकेश तिवारी के खेत तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पी यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला के अन्तर्गत मैदाचक सम्पर्क मार्ग से बन्तवारा तिलकपुर सम्पर्क मार्ग तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी नरायन साहू व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

2-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला के अन्तर्गत ग्राम केशवापुर रामकरन शुक्ला के घर से पंजवां प्राथमिक विद्यालय तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

3-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला के अन्तर्गत मल्हीपुर मार्ग से बैरागीपुरवा तक पिच रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम उजागर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

4-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड जमुनहा के अन्तर्गत गोपारा पुलिया से असनी सहादत नगर व गनेशपुर तक पिच रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ललित त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका तथा

5-जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला के अन्तर्गत भगवानपुर मार्ग से हड़िल्ला मन्सुखा मार्ग तक पिच रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम किवाड माइनर से हमा नंगली तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साकेत अली व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम आसराखेड़ा महमूदपुर मार्ग से अनीशा नंगली तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

3-जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत सहसपुर किवाड मार्ग से मेवा नवादा (लम्बाई लगभग 1300 मी0) तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महबूब आलम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका तथा

4-जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम मेवा नवादा से आशा खेडा महमूदपुर तक सड़क निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलफाम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका।

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद रायबरेली, विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर, विकास खण्ड-सतावं के अन्तर्गत ग्राम सभा सतांव के ग्राम शिवमंगल खेड़ा, ठकुराइनखेड़ा सम्पर्क मार्ग पर बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तराम एवं अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड खीरो के अन्तर्गत ग्राम मदनपुर में बचनू बया के खेत से बिन्दादीन के दरवाजे (लम्बाई लगभग 01 किमी0) तक सड़क मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड हरचन्दपुर के अन्तर्गत ग्राम बल्टूपुर में ढकिया रोड से शंकर कुरील के घर (लम्बाई लगभग 300 मी0) तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवा यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सतांव के अन्तर्गत ग्राम दुनियापत का पुरवा में मेन रोड से मानपुर पक्की रोड (लम्बाई लगभग 02 किमी0) तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोहन लोधी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका तथा

5-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सतांव के अन्तर्गत ग्राम सभा सतांव के ग्राम कोडर में हनुमान मंदिर के पास बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू पंच व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका।

---

† छापी नहीं गईं।

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित 01 याचिका तथा जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के भटौली घाट गंगा नदी पर नवनिर्मित पुल पर विद्युत लाइट की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर बिन्द एवं अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सिकरारा के अन्तर्गत ग्राम रीठी में गढ़ासेनी सम्पर्क मार्ग से महेन्द्र सिंह के आरा मशीन से रामनगर लम्बोदर नाथ मन्दिर सम्पर्क मार्ग तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री मनीष यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सिकरारा के अन्तर्गत जौनपुर-प्रयागराज राजमार्ग से सीहीपुर रेलवे क्रासिंग से ग्राम कन्धरपुर होते हुए रसैना पकड़ी चौराहा मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमा यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सिरकोनी में रसैना, कचगांव मार्ग कद्दूपुर तिराहा से श्रीनगर यादव बस्ती से रामदयालगंज बाजार तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष चन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

5-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सिकरारा के अन्तर्गत शाहपुर मार्ग से राजेश यादव के घर होते हुए ग्राम हरिरामपुर में स्व0 सभाजीत यादव के घर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम किशनपुर में सतीश वाल्मीकि के मकान से विनोद कुमार के खेत तक बाईपास काली रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम सहपानी में बब्लू गिरी के खेत से श्री सक्तन चौहान के खेत तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री सुमित प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

3-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम सूबरा में श्री ऋषिपाल के घर से ककोड़ तक काली सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री अभिनव ठाकुर व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम दादूपुर में गुलावठी सम्पर्क मार्ग से ग्राम पीरवियावानी तक काली सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री केशव यादव व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम आजमपुर हुसैनपुर से सम्पर्क मार्ग वैलाना तक काली सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिकायें (व्यपगत)†

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के ग्राम तकरोही में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्ययगत हुई।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मवई घनश्याम से गोपालगंज तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश पासी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कमलापुर से शीर्षापुरवा तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिवंश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चोरहा में बारातघर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

4-जनपद उन्नाव के वि0ख0 बांगरमऊ की ग्राम पंचायत कमलापुर में शिवपुरी चौराहे से परशुरामपुर सहजनी मार्ग तक मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिवंश तिवारी एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गईं।

5-जनपद उन्नाव के वि0ख0 बांगरमऊ की ग्राम पंचायत कमलापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिवंश तिवारी एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बहराइच की तहसील नानपारा के विकास खण्ड बलहा के ग्राम सभा जगन्नाथपुर बेचईपुरवा में भारत माता के एक प्राचीन मन्दिर को पुनर्जीवित किये जाने के सम्बन्ध में श्री गणेश शंकर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

2-जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा के विकास खण्ड बलहा के ग्राम सभा महोली शेरखां के ग्राम सभा सरैया तक लगभग 01 किमी0 ठोकर निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

3-जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा मोतीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहींपुरवा में ग्राम सभा सुजौली में 33 के0वी0ए0 सब-स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राजेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

4-जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा मोतीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा कुडवा में स्थित हनुमान मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक जिन्दल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका तथा

5-जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा मोतीपुर के विकास खण्ड बलहा के ग्राम सभा बगहा के मजरा गुड़ियानपुरवा में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में श्री धनीराम लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका।

श्री हंसु राम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ†

श्री हंसु राम, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थिति की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बलिया के ग्राम भीमपुरा नं0-2, ब्लाक-नगरा, तहसील बेल्थरा रोड में चकबन्दी प्रक्रिया में जो आदेश हुए हैं उसको 41 व 42 का पालन कराते हुए धारा-52 के प्रकाशन के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद बलिया के ग्राम तुर्की दौलतपुर, ब्लाक नगरा, तहसील बेल्थरा रोड, जनपद बलिया में स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में श्री कांशीराम एवं अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

3-जनपद बलिया के नगरा तुर्तीपार मार्ग पर से रामपुर चन्देला तक ब्लाक सीयर, तहसील बेल्थरा रोड, जनपद बलिया के लगभग 05 किमी0 जर्जर रोड के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अजय राजकुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

4-जनपद बलिया के सुजनापुर रनऊपुर मार्ग से पुरापुर राजभर बस्ती होते हुए कौवापुर तक ब्लाक नगरा, तहसील बेल्थरा रोड, जनपद बलिया के लगभग 03 किमी0 सड़क का नव निर्माण के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका तथा

5-जनपद बलिया के रतनपुरा भीमपुरा मार्ग से त्रिलोकमंदा तक ब्लाक नगरा, तहसील बेल्थरा रोड, जनपद बलिया के लगभग 05 किमी0 जर्जर रोड के निर्माण के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश एवं अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका।

श्री हरिओम, सदस्य विधान सभा की जनपद कासंगज से सम्बन्धित याचिका†

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज विधान सभा क्षेत्र-101, अमापुर के ग्राम मानपुर नगरिया में राकेश बघेल के घर से सेन्ट बी0एन0 पब्लिक स्कूल तक मार्ग पर सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज एवं अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम मौहम्मदपुर साकरपुर गन्ना सेन्टर से ग्राम नयागांव इनायतपुर तक लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री परमवीर व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थिति की हुई मानी गयीं :-

1-जिला जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कोठारी में दयाशंकर के घर से शेषनारायण के घर तक पिच रोड की मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रधान निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जिला जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-कटाहित खास से हरद्वारी तक आर0सी0 ड्रेन की सफाई के सम्बन्ध में श्री अशोक सोनकर निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जिला जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-सराययूसुफ में एन0एच0-31 कैलाश मौर्या के घर के पास खेल के मैदान तक मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जिला जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-मनिकापुर भरसवां तिराहे से सगरे नहर तक मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद गौतम, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका तथा

5-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चिंताव में राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय की दुकान से उदयशंकर के घर तक मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अर्जुन प्रसाद मौर्या, निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

श्रीमती गीता शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्रीमती गीता शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद प्रयागराज के ग्राम कठवर परेवपुर सीताराम के घर से राम बहादुर के घर तक नाला सहित पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सीताराम व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम कुसूंगर जिंसी सम्पर्क मार्ग की चक्की से पप्पू त्यागी के घर तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम महरौडा से छीतेमऊ तक कच्ची सड़क को पक्की सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम घीनपुर (महमतपुर) में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निसार अली व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अहिराई में ट्रासफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

---

† छापी नहीं गईं।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ†

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित हुई मानी गयीं :-

1-जनपद शाहजहाँपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत वि0ख0 निगोही में परसौना खलीलपुर मार्ग से चौड़ेरा मार्ग (लम्बाई लगभग 01 कि0मी0) सड़क का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहाँपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत वि0ख0 सिधौली में निगोही मुडिया वैश्य से नगरिया मार्ग (लम्बाई लगभग 1.70 कि0मी0) तक सड़क का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहाँपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत वि0ख0 निगोही के निगोही खुदागंज मार्ग से बरौरा सम्पर्क मार्ग (लम्बाई लगभग 1.30 कि0मी0) तक सड़क का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फूलबदन व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका तथा

4-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम रटी मार्ग से प्राथमिक विद्यालय रटी तक सम्पर्क मार्ग नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री सुरेश व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ†

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत बरगदवा से सिसई कला होते हुए कोडराव नानकर तक नाले के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अब्दुल सलाम निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका,

2-जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत बिथरियां में राप्ती नदी के तट पर साइफन के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मलिक मोहम्मद असजद निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गईं।

3-जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत ग्राम लटिया में सरयू नहर पर बने साइफन पर नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फैजान हुसैन व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका।

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएँ†

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयी :-

1-जनपद मथुरा के माँट तहसील के कस्बा नौहझील में मेन रोड के किनारे लोक निर्माण विभाग मथुरा द्वारा सरकारी जमीन को शीघ्र कार्रवाई कर अवैध कब्जाधारियों से कब्जामुक्त कराने के सम्बन्ध में श्री प्रशांत गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

2-जनपद मथुरा के माँट तहसील के अन्तर्गत श्री सरदार पटेल इण्टर कॉलेज देवनगर, माँट की प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये जमीन घोटाले व कतिपय वित्तीय अनियमितताओं की जाँच कराने के सम्बन्ध में श्री बनी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

3-जनपद मथुरा के माँट तहसील की ग्राम पंचायत दिल्लूपट्टी में बाजना मुडलिया रोड पर साईं धाम कालोनी में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री हरिओम पुजारी व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

4-जनपद मथुरा के छाता तहसील की ग्राम पंचायत शेरगढ़ व कतिपय स्थानों की पृथक-पृथक सीमांकन कराने के सम्बन्ध में श्री खेमचन्द पुजारी व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका तथा

5-जनपद मथुरा के माँट तहसील की ग्राम पंचायत पिहरी में सिंचाई विभाग के नाले के ऊपर कुछ हिस्से में किये गये अवैध कब्जे से कब्जामुक्त करा कर नाले को खुदवाने के सम्बन्ध में श्री रनवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ तथा जनपद कन्नौज व आगरा से सम्बन्धित 01-01 याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत ब्लाक गुरसरांय के ग्राम गुढ़ा (धासान नदी के तट पर) के पास झारखण्ड (विश्वामित्र की स्थली) पर रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद कन्नौज की ब्लाक तिर्वा, ग्राम पंचायत बिनौरा के ग्राम रामपुर में नाली एवं आर0सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतलेश राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज की याचिका,

3-जनपद आगरा की ब्लाक जैतपुर की ग्राम पंचायत पारना के मजरा फकीरे की मड़ैया को स्थायी रूप से इटावा जनपद की जसवन्तनगर से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

4-जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में वेयरहाउस बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री हर प्रसाद पटेल व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका तथा

5-जनपद झांसी की मुख्य बेतवा नहर के किनारों की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रहलाद दांगी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका।

श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत द्वारिकापुरी वार्ड में रामभरोसे स्कूल के पीछे अम्बेडकरपुरम तेलीबाग में सड़क व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री जमुना प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अध्यक्ष-

कुछ नहीं है। मद सं0-07, 08 व 09 में कुछ नहीं है।

अब मद संख्या-10

[08:15] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष आज दिनांक 28-02-2023 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 97 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री अनिल पाराशर की जनपद अलीगढ़ शहर में स्मार्ट सिटी योजना अन्तर्गत विद्युत पोल खड़ा कर छोड़ दिये जाने से हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती पूजा की जनपद आजमगढ़ में मूल्य समर्थित योजनान्तर्गत धान खरीद की ऑनलाइन फीडिंग न होने से जनपद के किसानों को होने वाली समस्या के समाधान के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री रामखिलाड़ी सिंह की कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वार्ड सं0-37 में कतिपय भू-खण्ड को अधिग्रहण से मुक्त करवाने अथवा उचित मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया की प्रदेश के नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिशासी अधिकारी की मूल विभाग में

---

† छापी नहीं गईं।

वापसी किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री मनीष असीजा की उ0प्र0 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्ड धारकों को त्यौहारों पर एक किलो चीनी प्रति कार्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा छठी सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद उन्नाव में वित्तीय अनियमितता के बावजूद ग्राम प्रधान को निलम्बित न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है वक्तत्व हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री राजपाल सिंह बालियान की जनपद मुजफ्फरनगर के बुढाना के समुदायिक केन्द्र में डॉक्टर/नर्स स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में है, तथा दूसरी सूचना श्री मो0 फहीम इरफान की जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी में भेला राम पेपर मिल में अवैध कब्जे व प्रदूषण आदि के निदान के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री ज्ञानेन्द्र सिंह की जनपद महराजगंज व ब्लॉक पनियरा से जिला मुख्यालय, गोरखपुर पर कतिपय पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर के भीटी बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर में जन्हेड़ा समसपुर से पहासू तक मार्ग चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री प्रभू नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली नगर पालिका परिषद् में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के बकाये भुगतान के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री रमेश जायसवाल- की जनपद मुगलसराय के नगर पालिका परिषद् में कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, तथा छठी सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की जनपद जालौन के काल्पी में समुदायिक स्वास्थ्य में डाक्टर की कमी एवं डाक्टरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है :-

श्रीमती सरिता भदौरिया, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री योगेश शुक्ला, श्री रमेश, श्री देवेन्द्र सिंह, श्रीमती सैय्यदा खातून, श्री संदीप सिंह, श्री प्रकाश द्विवेदी, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री राम अवतार सिंह सैनी, श्री जाहिद, डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, श्री राकेश कुमार गोस्वामी, श्री बम्बालाल, श्रीमती नीलिमा कटियार, श्री तेजपाल सिंह नागर, श्री राम दुलार, श्री ब्रजभूषण राजपूत, श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री राजीव कुमार, श्री मो0 ताहिर खान, श्री अरमान खान, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्री अनिल कुमार, श्रीमती अंजुला माहौर, डॉ0 शिव प्रताप यादव, श्री राम सिंह, श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री गौरव कुमार, डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री मो0 हसन रूमी, श्री संग्राम सिंह, ई0 बृजेश कठेरिया, श्री अजय सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, श्री ज्ञान तिवारी, श्री मानवेन्द्र सिंह, श्री पूरन प्रकाश, श्री पल्टूराम, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री गौरी शंकर वर्मा, श्री गणेश चन्द्र, श्री ऋषि त्रिपाठी, श्री बाबूलाल, श्री कमाल अख्तर, श्री बाबूराम, श्री जियाउर्रहमान बर्क, श्रीमती मनीषा, श्री बेदी, श्री राजेश चौधरी, श्री आनन्द कुमार यादव, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री जैकिशन साहू, डॉ0 नीरज बोरा, श्री राजेश्वर सिंह, श्री रामफेरन पाण्डेय, श्री साकेन्द्र प्रताप, श्री अशरफ अली खॉन, श्रीमती मनीषा रावत, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, डॉ0 मुकेश वर्मा,

ई0 सरवन कुमार निषाद, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री विनोद सरोज, श्री अभय सिंह, श्री विवेक कुमार वर्मा, श्री राम अचल राजभर, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री निर्मल वर्मा, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री लकी यादव, श्री मोहन वर्मा, श्री विपुल दुबे श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री अमरेश कुमार, श्री तसलीम अहमद, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री राजीव गुम्बर।

[08:18] जनपद मुजफ्फनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के विकास खण्ड मोरना में कतिपय ग्रामों के निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में श्री चन्दन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री ब्रिजेश)-

मान्यवर, ग्राम भौकरहेडी से खैर नगर मार्ग- उक्त मार्ग मोरना से भौकरहेडी होकर मजलिसपुर तौफीर खैर नगर सिताबपुरी होते हुए उत्तराखण्ड.....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक हैं, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तत्व लोक निर्माण राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[बार्डर तक जाता है। मार्ग की कुल लम्बाई 17.500 किमी0 है। यह मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। ग्राम खैर नगर उक्त मार्ग के किमी0-16 में पड़ता है। मार्ग का किमी0-7.300 भौकरहेडी आबादी भाग में सी0सी0 रोड एवं किमी0-8 में क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण का कार्य विशेष मरम्मत के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। किमी0-1 से 13 तक नवीनीकरण के कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। मार्ग का शेष भाग सन्तोषजनक अवस्था में है।

बरूकी से पचैण्डा तक मार्ग-उक्त मार्ग ग्राम बरूकी से पचैण्डा को जोड़ता है, जिसकी लम्बाई 3.00 किमी0 है। उक्त मार्ग के विशेष मरम्मत की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

तेवड़ा से खेडी फिरोजाबाद मार्ग-प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 2.00 किमी0 है, जो वर्तमान में खड़न्जे स्तर का मार्ग है। तेवडा एवं खेडी फिरोजाबाद मार्ग पूर्व में लेपित मार्ग से जुड़े हैं।

अतः मार्ग डबल कनेक्टिविटी की प्रकृति का होने के कारण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मोरना भोपा मार्ग से तिस्सा मार्ग-प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 4.20 किमी0 है, जिसके मरम्मत के कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

श्री अध्यक्ष-

मा0 चन्दन चौहान जी, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिये।

श्री चन्दन चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें नाम गलत लिखा है। इसमें मुजफ्फरनगर की जगह मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है। इसे करेक्ट करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मेरे ख्याल से गलती से मुजफ्फरपुर छप गया है, लेकिन उत्तर तो सही है।

श्री चन्दन चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, ज्यादातर जवाब इस तरह के आए हुए हैं कि स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, इसमें मेरा एक निवेदन है कि नियम-51 की इस प्रकार की जो सूचनाएं हम स्वीकार करते हैं वह बहुत कम संख्या में स्वीकार करते हैं, तो जो भी मा0 सदस्य सुबह से शाम तक बैठते हैं, मेहनत करते हैं और सूचनाएं लगाते हैं, तो यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति तब तक मान लीजिये जब तक आपके वित्त मद में पैसा है। यहाँ पर मा0 सदस्य बोलेंगे तो उनका जरूर स्वीकार होना चाहिये।

[08:20] जनपद-फिरोजाबाद के स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को पूर्ण क्षमता से शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, जनपद-फिरोजाबाद में स्थित स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को पूर्ण क्षमता से संचालित कराये जाने हेतु निम्न की आवश्यकता है। ...

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[1-स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में अनाविस्ट अस्पताल (कॉलेज परिसर), अस्पताल की लोकेशन में परिवर्तन, भूमि विवाद सामग्री/श्रमिक दरों में वृद्धि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के एवं अन्य मद जो स्वीकृत आगणन में नहीं थे, के कारण पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति की प्रत्याशा में शासन में लम्बित है। इसके कारण मेडिकल कॉलेज के कई महत्वपूर्ण कार्य अपूर्ण हैं, जिसमें रोगियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और थोड़े से कार्य के अपूर्ण होने की स्थिति में सारा सिस्टम अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है।

2-कांच चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादन के लिये प्रसिद्ध फिरोजाबाद में गर्म कांच की भट्ठियों एवं बर्नरों पर बड़े पैमाने पर कार्य करने वाले श्रमिकों की दुर्घटनावश जलने पर इलाज हेतु 'डेडिकेटेड बर्न यूनिट' न होने के कारण अन्यत्र रेफर कर दिया जाता है, जिसके कारण अधिकांश गम्भीर रूप से जले श्रमिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है तथा जनपद से सी0एम0ओ0 की रिपोर्ट भी इस आशय से शासन में प्रेषित की जा चुकी है।

3-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर अवस्थित 25 लाख से अधिक आबादी वाले औद्योगिक नगर फिरोजाबाद के मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर में एम0आर0आई0 मशीन की सुविधा नहीं होने के कारण गम्भीर रूप से घायल नागरिकों को आगरा आदि रेफर कर दिया जाता है, जिसके कारण अधिकांश को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाता है।

4-प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत 100 शैय्या के क्रिटिकल केयर ब्लाक हास्पिटल के शीघ्र निर्माण आरम्भ कराये जाने के क्रम में कार्यदायी संस्था का चयन कराये जाने के सम्बन्ध में।

5-स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में आडिटोरियम भवन की साज-सज्जा अपूर्ण पड़ी हुई है।

6-एम0बी0बी0एस0 बैच-2019 फाइनल वर्ष में प्रवेशित हैं एवं अप्रैल 2024 में उत्तीर्ण होने के उपरान्त उक्त बैच की इन्टर्नशिप प्रोग्राम प्रस्तावित है। इनके लिये 60 बेडेड पुरुष एवं 40 बेडेड महिला सिंगल सीटेड बहुमंजिला भवन मय गेस्ट हाउस एवं रिफ्रीयेशनल रूम, रिसेप्शन की आवश्यकता है।

7-वर्तमान में इस कॉलेज हेतु 36 सीनियर रेजीडेन्ट के पद सृजित हैं एनएमसी मानकों के अनुरूप सीनियर रेजीडेन्ट के पदों हेतु शत-प्रतिशत बहुमंजिला भवन की आवश्यकता है, जिससे कि महाविद्यालय के शैक्षणिक व चिकित्सकीय कार्य सुचारु रूप से चलते रहें।

8-चिकित्सा शिक्षकों हेतु मानकीकरण के अनुसार कुल 94 पद सृजित हैं, जिसमें इन चिकित्सा शिक्षकों के आवास हेतु टाइप-5 के 15 आवास, टाइप-4 के 20 आवास व टाइप-3 के 20 आवास की आवश्यकता है। क्योंकि यह महाविद्यालय शहर से लगभग 7 किमी0 दूर है एवं इसके चारों ओर सुविधा उपलब्ध नहीं है।

व्यापक जनहित के दृष्टिगत फिरोजाबाद के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृत कराये जाने, डेडीकेटेड बर्न यूनिट की स्थापना कराये जाने, एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना कराये जाने, 100 शैय्या क्रिटिकल केयर ब्लाक हास्पिटल का कार्य आरम्भ कराये जाने, ऑडिटोरियम की साज-सज्जा, इन्टर्न हॉस्टल, सीनियर रेजीडेन्ट हॉस्टल, चिकित्सा शिक्षकों हेतु आवासों की स्थापना कराये जाने की महती आवश्यकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये वक्तव्य की मांग करता हूँ।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में बिन्दुवार टिप्पणी निम्नवत् है :-

क्र0	मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना	टिप्पणी
1	स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में अनाविस्ट अस्पताल (कॉलेज परिसर), अस्पताल की लोकेशन में परिवर्तन, भूमि विवाद सामग्री/श्रमिक दरों में वृद्धि के एवं अन्य मद जो स्वीकृत आगणन में नहीं थे के कारण पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति की प्रत्याशा में शासन में लम्बित है। इसके कारण मेडिकल कॉलेज के कई महत्वपूर्ण कार्य अपूर्ण हैं, जिसमें रोगियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और थोड़े से कार्य के अपूर्ण होने की स्थिति में सारा सिस्टम अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है।	(1) शासनादेश दिनांक 26-07-2016 द्वारा मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद के निर्माण हेतु मूल लागत रु0 185.7333 करोड़ पर अनुमोदन प्रदान किया गया। (2) उक्त के उपरान्त शासनादेश दिनॉक 09-03-2019 द्वारा मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत रु0 193.2255 करोड़ (मूल लागत के सापेक्ष रु0 7.4922 करोड़ की वृद्धि) पर अनुमोदन प्रदान किया गया। (3) व्यय वित्त समिति (3) व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.12.2021 में प्रायोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत रु0 227.1861 करोड़ पर सहमति दी गई है जिस पर मा0 मंत्रि परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। (4) प्रायोजना की भौतिक प्रगति 94 प्रतिशत है। प्राथमिकता निर्धारित करते हुए अवशेष निर्माण कार्य कराया जायेगा।
2	कांच चूड़ी एवं अन्य काँच उत्पादन के लिये प्रसिद्ध फिरोजाबाद में गर्भ काँच की भट्टियों एवं बर्नरों पर बड़े पैमाने पर कार्य करने वाले श्रमिकों को दुर्घटनावश जलने पर इलाज हेतु 'डेडिकेटेड बर्न यूनिट' न होने के	(1) जिला चिकित्सालय के उच्चीकरण के परिणामस्वरूप संचालित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में जिला चिकित्सालय द्वारा पूर्व में प्रदान की जा रही द्वितीयक चिकित्सा सुविधायें भी उपलब्ध करायी जा रही है।

क्र0	मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना	टिप्पणी
	कारण अन्यत्र रेफर करा दिया जाता है, जिसके कारण अधिकांश गम्भीर रूप से जले श्रमिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है तथा जनपद से सी0एम0ओ0 की रिपोर्ट भी इस आशय से शासन में प्रेषित की जा चुकी है।	(2) यह मेडिकल कालेज सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत निरन्तर विकसित हो रहा है। ऐसी स्थिति में गम्भीर रूप से जले हुये रोगियों को तृतीयक स्तरीय चिकित्सा सुविधा हेतु सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थानों को रिफर किया जाता है।
3	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर अवस्थित 25 लाख से अधिक आबादी वाले औद्योगिक नगर फिरोजाबाद के मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर में एम0आर0आई0 मशीन की सुविधा नहीं होने के कारण गम्भीर रूप से घायल नागरिकों को आगरा आदि रेफर कर दिया जाता है, जिसके कारण अधिकांश को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाता है।	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 23-04-2022 द्वारा ईसीआरपी-2 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद हेतु 01 एमआरआई मशीन धनराशि रु0 13.55 करोड़ की लागत से स्थापना की अनुमति प्रदान की गयी है, इसके क्रय हेतु उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, लखनऊ को निर्देशित किया गया है।
4	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत 100 शैय्या के क्रिटिकल केपर ब्लाक हास्पिटल के शीघ्र निर्माण आरम्भ कराये जाने के क्रम में कार्यदायी संस्था का चयन कराये जाने के सम्बन्ध में।	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत 100 शैय्या का क्रिटिकल केयर ब्लाक हास्पिटल एन0एच0एम0 द्वारा स्वीकृत है।
5	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में आडिटोरियम भवन की साज-सज्जा अपूर्ण पड़ी हुई है।	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में आडिटोरियम भवन हेतु प्रस्ताव प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 13-02-2023 द्वारा शासन को सन्दर्भित किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है।
6	एम0बी0बी0एस0 बैच 2019 फाइनल वर्ष में प्रवेशित हैं एवं अप्रैल 2024 में उत्तीर्ण होने के उपरान्त उक्त बैच की	एम0बी0बी0एस0 बैच 2019, जो कि फाइनल वर्ष में प्रवेशित बताया गया है, के लिए 60 बेडेड पुरुष एवं 40 बेडेड महिला सिंगल

क्र0	मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना	टिप्पणी
	इन्टर्नशिप प्रोग्राम प्रस्तावित है। इनके लिये 60 बेडेड पुरुष एवं 40 बेडेड महिला सिंगल सीटेड बहुमंजिला भवन मय गेस्ट हाउस एवं रिफ्रीयेशनल रूम, रिसेप्शन की आवश्यकता है।	सीटेड मय गेस्ट हाउस एवं बहुमंजिला भवन रिफ्रीएशनल रूम, रिसेप्शन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 13-02-2023 द्वारा शासन को सन्दर्भित किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
7	वर्तमान में इस कॉलेज हेतु 36 सीनियर रेजीडेन्ट के पद सृजित हैं एनएमसी मानकों के अनुरूप सीनियर रेजीडेन्ट के पदों हेतु शतप्रतिशत बहुमंजिला भवन की आवश्यकता है जिससे कि महाविद्यालय के शैक्षणिक व चिकित्सकीय कार्य सुचारू रूप से चलते रहें।	सीनियर रेजीडेन्ट के 35 पदों हेतु बहुमंजिला भवन का प्रस्ताव प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 13-02-2023 द्वारा शासन को सन्दर्भित किया गया है। प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
8	चिकित्सा शिक्षकों हेतु मानकीकरण के अनुसार कुल 94 पद सृजित हैं जिसमें इन चिकित्सा शिक्षकों के आवास हेतु टाइप-5 के 15 आवास, टाइप-4 के 20 आवास व टाइप-3 के 20 आवास की आवश्यकता है, क्योंकि यह महाविद्यालय शहर से लगभग 7 किमी दूर है एवं इसके चारों ओर सुविधा उपलब्ध नहीं है।	चिकित्सा शिक्षकों के आवास हेतु टाइप-5 के 10 आवास व टाइप-4 के 20 आवास विषयक प्रस्ताव प्रधानाचार्य के पत्र दिनांक 13-02-2023 द्वारा शासन को सन्दर्भित किया गया है। प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।]

[08:22] जनपद-रायबरेली मे यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा एन0टी0पी0सी0 तापीय परियोजना के अन्तर्गत पुल/पुलियों का निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य

जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार, जनपद रायबरेली में नहरों की सफाई, पुल-पुलियों के निर्माण/मरम्मत हेतु एक परियोजना ....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(जल शक्ति मंत्री का वक्तत्व, उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[Restoration of Dalmau Pump Canal (Left) from Km. 0.000 to 28.646 and T.F.C. from Km. 0.000 to 13.071 for Extended 6th New unit of N.T.P.C. Unchahar, Raebareli बनायी गयी, जिसका वित्त पोषण एन0टी0पी0सी0 ऊँचाहार, रायबेरली द्वारा किया गया है।

परियोजना की लागत रु0 20.90 करोड़ है तथा प्रथम फेज में रु0 11.90 करोड़ का कार्य परियोजना के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है। कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 है ।

एन0टी0पी0सी0 ऊँचाहार, रायबेरली द्वारा दिनांक 28-10-2016 को धनराशि रु0 2 करोड़ 8 हजार की प्रथम किस्त सिंचाई विभाग को दी गयी है। उक्त धनराशि यू0पी0पी0सी0एल0 को दिनांक 14-02-2017 को उपलब्ध करा दी गयी है, जिसके सापेक्ष रु0 1.7371 करोड़ के कार्यों का सत्यापन संयुक्त रूप से एन0टी0पी0सी0, यू0पी0पी0सी0एल0 व सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया है तथा बीजक समायोजन हेतु एन0टी0पी0सी ऊँचाहार को दिनांक 07-11-2022 को प्रेषित कर दिया गया है।

यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा प्राप्त धनराशि से डलमऊ पम्प कैनाल में 39 वी0आर0बी0/डी0आर0बी0/पक्के मरम्मत के कार्यों के सापेक्ष 27 अदद वी0आर0बी0/डी0आर0बी0 के कार्य करा दिये गये हैं।

थर्मल फीडर चैनल के 15 वी0आर0बी0/डी0आर0बी0/पक्के कार्यों के सापेक्ष 10 कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं। लिंक चैनल के किमी0 0.000 से 03.200 तक एवं डलमऊ पम्प कैनाल के किमी0 00.000 से 01.070 तथा किमी0 23.000 से 28.646 तथा थर्मल फीडर चौनल के किमी0 0.000 से 13.071 तक नहर की सिल्ट सफाई/नहर के आन्तरिक भाग के पुनरोद्धार के कार्य करा दिये गये हैं।

डलमऊ पम्प कैनाल के किमी0 04.203 पर स्थित ग्राम दीनगंज की क्षतिग्रस्त पुलिया में ह्यूम पाइप डालकर अस्थायी रूप से आवागमन हेतु मरम्मत का कार्य करा दिया गया है, जिस पर आवागमन हो रहा है।

किमी0 16.161 एवं किमी0 18.481 के क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर ह्यूम पाइप डालकर अस्थायी रूप से आवागमन हेतु चालू करा दिया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माननीय सदस्य, विधान सभा के ही शिकायती पत्र पर 03-12-2019 को टी0ए0सी0 जाँच करने के आदेश दिये गये। टी0ए0सी0 द्वारा जांच सम्पन्न कर ली गयी है एवं टी0ए0सी0 से प्राप्त जाँच रिपोर्ट शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, रायबरेली खण्ड (द0) शारदा नहर, रायबरेली के पत्र दिनांक 16-11-2022 एवं पत्र दिनांक 05-01-2023 द्वारा भी परियोजना निर्माण हेतु धनराशि रु0 562.40 लाख की मांग एन0टी0पी0सी0 ऊँचाहार से की गई है, परन्तु अभी तक धन उपलब्ध नहीं हुआ है, एन0टी0पी0सी0 ऊँचाहार द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया है कि धन के अनुमोदन हेतु पत्रावली उच्च स्तर को प्रेषित की गई है, शीघ्र ही धन उपलब्ध करा दिया जायेगा। एन0टी0पी0सी0 द्वारा स्वीकृत परियोजना के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।]

श्री अध्यक्ष-

मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछ लें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, यह हमारे विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-डलमऊ की दो पुलियों के निर्माण के सम्बन्ध में है। कुल 30-35 लाख रुपये का काम है और दीनगंज तथा उधनपुर की लगभग 16 ग्राम पंचायतें तथा उसके साथ जुड़ी हुयी 12-13 ग्राम पंचायतों के लोगों का आवागमन बन्द है। मा0 मंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि इस पुलिया का निर्माण करा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी करा दीजिए।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

ठीक है मा0 अध्यक्ष जी करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी बहुत-बहुत धन्यवाद।

[08:24] जनपद-मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रूप से उपलब्ध कराये जाये के सम्बन्ध में श्री मौहम्मद फहीम इरफान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मंयकेशवर शरण सिंह)-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से जिला चिकित्सालय....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[जिला मुरादाबाद में हेपेटाइटिस-बी एवं सी के उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है। मुरादाबाद जिला चिकित्सालय में प्राविधान है, जिसे मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से रेफर होने की दशा में उपलब्ध करायी जा रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलारी पर दैनिक चिकित्सीय सुविधायें समस्त रोगियों को उपलब्ध करायी जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्स-रे टेक्नीशियन तैनात हैं तथा एक्स-रे की सुविधा प्रदान की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पी0पी0पी0 मोड से गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा एवं सिजेरियन प्रसव की सुविधा उपलब्ध है।]

श्री अध्यक्ष-

इरफान जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछ लीजिए।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मा0 अध्यक्ष जी यह बड़ा गम्भीर विषय है और इस पर मैं बताना चाहूँगा कि जनहित में लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत ग्राम बनियाठेर, थांवल, करसरा, नरसरा, बिचौला ढूकी, नसीरपुर धन्ना, रूस्तमपुर खास, बनियाठेर समेत कई गांवों में हेपेटाइटिस-बी और सी के मरीजों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर कोई स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं, तो पूछिए ।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मा0 अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि बिलारी नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हेपेटाइटिस-बी और सी का इलाज मुहैया कराने में मदद मिल जाए। दूसरी बात जिला अस्पतालों पर आपके द्वारा जो हेपेटाइटिस-बी और सी का इलाज कराने की पहल शुरू की गयी थी, वह सिर्फ कागज पूर्ति के लिए ही सुचारु है। धरातल पर इसका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। जिला अस्पताल के डाक्टर अस्पताल में जांच मशीन होने के बावजूद मरीजों को मेरठ या फिर मुरादाबाद के प्राइवेट लैबों पर जांच कराने के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लिए मजबूर करते हैं। जहां पर डाक्टरों की प्राइवेट लैबों के साथ पहले से ही अच्छी सांठ-गांठ होती है। इसके अलावा जब वह जांच कराकर लाते हैं और उनको यदि जांच में पॉजिटिव आता है तो उनको दवाई के लिए कई-कई दिन तक टाला जाता है। यदि मरीज ब्लड बैंक में मौजूद दवाई वितरकों की जेब गर्म कर दें तो उनको दवाई तुरन्त उपलब्ध हो जाती है। जिसके चलते मरीजों को मेरठ, दिल्ली आदि के अस्पतालों में पहुँचकर अपना इलाज कराना पड़ रहा है। मैं अपने मंत्री जी से अन्त में गुजारिश करना चाहूंगा कि क्योंकि बिलारी विधान सभा क्षेत्र के इन ग्रामों में हेपेटाइटिस-बी और सी लगातार पैर पसार रहा है, उनके रोकथम हेतु उचित जांच की व्यवस्था के साथ उनका प्रॉपर इलाज कराया जाना जनहित के लिए बेहद जरूरी है। इस पर माननीय मंत्री जी गोपनीय तरीके से जांच कराकर सम्बन्धित दोषियों पर कार्रवाई करने का कष्ट करें। साथ ही बिलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हेपेटाइटिस-बी और सी का इलाज उपलब्ध कराया जाए, जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के मरीजों को दूर-दराज न जाना पड़े।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो बिलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां पर कुल 18 पद सृजित हैं जनमें से 17 लोग कार्यरत हैं। हेपेटाइटिस सी के कुल केस वहां पर 2892 आए थे जिनमें से 1837 लोगों का इलाज हो गया है और वह पूर्ण रूप से ठीक होकर घर जा चुके हैं। मौजूदा समय में 1055 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हेपेटाइटिस बी के 12 मरीज आए हैं और उन सभी मरीजों का इलाज वर्तमान में चल रहा है और जो हमारा जिला अस्पताल है वह पूरी तरह से उनका इलाज कर रहा है।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, जो इलाज चल रहा है वह मुरादाबाद में चल रहा है मरीजों की तादात मुरादाबाद जिले में अगर कहीं पर है तो वह मेरी विधान सभा क्षेत्र बिलारी में है। पर्टीकुलर अगर यह केसेज सबसे ज्यादा कहीं मिल रहे हैं तो वह मेरी विधान सभा क्षेत्र बिलारी के उन गांवों में मिल रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। मैंने गुजारिश यह की थी कि जो हमारा अस्पताल है वह बिलारी में है उसमें यह व्यवस्था हो जाए। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है, मेरे पास साक्ष्य मौजूद हैं जो लोग हमारे मुरादाबाद जाते हैं इलाज कराने के लिए उनकी जांचे बाहर से करायी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मैं यह चाहता हूँ कि हमारे यहां 300 से ज्यादा की ओ0पी0डी0 है । मैं यह चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस सी की दवाई बिलारी अस्पताल में मुहैया हो जाए।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हेपेटाइटिस बी और सी यह एक तरह का इन्फेक्शन होता है और यह एक गम्भीर रोग है और सी0एच0सी0 स्तर पर इस तरह के गम्भीर रोगों का इलाज सम्भव नहीं है, इसके लिए स्पेशलिस्ट डाक्टर भी होने चाहिए। यह सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

[08:27] जनपद-अम्बेडकरनगर के कटेहरी बाजार (प्रतापपुर चमुर्खा) को नगर पंचायत बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तब्य

नगर विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पंचायतों के गठन हेतु पुनर्निर्धारित शासनादेश.....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(नगर विकास मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पंचायतों के गठन हेतु पुनर्निर्धारित शासनादेश संख्या- 2979/9-1-2016-426सा/2014, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है । जिसमें मुख्य मानक- प्रस्तावित क्षेत्र की जनसंख्या 20,000 या उससे अधिक होना, 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होना, शहरी गुण होना निर्धारित किया गया है।

उपयुक्त सूचना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के पत्र दिनांक 14-05-2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार कटेहरी बाजार, राजस्व ग्राम नहीं है, अपितु ग्राम पंचायत प्रतापपुर चमुर्खा में स्थित है। ग्राम पंचायत प्रतापपुर चमुर्खा विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के अन्तर्गत आता है, जो अयोध्या से अकबरपुर जनपदीय मार्ग पर अवस्थित है। कटेहरी बाजार की जनसंख्या लगभग 5500 है, जो ग्राम पंचायत प्रतापपुर चमुर्खा की कुल जनसंख्या 14534 में सम्मिलित है। यहाँ के निवासियों में 65 से 70 प्रतिशत लोगों का व्यवसाय कृषि है। यहॉ 07 प्राथमिक विद्यालय, 04 परिषदीय विद्यालय 03 डिग्री कालेज, प्राथमिक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चिकित्सालय, विकास खण्ड, विद्युत उपकेन्द्र, वन विभाग तथा रेलवे स्टेशन स्थित है, थाना स्थापित नहीं है। अतः कटेहरी बाजार (प्रतापपुर चमुर्खा), नगर पंचायत सृजन सम्बन्धी शासनादेश में निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं करता है।

अतएव जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त आख्या/प्रस्ताव से स्पष्ट है कि कटेहरी बाजार (प्रतापपुर चमुर्खा), जनपद अम्बेडकरनगर, नगर पंचायत बनाये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 06-10-2016 में निर्धारित मुख्य मानक जनसंख्या 20,000 या उससे अधिक होने, 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होने की पूर्ति नहीं कर रहा है । अतः मानक पूर्ण न होने के दृष्टि से उक्त क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने का अवसर नहीं है।]

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी अधिकारी से नेता बने हैं तो निश्चित रूप से इनकी परिभाषा अलग-अलग नहीं होनी चाहिए। हमारे जिले में इससे कम आबादी की नगर पंचायत बन गयी और प्रतापपुर चमुर्खा वर्ष 1911 की जनगणना में 14 हजार से ज्यादा की आबादी थी आज अगर 2021 में जनगणना हुई होती तो 25 हजार 30 हजार के लगभग आबादी होती ।

माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय भी है, ब्लाक भी है, स्टेशन भी है, सी0एच0सी0 भी है। उसके अलावा कम से कम 7-8 डिग्री कालेज उस गांव में स्थित है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। जब राजे सुल्तानपुर जो उसका आधा हिस्सा भी नहीं था। वह तो नगर पंचायत हो गया। अब प्रतापपुर चमुर्खा पूरे जिले में सबसे बड़ी जगह है वह नगर पंचायत आप नहीं बना रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यह पारशिएलिटी न हो। अगर उससे कम मानक पर दूसरे बन सकते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा मानक पर क्यों नहीं ? हमारा अम्बेडकरनगर, अकबरपुर नगर महापालिका है 27 गांव जोड़े गये हैं। जिन गांव में 70 नहीं 80-90 प्रतिशत कृषि का काम होता है। फिर भी जोड़ दिया गया। अगर वहां जोड़ा जा सकता है तो हमारे साथ भेद-भाव क्यों ? इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको नगर पंचायत बनाने की कृपा करें। यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से राजे सुल्तानपुर में मानक में ढील दी गयी है उसी तरह से ढील देते हुए इसको नगर पंचायत बनाने की कृपा करेंगे। आप विचार कर लीजिए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

किसी भी मानक में कोई ढील देने का किसी मंत्री को स्कोप नहीं होता है। विधायिका जो कानून बनाती है वह सबके लिए बंधनकर्ता होता है। रही बात आपने जिन पिछले दो नगरों

की बात की जहांगीर नगर और राजे सुल्तानपुर मान्यवर, 6 अक्टूबर, 2016 का अपना शासनादेश है जिसमें यह कहा गया है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से जो जनसंख्या आती है उसके हिसाब से यह निर्णय अभी हो रहा है। उस समय के जिलाधिकारी की रिपोर्ट तमाम तथ्यों के मद्देनजर जहांगीर नगर की जो जनसंख्या थी वह बीस हजार से ऊपर पाई गयी, इसलिए उसकी रचना की गयी है। उसी प्रकार राजे सुल्तानपुर जिलाधिकारी के पत्रांक 09/03/2015 और जहांगीर नगर का 22/09/2015 के पत्रों के हिसाब से वे मानक पूर्ण करते थे। इसलिए पूरी छानबीन के बाद उनको नगर पंचायत बनाने का 2020 में निर्णय लिया गया है। आप जिस गांव की बात कर रहे हैं कटहरी बाजार, प्रतापपुर चमुर्खा है। मान्यवर, कटहरी बाजार राजस्व गांव नहीं है। प्रतापपुर चमुर्खा राजस्व गांव है ९ जिसमें कटहरी की जनसंख्या लगभग 5500 है और प्रतापपुर चमुर्खा पूरे गांव की जनसंख्या 14534 है। 2011 की जनगणना के हिसाब से। इसलिए हमारा जो शासनादेश है और हमारी सरकार की जो नीति है उसमें यह गांव फिट नहीं होता है क्योंकि वह बीस हजार का मानक पूर्ण नहीं करता है। मान्यवर, अगली बात आपको अच्छी लगेगी इसलिए कह रहा हूं। जो गांव को जोड़ने की बात है। इस गांव में अन्य गांवों को जोड़कर नगर पंचायत बना दिया जाये। जिससे बीस हजार उसकी आबादी हो जाये। यह स्थानीय विधायक का, स्थानीय नेताओं का, स्थानीय प्रतिनिधियों का अगर सुझाव है और गांव तैयार होते हैं, ग्राम पंचायते तैयार होती हैं तो हमें इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिस गांव की आपने बात की है उस गांव की जनसंख्या मानक के हिसाब से कम है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहांगीर नगर और राजे सुल्तानपुर दोनों में चार-चार, पांच-पांच गांव मिलाकर उसकी जनसंख्या पूरी की गयी। प्रतापपुर चमुर्खा की आज की तारीख में अकेले जनसंख्या बीस हजार से ऊपर है।

श्री अध्यक्ष-

उस समय का सेन्सेक्स है उसमें लिया गया होगा। जैसा कि मंत्री जी ने कहा और आप स्वयं कह रहे हैं कि उसमें कई गांव मिलाकर जनसंख्या पूरी की गयी। यह तो मंत्री जी ने कहा ही है कि आप भी आस-पास के गांव है, उनसे प्रस्ताव करा दीजिए कि वे तैयार हैं तो मंत्री जी कर लेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

अगर मंत्री जी ऐसा कर देंगे तो बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, एक चीज और बता दूं कि अभी तक 2017 तक 652 के नगर निकाय थे पिछले महीनों में हम लोगों ने काफी कुछ इस दिशा में काम किया है और अब वह 762 हो

चुके हैं। इसमें आपका भी बनेगा तो हमे खुशी होगी, लेकिन वह आपको सूचित करना पड़ेगा। परन्तु जो भी अब होगा वह चुनाव के बाद होगा।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चीनी मिल गांगनौली बजाज .....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री का केवल वक्तव्य उन्होंने ही दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[08:29] जनपद-सहारनपुर के बजाज हिन्दुस्तान शुगर प्रा0लि0 में गन्ना किसानों का बकाया धनराशि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवन्द्र कुमार निम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री का केवल वक्तव्य

[हिन्दुस्थान शुगर लि0 समूह की एक इकाई है, जो जिला-सहारनपुर में स्थित है। इस चीनी मिल की पेराई क्षमता 9,000 टी0सी0डी0 है ।

प्रश्नगत चीनी मिल ने पेराई सत्र 2006-07 से अपना पेराई कार्य प्रारम्भ किया था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र, 2007-08 से 2011-12 तक कुल 211.38 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई करते हुए कुल रु0 399.54 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया था। इसी प्रकार पेराई सत्र, 2012-13 से 2016-17 तक कुल 245.77 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई करते हुए कुल रु0 698.33 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया था।

वर्तमान सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-18 से 2021-22 तक कुल 473.84 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई कराते हुए कुल रु0 1,517.43 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया है, जो विगत 10 पेराई सत्रों की गन्ना पेराई एवं कृत गन्ना मूल्य भुगतान से भी अधिक है। इसी के साथ वर्तमान पेराई सत्र, 2022-23 में दिनांक 25-02-2023 तक अद्यतन 81.72 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई चीनी मिल द्वारा की जा चुकी है।

अद्यतन सूचना के अनुसार बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0, गांगनौली द्वारा पेराई सत्र, 2021-22 के अन्तर्गत कुल देय गन्ना मूल्य रु0 359.61 करोड़ के सापेक्ष शत-प्रतिशत भुगतान

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया जा चुका है। पेराई सत्र, 2022-23 के अन्तर्गत चीनी मिल गांगनौली द्वारा अद्यतन देय गन्ना मूल्य रु0 247.86 करोड़ के सापेक्ष रु0 7.45 करोड़ का भुगतान किया गया है। अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु समय-समय पर सक्षम स्तर से आहूत समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रश्नगत चीनी मिल को निर्देश दिये गये हैं। पेराई सत्र 2022-23 अभी गतिमान हैं।

राज्य सरकार गांगनौली चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना कृषकों की समस्याओं एवं गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने हेतु सजग एवं कटिबद्ध है।

डॉ0 रागिनी-

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि यह गम्भीर बीमारी है और बहुत ही संक्रामक बीमारी है और यह पूरे परिवार में बहुत जल्दी फैलती है और इसका ट्रीटमेंट 6 से 12 महीने तक चलता है और उसको अपनी ही सी0एच0सी0 पर दवाई मिल जाये तो बहुत ही अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष-

आप कल इसको लिख कर दे दीजिएगा। अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 08 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 28 फरवरी, 2023 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिए अतारांकित प्रश्न-13 का उत्तर पीछे पृ0सं0-38-39 पर)

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अंग्रेजी माध्यम से संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का विवरण

कम-संख्या	जनपद का नाम	प्राथमिक विद्यालय
1	मेरठ	139
2	बुलन्दशहर	186
3	बागपत	102
4	हापुड़	45
5	गाजियाबाद	397
6	गौतमबुद्धनगर	471
7	सहारनपुर	236
8	शामली	106
9	मुजफ्फरनगर	142
10	आगरा	226
11	फिरोजाबाद	120
12	मथुरा	118
13	मैनपुरी	151
14	अलीगढ़	239
15	एटा	141
16	हाथरस	120
17	कासगंज	87
18	मुरादाबाद	158
19	अमरोहा	120
20	रामपुर	157
21	सम्भल	120

कम-संख्या	जनपद का नाम	प्राथमिक विद्यालय
22	बिजनौर	77
23	बरेली	286
24	बदायूँ	252
25	शाहजहाँपुर	258
26	पीलीभीत	131
27	आजमगढ़	365
28	बलिया	270
29	मऊ	153
30	फैजाबाद	188
31	बाराबंकी	159
32	अम्बेडकरनगर	112
33	अमेठी	215
34	सुल्तानपुर	239
35	बहराइच	209
36	गोण्डा	266
37	बलरामपुर	95
38	श्रावस्ती	90
39	इलाहाबाद	236
40	प्रतापगढ़	327
41	फतेहपुर	205
42	कौशाम्बी	97
43	झाँसी	156
44	जालौन	134
45	ललितपुर	104
46	चित्रकूट	109

कम-संख्या	जनपद का नाम	प्राथमिक विद्यालय
47	बांदा	92
48	महोबा	56
49	हमीरपुर	51
50	गोरखपुर	300
51	कुशीनगर	216
52	देवरिया	175
53	महराजगंज	187
54	बस्ती	196
55	सन्तकबीरनगर	92
56	सिद्धार्थनगर	215
57	कानपुर नगर	211
58	कानपुर देहात	100
59	औरैया	90
60	इटावा	92
61	कन्नौज	132
62	फर्रुखाबाद	85
63	वाराणसी	68
64	चन्दौली	100
65	गाजीपुर	271
66	जौनपुर	345
67	मिर्जापुर	224
68	सोनभद्र	135
69	भदोही	105
70	लखनऊ	136
71	उन्नाव	171

कम-संख्या	जनपद का नाम	प्राथमिक विद्यालय
72	सीतापुर	299
73	हरदोई	297
74	रायबरेली	271
75	लखीमपुर खीरी	224
	योग :	**13250**

नत्थी (ख)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-40 का उत्तर पीछे प्र0सं0-61-62 पर)

ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में जून, 2021 से नवम्बर, 2022 तक कराये गये कार्यों की सूची

विकास खण्ड-पुरवा, जनपद-उन्नाव

क्रम संख्या	कार्य का नाम	मापन/संख्या	अनुमानित धनराशि (रु0)	व्यय धनराशि
1	2	3	4	5
1	रम्माखेड़ा में कल्लू मिस्त्री के घर से विन्दा के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	46 मी0	198000	193645
2	शीतला देवी मन्दिर से रामपाल के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य।	69 मी0	335987	335987
3	कोदइया खेड़ा में विक्रम यादव के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	63 मी0	61000	59270
4	प्रा0वि0 कोदइया खेड़ा में टाईल्स का कार्य	1	173510	171502
5	ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में ओपेन जिम कार्य	1	236880	236880
6	कमला के घर से कोदइया खेड़ा पुलिया तक नाली निर्माण कार्य	163 मी0	250000	246044
7	राजेश के घर से मनोहर के घर तक नाली निर्माण कार्य	130 मी0	246000	241091
8	रम्माखेड़ा में कमला के घर से मनोहर के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	117.50 मी0	476000	474230
9	रम्माखेड़ा में रामपाल के घर से रामविलास के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	94 मी0	416000	402932
10	लाखन के घर से गणेश पण्डित के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	40 मी0	147000	140661
11	त्रिपुरारपुर खुर्द में भरोसे के घर से चन्द गौतम के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	54 मी0	228000	223612
12	पूरनखेड़ा में राजकुमार के घर से मनोज के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	73 मी0	246000	241153

1	2	3	4	5
13	मण्डफी देवी मन्दिर प्रांगण में इण्टरलॉकिंग कार्य	40 मी0	146000	159420
14	ओपेन जिम के चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	85 मी0	380000	375807
15	प्रा0वि0 त्रिपुरारपुर द्वितीय में झूला अवस्थापना कार्य	5 सेट	105480	85120
16	विभिन्न स्थानों पर ह्यूम पाइप का कार्य	6 अदद	15144	15144
17	ग्रा0पं0 में फर्नीचर, सोलर पैनल व कम्प्यूटर क्रय	1 सेट	175000	173524
18	गुडडा पण्डित के घर से रामविलास के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	16 मी0	62000	59009
19	त्रिपुरारपुर में सुन्दर के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य	1 अदद	79000	73324
20	प्रा0वि0 त्रिपुरारपुर प्रथम में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	1 अदद	259000	250753
21	प्रा0वि0 त्रिपुरारपुर प्रथम में शौचालय मरम्मत कार्य	1 अदद	43167	42989
22	प्रा0वि0 त्रिपुरारपुर प्रथम में रूफटाप रेनवाटर हारवेस्टिंग	1 अदद	110700	94936
23	प्रा0वि0 त्रिपुरारपुर पूरनदास खेड़ा में पोषण वाटिका	1	57259	48974
24	प्रा0वि0 त्रिपुरारपुर प्रथम में कायाकल्प कार्य	1	158000	157373
25	प्रा0वि0 त्रिपुरारपुर प्रथम में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	58 मी0	259000	250753
26	प्रा0वि0 त्रिपुरारपुर द्वितीय में शौचालय मरम्मत कार्य	1	52900	38032

उप निदेशक (पं0),
पंचायती राज, उ0प्र0।

नत्थी (ग)

देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-110 का उत्तर पीछे पृ0सं0-96 पर)

ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में कराये गये हैण्डपम्प मरम्मत की सूची

क्रम-सं0	हैण्डपम्प मरम्मत के नाम	ग्राम का नाम
1	रामखेलावन के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर खुर्द
2	मंगल पासी के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर खुर्द
3	सूर्यपाल पासी के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर खुर्द
4	मुन्नू की दुकान के पास हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर कला
5	रामदेव गुप्ता के घर के पास हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर कला
6	मनोज पटेल के घर के पास हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर कला
7	रामबहादुर गौतम के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर खुर्द
8	रघई की चक्की के पास हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	पूरनखेडा
9	पुत्ती पंडित के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर कला
10	लल्उनू के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	पूरन दासखेडा
11	मोनू के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर कला
12	पंचायत भवन त्रिपुरारपुर में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर कला
13	संतोष पासी के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर
14	आर्यावत ग्रामीण बैंक के पास हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर कला
15	प्यूस पटेल के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर कला
16	प्राथमिक विद्यालय द्वितीय मे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर कला
17	सुल्ला के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	रम्माखेड़ा
18	प्राथमिक विद्यालय पूरनखेड़ा में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	पूरनखेडा
19	काली माता मन्दिर के पास हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	पूरनखेड़ा
20	मास्टर के दरवाजे ईण्ड पम्प मरम्मत कार्य	पूरनखेडा
21	ब्रजलाल यादव के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	पूरन दासखेडा
22	सकतु के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर
23	दीपू के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	कोदईया खेदा

क्रम-सं0	हैण्डपम्प मरम्मत के नाम	ग्राम का नाम
24	अशर्फी मास्टर के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर कला
25	पब्लिस के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर कला
26	सुमित्रा के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	रम्माखेडा
27	मनीष निर्मल के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर कला
28	प्रा0वि0 कोदईयाखेडा में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	कोदईखेडा
29	महेश पासवान के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर खुर्द
30	रामसनेही यादव के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	पूरनदास खेड़ा
31	रामस्वरूप के दरवाजे हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	रम्माखेडा
32	प्रा0वि0 पूरनदास खेड़ा में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	पूरनदास खेडा
33	राजबहादुर के घर के पास हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	पूरनखेडा
34	रामविलास साहू के घर के पास हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर कला
35	रविदास मन्दिर के पास हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	रम्माखेडा
36	बालविद्या मन्दिर इण्टर कालेज हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर कला
37	देवीदीन बाबा मन्दिर के पास हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर कला
38	आर्याव्रत ग्रामीण बैंक के पास दोबारा हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	त्रिपुरारपुर कला

ग्राम पंचायत अधिकारी,

सहायक विकास अधिकारी,
विकास खण्ड पुरवा,
उन्नाव।

ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में कराये गये हैण्डपम्प रि-बोर की सूची

क्रम-सं0	हैण्डपम्प रि-बोर के नाम	व्यय धनराशि (रु0)
1	शारदा मन्दिर कोदईया खेड़ा में हैण्डपम्प रि-बोर कार्य	28120
2	कोदईया खेड़ा में बाबूलाल के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिवोर	26171
3	रम्माखेडा में रामस्वरूप के दरवाजे पर हैण्डपम्प रि-बोर कार्य	29320
4	साधन सहकारी समिति के पास हैण्डपम्प रि-बोर कार्य	29320
5	देवीदीन बाबा मन्दिर के प्रांगण में हैण्डपम्प रि-बोर कार्य	29520
6	प्रा0वि0 त्रिपुरारपुर प्रथम में हैण्डपम्प रि-बोर कार्य	29520
7	पूरन दास खेडा में बृजलाल यादव के दरवाजे पर हैण्डपम्प रि-बोर कार्य	29520
8	पूरन दास खेडा में सुबाष के दरवाजे पर हैण्डपम्प रि-बोर कार्य	22149
9	घोईयादीन के दरवाजे पर हैण्डपम्प रि-बोर कार्य	26100
10	भीमशंकर त्रिपाठी के दरवाजे पर हैण्डपम्प रि-बोर कार्य	28150
	योग :	**273890.00**

ग्राम पंचायत अधिकारी,

सहायक विकास अधिकारी,
विकास खण्ड पुरवा,
उन्नाव।

नत्थी (घ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-152 का उत्तर पीछे पृ0सं0-119-120 पर)

विकास खण्ड-जौनपुर

संगठन का नाम-शारदा सहायक

वर्ष 2023-23 रबी 1430 फसली में सिल्ट सफाई की जाने वाली नहर का विवरण

क्र0-सं0	जनपद का नाम	विधान सभा का नाम	प्रणाली का नाम मड़ियाहूँ शाखा	राजवाहा/ अल्पिका का नाम कुंवरपुर रा0	प्रस्तावित कार्यक्रम		अभ्युक्ति
					प्रस्तावित सिल्ट सफाई का कार्य	प्रस्तावित स्कैपिंग का कार्य	
					लम्बाई (किलोमीटर में)	लम्बाई (किलोमीटर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जौनपुर	मछलीशहर	मड़ियाहू शाखा	कुरपुर रा0	10.30	7.70	कार्य पूर्ण हो चुका है
2		मछलीशहर		मछलीशहर रा0	0.00	7.60	
3		मछलीशहर		मछलीशहर रा0	0.00	6.00	
4		मछलीशहर		पवारा मा0	3.00	0.00	
5		मछलीशहर		आसापुर मा0	4.00	1.30	
6		मछलीशहर		पूरया रा0	9.00	9.40	
		योग राजवाहा			**26.30**	**32.00**	
7		मछलीशहर	मडियाहूं शाखा	बरईपार मा0	3.40	0.00	
8		मछलीशहर		पतुलकी मा0	6.40	0.00	
9		मछलीशहर		मिर्जापुर मा0	5.80	0.00	
10		मछलीशहर		खिरयागड़ मा0	3.80	0.00	
11		मछलीशहर		तिलौरा मा0	3.00	0.80	
12		मछलीशहर		कल्यानपुर मा0	2.60	1.60	
13		मछलीशहर		रानीपुर मा0	2.60	3.00	
14		मछलीशहर		कुम्भी मा0	4.00	1.90	
15		**योग 8.00 क्यूसेक से अधिक की अल्पिकायें**			**31.60**	**7.30**	
16		मछलीशहर	मडियाहूं शाखा	राजगढ़ मा0	3.90	0.00	
17		मछलीशहर		साहिजदपुर मा0	4.20	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
18		मछलीशहर	मडियाहूँ शाखा	पहाड़पुर मा0	1.00	0.00	
19		मछलीशहर		निजामुद्दीनपुर मा0	1.50	0.00	
20		मछलीशहर		तुलापुर मा0	4.70	0.00	
21		मछलीशहर		जमालपुर मा0	1.40	0.00	
22		मछलीशहर		करौदा मा0	2.80	0.00	
23		मछलीशहर		घिसूआ मा0	4.50	0.00	
24		मछलीशहर		अल्लापुर मा0	2.50	0.00	
25		मछलीशहर		कल्यानपुर मा0	1.20	0.00	
26		मछलीशहर		पीरपुर मा0	1.80	0.00	
27		मछलीशहर		पीहा मा0	2.50	0.00	
28		मछलीशहर		रामपुर मा0	1.50	0.00	
29		मछलीशहर		गोहका मा0	1.70	0.00	
30		मछलीशहर		बीबीपुर मा0	2.00	1.00	
31		मछलीशहर		अरूआया मा0	1.50	0.90	
32		मछलीशहर		बड़ेरी मा0	0.00	1.60	
33		मछलीशहर		टेकरी मा0	2.20	0.00	
34		मछलीशहर		जमुआ मा0 प्रथम	0.00	1.40	
35		मछलीशहर		हसनपुर मा0	0.00	1.20	
36		मछलीशहर		बस्ती मा0	1.50	0.00	
37		मछलीशहर		बरौली मा0	1.70	0.00	
38		मछलीशहर		गौहर मा0	3.80	0.00	
39		मछलीशहर		मलिकानपुर मा0	1.05	0.00	
40		मछलीशहर		गौरा मा0	0.60	0.00	
41		मछलीशहर		मीरपुर मा0	1.70	0.00	
		योग 8.00 क्यूसेक से कम की अल्पिकायें			**51.25**	**6.10**	
		योग विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर			**109.15**	**45.40**	

पी0एस0यू0पी0 एल0 201 विधान सभा (324)-12-01-2024-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।